

प्रकाशक
अध्यापक प्रकाशन मण्डल
१६१, गडबडझाला पार्क,
लखनऊ ।

प्रथम संस्करण, १२००
मूल्य : तीन रुपया

मुद्रक
गौरीशंकर प्रेस
वनारस ।

अपनी ओर से

महामानव गांधी और पं० नेहरू भारतवर्ष के उन महान नेताओं तथा मूर्तिमान आदर्शों के रूप में माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति के साथ-साथ मानव-जाति को शान्ति-दूत की तरह सत्य, अहिंसा और मानवता का दिव्य सन्देश सुनाया है। बड़े-बड़े संवर्ष में दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के पूरक हो कार्य करते रहे, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक हों। दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण लगते थे। 'उन्हां के सफल नेतृत्व में देश ने पराधीनता की अन्धकारमयी निशा से निकल कर स्वाधीनता-सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों से जगमगाते हुए सुनहरे प्रभात के दर्शन किये।'

परन्तु उन दोनों व्यक्तियों का मानवीय मान्यताओं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण में अन्तर था। यद्यपि दोनों व्यक्ति के एक ही महान लक्ष्य थे परन्तु उस तक पहुँचने के भिन्न-भिन्न रास्ते थे। दोनों ही व्यक्तियों के विचारों में असमानता और कार्यक्रम में विपमता होते हुए भी उनमें अपूर्व सामंजस्य था। दोनों को ही कभी-कभी एक दूसरे के विचार अपरिचित से लगते थे तथा मतभेद की गरम हवा से झुलस कर दोनों ही तिलमिला उठते थे, लेकिन फिर भी दोनों ही के दिल एक दूसरे पर विश्वास करते थे। एक स्थान पर स्वयं नेहरू जी ने ही स्वीकार किया है "प्रायः प्रत्येक बात में मेरा उनका मतभेद है। तो भी वे अनमोल हैं, मैं उनका अनुसरण करता हूँ।" महात्मा गांधी ने एक बार कुछ विश्वास और गर्व से लिखा था "विचारों में मतभेद होने के पश्चात् भी मैं यह जानता हूँ कि जत्र मैं न रहूँगा, तो वह मेरी ही भाषा बोलेंगे।" सचमुच यद्यपि आज युग-पुरुष महामानव गांधी न रहे, किन्तु उनके व्यक्तित्व और आदर्श का मूर्तमान रूप नेहरू में व्याप्त हो देश की रक्षा कर रहा है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भी वे आज अहिंसा और सत्य की बुनियाद

लेकर, भ्रातृप्रेम और समानता के धरातल पर, सुख-शांति से परिपूर्ण महान भारत के निर्माण में, महात्मा गांधी के निदेशानुसार, रत है। पं० नेहरू के जीवन के साथ आज हम पैंतीस कोटि भारतीयों का भाग्य बंधा हुआ है। उनके जीवन की प्रत्येक सौंस स्पन्दित हो, आज राष्ट्र के कण-कण को जीवन-दान दे रही है। उनके जीवन का प्रत्येक अंग हमारे लिए आराध्य बन गया है, और उनके इङ्कित मात्र पर उन्हीं के पद-चिह्नों का अनुसरण करता हुआ राष्ट्र का कारवों आज उन्नति की मंजिल तय कर रहा है।

महात्मा गांधी ने वर्षों पहले नेहरू जी के सम्बन्ध में कहा था, “बहादुरी में उनसे बढ़ कर कोई नहीं है। देश-प्रेम में उनसे बढ़ कर कौन हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि वे जल्दवाजी करनेवाले गरम मिजाज के हैं। वर्तमान समय में तो यह गुण है। यदि उनमें योद्धा की तीव्रता और उतावलापन है, तो साथ ही एक राजनीतिज्ञ की विलक्षण बुद्धि भी है। . . . निःसंदेह वे ऐसे उग्र विचार के हैं, जो अपने चारों ओर के वातावरण से बहुत आगे सोचते हैं। किन्तु वे इतने विनम्र और व्यावहारिक भी हैं कि इतना पग नहीं बढ़ाते कि वैमनस्य पैदा हो जाये। वे स्फटिक के समान निर्मल हैं और उनकी सच्चाई सन्देह से परे है। वे निर्भय एवं अनिच्छ योद्धा हैं। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है।” सचमुच गांधी जी के राजनीतिक गणित में नेहरू जी एक विशेष अंक थे।

१९४२ में स्वयं डा० पट्टाभि सातारमैय्या ने पं नेहरू और महात्मा गांधी के बारे में लिखा था, “शारीरिक रचना, विश्वास और तर्क-विद्या में एक दूसरे में पृथ्वी के ध्रुवों का सा अन्तर है। . . . गांधी जी एक तत्वशानी हैं, जब कि जवाहरलाल एक राजनीतिक और सासारिक पुरुष हैं। तो भी गांधी जी प्रेरणा हैं और जवाहरलाल साधन हैं। . . गांधी जी और जवाहरलाल गंगा-यमुना के संगम के समान हैं, एक अहिंसा के अपने निर्मल जल के साथ है और दूसरे में रोष, क्रोध और आवेग का किंचित् मटमैलापन है। लेकिन दोनों ही दो धार की तरह थोड़ी देर तक

एक दूसरे ने अलग-अलग चल कर एक हो जाते हैं, जिससे कि चौड़ाई और गहराई का ऊँचाई के साथ, विज्ञान का तर्क शास्त्र के साथ, भौतिकता का आध्यात्मिकता के साथ और हिंसा का अहिंसा के साथ मिलाप हो जाता है ।”

गांधी जी के एक विश्वस्त शिष्य और सहयोगी होने के कारण नेहरू जी ने अपनी असाधारण योग्यता से देश की राजनीति में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है । भारत के लिए पं० नेहरू की सेवाएँ अपूर्व हैं । उनके विचार अपना पृथक् और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । भारतीय जनता उन विचारों की तरंगों में बहती हुई स्वर्णिम विहान का स्वप्न देख रही है ।।

गांधी जी के विपरीत नेहरू जी के विचारों की पृष्ठभूमि धार्मिक नहीं है । परन्तु उन्हीं की तरह नेहरू जी को भी उन धार्मिक मनुष्यों से घृणा है, जो समाज की आवश्यकताओं की उपेक्षा कर केवल अपनी ही मुक्ति में लगे रहते हैं । वे उन धार्मिक बंधनों तथा रुढ़ियों की वेडियों का भन-भना कर तोड़ डालना चाहते हैं जो समाज में वर्ग और वर्ण-व्यवस्था को आश्रय देती है । नेहरू जी तथाकथित धर्म को अफीम मानते हैं जो व्यक्तियों में अन्धविश्वास, कट्टरता, साम्प्रदायिक धार्मिक मनोवृत्ति और असहायों के शोषण की शिक्षा देता है । वे मानवमात्र के लिए धर्म का परिभाषा बदलना चाहते हैं तथा उसे संसार में प्रेम, साहचर्य और सहायता का प्रतीक बनाना चाहते हैं । वे फ्रेन्च दार्शनिक रोम्यो रोला की धर्म समझ की निम्न परिभाषा से कदाचित् अत्यन्त प्रभावित हुए हैं, “सत्य की खोज में समस्त कष्ट उठा कर और एकचित्त होकर ईमानदारी के साथ आत्मत्याग करने के लिए तैयार रहो, मानव-प्रयत्न के एक अंतिम उद्देश्य में विश्वास रखो, जो वर्तमान समाज और समस्त मानव जाति के जीवन से भी अधिक ऊँचा है ।”

नेहरू जी पाश्चात्य संस्कृति और रहन-सहन में स्थित अच्छे तत्वों से भी प्रभावित हैं, और वे समझते हैं कि यदि भारत विकास और उन्नति की

दौड़ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पाश्चात्य सस्कृति के उच्च गुणों को ग्रहण करना होगा। वे नागरिक जीवन को उन्नत करना चाहते हैं तथा किसान और मजदूरों की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्हें अधनंगे और अधमूखे कृषकों की दैन्य अवस्था ने अरुचि है। वे इन शोषित-शापित मानवों को पशु की तरह जीवन व्यतीत करने से मुक्त करना चाहते हैं।

नेहरू जी औद्योगीकरण के पक्ष में हैं और वे सोचते हैं कि आज के मर्गान के युग में देश की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन मशीनों द्वारा ही हो सकता है। परन्तु भारत के यात्रिक विकास के द्वारा, उनका उद्देश्य किर्न। अन्य निर्वल राष्ट्र पर, पश्चिम के बड़े राष्ट्रों की भाँति, अपना आर्थिक प्रभुत्व (Economic Imperialism) स्थापित करना नहीं है। वे भारत के साथ ही सभी राष्ट्रों को सुखी और समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं। वे गरीबों को अभिशाप समझते हैं, तथा सोचते हैं, कि व्यक्ति के मानवोचित गुणों का विकास इस स्थिति में कदापि नहीं हो सकता। उनके अनुसार किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अवकाश के समय चरखे चलाना तथा अन्य उद्योग-वन्धे करना चाहिए।

नेहरू जी कार्ल मार्क्स के साम्यवादी सिद्धान्तों के अनुयायी अवश्य हैं किन्तु लाल रूस के वादिक दास नहीं। वे मानवीय प्रवृत्तियों के पूर्ण विकास के लिए सभी व्यक्तियों में समता आवश्यक समझते हैं। उनके अनुसार जिन लोगों को केवल पेट भरने के लिए परिश्रम करके केवल दो पैसे क्रमान की चिन्ता है, वे केन्द्रीय नैतिक सुधार, राष्ट्रप्रेम, साहित्य, कला और सादर्य की बातों को कहाँ तक समझ कर उनमें योग दे सकते हैं? वे उन व्यक्तियों की ओर करुण दृष्टि से देखते हैं जो गरीबों और श्रम के शिकार हैं, जिनकी गर्दन और पाँठ झुकी हुई है और आत्मा कुचली हुई। वे उनकी उन्नति के लिए अपने को जिम्मेदार समझते हैं अतः उन्हें उनकी चिन्ता है। वे जानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने पर व्यक्तियों के रहन-सहन में स्वयं परिवर्तन होने लगेगा

और तब व्यक्तियों को आत्मोन्नति का अवसर मिलेगा । आज के वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति के युग में किसी देश में गरीबी को रहने का कोई अधिकार नहीं है । वे समझते हैं कि यदि किसी राष्ट्र में इस कोढ़ के कीटाणुओं ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है तो इसके लिये दोषी उस देश की जनता तथा जन-नेता हैं ।

नेहरू जी धार्मिक आधार पर बने हुए, भारत के सम्पूर्ण पोंगा पंथी सामाजिक ढाँचे के विरोधी हैं तथा उसे उत्साहपूर्वक नये प्रगतिशील आधार पर निर्मित करना चाहते हैं । वे वर्ण-व्यवस्था भंग कर दलित अछूतों को सबर्णों की श्रेणी में बैठाना चाहते हैं । वे उन्हें वह सभी सुविधाएँ प्रदान करना चाहते हैं जिन्हें सृष्टिवादी धर्म ने सिर्फ सबर्णों को ही सौंप दिया है । वे पशु सा जीवन व्यतीत करने वाले दलित वर्ग को समता के सिद्धान्त के अनुसार पुनः मानव की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं । वे जानते हैं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम उनकी आर्थिक स्थिति सुधार कर उनमें शिक्षा का प्रसार करना आवश्यक है ।

राजाओं, पूँजीपतियों और जमींदारों से नेहरू जी की कभी भी सहानुभूति नहीं थी । नेहरू जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, “राजा, नवाब और जमींदार आदि ‘मध्यकालीन युग की स्वेच्छाचरिता’ के यादगार हैं, जो अपने निजी ऐश-आराम के लिए दीन प्रजा का घन पानी की तरह बहाते हैं । उन्हें अपनी प्रजा के सुख-दुख की कोई भी चिन्ता नहीं है ।” नेहरू जी का यह विश्वास था कि यह वर्ग कभी भी सुधारा नहीं जा सकता अतः इसका अन्त भारत की उन्नति के लिए आवश्यक है । वे स्वतंत्र भारत में स्वेच्छाचारी राजाओं तथा जमींदारों के लिए कोई भी स्थान नहीं रखना चाहते थे । भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् उन्होंने अपने निश्चयानुसार इस दिशा में कदम बढ़ाया तथा भारत के इन देशी राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को भारतीय राष्ट्र में विलीन कर उन्हें नौ प्रान्तों का रूप दे दिया । इसी प्रकार उनके प्रयत्न से भारतीय धारासभा में

जमींदारी-उन्मूलन-बिल भी पास हो गया तथा इस दिशा में अनेक प्रान्तों में काफी कार्य भी हो चुका है, और मुपतखोर जमींदारों का अनंक स्थानों पर पूर्णतः अन्त भी हो चुका है। पूँजीवाद का अन्त करने के लिए कोई सुदृढ़ तथा परिवर्तनकारी कदम अभी नेहरू-सरकार की ओर से नहीं लिया गया है परन्तु इस दिशा में भी वे प्रयत्नशील है। राष्ट्र के पूर्ण विकसित हो जाने के पश्चात् सभी बड़े उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीयकरण कर लेने की घोषणा सरकार की वाणिज्य नीति में हो ही चुकी है।

यद्यपि नेहरू जी गांधी जी के अहिंसा के सिद्धान्त को मानते हैं किन्तु इसका यह कदापि तात्पर्य नहीं कि वे राष्ट्रीय हित को सकट में देख कर भी उसका राग अलापते रहेंगे। नेहरू जी की अहिंसा की नीति एक सिद्धान्त है जिसका उद्देश्य है शान्ति, तथा अकारण हो दूसरों पर अपनी शक्ति और सत्ता का प्रयोग न करना। परन्तु यदि आवश्यकता होगी और परिस्थितियों बाध्य करेगी तो वे अपने देश और जनता की रक्षा के लिए तलवार उठाने में कदापि न हिचकेंगे। जैसा कि वे लुटेरे आततायी आक्रमणकारियों के विरुद्ध काश्मीर में, वहाँ की जनता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कर रहे हैं, और हैदराबाद में सफलतापूर्वक कर चुके हैं। वे जानते हैं कि साम्राज्यवादी शोषण और आक्रमण के लिए उठी तलवार का जवाब तलवार से ही देना होगा, तथा साम्राज्यवाद और पूँजीवाद की जर्जर भित्तियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी पश्चिम के उठे कदमों को, विश्व-कल्याण के लिए थोड़ा-थोड़ा छोटा कर देना होगा।

१६/४६ ठठेरी बाजार,
काशी। }

प्रमोद कुमार अग्रवाल

धन्यवाद-प्रकाशन

सर्वप्रथम मैं श्री सुधाकर पाण्डेय के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिनके अदम्य परिश्रम के फलस्वरूप यह पुस्तक इतनी शीघ्रता के साथ मुद्रित हो सकी। पाठकों के समक्ष इस रूप में पुस्तक उपस्थित होने का सारा श्रेय श्री कृष्णचन्द्र वेरी को है, अतः वे मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मैं उन लेखकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनकी बहुमूल्य रचना से मैंने इस पुस्तक के निर्माण में सहायता ली। उन सभी मित्रों तथा सहयोगियों को भी, जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपने श्रम अथवा प्रोत्साहन से इस कार्य में मुझे सहायता दी है, मैं धन्यवाद देता हूँ।

अत्यधिक शीघ्रता के कारण मुद्रण में त्रुटियाँ रह गयी हैं, अतः पाठकों से मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ। पुस्तक के सम्बन्ध में आपके विचारों तथा सुझावों का मैं स्वागत करूँगा।

—लेखक

समर्पण



उसी महान् आत्मा को, जिसने
समर्पण की मेरी किञ्चित्
आकाक्षा को निर्ममता
पूर्वक दुकरा
दिया ।



अकिञ्चन—
प्रमोद

सूचीपत्र

संख्या	क्रम	पृष्ठ संख्या
(१)	वंश-परिचय	१
(२)	वचन और शिक्षा	७
(३)	विदेश-यात्रा तथा उच्च शिक्षा	१४
(४)	भारतीय राजनीति में पदार्पण	२०
(५)	राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का प्रवेश तथा प्रभाव	२८
(६)	किसान-आन्दोलन के नेता	३३
(७)	असहयोग-आन्दोलन और जेलयात्रा	४१
(८)	कांग्रेस में सैद्धान्तिक मतभेद	५८
(९)	नेहरू और नाभा-आन्दोलन	६३
(१०)	राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक सेवा	६६
(११)	यूरोप-यात्रा	७१
(१२)	भारत की राजनीतिक-स्थिति तथा साइमन कमीशन	७७
(१३)	जननेतृत्व	८६
(१४)	राष्ट्रपति जवाहरलाल	९०
(१५)	सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन	९७
(१६)	यरवदा-सन्धि-चर्चा तथा कर-बंदी आन्दोलन	१०२
(१७)	पं० मोतीलाल का देहावसान	१०७
(१८)	गांधी-इर्विङ्ग-पैकट और उसके पश्चात्	१०९
(१९)	गोलमेज-परिषद् की असफलता और उसके पश्चात्	११५
(२०)	जन-आन्दोलन, जेल-जीवन तथा अन्य कार्य	१२४
(२१)	बिहार-भूकम्प में नेहरू जी के कार्य	१३२
(२२)	श्रीमती कमला नेहरू	१३९

संख्या	क्रम	पृष्ठ संख्या
(२३)	लखनऊ और फैजपुर-कांग्रेस एवं चुनाव	१४८
(२४)	युद्ध-संकट और भारत	१५६
(२५)	सन् वयालीस	१६७
(२६)	आजाद हिन्द फौज के मुकदमे	१७३
(२७)	पाकिस्तान की माँग	१८०
(२८)	प्रधान मन्त्री नेहरू	१८७
(२९)	विधान-परिषद् और नेहरू	१९८
(३०)	एशियाई सम्मेलन और नेहरू	२०३
(३१)	भारतीय स्वतन्त्रता दिवस	२१०
(३२)	साम्प्रदायिक दंगे	२१६
(३३)	महामानव गार्धी का महाप्रयाण	२२४
(३४)	देशी रियासतों की समस्या	२३१
(३५)	काश्मीर की समस्या	२४५
(३६)	अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अव्येता और आलोचक नेहरू	२५७
(३७)	नेहरू और ब्रिटिश कामनवेल्थ	२६४
(३८)	प्रधान-मन्त्री नेहरू का अमेरिका में पदार्पण	२७७
(३९)	चीन और पं० नेहरू	२८६
(४०)	सोवियत रूस और पं० नेहरू	२९७
(४१)	नेहरू-सरकार की वैदेशिक नीति	३०८

ये हैं हमारे राष्ट्रायक जवाहरलाल नेहरू

जनतन्त्रात्मक महान् भारत के प्रथम प्रधान मंत्री । एकहरा किन्तु नरा
हुआ वदन, उन्नत ललाट पर खल्वाट खोपड़ी और चेहरे पर एक दृष्टि
हँसता हुआ पश्चिम सागर की ओर झुकते हुए सांध्य रवि सा तेज ।
आकृति में स्पष्ट काश्मीरी या योरोपीय । अब भी युवा, भावुक, विनोदी,
उत्साही, सुदर्शन और फक्कड़ !

एक !

✽

✽

✽

स्वभाव फुर्तीला, किन्तु थोड़ा सहसाकर्मी मिलनसार के साथ ही
साथ झुंझला पड़ने की आदत । थोड़े जिद्दी तब तक किसी की बात
न मानेंगे जब तक कोई उनमें भी अधिक झुंझलाकर वह बात उन्हें
मनवा न दे । जब हँसते हैं तो बिल्कुल मामूली वच्चों की तरह, प्रधान
मंत्री की तरह नहीं, और बिल्कुल जी खोलकर ।

दो !!

✽

✽

✽

वेश-भूषा तीन प्रकार की सफेद गाँधी टोपी, खड़ी बा कुर्ता, बाँता
और सदरी । विदेश में जाते हैं तो सूट और हेट पहन लेते हैं ।

तीन !!!

✽

✽

✽

कट्टर देशभक्त, पर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के समर्थक । भारत-गिराई
बात से चिढ़; जीवन के प्रत्येक पहलू में नानाविधान का पुट । अनु-

शासन और नियंत्रण के पुजारी और निश्चित समय पर निश्चित काम; कुछ जल्द बाज । देश-द्रोहियों की सूरत से नफरत । जो कहेंगे वही करेंगे । व्यर्थ की बात सुनते ही भुँकला पड़ेगे । जरा सा मन के विरुद्ध काम होने पर सब को डोट देंगे, परन्तु कुछ क्षण पश्चात् ही उससे क्षमा भी माँगेगे । तर्क में गांधी जी से नहीं चली नहीं तो सभी को दबा दिया, सदैव ।

चार ।

✱

✱

✱

पत्थर से कठोर और नवजात पुष्प से भी कोमल । क्रोध की मूर्ति, पर करुणा के अवतार । धनी कुल में उत्पन्न होकर निर्धन से निर्धन और दलित से दलित से भी भाईचारा जोड़नेवाले, तथा उनके दिल की दशा समझनेवाले । मानवता के पुजारी पर दानवता के कट्टर शत्रु । रहस्यमय, किन्तु स्पष्टवादी । उच्चश्रेणी के आत्मामिमामी, किन्तु देश और पीड़ितों के लिए अपमान सहनेवाले । हृदय में दो विरोधी भावों और विचारों में सदा संघर्ष तथा अन्तर्द्वन्द्व, किन्तु उसे प्रकट करने में बिल्कुल स्पष्ट ।

पाँच !!

✱

✱

✱

साम्राज्यवाद और सम्प्रदायवाद के कट्टर शत्रु, किन्तु समाजवाद के समर्थक । अपनी मौलिकता के लिए प्रसिद्ध, पर बहुमत के आगे नत-मस्तक । कठोर शासक किन्तु प्रजातंत्र के पुजारी ।

छः !!!

✱

✱

✱

विधुर । दो बहिनें और भाजियों । एक मात्र पुत्री और दो नन्हे दौहित्र का छोटा सा परिवार । राजनीतिक और देश सम्बन्धी कार्यों से जब अवकाश मिलता है तब कभी-कभी छोटे-छोटे दौहित्रों से खेल लेते

हैं—कभी कंधे पर चढ़ाते हैं, और कभी एक को सवार बनाकर स्वयं घोड़ा बन जाते हैं।—इतने महान् व्यक्ति का यही छोटा सा पारिवारिक जीवन है।

सात !

*

*

*

उनसे बात करना क्या उनके दर्शन मात्र से हृदय प्रसन्न हो जाता है। वे कभी-कभी भूल से जाते हैं कि उनपर इतने बड़े देश का इतना महान् उत्तरदायित्व है। उस समय वे वच्चो से भी सरल मालूम होते हैं। उनकी मुस्कुराहट से बरबस उनकी ओर प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो जाता है।

आठ !!

*

*

*

लेखक हैं और कविताओं से प्रेम करते हैं। अंग्रेजी साहित्याकाश के चमकते हुए नक्षत्र हैं। कई महान् ग्रंथों के प्रणेता। उनकी लेखनी में ओज है, और है विचारों का अन्तर्द्वन्द्व। उनके विषय में मैडम च्याङ्गकाई शेक ने लिखा है कि जब उनका राजनीतिक कार्य समाप्त होगा तो वे साहित्यिक की भोंति जीवित रहेंगे।

नौ !!!

*

*

*

पक्षियों, फूलों और पर्वतों, झरनों और हिम प्रदेशों से विशेष प्रेम, परन्तु अपने प्रिय स्थानों को देखने का अवकाश नहीं है। कभी-कभी उदास और अंतस की गहराइयों का अनुभव करने वाले।

दस !

*

*

*

स्त्रियों आकृति पर विशेष आकृष्ट होती हैं; क्योंकि उनके रूप के अलावा उनकी हँसती हुई आँखों में एक अजीब आकर्षण है। कोई-कोई

(१६)

प्रगल्भा तो मुस्कराकर यहाँ तक कहती है कि कमला दीदी की मृत्यु के पश्चात् इतने दिनों तक अकेले रहने का उन्हें कोई 'हक' नहीं था ।

ग्यारह !!

*

*

*

आने वाले युग उनके त्याग की कहानियों अपने बच्चों को सुनाकर उन्हें राष्ट्र-प्रेम के लिए बावला बनाते रहेंगे । देश के इतिहास में उनका नाम तब तक स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा, जब तक भारत का एक बच्चा भी जीवित रहेगा ।

बारह !!!

*

*

*

— — —

वंश-परिचय

अठारहवीं शताब्दीके आरम्भ में काश्मीर की सुन्दर, शस्य श्यामला तलहटी में उन अभागों की वस्ती थी जो प्रकृति की परिपूर्ण श्री पाकर भी सैकड़ों वर्षों से धैर्यपूर्वक केवल दुसह दारिद्र्य में पलने के आदी हो चुके थे, और जिनमें भावी उन्नति की कभी एक किरण भी नहीं दिखलाई पड़ी। घरती के उस एकान्त कोने के उन अपद पर निष्कूल परिवारों में कुछ ऐसे ब्राह्मण परिवार भी थे जो अपनी ज्ञान-गरिमा से सम्पूर्ण काश्मीर में प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रतिष्ठित परिवारों में से एक कौल वंश भी था। जीवन की अलभ्य आवश्यकताओं की कड़ी चोट से आक्रान्त इस काश्मीरी समाज के कुछ परिवारों ने अपने दिल पर पत्थर रखकर साहसपूर्वक अपना सुन्दर, पर निर्धन देश छोड़ कर समतल भूमि पर जीविका की खोज के लिए उतर आये। यह छोटा सा प्रवासी समाज अपनी आदि भूमि, अपने शारीरिक सौन्दर्य और अपनी कुशाग्र बुद्धि पर आज भी उचित गर्व करता है। यद्यपि पं० नेहरू के पूर्वज कौल वंशियों को अपनी जन्मस्थली से काफी स्नेह था और वे साधारण ऐश्वर्य की लालसा में पड़ कर अन्य लोगों की भाँति अपने प्रदेश को छोड़ने के लिए प्रस्तुत न थे; किन्तु नियति को यह अमीष्ट न था। उसे तो उनकी आगत संतानों से राष्ट्र का भाग्य संचालन कराना था।

१८ शताब्दी के आरम्भ होते होते मुगल सल्तनत का पूर्ण पतन हो चुका था। मुगल औलादों के रक्त ठंडे पड़ चुके थे। विलास की ओंधी में यद्यपि वे शौर्य और कर्तव्य का मार्ग भूल चुके थे फिर भी परम्परागत

संस्कारों से प्राप्त मानव-रत्न को परखने की सहज बुद्धि अभी उन्होंने खोयी नहीं। औरंगजेब की सल्तनत का नाम मात्र का वारिस फर्रुखसियर जब काश्मीर गया तब उसकी दृष्टि कौल वंश के तत्कालीन कुलपति राज-कौल पर पड़ी। वह उनका संस्कृत और फारसी का ज्ञान देख कर मुग्ध हो गया। बादशाह के प्रस्ताव पर राजकौल ने कुछ तो कुतूहलवश और कुछ महत्वाकांक्षा के वश होकर उनके साथ दिल्ली चलना स्वीकार कर लिया।

दिल्ली आगमन के पश्चात् बादशाह ने अपने स्नेहभाजक राजकौल के निवास के लिए एक भवन तथा कुछ जागीर देकर दिल्ली दरबार में सम्मानित किया। मकान नहर के किनारे होने से स्वभावतः परिवारवाले 'नेहरू' शब्द से सम्बोधित किये जाने लगे। यहाँ तक कि 'कौल' शब्द के अंत में 'नेहरू' लगाकर अब उन्हें 'कौल-नेहरू' कहा जाने लगा, परन्तु कालान्तर पश्चात् 'कौल' शब्द लोप गया और सिर्फ 'नेहरू' हो रह गया। उसी प्राचीन कौल वंश में हमारे राष्ट्र नायक जवाहरलाल नेहरू का १४ नवम्बर, सन् १८८६ को जन्म हुआ।

जमाने की तेज रफ्तार के साथ-साथ राजनीतिक उथल-पुथल का युग आरम्भ हुआ फलस्वरूप नेहरू परिवार के कौटुम्बिक वैभव-सूर्य का अवसान हो गया और सम्पूर्ण जागीर तहस-नहस हो गयी। जवाहरलालजी के प्रपितामह श्री लक्ष्मीनारायण नेहरू दिल्ली बादशाह के ज्यग्रस्त, नाम मात्र के दरबार में कम्पनी सरकार की ओर से पहले वकील नियुक्त हुए। लक्ष्मीनारायण जी के पुत्र तथा जवाहरलाल जी के पितामह पं० गंगाधर नेहरू गदर के कुछ वर्ष पूर्व तक दिल्ली नगर के कोतवाल थे। परन्तु अकाल ही ३४ वर्ष की अल्पायु में, सन् १८६१ में उनकी मृत्यु हो गयी।

सन् ५७ के विद्रोह के पश्चात् मुगल साम्राज्य ने अंग्रेजों से अंतिम वार लोहा लेने के पश्चात् दम तोड़ दिया। जो लोग उन लोगों के प्रभुत्व से चिढ़ते थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया इस प्रकार अंग्रेजों को अपना प्रभुत्व स्थापित करने में पर्याप्त सहायता मिली। मुगल दरबार के नष्ट हो

जाने के पश्चात् नेहरू-परिवार का दिल्ली से सम्बन्ध टूट गया। जागीर के साथ साथ वंश के जल्दी कागज-पत्र और दस्तावेज आदि भी नष्ट हो गये, और इस तरह अपना सब कुछ—सम्मान और वैभव—खो कर हत-भ्रम नेहरू परिवार ने आगरे की ओर प्रस्थान कर दिया। अंग्रेजों के बढ़ते हुए साम्राज्य तथा चतुर्दिक सफलता ने उनकी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति कितनी निरंकुश तथा निर्दय बना दी थी उसका चित्रण स्वयं जवाहरलाल जी ने अपनी जीवन-गाथा में अपने ही-परिवार पर घटित एक दुर्घटना से इस प्रकार दिया है। “तब मेरे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन मेरे दो चाचा जवान थे और कुछ अंग्रेजी जानते थे। उनके इस अंग्रेजी जानने की वदौलत मेरे छोटे चाचा और परिवार के कुछ दूसरे लोग एक बुरी और अचानक मौत से बच पाये। हमारे परिवार के कुछ लोगो के साथ वे दिल्ली से कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनकी एक छोटी बहन भी थी, जिसका रूप रंग गोरा और बहुत खूबसूरत था जैसा कि अक्सर काश्मीरी बच्चों का हुआ करता है। इत्तिफाक से कुछ अंग्रेज सिपाही उन्हें रास्ते में मिल गये। उन्हें शक हुआ कि हो-न-हो यह लड़की किसी अंग्रेज की हो और ये लोग इसे भगाये लिए जा रहे हैं। उन दिनों सरसरी तौर पर बिना मुकदमा किये सजा ठोक देना मामूली बात थी। इसलिए मेरे चाचा तथा परिवार के दूसरे लोग किसी नजदीकी पेड़ पर जल्द फाँसी दे दिये गये होते; मगर खुशकिस्मती से मेरे चाचा के अंग्रेजी ज्ञान ने मदद की, जिससे इस फैसले में कुछ देरी हुई। इतने में उधर से एक शख्स गुजरा, जो मेरे चाचा वगैरह को जानता था, उसने उनकी तथा परिवार के दूसरे लोगों की जान बचायी।”

पं० गंगाधर नेहरू की मृत्यु के तीन मास पश्चात्, आगरे में ६ मई १८६१ को पं० मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। ठीक उसी दिन, उसी महीने तथा उसी वर्ष महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का भी जन्म हुआ था। वास्तव में यह एक मजेशर और अजीब संयोग है। कौन जानता था कि पिता के स्नेह और आश्रय से बचिने वाला मोतीलाल वंश को मर्यादा को

उन्नति के शिखर पर पहुँचायेगा; और भारत के भाग्य विधायक के पितृ के नाने उसका नाम विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायेगा ।

पितामह की मृत्यु के पश्चात् परिवार के पोषण का भार पं० जवाहर लाल के दोनों चाचाओं, श्री वंशीधर तथा श्री नंदलाल नेहरू पर आ पड़ा । श्री वंशीधर अंग्रेज सरकार के न्याय विभाग में नौकर थे; और नंदलाल राजपूताना में खेनडी राज्य के दीवान । परन्तु १० वर्ष पश्चात् उन्होंने पद त्याग कर कानून का अध्ययन आरम्भ किया तत्पश्चात् आगरे में ही वकालत आरम्भ की । इन्हीं व्यक्तियों की स्नेह पूर्ण छद्मच्छाया में बालक मोतीलाल का लालन-पालन हुआ । माता और भाइयों के अनन्य प्रेम से उन्हें कर्मा काँडे अभाव न हुआ तथा उनकी उच्च शिक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखा गया । मोतीलाल जी की शिक्षा का आरम्भ अरबी और फारसी में हुआ । उनकी अंग्रेजी की शिक्षा १२-१३ साल की उम्र के पश्चात् आरम्भ हुई । कालेज में उनका मन पढ़ने में कम तथा खेल-कूद, धीगा-कुश्ती में अधिक लगना था । कालेज के प्रोफेसर उनकी इस 'स्प्रिट' को पसन्द करते थे ।

इसी बीच हार्डिगर्ट का स्थानान्तर प्रयाग हो गया । फलस्वरूप नेहरू परिवार भी आगरे में प्रयाग चला आया । कुछ ही दिन पश्चात् पं० नंदलाल की वकालत चल निकली और परिवार पहले से अधिक सम्पन्न हो गया । अब उनकी गिनती प्रयाग के बड़े-बड़े वकीलों में होने लगी थी । मोतीलाल के अध्ययन का भी क्रम उसी प्रकार चलता रहा; परन्तु बी० ए० में एक परचा खराब हो जाने के फल स्वरूप वे अन्य परचों को हल करने के लिए परीक्षा भवन में उपस्थित नहीं हुए । बाद में उन्हें इस कार्य के लिए अपने अध्यापकों की ताडना भी सहनी पड़ी थी । अंत में वे बी० ए० करने की फिक्र छोड़कर वे हार्डिगर्ट की वकालत की परीक्षा में बैठे और ससम्मान सर्वप्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए । उन्होंने कानपुर में ही परिश्रम के साथ प्रैक्टिस आरम्भ किया । अव्यवसाय और लगन से उनकी वकालत चमक उठी । ३ साल पश्चात् उन्होंने प्रयाग में

प्रेक्टिस करना आरम्भ कर दिया। इसी बीच उनके बड़े भाई पं० नन्दलालजी का स्वर्गवास हो गया। पं० मोतीलालजी पर इसका ज़रूरदस्त धक्का लगा। वह उनका भाई ही नहीं बरन पिता की तरह सम्मान करते थे। परिवार का सम्पूर्ण भार उनके तरुण कंधों पर आ पड़ा। सचमुच व्यक्ति के चरित्र की दृढ़ता, उसकी महानता, कठिनाइयों की प्रज्ज्वलित वह्नि में परिपूर्ण तप कर ही कचन सी निरखती है, और फिर भौतिक जगत के कालकूट उस नीलकण्ठ पर अपनी विजय-पताका फहराने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः कर्मठ पुरुष पं० मोतीलाल इससे कब विचलित होने वाले थे? थोड़े ही दिनों के परिश्रम से उन्हें अपने बड़े भाई के समी मुकदमे मिल गये, तथा उनमें यथा योग्य सफलता प्राप्त करने पर उनकी वकालत चमक निकली और वे प्रयाग के प्रमुख ऐडवोकेटों में गिने जाने लगे। युवावस्था में ही यश के साथ ही धन का भी अञ्जु आगमन हुआ। प्रयाग में उस समय कई अच्छे वकील थे जिनमें मोतीलालजी के अलावा सर सुन्दरलाल, सतीश बनर्जी, आलस्टन तथा सर सभू प्रमुख थे। मोतीलाल अपने प्रतिद्वन्दी सर सुन्दरलाल की भौति कानून के विशारद नहीं थे; परन्तु उनका व्यक्तित्व, उनकी अद्भुत मेधा शक्ति और पेंचीदे मामले को आसानी से समझने और सुलझाने की शक्ति ने उन्हें देश के प्रमुख वकीलों का स्थान दे दिया था।

उन दिनों स्वभावतः एक सफल वकील पाश्चात्य रहन-सहन की कृत्रिमता को अपना लेता था। भारत पर इंग्लैंड ने सिर्फ शासकीय ही नहीं बरन पूर्ण सामाजिक आधिपत्य भी स्थापित कर लिया था, क्योंकि भारत के रूढ़िवादी जीवन और विचार में भी पाश्चात्य रीति ने धर कर लिया था। भारतीयों में एक नये समाज का जन्म हो रहा था, जिसके सदस्य संस्कृति के लिए पश्चिम का मुँह जोहते थे, और अपने से कम ऐश्वर्यशाला और भाग्यवान बंधुओं से क्रमशः अलग होते जा रहे थे। यह समाज शासक वर्ग के रहन-सहन की मकल करता था, क्योंकि शिष्टा और संस्कृति का मापदंड यह हो गया था कि कौन कितनी अच्छी

अंग्रेजी और किस हद तक अंग्रेजी लहजे में बोल सकता है। पं० मोतीलाल भी प्रारम्भ में इस विपाक्त वातावरण के पंजे से न बच सके और वैभव के साथ ही साथ वे पाश्चात्य रहन-सहन और ठाठ की ओर पूर्णतः मुखाकृत हुए।

काग्रसे उन दिनों मध्यम श्रेणी के अंग्रेजी पढ़े लिखे कुछ लोगों की संस्था थी। प्रारम्भ में उसकी ओर मोतीलालजी का ध्यान अवश्य खिंचा, परन्तु कार्याधिक्य के कारण न तो वह उसकी ओर विशेष ध्यान ही दे सके न उनकी कार्यवाही में पूर्ण रूप से भाग ही ले सके। साधारण अर्थ में वे राष्ट्रवादी अवश्य ही थे परन्तु अंग्रेजी संस्कृति के कद्रदों भी थे। जवाहरलाल के शब्दों में ही “प्रारम्भ में उनका यह ख्याल था कि हमारे देशवासी ही नीचे गिर गये हैं और वे जिस हालत में हैं बहुत कुछ उसी के लायक भी हैं। जो राजनैतिक नेता सिर्फ जवानी जमा खर्च किया करते थे उनसे उनको मन-ही-मन सरत नफरत थी, यद्यपि वे नहीं जानते थे कि उससे ज्यादा वे कर ही क्या सकते हैं ? हाँ ! एक और ख्याल भी उनके दिमाग में उस समय था जो कि उनकी कामयाबी के नशे से पैदा हुआ था; वह यह कि जो राजनीति में पड़े हैं, उनमें अधिकतर—सब नहो—वे लोग हैं, जो अपने जीवन में नाकामयाब साबित हुए हैं।” पाश्चात्य संस्कृति की अनन्य भक्ति, उपयुक्त विचारधारा तथा सफलता के नशे ने उस समय उन्हें इस प्रकार के राजनैतिक वातावरण से अलग ही रखा परन्तु भविष्य और भारत-माता ने अपने क्रोध के इस रत्न का अपनी दैन्य स्थिति से अधिक दिन तक अनभिज्ञ नहीं रखा।

बचपन और शिक्षा

श्री मोतीलालजी के सम्पन्न परिवार में १४ नवम्बर, सन् १८८९ ई० को

जवाहरलाल ऐसे पुत्र रत्न का जन्म हुआ। छुटपन में ही वे हमजोली भाई-बहनों अथवा मित्रों के धमा-चौकड़ी पूर्ण स्नेह से वंचित रहे। दुनिया के हर मासूम बच्चे अपने माँ-पा के दुलारे होते हैं, फिर वे तो घर की रोशनी, मोतीलालजी के एक मात्र पुत्र थे, उनके लाडल्यार का क्या कहना। परिवार के उस जीवन-सर्वस्व का नाम माता-पिता ने बचपन में प्यार से नन्हा रखा। नन्हा की तोतली बोली सुनकर घरवालों की हृदय-कली उल्लास से खिल जाती। लगता सने जीवन में वसंत की प्रभाती बोल उठी हो।

माँ की गोद में खेलते अपने नन्हे-नन्हे भाई और बहनों को देखने की जवाहर की बाल-इच्छा ११ वर्ष की उम्र तक पूरी न हुई। कृष्णा और विजयालक्ष्मी जो भाई से काफी छोटी थीं, वे उसके बाल-हृदय की इच्छा,—हम उम्र साथी के साथ खेलने की इच्छा—को पूर्ण न कर सकती थी। भाग्य की मार, उन्हें कोई स्कूल का साथी भी न मिला, क्योंकि वे अन्य बच्चों की तरह किसी पाठशाला या किंडर गार्टन में पढ़ने के लिए नहीं बैठाये गये। उनकी प्रारम्भिक पढ़ाई अंग्रेज और हिन्दो-स्तानी मास्टर्स के अन्तर्गत हुई। उनके सभी चचेरे भाई स्कूल की उच्च कक्षाओं या विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे। वे उनसे उम्र में काफी बड़े थे। उनकी नजरों में बालक जवाहर भले प्यार करने योग्य हो परन्तु उनकी बात चीत, कामों, तथा खेल-कूद में शरीर होने लायक नहीं था। बालक जवाहर प्रायः अपने चचेरे भाइयों की बात ध्यान पूर्वक सुनता

यद्यपि सभी बातें उसकी नन्ही सी बुद्धि में घुस न पाती थी। अक्सर उसके भाई अंग्रेजों की निरंकुशता तथा उनका हिन्दुस्तानियों के साथ अपमान पूर्ण व्यवहार की बात करते और इसे 'हरगिज बर्दास्त न होने वाली बात' कहकर अपने दिल का गुब्बार निकालते। यह वह युग था जब रेलगाड़ियों में अंग्रेजों के लिए डिब्बे और सीटें अलग होती थी जिनमें कोई हिन्दुस्तानी चढ़ नहीं सकता था। अंग्रेजों को एक प्रकार से 'सात खून तक' माफ थे। भाइयों की सुना सुनी बालक नेहरू का मामूम दिल, मन ही मन ऐसी सत्ता के प्रति बगावत करता रहता, और भविष्य में उसे उखाड़ फेंकने के सपने हर रोज देखा करता। परंतु तब भी उसे अंग्रेजों से व्यक्तिगत घृणा न थी और वह उन्हें इज्जत की निगाह से देखता।

घर में रोज शामको मोतीलाल जी के अंग्रेज और हिन्दुस्तानी मित्र आते। जिनके साथ मोतीलाल जी स्वच्छंद रूप से अट्टहास करते। बालक जवाहर को वे आदमी, उनकी बात और पिता की हँसी अजीब सी लगती। वह पदों की ओर में झिपा उनकी ओर कौतूहलपूर्ण दृष्टि से देखा करता और जब कभी उसकी यह 'चोरी' पकड़ा जाती तो वह मामूम खिलौना मित्रों द्वारा जबरदस्ती पिता की गोद में बैठा दिया जाता।

अबोध बालक नेहरू अपने पिता की बहुत इज्जत करता था परन्तु साथ ही उनसे डरता भी बहुत था। वह पिता की भोँति महान होने का, तथा नाम कमाने का मंसूबा शुरू से ही बोधने लगा था। पं० मोतीलाल जी जब नौकरों पर बिगड़ते तब उनकी लाल ओख और क्रोधित मुखाकृति देखकर उसके तो देवता ही कूँच कर जाते थे। कभी कभी उसे पिता के इस व्यवहार पर मन ही मन क्रोध भी आता, परन्तु पिता की स्वच्छन्द हँसी पल भर बाद ही उसके इस रोष को दूर कर देती। जवाहर लाल ने स्वयं पिता के उग्र स्वभाव की एक विचित्र घटना वर्णित की है। नन्हें जवाहर की आयु करीब ५-६ वर्ष की रही होगी।

एक दिन उसने अग्ने गिता की मेज पर जो गेने देरी। पत्नी नहीं लालच वश अथवा साम्यवादी प्रत्युत्पन्न मनोवृत्ति से, बालक ने उनमें से एक, यह सोचते हुए कि गिता दो बालकों का क्या करेंगे, उठाकर कर्मा केर से डाल लिया। माता वलारों होने पर माँ न्यस्त बालक ने कर्मा कर्मा के बारे में गिता को न बतलाया। येन उनकी स्नेह में नित रग्यः और उस नन्हें गुनहवार की लड़ नरम्भत हुई। गिता के क्रोध से बचाने के लिए, दुनिया के कर नादान बच्चों की तरह, माँ को अगाध मनता ने उन्हें भी अग्ने दूध नरे अंचल में छिगा कर विग्राम दिया: और अग्ने स्नेह-जल से सिंचित करती हुई कई दिन तक उस नार से दर्द करत सुकुमार वदन पर, क्रान और नन्दन की नातिश करती रही।

बालक जवाहर का एक अन्य व्यक्ति ने माँ को नोहे था: और वे थे उसके गिता के दुर्शा सुगरककर्ता। सुजायों ने उन्हें घर-वार और सुख-शान्ति से अलग कर अनन्त दुख-सागर में डुबेत दिया था। उनका बालक जवाहर पर काती लेह था। वे उसे कतिन सैता के किस्से प्रायः सुनाया करते थे। किंतु उनकी रई सी बहिया संतद दाई जवाहर की आखों को उन काल्पनिक पर्यदेश की ब्रह्मानियों से नी अविक्र मला लगती, और त्वं नालगी चाहत उसे पुपनी जनकारियों के खजाने लगते।

धर्म के विषय में घर के अन्य पुरख व्यक्तियों की तरह उन्हें माँ विशेष दिलचस्पी न थी; यद्यपि उनके समारम्भ को वह सुत्त और सुहल को आँखों से देखा करते, और प्रायः घर की वृद्धा औरतों के साथ अपने भाग भी लेते। उनकी एक विषया चाची कर्मा कर्मा उन्हें पौषणिक कथाओं सुनाया करती जिन्हें सुनचाग बैठ कर वे बड़े चार से सुना करते।

साल के त्योहारों की बहल-बहल और चमक-दमक में उन्हें बड़ा आनंद आता। परंतु उन सभी उत्सवों में एक ऐसा उत्सव माँ था जिसमें वे विशेष दिलचस्पी लेते: और उत्सुक्तापूर्व दिल में उसके

आगमन की प्रतीक्षा किया करते। यह विशेष उत्सव था उनके जन्म दिवस का वार्षिक समारोह। उस दिन के वे राजा होते, और सभी उन्हें होंथों होंथ उठाकर प्यार करते तथा कुछ न कुछ सौगात अवश्य देते। उनको कभी कभी भुंभलाहट होती और साथ ही दुख भी होता कि ऐसा अवसर साल में एक ही बार क्यों आता है, और हर रोज उनका ऐसा ही स्वागत क्यों नहीं होता ? उस समय उस अशोध बालक को क्या मालूम था कि हर आने वाली वर्षगोठ बुढ़ापे की याद दिलाती है, और उस दिन जिन्दगी का एक अनमोल साल मौत की ओर चुपचाप झुक जाता है।

जब जवाहरलाल १० साल के थे तभी वह एक नये तथा काफी भव्य प्रासाद में आ गये थे। वह इमारत आनंद भवन के नाम से प्रयाग में प्रसिद्ध थी—“जिस जगह पर यह प्रासाद बना है उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि हिंदू जनता का आम विश्वास है कि वही वह स्थान है जहाँ रामचंद्र जी के चौदह वर्ष के वनवास से लौटने पर भरत जी से उनका मिलाप हुआ था। करीब ही भारद्वाज आश्रम भी है।” (श्रीमती कृष्णा हठी सिंह) उस इमारत के बाग के तालाब में अक्सर उनके पिता के चंद दोस्त शाम को नहाने आते। उनमें कभी-कभी सर तेज बहादुर सप्रू भी आया करते। वे तैरना नहीं जानते थे, अतः सीढ़ी पर, १५ इंच पानी में ही बैठ जाते, और कसम खाने को एक सीढ़ी भी नीचे नहीं उतरते थे। यदि कोई उन्हें आगे खींचने की कोशिश करता तो वे जोर से चिल्ला पड़ते। बालक जवाहर को उन नहाने वालों के मुण्ड में बड़ा मजा आता, और जो तैरना नहीं जानते थे उनमें से किसी को आगे धक्का देकर या पीछे खींच कर डराने में इसे बड़ा आनंद आता। इस प्रकार आनंद भवन में काफी चहल पहल रहती। कालांतर पश्चात् जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में पं० मोतीलाल जी असहयोग आंदोलन में शरीक हुए, तो उन्होंने आनंद भवन का एक भाग कांग्रेस-कार्यों के लिए राष्ट्र-सेवियों को दे दिया, और उसका नाम ‘स्वराज्य भवन’ रखा।

इस 'स्वराज्य भवन' में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रधान कार्यालय अनेक वर्षों तक रहा। यह एक ऐसा सुंदर तथा पवित्र स्मृति-भवन है जिसे प्रयाग में बाहर से आने वाले यात्री एक बार आवश्यक देखते हैं।

उन दिनों वोअर युद्ध हो रहा था। स्वाभाविक था कि माधुक बालक नेहरू को वोअरों के प्रति हमदर्दी हो। वह रोज लड़ाई की खबरें जानने के लिए अखबार पढ़ता। उसे वोअर स्वातंत्र के प्रति सहानुभूति थी क्योंकि वह अपने बड़े भाइयों से, परतंत्र देशों में नावदान के कीड़े सी जिंदगी बिताने वाले इंसानों की दर्द कहानी सुन चुका था।

उन दिनों अंग्रेजों के सम्पर्क के फलस्वरूप, पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता से प्रभावित, एक सम्पन्न परिवार की सन्तान के लिए जैसा कि स्वाभाविक था, जवाहरलाल नेहरू को भारतीय स्कूलों में शिक्षा नहीं दी गयी। ग्यारह वर्ष की आयु में एफ. टी. ब्रुक्स नामक एक नये शिक्षक अभ्यापन कार्य के लिए नियुक्त हुए। अच्छा गुरु भी भाग्य से ही मिलता है। यह सौभाग्य था कि ब्रुक्स महोदय थियोसॉफिस्ट थे। उनके उच्च आदर्शों तथा सरल जीवन ने बालक नेहरू के ऊपर अपना स्थायी प्रभाव किया; तथा उसकी अन्तरात्मा में एक नवीन ज्योति जगा दी। जब निर्दोष स्वच्छ दर्पण पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब उसका तेज और प्रकाश द्विगुणित आभा के साथ विकीर्ण होता है। उसकी ओर देखनेवालों की नजर ओखें असह्य ज्योति के कारण बन्द हो जाती हैं, और उसका मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। मिस्टर ब्रुक्स उन शिक्षकों में न थे जो विद्यार्थियों को केवल अक्षर और अर्थ ज्ञान देना ही अपना कर्तव्य समझते हों, उनकी दृष्टि में उनका कर्तव्य था जवाहर को मनुष्य बनाना। वे स्वयं थियोसॉफिस्ट थे और उन्हीं भावों का प्रवेश अपने शिष्य की विचारधारा में भी किया करते थे। मि० ब्रुक्स के साहचर्य से बालक जवाहर को प्रारम्भ से ही विज्ञान तथा अन्य विषयों की पुस्तक को पढ़ने की चाह लग गयी। वह मि० ब्रुक्स के साथ थियोसॉफिस्टों की सभाओं में जाया करता और उनके नेताओं का भाषण ध्यानपूर्वक सुनता था।

यियासाफिकल सोसाइटी उन दिनों उन इनी-गिनी संस्थाओं ने से थी जो योरोपीय संचालकों द्वारा संचालित होने पर भी भारत के गौरवपूर्ण चुनहरे अतीत को अत्यन्त महत्व देती थी और उसे नानक नात्र की प्रेरणा तथा उनमें जीवन संचार करनेवाली मानती थी। इसने भारतीय भी सदस्य होकर गौरे सदस्यों के साथ समानता पाते थे। पं० मोतीलाल जी भी इस संस्था के सदस्य हो गये थे, यद्यपि उसकी मीटिंगों में उन्होंने सक्रिय भाग कभी नहीं लिया। मिसेज वेसेंट के भाषणों से अत्यन्त प्रभावित हो स्वयं जवाहरलाल ने १३ वर्ष की अवस्था में श्रीमती वेसेंट के ही करकमलों द्वारा यियोसोफी की दोक्षा पायी थी। आज की पीढ़ी के लिए यियासाफी के आन्दोलन का महत्व ओंकना कठिन है। समय के प्रभाव में पड़ कर अपने नेताओं को भूल जाने वाली दुनिया यह भी ठीक ठीक नहीं समझ सकती कि अपनी सुदूर मातृभूमि आयरलैण्ड से सेवा का व्रत लेकर भारत में आनेवाली इस अद्भुत महिला ने, जिसका मानवमान की सेवा के हित समर्पित भौतिक जीवन मद्रास के अड्यार नदी के तट पर शेष हो गया, भारत की कितनी महत्वपूर्ण सेवा की, जिसे आनेवाले इतिहास के पृष्ठ कदापि भुला नहीं सकते। ।

आगमन के तीन वर्ष पश्चात् मि० ब्रुक्स का संरक्षण जवाहर लाल पर से उठ गया। ब्रुक्स के अलग होते ही यियासाफी की विचारधारा का नशा भी उनके मस्तिष्क से उतर गया। इन्हीं दिनों जब मि० ब्रुक्स शिक्षक रखे गये थे, एक और शिक्षक, बड़े पंडितजी, जवाहरलाल को हिन्दी और संस्कृत पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए, परन्तु कई वर्ष पश्चात् भी इन भाषाओं का ज्ञान उन्हें विशेष न हो सका।

पहले ही कहा जा चुका है कि बालक जवाहर के मन में अज्ञात रूप का देश-भक्ति का बीजाकुर बहुत पहले से ही उग चुका था। बोअर युद्ध में उन्हें बोअरों के प्रति सहानुभूति भी थी। रूस और जापान के युद्ध में भी जवाहर की सहानुभूति पूर्णतः जापान की ओर गयी। वे जापान की विजय चाहते थे। इतनी छोटी अवस्था में ही उन्हें न केवल भारत के राष्ट्रीय

स्वातंत्र्य से ही प्रेम था, बल्कि योरोप के हाथों से एशिया को भी वे अलग देखना चाहते थे । उनका मासूम दिल बड़े-बड़े बहादुरी के मंसूबे ब्रोधता कि कैसे हाथ में तलवार लेकर मैं भी हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ूँगा । इसी कारण जापान के प्रति उनकी सहानुभूति बढ़ गयी और वे जापान के सरदारों की वीरोचित कहानियों बड़े चाव से पढ़ते ।

यौवन के गर्म रक्त के संचार के साथ साथ रहस्यपूर्ण नारी-सौन्दर्य कौतूहलपूर्ण दृष्टि से उनके अंतर में भौंकने लगा । यद्यपि अब भी लड़कियों से सम्पर्क बढ़ाना वे अपनी शान के खिलाफ समझते थे । लेकिन कभी-कभी काश्मीरी दावतों में जहाँ सुन्दर लड़कियों का अभाव न था—निगाह या बदन के आपस में छू जाने से एक अज्ञात भावना से। उनका सम्पूर्ण शरीर रोमांचित हो जाता ।

विदेश यात्रा तथा उच्च शिक्षा

वह समय था बिलायत प्रेम का । शासकों की प्रत्येक बात आदरणीय और अनुकरणीय समझी जाती थी । उनके साथ उनके ही देश में शिक्षा पाना एक गौरव की बात समझी जाती थी । महत्वाकांक्षी और बड़े बाप अपने बेटों को मविष्य के अनेक सुनहरे स्वप्न सजाये विदेश भेजते थे । इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर जवाहरलाल जी के माता-पिता ने भी १९६५ में इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया । कुछ दिनों के विदेश-भर्यटन के पश्चात्, अपने प्रिय पुत्र को सुप्रसिद्ध हैरो विद्यालय में भरती कराकर माता पिता स्वदेश लौट आये । हैरो इंग्लैंड का वह सुप्रसिद्ध पब्लिक स्कूल है, जहाँ उच्च कोटि के धनाढ्य पुरुषों के सौभाग्यशाली बालकों को ही स्थान दिया जाता है ! इस स्कूल ने इंग्लैंड के राजनैतिक इतिहास में प्रसिद्ध अनेकों महापुरुषों की रचना की है । स्पेन्सर पर्सीवेल, राबर्ट पील, पामर्सटन, स्टेनली, वाल्डविन आदि ब्रिटिश साम्राज्य के स्तम्भ स्वरूप प्रधान मंत्रियों की प्रारम्भिक बौद्धिक रचना इसी स्कूल द्वारा हुई थी । इसी स्कूल के पढ़े हुए कई विद्यार्थी भारत के वायसराय भी हुए; जिनमें, डलहौजी, वेल्सली, लिटन और हार्डिंग के नाम प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त अनेक प्रसिद्ध साहित्यकारों की भी रचना-भूमि यही थी ! यह एक पहाड़ी पर बसा हुआ है तथा प्रकृति ने इसकी स्थिति बड़ी ही रमणीय बना दी है ।

लेटिन कि आवश्यक जानकारी न होने के कारण आरम्भ में जवाहरलाल छोटी कक्षा में भरती किये गये परन्तु शीघ्र ही उन्हें उन्नति मिल गयी । वे अपने हम उम्र विद्यार्थियों से, समाचार पत्र और पुस्तकों का

अधिक पठन-पाठन करने से, ग्राम बातों में अधिक जानकारी रखते थे । एक बार कुछ गर्व के साथ उन्होंने अपने पिता को एक पत्र में लिखा भी था कि अंग्रेज लड़के खेल-कूद में बड़े सुस्त, और कुन्द-जेहन होते हैं । स्कूल में वे औसत दर्जे के ही विद्यार्थी रहे यद्यपि इनकी बुद्धि काफी प्रखर थी एक अंग्रेज लेखक के शब्दों में “स्कूल में आप क्रमशः जीवन की गतिधियों का अध्ययन करते और सासारिक अनुभव को प्राप्त करते थे ।”

आरम्भ में मों-त्राप के बरदहस्त और स्नेहछाया के नीचे रहनेवाले जवाहरलाल को वह अजनबी वातावरण सूना-सूना सा लगा । परन्तु कुछ ही दिनों पश्चात् वे स्कूल के जीवन में हिल मिल गये और दैनिक कार्य तथा खेल कूद में पूरा पूरा हिस्सा लेने लगे ।

एक बार एक मनोरंजक घटना घटित हुई । १९०५ में इंग्लैण्ड में नया चुनाव हुआ और लिबरल दल की जीत हुई । कुछ दिनों पश्चात् नयी सरकार के विषय में अव्यापक ने कक्षा के विद्यार्थियों से कई प्रश्न पूछे । नेहरू के अतिरिक्त कोई भी ठीक उत्तर न दे सका अव्यापक को एक हिन्दुस्तानी लड़के के इस ज्ञान पर आश्चर्य हुआ । इन राजनीतिक विषयों के अतिरिक्त उनकी रुचि विज्ञान की ओर विशेष थी । वायु यानों के प्रति उनका विशेष आकर्षण था । एक बार उन्होंने उत्साह से अपने पिता को लिखा था कि अब विमान द्वारा प्रति सप्ताह मैं आप से मिलने आ सकूँगा ।

हैरो विद्यालय में जब जवाहर लाल पढ़ते थे उसी समय से उनका आकर्षण भारत की राजनैतिक अवस्था की ओर था । सन् १९०६ और १९०७ में नौकरशाही के द्वारा जो उत्पात भारत में हो रहे थे उन समाचारों को अंग्रेजी पत्र में पढ़ कर उनके युवा-हृदय में एक अमिट पीड़ा उठती । बंगाल और पंजाब की घटनायें उनके हृदय पर सोंप सी लोटती । उस समय तक भारतीय नेता लाला लाजपत राय और सरदार अजित सिंह को देश निकाला हो चुका था । पूना में तिलक का नाम विजली की तरह चमक रहा था और स्वदेशी का इस्तेमाल तथा विदेशी

माल का बहिष्कार गगनभेदी-नाद से पूना के उस सिंह के स्वरों में गूँज रहा था। तमस-निद्रा में सोया देश, माता की पुकार सुन कर करवट बदल कर जाग उठा था। तिलक की आवाज 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर जवामर्द हिन्दुस्तानी के दिल और दिमाग में अपना स्थान बना चुकी थी। फिर भला जवाहरलाल, जो एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र वातावरण में उस समय पल तथा शिक्षित हो रहे थे, इस प्रभाव से अपने को कैसे बचा सकते ? हैरो में एक भी ऐसा व्यक्ति न था जिससे वे दिल खोल कर इस विषय पर बात कर सकते। उन्हीं के शब्दों में, अपने मविष्य के कार्यक्रमों का मन ही मन काल्पनिक बोंधनू बोंधते हुए "मैं आजादी की बहादुराना लड़ाई के अजीब ख़ाव देखने लगा।" हैरो के उस संकुचित वातावरण से भाग पाकर अब वे जीवन और उसमें स्थित आदर्शों को बृहत पृष्ठभूमि पर देखना चाहते थे। उन्होंने पिता से विश्वविद्यालय में दाखिल होने की आज्ञा माँगी।

१७-१८ वर्ष की आयु में, १९०७ में उन्होंने केंब्रिज के ट्रिन्टी कॉलेज में पदार्पण किया। हैरो को छोड़ते समय उनकी आँखें सजल हो गयी थी, और वहाँ की परम्परा और सुमधुर गीत उनके भावुक हृदय को बहुत काल तक उसकी याद दिला-दिला कर कचोटते रहे। घीमी घीमी बहने वाली कैम नदी की भोंति उनके ३ वर्ष विश्वविद्यालय में बीत गये।

बीसवीं शती के पहले दशक में केंब्रिज का जीवन सुखी और बौद्धिक जिज्ञासा से भरा हुआ था। कॉलेज का वातावरण निःसन्देह उन भारतीयों के लिये विशेष स्फूर्तिप्रद था जो उस काल विद्यालय में थे। जवाहरलाल जी को भी इस वातावरण से उत्साह मिला। उनका प्रिय विषय प्राकृतिक विज्ञान था। अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त वे अन्य विषयों की पुस्तक भी पढ़ते थे; और अपने अन्य मित्रों की ही भोंति अपनी मडली में, उन विषयों का अपरिपक्व ज्ञान होने पर भी बड़े गर्व से, एक 'बुजुर्ग अक्लमंद' की भोंति वाद-विवाद किया करते थे। वहाँ

पढ़ने वाले भारतीय युवक स्वाभावतः भारतीय स्वतंत्रता-आन्दोलन पर बड़ी सूक्ष्मता से तर्क करने, और सभी एक स्वर से अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध तर्क पेश करने। सभी बिना किसी अपवाद के तिलक दल-या गरम दल कहो—के पक्ष में थे।

केम्ब्रिज में भारतीयों का एक संगठन 'इंडियन मजलिस' नाम का था। जो कि उनका सामाजिक क्लब भी था और राजनैतिक विवादों का केन्द्र भी, परंतु जवाहरलाल इतने संकोची तथा समाभीरु थे, जैसा कि प्रायः युवकों में पाया जाता है, कि उन्होंने न तो कभी इस मजलिस में भाग ही लिया न अपने कालेज की विवाद समा 'मैगपाई एण्ड स्टम्प' में ही। फलस्वरूप उन्हें नियमानुसार इसके लिये जुर्माना भी देना पड़ता था।

उन दिनों भारत-स्वातंत्र्य-युद्ध के नामी राजनैतिक थोड़ा अपनी इंग्लैण्ड यात्रा में इन विद्यालयों में भी जाया करते तथा हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों से मिला करते। एकवार श्री गोखले, लाला लाजपतराय तथा विपिन चन्द्र पाल, नेहरू के अध्ययन काल में ही वहाँ गये थे, तथा उन लोगों ने उनकी मजलिस में भाषण भी दिया था। नेहरू जी को विपिनचन्द्र पाल से अधिक लाला लाजपतराय के भाषण में आनन्द आया तथा वे उनसे प्रभावित भी हुए। भारत के सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी लाला हरदयाल उन दिनों वही थे। नेहरू जी ने स्वयं उनसे दो तीन बार भेंट भी किया था। यद्यपि सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्यामजी वर्मा उन दिनों विलायत में ही रह रहे थे परंतु वहाँ उनसे नेहरू जी की कभी भेंट न हुई। कभी कभी वे उनका समाचार पत्र 'इंडियन सोसियलाजिस्ट' देखने का अवसर अवश्य पा लेते थे। इसके बहुत दिनों बाद सन् १९३६ में नेहरू जी ने उनसे जेनेवा में भेंट की थी।

तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्जन की बगाल-विभाजन-नीति से भारत में आन्दोलन की लहर ने भीषण रूप धारण कर लिया था। अहंकारी कर्जन का विश्वास था कि निर्बल देशों पर ईश्वर ने इंग्लैंड को

शासन करने का अधिकार न दिया है। उसके कथनानुसार 'भारत तलवार-के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही आधीन रखा जायेगा।' नेहरू इन्हें बराबर समाचार पत्र में पढ़ते रहते और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोहाग्नि उनके रूखा हृदय में सुलगा करतीं।

उन्हीं दिनों देश की स्थिति तथा अंग्रेजों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों को देख कर पं० मोतीलाल भी कांग्रेस के लिबरल दल की ओर मुखाकृत हुए थे। वे अन्न भी अंग्रेजों को आदर्श तथा अनुसरणीय समझते थे। वे गरम दल वालों को 'कल के छोकरे' और 'देश को तबाह करनेवाले, समझते थे। एक बार उन्होंने कुछ इसी प्रकार का लेख एक पत्रिका में लिखा था। कैम्ब्रिज के विद्यार्थी युवा पुत्र ने जब यह लेख पढ़ा तब वह पिता से बहुत ही असन्तुष्ट हुआ, और उन्माद में उसी समय अपने पिता को एक धृष्टतापूर्ण पत्र लिख डाला, जिसमें उसने उनको यह कह कर अपने दिल का गुब्बार निकाला था कि आपकी राजनैतिक कार्रवाइयों से अवश्य ही ब्रिटिश सरकार अत्यन्त प्रसन्न हुई होगी। पिता, पुत्र की इस टीठाई पर काफी नाराज भी हुए थे, और करीब करीब उन्हें इंग्लैंड से वापस बुला लेने का निश्चय ही कर चुके थे, ताकि धृष्ट पुत्र को पिता के साथ अधिक आदर और सद्व्यवहार करने की शिक्षा और ताड़ना मिल सके। पर बाद में पुत्र के भविष्य को सोच कर उन्होंने यह विचार त्याग दिया।

१९१० में जवाहरलाल जी कैम्ब्रिज से विज्ञान के तीन विषयों में ससम्मान द्वितीय श्रेणी में पास हो गये। तत्पश्चात् कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे लंडन के ही 'इनर टेम्पुल' में भरती हुए। इसी बीच कानून की पढ़ाई से समय निकाल कर उन्होंने फेमियन और समाज-वादी विचार धाराओं का अध्ययन किया।

१९१० में कैम्ब्रिज से डिग्री लेने के पश्चात् जवाहरलाल नावें सैर-सपाटे के लिए गये जिसमें एक दुर्घटना से वे बाल-बाल बचे। एक दिन एक नौजवान अंग्रेज मित्र के साथ वह एक पहाड़ी झरने में नहाने गये थे।

नहाते समय दुर्भाग्य वश उनका पोंव फिसल गया । तूफानी धारा के साथ वे वेग से बहने लगे । काफी देर बहने के बाद उस अंग्रेज मित्र ने उन्हें चड़ी काठनाई से बाहर निकाला । मरना थोड़ी दूर और बहने के पश्चात् एक जल प्रपात के रूप में काफी नीचे पहाड़ी में गिरता था । यदि कुछ मिनटों तक और उनकी जीवन-रक्षा न हो पाती तो शायद भारत के भविष्य का यह आशा-दीप उस दिन बुझ जाता ।

१९१२ में उन्होंने 'इनर टेम्पुल' से बार-एट-ला की डिग्री पा ली, और ७ साल से अंग्रेज विदेश में रह कर वे शरद ऋतु में भारत लौटे । सात वर्ष के पूर्व के नेहरू और अब के सम्मानित नेहरू में जनीन-आत्मान का अंतर था, जब वे भारत के लिए खाना हुए तो उनके शारीरिक परिधान का बाह्यरूप तो विदेशी अवश्य था पर भीतर हृदय में भारतीयता की चिनगारी बुझने न पायी थी । यही चिनगारी यहाँ लौटने पर विशाल स्वदेश-प्रेम की अग्नि सी प्रज्वलित हो उठी ।



भारतीय राजनीति में पदार्पण

१९१२ में जब नेहरू जी भारत लौटे उस समय भारतीय-राष्ट्रीय आन्दोलन में जीवन न था। सभी चोटी के नेता जेल में थे। तिलक के जेल में होने के कारण, सुयोग्य नेता से रहित गरम दल के अनुनायी दूरतः कुचल दिखे गये थे। वंग-भंग-योजना रद्द कर, संतप्त हृदय मार्तण्डों के, विशेषतः नाडरेटों के अग्नी शोर मिलाने में सरकार नन्त हो चुकी थी। नाल्ले-मिन्दो-योजना विरोध की खाई को पाटने में बहुत कुछ नन्त हुई थी। यद्यपि भारत की गृह-राजनीति पर कुछ दिनों के लिए ठंडी गन्ध पड़ चुकी थी, फिर भी चन्द भारतीयों की विदेश में छुटने राष्ट्र भाइयों की नेत्र, सदैव पड़ रहे नून में गर्मी ला रही थी। उन दिनों अफ्रीका में भारतीयों के साथ अत्याचार किये जा रहे थे; काले और गेरे का मेद जौर पकड़ रहा था, और भारतीय सरकार प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा में अन्यन्तत्ता दिखा रही थी। महानना गोम्वले ने नन्त के नौनिहालों से छुटने अफ्रीकन भाइयों की सहायता के लिए धन की संग्रह की। उस अफ्रीका के अनुसार चंदा एकत्रित करने के लिए प्रयाग में एक समिति बनी, जवाहरलाल जी उसके नंत्री थे। इसके अतिरिक्त भारतीय नजदूरों को अनुचित इकरारनामों लिखाकर विदेश ले जाने के विरुद्ध जो आन्दोलन देश में, विशेषतः प्रयाग में उठा था, उसके आन प्राप्त थे।

बिलायत ने लौटने के पश्चात् ही १९१२ में नेहरू जी एक डेलिगेट की हैसियत में बर्किंगहम कांग्रेस में उपस्थित हुए थे। उसके पहले वचन में ही एक्टर के कांग्रेस के उस अभिवेशन को देख आये थे जिसकी

वैठक बम्बई में सर हेनरी काउन के समापतित्व में हुई थी। सन १९१३ में वे युक्त-प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मेम्बर बने और उसी समय से प्रांतीय कांग्रेस के कार्यों में उचित भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। उन दिनों कांग्रेस का संगठन, कार्यक्रम और रूप आज कल का सा नहीं था, चन्द्र धनाढ्य और शिक्षित लोग ही उसके सदस्य होते थे। कांग्रेस अधिवेशन एक तरह के सामाजिक उत्सव से होते थे जहाँ विशेषतः अंग्रेजी जानने वाले उच्च श्रेणी के लोग, सुन्दर इस्त्री किये हुए, कोट-पतलून में दिखालाई देते थे, जहाँ वे अपना लच्छेदार अंग्रेजी भाषा का चमत्कार दिखाना ही बहुत बड़ी देश-सेवा समझते थे।

जवाहरलाल जी जब इंग्लैंड से आये थे तभी से उनका यह विचार था की वे अपने अमूल्य समय में से आधा तो वकालत के पेशे में देंगे और आधा देश की सेवा में। परन्तु इंग्लैंड की स्वतन्त्र वायु और विचारधारा में पले हुए, तथा शिक्षित इस युवक को अपने देश की परतन्त्रता खलने लगी। अंग्रेजों द्वारा दूषित हुई यहाँ की वायु उनका दम घोटने लगी। यद्यपि वे दैनिक जीवन की खानापूरी करने के लिए वेमन से अदालत जाते थे, परन्तु उनके युवा हृदय में देश की परिस्थिति से असन्तोष का जन्म हो चुका था। पिता और उनके दूसरे बड़े बकील मित्रों का परिश्रम भी जवाहर को अपने पेशे की ओर पूर्णतः न न्वाँच सका। उनकी दृष्टि तो गुलामी से जकड़ी हुई भारत-माता की हथकड़ियों की ओर जा चुकी थी। धन और सम्मान से पूर्ण अपने वकालत के पेशे से दूर, वे प्रायः देश की राजनैतिक परिस्थिति पर विचार करते। उनके हृदय में क्षोभ था, विषाद था, और था भारतीय संग्राम की रूप रेखा तैयार करने का उत्साह। विदेशी शासन के प्रति वे जोरदार आंदोलन की बात सोचा करते। वे चारों ओर दृष्टि दौड़ाते परन्तु कहाँ किनारा नजर न आता। उनकी दृष्टि अपने विचार के से व्यक्ति की नोज में थी—किन्तु उनकी गुंजाइश न दिखलाई पड़ती थी। वे स्वयं अंग्रेजों से किसी प्रकार के लाभ की आशा न रखने थे बल्कि देश की समस्त दुर्दशा के लिये

उसी शासक वर्ग को वे एकमात्र उत्तरदायी समझते थे। उन्होंने इंग्लैंड में रहकर अंग्रेजों को बहुत निकट से देखा था, और उनकी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति पहचानते थे। भारत में अंग्रेजी शासन के पिछले सौ वर्षों के अन्याय और अत्याचार-पूर्ण नीति का ध्यान कर नेहरू की विचारधारा किसी अन्य दिशा में काम करने लगी थी। भारतीय इतिहास में राष्ट्रीयता पैदा करने वाले गुण मौजूद थे, और उन्हीं के प्रभाव से नेहरू जी सरीखे सच्चे राष्ट्रीयतावादी, भारतीय राजनीति के मंच पर ऐसे समय आये जब उनका आगमन देश के लिए बहुत ही आवश्यक था।

सन् १८८५ में ही कुछ अंग्रेजों के सहयोग से, विशेषतः मिस्टर ह्यूम के अथक परिश्रम से, राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हो चुका था। उस समय उसका उद्देश्य सिर्फ देश की सामाजिक और राजनैतिक स्थिति का सविनय ज्ञान, शासकों को कराकर, राजभक्ति के साथ सुधारों की माँग करना था। कांग्रेस का उस समय आन्दोलनकारी रूप न था। इसलिए ब्रिटिश सरकार भी उसके इन कार्यों में हस्तक्षेप न करती थी, बल्कि उसे शासन में विशेष हितकर पाकर प्रारम्भ में उसने उसे विशेष सहयोग ही दिया। परन्तु कुछ वर्षों बाद ही उन्हें अपनी गलती महसूस हो गयी। उनके द्वारा ही आरोपित वृद्ध अब उन्हें फल के स्थान पर काँटे प्रदान करने लगा। वे तिलमिला गये और उसे समूल नष्ट करने की चेष्टा में लग गये परन्तु अब कुछ नहीं हो सकता था; वृद्ध की जड़े देशभक्ति की धरती में काफी दूर तक फैल चुकी थी। इस राजनीतिक आग की धीरे-धीरे जलती हुई पहली लपट ने १९०७ में, जब सत्ता मदान्ध लार्ड कर्जन ने बग-विभाजन किया, देश की सोई हुई जनता में प्रतिहिंसात्मक ब्योति भर दी जिससे देश-भक्ति और क्रान्ति की एक नवीन लहर सी दौड़ गयी। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी के जन-नेतृत्व ने ब्रिटिश सरकार को अपने कदम पीछे हटाने और बग-भग करने की भारी भूल को सुधारने के लिए विवश किया। पर अंग्रेजों ने इस आन्दोलन के लिए जो भीषण अत्याचार किये थे, उनकी यादगार भूल सुधारे जाने के बाद भी समस्त भारतीयों के दिल में

कायम रही, और विदेशी शासन के प्रति भारतीयों की विरोधाग्नि घबकती रही ।

उन दिनों, जब जवाहरलाल विलायत से लौटे, मॉडरेट (नरम) दल वालों के हाँथ में कांग्रेस थी । वे बंगाल में होने वाले आन्दोलन के दंग को देश के लिये अहितकर समझते थे । उनकी दृष्टि में भारतीयों को अंग्रेजों से शिष्टमण्डलों, सिफारिशों और अन्य नरम तरीकों द्वारा शासन में सुधार-व्यवस्था करने की माँग करना चाहिए था । नेहरू तथा अन्य नये और गर्म रक्त वाले नवयुवकों को यह तरीका पसन्द न था । वे अपने अधिकारों को हाथ पसार कर भिखारी की भाँति, नहीं अपितु एक योद्धा की भाँति लेना चाहते थे । वे ब्रिटिश शासक-वर्ग को इतना सम्य और सहृदय नहीं समझते थे कि वे सिर्फ माँगों के आधार पर ही उन्हें सभी इच्छित सुधार देने के लिए तैयार हो जायेंगे । अतः जवाहरलाल जी के अनुसार तत्कालीन भारतीय राजनीति का अर्थ विदेशी शासन के विरुद्ध उग्र रूप से आन्दोलन था जिसमें देश की सभी जनता और सभी वर्ग पूर्ण रूप से सहयोग दे सकें । किन्तु उस समय की नरम राजनीति में जवाहर के विचारों की उग्रता कैसे आ पाती जब कांग्रेस के कर्णधार स्वयं मॉडरेट (नरम) दल के थे ? स्वयं उनके पिता मोतीलाल जी ही उनके इस विचार परिवर्तन को बहुत सन्देह और भय की निगाह से देख रहे थे ।

इन्हीं उग्र विचारों के फल स्वरूप, नेहरू जी ने गोलखले द्वारा स्थापित भारत-सेवक-समिति को काफी सम्मान की दृष्टि से देखते हुये भी, उसके नरम विचारों के कारण कभी उसके मेम्बर होकर उसमें शामिल होने की बात न सोची ।

१९१४ में यूरोप में विश्वव्यापी युद्ध आरम्भ हुआ, सम्पूर्ण संसार की दृष्टि दृत्तचित्त होकर उधर ही लग गई । भारतीयों की दृष्टि भी उसकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था । परन्तु अंग्रेजों ने बिना भारतीयों की मनोवृत्ति और भावनाओं को जाने हुए, बजाये प्रेम और सहानुभूति

के, जबरदस्ती उनसे प्रचुर मात्रा में धन और जन की सहायता ली। इससे भारतीयों के दिल में यह बात और भी जैठ गयी कि ये विदेशी शासक न तो कभी अपने थे और न कभी नविष्णु में ही उनके दुःख दुल के नाथी होंगे। अतः युद्ध में अंग्रेजों के साथ उनकी बहुत ही कम हमदर्दी रह गयी। जर्मनी की जीत की खबर सुनकर ब्या नाटरेट और क्या गरम दल जाते, दोनों ही प्रसन्न होते थे। इसलिए नहीं कि उन्हें जर्मनी से प्रेम था, बल्कि इस स्वाभाविक इच्छा की पूर्ति के कारण की हनारे इन बताते आये हुए महाप्रभुओं का गलर उतर रहा है। कमजोर और कमहाय मनुष्यों के ननने अपने से जबरदस्त को दूसरे से पीटे जाने की खबर सुनकर वैसी खुशी होती है, कुछ वैसा ही यह भाव नों था।

इन्हीं दिनों पंजाब और बंगाल में नवयुवक क्रांतिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की ङड़ा धूम थी। युद्ध के दूसरे वर्ष से ही षड्यन्त्रों और गोखियों से उड़ाये जाने के समाचार मिलने लगे थे। ब्रिटेन के 'डिपेन्ड आफ रिप्लम एक्ट' की तरह भारत में भी रक्षा कानून बना; पर वह कानून वास्तव में भारत-रक्षा के लिये नहीं, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता तथा उनकी जड़े और मजबूत करने के लिए बना था। देश में सरकार द्वारा बनाये हुए दमनकारी कानूनों और जागों की सर्वत्र धूम थी। पर इस दमन से राजनैतिक जीवन बूझने के बढते और अधिक उमरने लगा। जनता एक नवीन चेतना-शक्ति से जाग्रित हो रही थी। ऐसी चेतना-शक्ति जो बार-बार ठोकर लगने के बाद आती है। ऐसी चेतन-ज्ञान जो बच्चों को आग में उँगली जलने के पश्चात् आता है।

धीरे-धीरे राजनैतिक जीवन फिर बढने लगा था, लोकमान्य तिलक जेल में बाहर आ गये थे। उन्होंने तथा मिलेज-ब्रेस्ट ने होनरल्ल लीग की स्थापना का विचार किया। मिलर सिन्हा की अध्यक्षता में होने वाली बंबई की कांग्रेस कान्फरेन्स में होनरल्ल लीग स्थापन का प्रस्ताव भी श्रीमती बेनेट ने रखा था, जिसका उद्देश्य स्वराज्य-प्राप्ति तथा जन-साधारण को कांग्रेस के उद्देश्यों तथा कार्यों से परिचित करना था। यद्यपि उस

अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकृत न हो पाया फिर भी जवाहरलाल जी उसके पक्ष में थे । कांग्रेस में सफल न होने पर भी देवी बेसेन्ट ने कांग्रेस से अलग होमरूल लीग की स्थापना का निश्चय किया, और अथक परिश्रम के पश्चात् मास में पहले पहल उसकी स्थापना भी कर लिया । अन्य प्रसिद्ध नगरों की भाँति थोड़े ही समय में प्रयाग में भी जवाहरलाल नेहरू तथा श्री मजरअली सोख्ता के अथक परिश्रम, और पं० मोतीलाल, सर सप्रू, श्री चिन्तामणि और बाबू ईश्वरशरण के आश्वासन के कारण होमरूल लीग की स्थापना हुई । पं० जवाहरलाल प्रयाग लीग के संयुक्त-मंत्री थे । धन एकत्रित करने तथा संगठन का भार उन्हें ही दिया गया, जिन्हें उन्होंने सुचारु रूप से सम्पन्न करने में कोई कसर नहीं किया । इन सब के फल-स्वरूप कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में कुछ अधिक जोश भर गया और मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ-साथ कदम मिलाकर चलने लगी । वायु मंडल में बिजली सी दौड़ गयी और अधिकांश नवयुवकों के दिल फड़कने लगे । लगता देशप्रेम के प्रबल झुझावात ने अचल और निष्प्रम तिनकों को भी जीवन दानकर उनमें अपार शक्ति फूक दी है ।

होमरूल लीग का यह प्रबल प्रचार देखकर ब्रिटिश सरकार घबड़ा उठी, साम्राज्यवादी सिंहासन हिल उठा और दमन नीति काम में लायी गयी । आन्दोलन की प्रमुख नेत्री देवी बेसेन्ट और उनके साथी मि० अरडेल्ल, श्री० पी० वाडिया आदि नजर बंद कर लिये गये । देश भर में इस अन्याय के प्रति क्रोध और घृणा प्रकट किया गया । पढ़े लिखे लोगों में उत्तेजना काफी बढ़ गयी जिसने होमरूल आन्दोलन में और भी जान डाल दिया, अनेक माडरेट विचार वाले जिनके विरोधी थे वे भी इसमें शामिल हो गये । स्वयं पं० मोतीलाल जी जो नरम विचारधारा के थे, होमरूल लीग में शरीक होकर उसकी प्रयाग-शाखा के अध्यक्ष हुए और धीरे-धीरे वे माडरेटों की विचार-धारा से अलग होने लगे ।

१९१४ में आरम्भ हुए महासमर में भारत ने ब्रिटेन के झूठे नारे 'प्रजातंत्र की रक्षा' के नाम पर, युद्ध के अंत के पश्चात् मावी स्वराज्य के

मिलने की किञ्चित् आशा लेकर, माता के लाखों लालों को मैदान में उतार कर मित्रराष्ट्रों की विजय के लिए उन्हें जीवन की बाजी लगाने की प्रेरणा दी थी। किन्तु युद्ध में विजयी होने के पश्चात् उपहार में उन्हें भीगी आँखें पोछने के लिए मिला क्या ! सहृदय माटेग्यू की अनन्त चेष्टाओं के पश्चात् ब्रिटिश पार्लियामेन्ट से पास एक अधूरा और अनर्थक शासन-विधान; तत्पश्चात् रौलेट एक्ट और मार्शल ला। सम्पूर्ण भारत, इस अपमानपूर्ण विश्वासघात की वेदना से उन्मत्त हो उठा। राष्ट्र ने आँखें खोली, सारे देश में भीषण तहलका मच गया और उसने ५० मोतीलाल को माइरेटों से पूर्ण अलग कर दिया। उनका वकालत में लगने वाला समय भी अब अधिक से अधिक देश-सेवा में लगने लगा।

यह सब हुई उस समय की राजनीतिक प्रगति, परन्तु जवाहरलाल अभीतक खुलकर राजनीतिक और सार्वजनिक कार्यों में आगे नहीं आये थे। १९१५ में इलाहाबाद की एक सार्वजनिक सभा में प्रेस का मुँह बंद करने वाले एक काले कानून के विरोध में वह पहली बार अंग्रेजी में बोले। सभा समाप्त होने के पश्चात् ही वहाँ पर उपस्थित सर सप्रू ने उनके इस साहस पर, सब के सामने ही मंच पर उनका आलिङ्गन कर प्रेम से चुम्बन ले लिया।

नवयुवक जवाहरलाल पर तत्कालीन परिस्थितियों के अतिरिक्त कुछ अन्य नेताओं का भी काफी प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी से उनकी भेट सर्वप्रथम १९१६ में लखनऊ-कांग्रेस में हुई। दक्षिण अफ्रिका में किये गये उनके कार्यों को अन्य नवयुवकों की भाँति जवाहरलाल जी भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। जिस उत्साह के साथ वे प्रवासी भारतीयों के मसले को, कांग्रेस से अलग रहकर अपना रहे थे उससे बिना प्रभावित हुए नहीं रहा जा सकता था। चम्पारन में निहले गोरों के कारण होने वाले किसानों के कष्ट को दूर करने में उन्होंने जैसा साहस दिखलाया और इस मामले में उनकी जो जीत हुई, उससे उनमें और भी उत्साह भर गया। नवयुवक जवाहर ने देखा कि वे हिन्दुस्तान में भी अपने इस तरीके

से कार्य लेने के लिए तैयार है और उससे काफी सफलता की भी आशा है ।

गांधीजी के अतिरिक्त, लखनऊ-कांग्रेस के पश्चात् प्रयाग में दिये गये सरोजनी नायडू के भाषणों का भी नेहरूजी पर अच्छा प्रभाव पड़ा । राष्ट्रीयतापूर्ण और देशभक्ति से सराबोर वे भाषण उनका युवक दिल हिला देते थे । १९१६ में आयरलैंड की बगावत के नेता ने फाँसी के तख्ते से अपने मुकदमे के बारे में जो चिरस्मरणीय आश्चर्यजनक भाषण दिया था, और गुलाम जाति के भावों और उनकी निरीह स्थिति की जो व्याख्या की थी, उसने भी निश्चित ही उन्हें अपनी ओर खींचा था । नेहरू के ही शब्दों में “आयरलैंड में ईस्टर के दिनों में जो बगावत हुई, उसकी विफलता ने भी हमें अपनी ओर खींचा, क्योंकि जो वर्तमान विफलता पर हँसता हुआ ससार के सामने यह घोषणा करता है कि एक राष्ट्र की अजेय आत्मा को कोई भी पाशविक शारीरिक शक्ति नहीं कुचल सकती, वह अद्वितीय सच्चा साहस ही है ।”



राजनैतिक क्षेत्र में गांधी जी का प्रवेश तथा प्रभाव

अपने दक्षिणी अफ्रीका में किये गये कार्यों के फलस्वरूप गांधी जी पहले से ही नवयुवक हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर चुके थे। स्वयं नेहरू जी भी नये अनुभव और नये साहसिक कार्यों के लिए ललक रहे थे। अतः स्वाभाविक था कि दक्षिणी अफ्रीका से लौटे हुए इस पतले-दुबले और बहुत ही साधारण दीखनेवाले व्यक्ति के अद्भुत और नये दंग के अपनाये हुए राजनैतिक रास्ते की ओर उनकी दृष्टि जाती। सन् १९१६ में उनकी भेंट गांधी जी से सर्वप्रथम लखनऊ कांग्रेस में हुई। सन् १९२७ में गांधी जी ने अपनी नयी कार्य-यद्यपि के दो प्रयोग, यद्यपि छोटे पैमाने पर ही, कर लिए थे।—एक तो चम्पारन जिले में और दूसरा खेड़ा (गुजरात) में। चम्पारन और खेड़ा के किसान-सत्याग्रह पं० जवाहरलाल को कर्मक्षेत्र में उतरने के लिए आवाहन कर रहे थे। अवध के असहाय किसानों के बहते आँसुओं को देख कर तो उनका धैर्य छूट गया। उन्होंने आनन्द भवन के मुलायम गद्दे और वैभव विलास से पूर्ण मगलमय जीवन को त्याग दिया। पहली बार उन्होंने भारत का वास्तविक स्वरूप दीन-हीन, खोखली हड्डियों के सोंचे में ढले, मास-विहीन शरीर पर चिथड़े लपेटे, मनुष्य कहे जाने वाले श्रमसिक्त निर्जाब किसानों में देखा जिन्हें दिन रात पिसने के पश्चात् भी भरपेट रोटी स्वप्न थी।

प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने के पश्चात् हिन्दुस्तानियों की आशा के विरुद्ध रौलेट एक्ट का भारत में आगमन हुआ। यह राजनीतिक नेताओं का दमन करनेवाली तथा पत्रों का खुला वाचाल मुँह बंद कर देने वाली सरकार की एक नयी 'लिखित व्यवस्था' थी। इसमें कानूनी काररवाई के

बिना भी गिरफ्तार करने और सजा ठोक देने की धाराएँ रखी गयी थी। हिन्दुस्तानियों के विरोध के बावजूद भी ३ साल के लिए यह एकट उन पर लागू हो गया।

सन् १९१६ में गांधी जी बहुत बीमार थे। उन्होंने जब इस नये ऐक्ट के बारे में सुना तो रोग-शैया से ही इसके विरोध में आवाज उठायी: और वायसराय से अपील की कि वह इस आपत्तिजनक कानून को अपनी स्वीकृति न दे। अन्य अपीलों की तरह उनकी इस अपील की भी परवाह न की गयी। फलस्वरूप कर्मवीर गांधी को अपनी इच्छा के खिलाफ मैदान में आना पड़ा। उन्होंने 'सत्याग्रह समा' का आरम्भ किया और एक ऐसे कार्य क्रम के लिए स्वयंसेवक भरती करने शुरू किये जिसमें अप्रीतिकर सम्भावनाएँ स्पष्ट दीखती थी। उन्होंने जनता को इस अपमानकारी कानून को अमान्य करने की प्रेरणा दी। स्वयंसेवकों से प्रतिज्ञा करायी कि वे इसका विरोध करेंगे और हँसते-हँसते जेल जायेंगे। यह १८५७ के बाद पहला देशन्यायी आन्दोलन था। तब जवाहरलाल को उस नये व्यक्तित्व से एक नया और अपरिचित ही, परन्तु हृदय को अच्छा लगनेवाला स्वर सुनायी दिया, "जो कि दूसरे स्वरों से सर्वथा भिन्न था। वह शान्त और धीमा था परन्तु भीड़ की चिल्लाहट में भी सुनायी पड़ता था, मधुर और कोमल था परन्तु उसमें इस्पात की कठोरता भी छिपी हुई थी,..... प्रत्येक शब्द अर्थ भरा और दृढ़ता-सूचक था,यह वचन की नहीं, कर्म की राजनीति का स्वर था।" जवाहरलाल जी ने भी गांधी जी का यह आह्वान सुना और उससे पुलकित हो उठे। वे तो तत्काल ही सत्याग्रह के इस नये सगठन में मर्तों हो जाने के पक्ष में थे—यौवन परिणाम को नहीं सोचता, उसकी भावुकता नये साहसिक कर्म के अवसर खोजती है। किन्तु अनुमवी मोतीलाल जी कानून-भग करने और साम्राज्य की शक्ति से लोहा लेने वाले इस आन्दोलन के परिणाम को खूब जानते थे। यह स्वाभाविक ही था कि वे अपने एकमात्र पुत्र के किसी भी ऐसे कार्य में सहयोग देने का विरोध करते।

गये रक्त ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आन्दोलन की शपथ को और पक्का कर दिया । अपनी अजेयता का दाम्मिक दावा करने में ही बृटिश सत्ता ने अपना समाधि-लेख भी तैयार कर लिया था ।

सत्याग्रह आन्दोलन के कारण जो घटनाये घटी उनसे गांधी जी को गहरा क्षोभ हुआ । उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनसे महान् भूल हुई है । उनके अनुसार उन्होंने सत्याग्रह के अन्न का प्रयोग ऐसे समय किया जब कि सम्पूर्ण देश उनके लिए तैयार न था; जिसके कारण ऐसे लोगों को गड़बड़ फैलाने का अवसर मिला जो वास्तव में सत्याग्रही नहीं, अपितु अवसरवादी थे । अतः उन्होंने आन्दोलन उचित समय तक के लिए स्थगित कर दिया ।

कांग्रेस का अगला वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था । लोकमान्य तिलक तथा अन्य पुराने नेता भी उपस्थित थे, लेकिन भारत के राजनैतिक आकाश पर गांधी के रूप में एक नये सूर्य का उदय हो चुका था । सम्पूर्ण वातावरण 'गांधी जी की जय' के उस नारे से गूँजने लगा था जो १९४८ में गांधी जी की मृत्यु के पश्चात् भी समाधि न ले सका और राजनीतिक वायुमंडल में, जन-जन के हृदय में, अब भी गूँज रहा है । उनकी विचारधारा उस समय भारतीय विचार परम्परा को प्रभावित कर रही थी और कदाचित् आज भी कांग्रेस की सबसे बड़ी पूँजी है ।

अमृतसर कांग्रेस के समापति पं० मोतीलाल नेहरू हुए । यहाँ का कार्यक्रम विशेष नहां था, क्योंकि सारा देश 'हंटर कमेरी' की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा था, जो पंजाब की दुर्घटना की जाँच के लिए नियुक्त हुई थी । अमृतसर की इस कांग्रेस में अली-बंघु भी उपस्थित थे जो अभी हाल में ही नजरबंदी से छूट थे । राष्ट्रीय आन्दोलन एक नया रूप धारण कर रहा था और उसकी नयी नीति-निर्माण करने में गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था ।

मौलाना मुहम्मद अली के खिलाफत-डेपुटेशन में योरोप चले जाने के पश्चात्, भारत में गांधीजी ने स्वयं खिलाफ आन्दोलन का साथ दिया

और कांग्रेस से साथ देने की अपील की। खिलाफत आन्दोलन से सम्बंधित जो प्रार्थना पत्र वायसराय के पास भेजा जा चुका था, उसकी बहुत से शब्दों में व्यक्त पर गोल-मोल और अस्पष्ट बातों, तथा बहुत सारी माँगों के गांधीजी खिलाफ थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वह वायसराय से मिलने जाने वाली खिलाफत डेपुटेशन का साथ तभी दूँगे जब उसमें उनके कथनानुसार उचित रद्दोबद्दल किया जाय। बहुत वादा-विवाद के पश्चात् मुसलमानों ने उनकी बात मान ली और एक नया मसौदा तैयार कर वायसराय के पास भेजा गया जिसे गांधी जी ने मंजूर किया तथा डेपुटेशन का साथ दिया। परन्तु मुसलमानों की माँगें स्वीकार न हुईं; फलस्वरूप आन्दोलन की बात उठी। गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं आपका नेतृत्व तभी कर सकूँगा जब आप अपने आन्दोलन में अहिंसक नीति का पालन करें। काफी वादविवाद के पश्चात् मुसलमानों की ओर से यह प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया। खिलाफत कमेटी ने १ अगस्त लड़ाई जारी करने का दिन मुकर्रर किया। यद्यपि सभी व्यक्तियों ने आन्दोलन निश्चित तारीख को आरम्भ कर देने के लिए अपनी राय दे दी थी, परन्तु दिल ही दिल में खिलाफत आन्दोलन के सभी नेता डर रहे थे। इस कायर मनोवृत्ति और ऐसे वातावरण को देखकर युवक जवाहरलाल को उनपर एक अजीब सी खींझ और क्रोध उत्पन्न हो रहा था। वे सोचते थे क्या ऐसे ही लोग क्रान्तिकारी आन्दोलन के अगुवा होंगे और ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देंगे? कहीं तो उन्होंने सोचा था कि वहाँ जोश और उत्साह की गरमागरम भाषा और ओखों से आग की चिनगारियाँ निकलती मिलेंगी और कहीं उन्हें वहाँ इसके बजाय पालतू, डरपोक और अधेड़ लोगों का जमघट दिखलायी दिया।

१ अगस्त को गांधी जी ने असहयोग की शुरुआत की और बंबई में उसका नेतृत्व भी किया, जिसमें जवाहरलाल उनके साथ थे और असहयोग के उस बृहत् जुलूस में शरीक भी हुए थे!

किसान-आन्दोलन के नेता

भारत का भविष्य किसानों के हाथ है (जवाहरलाल)

यह एक विचित्र बात थी कि कर्मक्षेत्र के वास्तविक दिशा—किसानों का नेतृत्व और उनके जागृति—की ओर मुड़ने के पूर्व, बुद्ध की भोंति जवाहरलाल जी को भी भारत के दरिद्र और दीनहीन कृषक और मजदूर वर्ग की वास्तविक स्थिति से विशेष परिचय न था। अन्य उच्च मध्यवर्गीय नेताओं की भोंति वे भी राजनीति-सागर की सतह पर ही हाथ पैर मारा करते थे। कल-कारखानों और खेतों में काम करने वाले जर्द चेहरेवाले मजदूरों की वास्तविक दशा से अनभिज्ञ, उनका दृष्टिकोण भी कुछ कुछ मध्यम वर्गीय रईस नेताओं की भोंति था, जिनके मस्तिष्क में बहुत धुँधले स्वप्न की ही भोंति यह स्पष्ट चित्रित था कि उनका सोने का देश गरीब है, जहाँ बेकारी और भुखमरी है, और जिसका नेतृत्व उन्हें ही करना है। इस अज्ञानता का सब दोष इन नेताओं को ही नहीं दिया जा सकता। उन दिनों कोई भी ऐसा पत्र न था जो अंग्रेज अफसरों की खुश-नुमा जिन्दगी और दिलपसन्द नाच गानों से भरी हुई उनकी पार्टियों की खबर छोड़ कर, इन करोड़ों भारत की पैबद लगी आत्मा की बात छापते। परन्तु पत्रों की यह स्थिति असहयोग आन्दोलन आरम्भ होने के पश्चात् अधिक दिन तक न रह सकी ! हिन्दुस्तान के बढ़ते हुए राजनैतिक आन्दोलन तथा राष्ट्रीय प्रश्नों को अपने अखबार में अंग्रेजी पत्रों को भी स्थान देना पड़ा, क्योंकि यदि वे ऐसा न करते तो जागृति के फलस्वरूप देश की वास्तविक मौजूदा हालत जानने के लिए उत्सुक पढ़ी लिखी जनता उन्हें खरीदना-बंद कर देती, और उन्हें अपनी रोजी के लाले पड़ने पड़ते।

देश की इन करोड़ों जनता की वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ आनन्द । भवन में आराम कुर्सी पर बैठे तब के नेहरू एक भूली बात की तरह सोचा करते “उनके देश की जनता गरीब है और उनके दुख भयंकर हैं । राजनैतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान के आजाद हो जाने के बाद हमलोगों का पहला काम गरीबी के मसले को हल करना होगा ।” उन्हें सबसे पहली सीढ़ी तो राजनैतिक आजादी ही दिखलाई देती थी, जिसमें मध्यम वर्ग की प्रधानता हुए बिना नहीं रह सकती । वे गांधी जी के चम्पारन और खेड़ा आन्दोलन के पश्चात् किसान समस्या पर अधिक ध्यान देने लगे थे । फिर भी उनका ध्यान १९२० तक राजनैतिक बातों में और असहयोग के आगमन में लगा रहा जिसकी चर्चा से तत्कालीन वायुमंडल भरा था । परन्तु १९२० में एकाएक एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने नेहरू की जीवन-धारा को मोड़ दिया । जिसने नेहरू के जीवन को रचनात्मक कार्यों की ओर आकर्षित किया और उनको गरीब देश के प्राण, किसानों और मजदूरों में ला खड़ा किया, जिनसे वे किताबी जानकारी के अलावा एक दम अनभिज्ञ थे । यह महत्वपूर्ण घटना थी नेहरू का मसूरी से निर्वासन ।

पंजाब से लौटने के पश्चात् नेहरू ने जब माँ और पत्नी के गिरे हुए स्वास्थ्य को देखा तो वे उन्हें लेकर प्रकृति की गोद—मसूरी—में पहुँचे और वहाँ सेवाद होटल में ठहरे । सरकार की क्रूर दृष्टि नेहरूजी पर पड़ चुकी थी और वह उन पर अपना दमन-चक्र चलाने की घात में थी । उन्हीं दिनों अफगान प्रतिनिधि मंडल भी, जो ब्रिटिश-राज-प्रतिनिधियों से संधि की शर्तों को निश्चित करने आया था उसी होटल में टिका था । जिले के अधिकारी प० जी की एकाएक उपस्थिति से भयभीत हुए—यद्यपि उनका यह भय निमूल था क्योंकि जवाहरलाल जी ने न तो उनमें से किसी प्रतिनिधि से बात ही की थी और न उन्हें किसी दिन देखा ही था । अधिकारियों ने पंडित जी से यह वादा करने के लिए कहा कि वे अफगानियों के किसी प्रतिनिधि से बात न करेंगे । अफगान मंडल से पूर्ण

अपरिचित होते हुए भी नेहरू जी को इस प्रकार का प्रस्ताव अपने सम्मान के विपरीत लगा। वे सिद्धान्त के दृढ़ थे, और सिद्धान्ततः इस आज्ञा को अनुचित समझते थे। अतः उन्होंने इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव में वचनबद्ध होने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप उन्हें २४ घंटे के अन्दर ही राजाजा से, माता, पत्नी और बहन को बीमारी हालत में छोड़कर, मंसूरी से हठ जाना पड़ा। पिता और पुत्र ने तत्कालीन युक्तप्रान्तीय गवर्नर सर हारकोर्ट बटलर को सूचित किया कि चाहे वे इस प्रकार की आज्ञा रद्द करे या न करे; जवाहरलाल, माँ और पत्नी की हालत खराब होने पर, आज्ञा की अवज्ञा कर के भी मंसूरी अवश्य जायेंगे। हुक्म वापस ले लिया गया और जवाहरलाल अपने उस छोटे से परिवार से मिलने फिर मंसूरी जा पहुँचे। इस घटना से जवाहरलाल जी के सिद्धान्त प्रेम, स्वातंत्र्यप्रियता और आत्मसम्मान का परिचय मिलता है।

मंसूरी-निर्वासन-काल में ही ५० जवाहरलाल नेहरू अचानक ही किसान-आन्दोलन में जा पड़े। जून १९२० के आरम्भ में, एक दिन एका-एक प्रतापगढ़ के करीब दो सौ किसान-करीब ५० मील चल कर प्रयाग में किसी उच्च नेता का, अपने प्रति किये जाने वाले जर्मीदारों के जुल्मों की की ओर ध्यान आकर्षित कराने के उद्देश्य से आये। यमुना-घाट पर उनकी श्री जवाहरलाल से भेंट हो गयी। उन्होंने उनसे गाँवों में आकर अपने प्रति किये जा रहे अत्याचारों का विरोध करने का वादा करा लिया।

जवाहरलाल जी ने पहले पहल भारत की जनता-जनार्दन की भल्लक जाकर उन गाँवों में देखी। उनके आगमन से सम्पूर्ण देहात में उत्साह की एक लहर फैल गयी। उनके आह्वान पर प्रेममग्न जनता की उच्च 'सीताराम' की धुन सुन पड़ती, जो आकाश में गूँज उठती और चारों तरफ दूर-दूर तक फैल जाती। दूसरे गाँव से उसी की प्रतिध्वनि सुनायी पड़ती और अपार जन-समुद्र उन्मुक्त अजस्र-धारा की भाँति दौड़ा चला आता। मर्द, औरत और बच्चों की फटो आँखों में एक नवीन ज्योति दिखलायी पड़ती, मानो वे किसी देवदूत का पावन सन्देश सुन रहे हों।

वास्तविकता के उस दर्पण में देश का स्वरूप देखकर नेहरू का भावुक हृदय दुःख से रो उठता। उन्हीं के शब्दों में “मुझे दुःख तो हिन्दुस्तान की जबरदस्त गरीबी और जिल्लत पर, और शर्म मेरी अपनी आराम की जिन्दगी पर और शहरों की उस बेकार राजनीति पर आता था, जिसमें भारत के इन अधनंगे करोड़ों पुत्र-पुत्रियों के लिए कोई स्थान न था।” उसी दिन से उनके युवक दिल ने उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस की, और अब तक उसे अपने दिल के एक कोने में पाले वे उस पर अमल करते रहे।

इस नये कर्म-ज्ञान ने उनके दिल में एक नयी ज्योति जगा दी। अतः उन्हें उन गंदे मनुष्यों के बीच कंधे से कंधा भिड़ाकर काम करने में शर्म और सकोच नहीं मालूम होने लगा। गमों की तेज धूप और दुपहरिया की तपन में वे उनकी दर्द कहानी सुनते और अपनी मधुरवाणी से उनके दिल के फफोलों पर मरहम लगाते। उन्हीं के साथ गाँव-गाँव घूमते, खाते और कच्चे भोजन में सो रहते। खुफिया पुलिस उनके इन कामों को सन्देह की निगाह से देखती और उनके पीछे-पीछे घूमा करती। नेहरू उस निष्कपट और सच्ची जनता के सामने प्रभाव-शाली ढंग से भाषण देते, यद्यपि उनकी सब बातें जनता की वह भीड़ न सुन पाती, न समझ पाती, लेकिन जैसे उसका दिल, एक एक रोआ उसके मस्तिष्क के अन्जाने में उस तेजस्वी नवयुवक की बात समझ जाता, उसे पी जाता।

दुनिया के हर एक क्रान्तिकारी देश को, जिसने विदेशी सत्ता से अपनी स्वतंत्रता के लिए मोर्चा लिया, विधाता ने ऐसे ही नेता प्रदान किये थे, जो देश के किसान और मजदूर में, दलित वर्गों में, जाग्रिति उत्पन्न कर सके। असली क्रान्ति तो वास्तव में वही है जो इन अशिक्षित क्रान्तिकारियों के बीच उत्पन्न की जाये। इसीलिए गाँधी और लेनिन ने भी भ्रमजीवी आन्दोलन को ही मुख्य रूप से अपनी क्रान्ति का आधार बनाया था। नेहरू ने भी अहिंसक क्रान्ति-प्रचार के इस कार्य में प्रमुख होंथ बढ़ाया।

पीड़ित किसानों में एक नया आत्म विश्वास पैदा हुआ और वे सिर ऊँचा करके चलने लगे। जमीन्दारों के कारिन्दों, और पुलिस का डर उनके दिलों में कम हो गया। यदि किसी किसान का खेत बेदखल कर लिया जाता तो दूसरा किसान उसे लेने से इनकार कर देता। जमींदारों के नौकरों का उन्हें मारना पीटना तथा वेगार आदि लेना काफी कम हो गया। जब कोई इस प्रकार की घटना होती तो उसकी जाँच करने का प्रयत्न किया जाता। इससे जमीन्दारों के कारिन्दों और पुलिस के अत्याचार बहुत घट गये। जमींदार और ताल्लुकेदार धबड़ाये और अपनी रक्षा का उपाय ढूँढ़ने लगे। नेहरू के प्रभाव से किसान आन्दोलन का प्रबल वेग बढ़ते देख, शक्ति सरकार ने अवध-कास्तकारी-कानून में सुधार करने का वादा किया। कृषक-क्रान्ति का सन्देश दूर-दूर तक के गाँवों में पहुँच गया और किसान पहली बार अब सरकारी आशाओं पर प्रश्न और आपत्ति करने का साहस करने लगे।

‘स्वराज्य’ एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें सब कुछ आ जाता है, फिर भी उन दिनों दोनों आन्दोलन—असहयोग और किसान आन्दोलन—विलकुल अलग-अलग थे। यद्यपि संयुक्तप्रान्त में दोनों ही एक दूसरे पर पर्याप्त असर डालते थे। कांग्रेस के प्रचार, और नेहरू आदि के इन कार्यों का परिणाम यह हुआ कि ग्रामीणों के बीच होने वाली आपसी मुकदमे-बाजी एकबारगी कम हो गयी। गाँवों में पंचायतें कायम हो गयीं, जो अपने बीच के झगड़ों का फैसला स्वयं करने लगीं। कांग्रेस का असर शान्ति के हक में खास तौर पर ज्यादा पड़ा, क्योंकि जहाँ भी कोई कांग्रेसी कार्य करने जाता वहाँ वह इस नये अहिंसा के सिद्धान्त पर अधिक जोर देता, इससे किसानों के बीच होने वाले युद्ध अवश्य कम हो गये।

भारत विशेषतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ८५% जन-संख्या गाँवों में निवास करती है। तीन चौथाई जन संख्या खेतिहर है, शेष एक चौथाई जन-संख्या भी उन्हीं के खून और पसीने पर आश्रित है। स्वयं जवाहरलाल जो के ही शब्दों में “सरकार की सारी मशीन किसानों

के पैसे से ही चल रही है। फौज व्यय में, वायसराय, गवर्नरों और दूसरे अफसरों की लम्बी चौड़ी तन्खाहों में जो रुपया खर्च किया जाता है वह कहीं से आता है ? भारत के दरिद्रतापूर्ण देहातो से। हमारे शहर देहातो के व्यय पर ही गुजर बसर करते हैं।” अस्तु, भारत के किसानों के उद्धार और भारत के उद्धार का अर्थ एक ही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संयुक्तप्रान्त, और विशेषतः अवध के किसानों को उन्नतिशील बनाने के लिए महामना मालवीय जी के प्रयत्न से १९१५ में किसान सभा की स्थापना हुई थी। आगे चलकर इसके श्री जवाहरलाल जी उपसभापति भी हुए थे। किसान-समस्या के सम्पर्क में आने के पश्चात् उन्हें इन भुखमरो से स्वाभाविक प्रेम हो गया था। तत्कालीन समाज, पूर्वावाद और ब्रिटिश सरकार से उन्हें पूर्णतः घृणा हो गयी थी, और वे उस व्यवस्था को, जो इन सभी की कारण थी, समूल उखाड़ फेंकना चाहते थे। वे इसमें पूर्ण रूप से लग भी गये और किसानों को उनकी वास्तविक दशा का ज्ञान कराने लगे। वे अहिंसक क्रान्ति का संदेश पहुँचाते जो किसानों के बीच एक विचित्र जोश भर देता था। नेताओं की एक पुकार पर वे सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार थे। एक चिनगारी पड़ने की देर थी कि आग धधक उठती। फिर भी उन्होंने गजब की शान्ति दिखलायी। यद्यपि कभी-कभी यह अग्नि कुछ छुट-पुट रूप में फूट पड़ती।

परन्तु अशान्ति की यह वह्नि अधिक दिन तक दिल में न दब सकी। १९२१ की जनवरी में रायबरेली का हत्या कांड हुआ, जो इस आन्दोलन की एक प्रमुख घटना है। अवध के एक तारलुके के राजा साहब अत्यधिक विलासी थे, और अपनी रानी को बहुत ही कष्ट देते थे। रानी ने अपने पति के विरुद्ध गाँव की पंचायत से अपील की, पंचों ने रानी के पक्ष में फैसला दिया और राजा को पंचायती न्याय मानने के लिए मजबूर किया। राजा उस समय मान गये पश्चात् पुलिस को ‘बगावत’ की सूचना देकर, उन पंचों और किसानों के कुछ अन्य नेताओं को गिरफ्तार करा दिया। असंतुष्ट किसानों की अपार भीड़ रायबरेली जा पहुँची। सरकार भी वे-

सुघ न थी, किसानों को तुला हुआ देखकर उसे बलवा होने का पूरा भय था । सशस्त्र पुलिस और फौज के जवान उस निहत्थे जनसमूह के विरुद्ध पुल के इस पार तैनात किये गये, किसान-नेताओं और पंचों को छोड़ने की माँग करते और पुलिस शस्त्र का भय दिखला कर उन्हें तुरन्त लौट जाने की आज्ञा देती । स्थिति की गम्भीरता देखकर नेहरू जी को प्रयाग पहले ही तार दिया जा चुका था । वे नागपुर कांग्रेस से थक कर लौटे ही थे कि उन्हें तार मिला । नेहरू जी तुरन्त ही रायवरेली की ओर चल पड़े । स्टेशन पर पहुँचते ही उन्हें स्थिति की गम्भीरता की खबर लगी, वे फौरन ही नदी की ओर चल पड़े जिधर सशस्त्र फौजी पुलिस किसानों का सामना करने के लिए खड़ी थी । रास्ते में उन्हें जिला मजिस्ट्रेट का एक लिखित आज्ञा-पत्र मिला कि तुम तुरन्त वापस लौट जाओ । अपने संकट का ख्याल न करते हुए नेहरू जी ने तुरन्त ही उस पुरजे की पीठ पर यह लिखकर, कि 'आप कानून की किस धारा के अनुसार मुझे, वापस लौटाना चाहते हैं बिना यह जाने मैं अपना कार्य जारी रखूँगा' उस पुरजे को संदेश वाहक के हाथ में वापस लौट दिया । नेहरूजी ने उसपर किसानों के बीच पहुँचने की बहुत चेष्टा की, किन्तु एक फौजी सिपाही द्वारा वे बलपूर्वक रोक लिए गये । अपार भीड़ पर जिस समय गोली चली, उनका हृदय टूट गया, प्रत्येक गोली जो किसानों को लगी सदा के लिए उनके दिल में बैठ गयी । ५ मिनट तक गोली चलती रही । घबड़ाये हुए किसानों का जत्था उन्हें देख कर एक नवीन आशा से उनकी ओर दौड़ा । उन्होंने तत्काल कुछ हजार किसानों को जमा कर अपने शब्दों से उनकी उत्तेजना और डर कम करने का प्रयत्न किया । नेहरू के जीवन में यह पहला अवसर था जब उन्होंने अपने निहत्थे भाइयों पर नृससता के साथ इस प्रकार गोली चलते देखा था । सारे हिन्दुस्तान की दृष्टि में यह क्षोभप्रद घटना बड़ी मामूली समझी गयी और उसपर कुछ भी ध्यान न दिया गया । यहाँ तक कि अखबारों ने भी उसे एक महत्वहीन घटना समझा और अपना 'सम्मानित पत्र' ऐसी 'छोटी और अनर्गल बातों' से भरना

ठीक न समझा, इन सम्पादकों और अधिकांश शहराती पाठकों के लिए नगे किसानों की जमातों के उन कामों में कोई 'असली राजनीतिक' या दूसरे प्रकार का महत्व नहीं छिपा था ।

किसानों का आन्दोलन प्रबल वेग से बढ़ता रहा । सरकार भी इसे पूर्ण रूप से कुचल देने के लिए कटिबद्ध हो चुकी थी, रायबरेली में दो बार और गोली चली । प्रमुख किसान कार्यकर्ता तथा पचायत के सदस्य गिरफ्तार होने लगे । कांग्रेस की प्रेरणा से किसानों में चरखा चलाने की प्रवृत्ति आ गयी थी; परन्तु अब जिस ग्रामीण के घर में पुलिस चरखा देखती, उसे गिरफ्तार कर लेती या अन्य प्रकार से कष्ट देती । बहुतेरे चरखे जला दिये गये । सैकड़ों गिरफ्तारियाँ हुईं और दमन-चक्र का वेग प्रबल हो उठा । किसान-आन्दोलन की सफलता का यही प्रमाण था कि सरकार की बहुमुखी दमन-शक्तियों कृषकों को कुचलने में लगी थी । यद्यपि जाहिर तौर पर यह आन्दोलन बहुत कुछ दब गया, परन्तु कृषकों के हृदय में दमन के साथ असंतोष भी तीव्रता से बढ़ता रहा, और देखते-देखते वह आन्दोलन देश व्यापी हो गया । कांग्रेस के अहिंसात्मक आन्दोलन के साथ जनतंत्रवादी, समाजवादी, साम्यवादी और क्रांतिकारी सभी प्रकार के आन्दोलन ब्रिटिश सत्ता की जड़ हिलाकर खोखली करने लगे, और देश तीव्रता से स्वतंत्रता एवं समानता की ओर बढ़ने लगा ।

असहयोग-आन्दोलन और जेलयात्रा

असहयोग वह भावना है जो हमें बताती है कि हमारे लिए, विदेशियों को अपनी हुकूमत हम पर जमाये रखने में सहायता पहुँचाना खतरनाक और शर्मनाक है। (सिल्ली)

अमृतसर की खूँ रेजी ने देश में असन्तोष की आग फूँक दी थी। रौलट एक्ट और मार्शल ला लोगों के हृदय में विष-बाण की तरह चुभ गये थे। जलियाँवाले बाग के हत्यारे डायर को उचित दंड न देकर ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक स्वामिमानी भारतवासी को अपना शत्रु बना लिया था। मुसलमान, तुर्की के खिलाफत के प्रश्न को लेकर ब्रिटिश सरकार पर बिगड़े हुए थे। भारतीय जनता मान्टेग्यू-चेम्सफोर्ड-सुधारों से असन्तुष्ट होकर राजनैतिक समस्याओं का स्वयं ही निबटारा कर लेने पर तुल्ली हुई थी। इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए महात्मा गांधी ने उचित अवसर पर देश का नेतृत्व कर, उसके समक्ष असहयोग का कार्यक्रम उपस्थित किया।

गांधी जी के नेतृत्व में अटल विश्वास होने के फलस्वरूप, असहयोग आन्दोलन की सफलता और सिद्धान्त के प्रति कुछ शंका होने के पश्चात् भी, नेहरूजी ने उसमें आरम्भ से ही सहयोग दिया, और उसके प्रचार में प्राणप्रण से जुट गये; यद्यपि नेहरूजी को किसी देश के स्वातंत्र्य-युद्ध में, अहिंसात्मक असहयोग से विशेष कार्यसिद्धि होने पर विश्वास नहीं था। उन्हीं के शब्दों में “मैं जिस बात का आदर करता था वह था उस आन्दोलन का नैतिक और सदाचार सम्बन्धी पहलू तथा सत्याग्रह। मैंने अहिंसा के सिद्धान्त पर सोलहो आने नहीं विश्वास कर लिया था, लेकिन हाँ, वह मुझे अधिकाधिक अपनी ओर खींचता जा रहा था, और यह विश्वास मेरे

दिल में पक्का बैठता जा रहा था कि हिन्दुस्तान की जैसी परिस्थिति बन गयी है, हमारी जैसी परम्परा और संस्कार हैं, उन्हें देखते हुए यही हमारे लिए सही रास्ता है।" और अंत में नेहरूजी ने यही रास्ता पकड़ना उचित समझा, जिसकी ओर बढ़ने के लिए देश के राजनैतिक चौराहे पर खड़े सर्वशक्तिमान नेता गांधी ने इंगित किया था।

यों तो अहिंसात्मक असहयोग का उद्देश्य परतंत्र भारत की वेड़ियों को तोड़ने की गरज से अंग्रेजों से लोहा लेना था; परन्तु उस समय कांग्रेस के सामने दो बड़े प्रश्न थे—पंजाब का हत्याकांड और तुर्की की खिलाफत। उन्हीं के हल के लिए इम आन्दोलन का संगठन और नेतृत्व करने का महात्मा गांधी ने निश्चय किया।

असहयोग-आन्दोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक काशी में हुई। कमेटी ने कार्यक्रम स्वीकार करते हुए पुनर्विचार के लिए कांग्रेस महासभा का विशेष अधिवेशन कलकत्ते में बुलाना निश्चित किया। सितम्बर १९२० में, कलकत्ता में कांग्रेस का यह पर्व निश्चित विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय के समापतित्व में हुआ, जो लम्बे अरसे तक देश से बाहर रहने के पश्चात् हाल में ही अमेरिका में लौटे थे। अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी ने हिन्दू और मुसलमान दोनों कौमों से, एक साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर आन्दोलन को सफल बनाने की अपील की। उनके अनुसार असहयोग का अर्थ था, शासन यंत्र के संचालन में देश का एक बच्चा भी सरकार का साथ न दे। भारतीय सरकारी नौकर नौकरी छोड़ दें, वकील ब्रिटिश पत्रपात पूर्ण अदालतों में बकालत छोड़ दें। विद्यार्थीगण गुलामी सिखलाने वाले शिक्षा-क्रम से नाता तोड़ लें। प्रत्येक विदेशी वस्तु, और विशेषतः विदेशी वस्त्रों का पूर्ण बहिष्कार किया जाये, और खहर को देश का कौमी वस्त्र समझ कर अपनाया जाये। ग्रामीण अपने भूगढ़ों का फंसला पंचायतों द्वारा करें काउन्सिल और उनके चुनाव में भाग लेना त्याग्य नमझा जाये।

तत्कालीन कलकत्ता-कांग्रेस के अध्यक्ष तिलक को सहयोग की यह नयी योजना नापसंद थी। कांग्रेस के अन्य पुराने प्रतिभाशाली महारथियों के साथ उन्होंने इस नीति का विरोध किया। स्वयं देशबन्धु श्री चित्तरंजन दास उस विरोध के अगुआ थे, उनका विरोध इसलिये नहीं था कि वे उस आन्दोलन के मूलभाव को नापसंद करते थे—वे तो उस हद तक, वल्कि उससे भी आगे जाने के लिये तैयार थे, वे विरोध खासकर इसलिये कर रहे थे की नयी काउन्सिलों के बहिष्कार पर उन्हें एतराज था। इन सब विरोधों के होते हुये भी श्री मोतीलाल जी ने गांधीजी का साथ दिया अन्त में उस अधिवेशन में कुछ चोटी के नेताओं—लाला लाजपत राय देश बन्धुदास, श्री मदन मोहन मालवीय आदि—को छोड़कर असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के सदस्य कार्यक्रम को जी जान से पूर्णतः सम्पन्न करने के लिये तत्पर हो गये। सारा देश गांधी की पुकार पर असहयोग के लिये तत्पर हो गया। योग्य नेता के नेतृत्व में देश में संगठन आरम्भ हुआ और काश्मीर से कन्याकुमारी तक असहयोग की प्रचंड अग्नि जल उठी। गांधी ने अपनी गम्भीर वाणी से भारत की शत-शत जनता के हृदय में अमूल्य मंत्र फूका “आजाद हो जाओ, गुलाम मत बने रहो।” हिमालय से टकराकर वह बुलन्द आवाज देश के कोने-कोने तक फैल गयी, और उसकी गम्भीर प्रतिध्वनि से सोये हुये जड़ राष्ट्र की हततंत्री भन-भनना उठी। नेहरू की आत्मा भी परतंत्रता के असह्य बोझ से छुटकारा पाने की उम्मीद में खुशी से नाच उठी। एक आकस्मिक भटके के साथ भारतमाता की वेड़ियाँ दीली होने लगी, और आजादी का विशाल सिंह-द्वार धीरे-धीरे खुलने लगा।

वृष्टि साम्राज्यवादों शक्ति से ज़ोरदार टक्कर लेने के एक नये रास्ते, ‘आसहयोग’ को पाकर, अन्य नवयुवकों की भाँति जवाहरलाल का भी गर्म और जवान खून और तेजाँ से उनकी नसों में दौड़ने लगी। उन्हीं के शब्दों में, “हमारे उत्साह, साहस और आशावाद का कुछ ठिकाना न था। हम ऐसे मुख और आनन्द का अनुभव हो रहा था

जैसे हम जिन्नी शुभ कार्य के लिये धर्म-युद्ध में जा रहे हैं। हमारे मन में उस समय संकोच और शंका के लिये स्थान न रह गया था। हमारे मनमें हमारा मार्ग एक ठन लुप्त हो गया था, और हम एकदम ड्रागे जड़े चले जा रहे थे।.....हम जानते थे कि एक शक्तिशाली सरकार से शंभ्र ही मुकाबला होनेवाला है, और इससे पहले की सरकार हमें अलग कर दे (अर्थात् जेल में बन्द कर दे) हम अधिक से अधिक कार्य कर डालना चाहते थे।.....इन सब बातों से बड़ कर हमारे अन्दर आजादी का, और आजादी के गर्व का भाव आ गया था। वह पुराना भाव कि हम ठगे हुये हैं, और हमें अन्यायों नहीं मिल सकतें। विलकुल मिट गया था।”

कलकत्ता के उस विशेष अधिवेशन तथा अन्तर्द्वेषों का सफलता ने कांग्रेस का राजनीति में गांधी-युग का आरम्भ किया। अन्तर्द्वेषों के तीन मान के सफल आन्दोलन के पश्चात्, दिसम्बर १९२० का नागपुर कांग्रेस में, कलकत्ता कांग्रेस में उत्तरी उपयोगिता पर संदेह करने वाले देशबन्धु दास आदि अनेक नेताओं ने, उसके कार्यक्रम को मान लिया। नया चुनाव हो जाने के बाद मतभेद भी दूर हो गया और नागपुर कांग्रेस के इस अधिवेशन में फिर बहुत से पुराने कांग्रेसी नेता अन्तर्द्वेषों के मंच पर आम्र मिल गये। इस आन्दोलन को कमयाजी ने बहुतरे अविश्वस और संदेह रखने वालों को इसका प्रयत्न कर दिया। फिर भी कलकत्ते के कुछ पुराने नेता इस नये आन्दोलन के फलस्वरूप कांग्रेस में गँछे ही रहे; जिनमें एक नरहर और लोकप्रिय सुसज्जित नेता थे श्री जिन्ना। नेहरूजी के शब्दों में इसका कारण “कांग्रेस का पूर्णतः जनता का संगठन बन जाना था, जो उन्हें ज़ाई नापसंद था” अब तब जनता के ये नेता जनता के समर्थ से दूर ही थे। अब यह नर्गल वातावरण उन्हें कुछ अजीब तथा अग्नी राजनीति के प्रतिफल का लग रहा था। “कांग्रेस के इस नये रंग-रूप से उनके स्वभाव का नेत्र न लाता था। उन लहरधारी मन्त्र में, जो हिन्दुस्तानी में व्याप्तान देने की नाँव

करता था, वं अपने को विल्कुल बेमेल पाते थे । बाहर लोगों में जो जोश था वह उन्हें पागलों की उछल कूद सा मालूम होता था । उनमें और भारतीय जनता में उनता ही फर्क था जितना कि सेवाइल वांड स्ट्रीट में और भारत के भोपड़े वाले गांवों में है ।” इनके अतिरिक्त माडरेट लोग अब पूर्णतः कांग्रेस से अलग हो गये थे तथा इस दल के अधिकतर नेताओं ने राजनीति के रंगस्थल को प्रायः त्याग ही दिया था ।

परन्तु यह सब कुछ छायाएँ असहयोग के तीव्र तेज को रोक न सकी । आन्दोलन बढ़ता ही गया और वह पूर्ण रूप से देश व्यापी हो गया । नेहरू जी आदि अनेक वर्कियों ने असहयोग के कार्यक्रम के अनुसार अदालत से नाता तोड़ लिया, और अपनी सम्पूर्ण शक्ति कांग्रेस महासभा के सत्कार्य और सेवा में लगा दिया । पं० जवाहरलाल उन दिनों युक्त प्रान्तीय कांग्रेस के महामंत्री थे । प्रान्त के सारे सगठन का भार उन्हीं के कंधों पर था । नयी क्रमेष्टियों का स्थापित करना, प्रान्तीय कार्यालय का सारा कार्य निपटाना, और प्रान्त में घूम घूम कर प्रचार करना उनका दैनिक कार्यक्रम था । उनका अविश्रान्त परिश्रम, उनके हृदय का अगाध प्रेम, उनकी तेजी, फुर्ती और गम्भीरता देखकर सहकारियों का हृदय वल्लियों उछल जाता था, उनकी उपस्थिति उनमें उत्साह फूक देती थी । खादी प्रचार, मद्य-निषेध, पंचायतों की स्थापना, अहिंसात्मक अवज्ञा की तैयारी और किसानों द्वारा कर न देने की व्यवस्था, सभी ओर वे पर्याप्त ध्यान देते थे, और जनता का अभूतपूर्व सहयोग पाकर के सफलता की सीढियाँ लोंघते अपने लक्ष्य की ओर चले जा रहे थे । सारे देश में एक बवंडर सा आया था । आधुनिक शासन सत्ता के प्रति लोगों के हृदय में अविश्वास और घृणा के भाव भर गये थे और भारत का बच्चा-बच्चा अपने जीवन की बलि देने के लिए प्रस्तुत था । एक सिरे से दूसरे सिरे तक भारतीय जनता माता को दासत्व-शृंखला से मुक्त करने के लिए पागल हो रही थी । ज्यों-ज्यों सत्याग्रहियों का नैतिक तेज बढ़ता गया त्यों-त्यों सरकार का तेज घटता गया । नौकरशाही के बल पर चलने वाली सरकार

को ऐसा लग रहा था कि हिन्दुस्तान में उसकी परिचित पुरानी हुकूमत की दुनियाँ दिन-प्रतिदिन ढही जा रही है। हिन्दुस्तानियों में दूर-दूर तक एक नया आक्रामक भाव-आत्मावलम्बन और निर्भयता का भाव—फैल रहा था, और भारत में ब्रिटिश हुकूमत का बहुत बड़ा नहरा—‘रौब’—स्पष्टतः दूर होता जा रहा था। थोड़े बहुत दमन में आन्दोलन छूटते बढ़ता ही जा रहा था। सरकार बहुत दिनों तक बड़े-बड़े नेताओं पर हाँथ डालते दिव्यन्ती रही वह नहीं जानती थी कि उनका अंतिम परिणाम क्या होगा। दिसम्बर १९२१ में लार्ड रीडिंग ने तो यहाँ तक कहा था इन हिन्दुस्तान की माता हासल ने “हंगन और परेशान हो रहे हैं।” इन अंग्रेजी शासकों के इशारे पर दुन हिलाने वाला पुराना पालनू भारत, अहिंसात्मक विद्रोहों के रूप में अब उन्हें अस्मरिचित सा, भय उत्पन्न करने वाला लग रहा था। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में भारत-मंत्री श्री नाटिंग्यू पर असहयोग आन्दोलन बढ़ने के कारण प्रबल आक्षेप हो रहे थे। पर दुनिया जानती है इनमें केचारे नाटिंग्यू का कोई दोष न था।

उन्हीं दिनों १९२१ की गर्मियों में, युक्तप्रान्तीय सरकार की ओर से जिला अदमरों के नाम, आन्दोलन दबाने के हेतु, एक विदायर्ता गुन गन्ती निष्ठी भेजी गयी: पर आन्दोलन जगज्ज बढ़ता रहा और वह एक तीव्र प्रकाश की तरह कुशामन की जालिना पर ऐसा छा गया कि निरंकुश ब्रिटिश शासकों की आँखें चञ्चल हो गयी, और वे क्लिप्तव्यविमूढ़ की तरह चारों ओर हाँथ-पाँव फैलने लगे। हाकिमों के हृदयाक्रांश पर चिन्ता के घने बादल नड़न गहे थे: कि भी चूँकि अंग्रेज के नावन शान्तिमय थे, उन्हें उनका मुचाबला हिंसात्मक रूप से करने और जोर के साथ छ दबाने का मौका नहीं मिलता था।

असहयोग के इस आन्दोलन ने नेहन को कार्य करने की एक नयी शक्ति प्रदान की। स्वयं उन्हीं के शब्दों में “असहयोग आन्दोलन ने मुझे वह चीज दी जो मैं चाहता था, वह था औनी आजादी का ध्येय तथा निश्चित दज के लोगों के शोषण का अंत, और ऐसे नावन जो मेरे नैतिक

भावों के अनुकूल थे तथा जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ज्ञान कराया था। इससे मुझे व्यक्तिगत संतोष इतना अधिक मिला कि आन्दोलन के नाकामयाबी के अंदेशों को भी मैं अधिक महत्व न देता था; क्योंकि ऐसी असफलता तो थोड़े समय के ही लिए हो सकती है।”

नेहरू जी स्वयं जी-जान से असहयोग में लगे हुए थे। उन्होंने अपने सब निजी कार्य और सम्बंध, पुराने मित्रों और पुस्तकों का पठन पाठन भी कुछ समय तक के लिए स्थगित कर दिया था। देश और ससार की आवश्यक घटनाओं को जानने के लिए वे केवल समाचार पत्रापत्र लिखा करते थे। व्यक्ति एक पारिवारिक जीव है। उसमें कौटुम्बिक मोह स्वभाव से ही कुछ अधिक है, पर नेहरू उस आन्दोलन की तीव्रता में परिवार, पत्नी और प्यारी पुत्री को भी भूल से गये थे। गांधी के नेतृत्व ने उन्हें अपना न रहने दिया था, अब वे एकमात्र राष्ट्रीय सम्पत्ति थे। वह एक व्यक्ति, एक इकाई ही नहीं रह गये थे, बल्कि भारत के लिए मूर्तिमान आदर्श स्वरूप थे। भारत की भावी धुधली आशाओं का मूर्त रूप उनमें केन्द्रित हो चुका था। कार्यालय, कमेटी और भीड़ का व्यस्त जीवन उनका घर बन गया था। हिमालय के उच्चतम शिखर पर खड़े किसी कर्मयोगी की आवाज की भाँति, गांधी का “गँवो मे जाओ” स्वर गूँज उठा था, इस स्वर की मद्र ताल पर पैदल ही गाँव की सौधी मिट्टी कोसों पार कर नेहरू पहुँचते और सरल ग्रामीणों के श्रद्धानत दिल में वे अपनी स्वरशक्ति से शोले दहका देते।

सरकार अपनी सत्ता की नींव को हिलाते देखकर आँख मूँदे बैठी कैसे रह सकती थी ? असहयोग-आन्दोलन और दमन-चक्र दोनों ही तेजी के साथ चले, लगता जैसे दोनों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ सी लगी है। सन् १९२१ के वर्ष भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियाँ और सजाये होती रही मगर अब तक सामूहिक गिरफ्तारियाँ नहीं हुई थी। अली बंधुओं को हिन्दुस्तानी फौज में असन्तोष पैदा करने के जुर्म में लम्बी-लम्बी सजाये दी गयी थी। जिन शब्दों के लिए उन्हें सजा मिली

थी उन्हीं को अनेक मंचों से शत-शत नेताओं के कल-कठां ने फिर से दुहराया । नेहरू पर भी अंततः ग्रीष्म में राजद्रोहात्मक भाषणों के लिए मुकदमा चलाने की धमकी दी गयी । सरकार धमकियों से उस सिंह को दवाना चाहती थी जिसकी दहाड़ से उनका दिल कॉप रहा था । परन्तु उस समय सरकार ने न जाने क्या सोचकर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न की ।

उन्हां दिनों 'प्रिन्स आफ वेल्स' हिन्दुस्तान आनेवाले थे । कांग्रेस ने उनके आगमन के संबंध में की जानेवाली सभी कार्रवाइयों के वहिष्कार की अपील जनता से की । सरकार सात समुद्रपार से आनेवाले अपने युवराज का धूमधाम से स्वागत करने के लिए अत्यन्त उत्सुक थी । उसने साम, दाम, दंड, भेद, सभी नीतियों से कार्य लेकर आन्दोलन और वहिष्कार की इस उग्रता को दवाना चाहा । फलस्वरूप नवम्बर के अंत तक बंगाल में, कांग्रेस स्वयंसेवक-दल गैरकानूनी करार कर दिया गया, और इसके बाद युक्तप्रान्त में भी ऐसी ही घोषणा की गयी । देशबंधु चित्तरजन दास ने उस समय समस्त बंगाल को एक मर्मस्पर्शा सदेश दिया, "मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और मेरा सारा शरीर लोहे के बजरी जर्जरों से जकड़ा हुआ है । यह है दासत्व की वेदना और यंत्रणा । सारा हिन्दुस्तान एक बड़ा कारावास हो गया है । कांग्रेस का कार्य हर हालत में जारी रहना चाहिए । इसकी परवाह नहीं कि मैं पकड़ा जाऊँ । इसकी भी चिन्ता नहीं कि मैं मर जाऊँ या जिन्दा रहूँ ।" इसके पश्चात् बंगाल में, विशेषतः कलकत्ते में आन्दोलन ने ऐसा जोर पकड़ा कि गवर्नमेन्ट हाउस की दीवारों के भीतर बैठे अंग्रेज अफसर घबड़ा गये । देश के अन्य भागों की तरह युक्तप्रान्त में भी आन्दोलन की गति बहुत तीव्र थी । नेहरू स्वयं एक पटु नेता की तरह सर्वत्र दौड़-दौड़ कर संगठन कार्य में व्यस्त रहते थे । प्रान्तीय कांग्रेस ने घोषणा की कि स्वयं सेवक-दल का संगठन कायम रहेगा । दैनिक पत्रों में स्वयंसेवकों की नामावलि भी प्रकाशित हो गयी जिसकी सूची में सर्व प्रथम नाम मोतीलाल

नेहरू का था । वह यद्यपि स्वयं स्वयंसेवक नहीं थे, पर केवल सरकारों आजा की अवज्ञा करने के लिए उन्होंने स्वयंसेवकों में अपना नाम प्रकाशित कराया था । दिसम्बर के प्रारम्भ में युवराज के आगमन के कुछ दिन पूर्व सामूहिक गिरफ्तारियाँ आरम्भ हो गयीं ।

परिस्थितियों को देखते हुए सभी व्यक्तियों का यह अनुमान हो गया था कि जीत और हार का पासा पड़ गया है; कांग्रेस और सरकार ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति ढोंच पर लगा दी है । प्रत्यक्ष संघर्ष आरम्भ होने वाला है । सदस्य गण भी इसके लिये पूर्णरूपेण तैयार बैठे थे ।

नेहरू जी के लिए जेल एक अपरिचित स्थान था । परन्तु सरकार के लिए उनके कार्य असह्य हो गये थे, और उसमें उसे शासन सत्ता के प्रति विद्रोह की गन्ध आने लगी थी । ६ दिसम्बर १९२१ के दिन प्रयाग में गिरफ्तारियाँ आरम्भ हो गयीं: चुन-चुन कर प्रान्त के सभी नेता पकड़े जाने लगे ।

उन दिनों प्रान्तीय कांग्रेस का दफ्तर हीवेट रोड पर और अखिल भारतीय कांग्रेस का दफ्तर आनन्द-भवन में था । पिता और पुत्र, क्रमशः अ० भारतीय और प्रान्तीय कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे । अपनी प्रथम जेलयात्रा के दिन नेहरू जी उक्त कार्यालय में कुछ आवश्यक कार्य कर रहे थे; इतने में ही एक क्लर्क ने उन्हें आकर सूचना दी कि पुलिस कार्यालय की तलाशी लेने आयी है । नेहरू जी को तत्काल अपनी गिरफ्तारी का भी अंदेशा हो गया था, अतः वे क्लर्क को आवश्यक आज्ञा दे कर, और अपनी अनुपस्थिति में किये जाने वाले कार्यों को समझा कर, जेल-यात्रा के पूर्व कुछ आवश्यक पत्र लिखने बैठ गये । इसके पश्चात् वे शान को घर की ओर लौटे, उन्होंने वहाँ भी पुलिस को सर्वत्र फैले देखा । विशाल आनन्द-भवन के लम्बे चौड़े भागों की तलाशी लेने में पुलिस व्यस्त थी । पुलिस, उनकी तथा पं० मोतीलाल जी की गिरफ्तारी करने आयी थी । नेहरू जी को देखते ही पुलिस-अधिकारियों ने उन्हें ललनऊ में युवराज का बहिष्कार करने के लिए पर्वे बॉटने, तथा राजद्रोहात्मक भाषण

देने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया । नेहरू की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही आनन्द-भवन की ओर नागरिकों का तौता लग गया । अपने प्रिय नेताओं की जय बोल कर जनता प्रमत्त हो रही थी । नेहरू जी ने जनता को शान्त करते हुए उनसे पुनः युवराज सम्बन्धी स्वागत के बहिष्कार करने की अपील की । उत्तेजित जनता को उन्होंने अपनी प्रथम जेल-यात्रा के समय संदेश दिया—“हम खुश हैं की हम देश के लिए जेल जा रहे हैं । मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हमारे कार्य को लाभ होगा और हमारी विजय निकट आयेगी । याद रखिये १२ तारीख को हड़ताल है; प्रत्येक व्यक्ति का यह कार्य है कि वह स्वयंसेवक बने, तथा सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग शान्त रहें । आपके हाथ में इलाहाबाद की इज्जत है ।” इसके पश्चात् पं० जवाहरलाल जी लखनऊ भेज दिये गये और पं० मोतीलाल आदि नेता प्रयाग जेल में ही रखे गये । दोनों व्यक्तियों को ६-६ महीने की सजा हो गयी ।

इस बहिष्कार के फल स्वरूप, युवराज जब भारत आये तो इने गिने सरकार पिछुओं को छोड़ कर, कोई भी स्वाभिमानी भारतवासी उनके स्वागत में शामिल नहीं हुआ । जहाँ जहाँ युवराज जाते वही भीषण हड़ताल होती थी और शोक दिवस मनाया जाता था । सरकार भी खाली न बैठी थी । उसने कांग्रेस के संगठन को मटियामेट कर देने को ठान ली थी । फलस्वरूप सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता पकड़ लिये गये । युक्तप्रातीय कांग्रेस-कमेटी के सभी लोग, (५५ व्यक्ति) जब वे कमेटी की एक मीटिंग कर रहे थे, एक साथ गिरफ्तार कर लिए गये; फलस्वरूप असहयोग आंदोलन और बढ़ा । यद्यपि सभी विश्वस्त कार्यकर्ता जेल में थे, परन्तु फिर भी आंदोलन में अनिश्चितता और असहायता का भाव नहीं आया । वातावरण में बिजली मरी हुई थी और चारों ओर गडगड़ाहट हो रही थी । ऐसा जान पड़ता था कि अन्दर ही अन्दर क्रांति की तैयारी हो रही है । यद्यपि दिसम्बर १९२१ और जनवरी १९२२ तक, करीब ३० हजार व्यक्ति असहयोग से सम्बद्ध हो जेल जा चुके थे, परन्तु फिर भी

आंदोलन के जननायक और प्राण महात्मा गांधी अभी बाहर ही थे, और अपने ओजस्वी सदेश से लोगों में स्फूर्ति प्रदान कर रहे थे। सरकार शायद भयकर कुपरिणाम की आशंका से अब तक उनपर हाँथ नहीं डाल पायी थी।

आंदोलन वेग पर था कि एकाएक चौरीचौरा के हिंसक कांड के फलस्वरूप लुब्ध गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया, और सत्याग्रह का कार्यक्रम स्थगित हो गया। चौरीचौरा नामक गाँव के पास उत्तेजित भीड़ ने, बदले की भावना से, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। फलस्वरूप आधे दर्जन पुलिसवाले उसमें जल मरे थे। गांधी जी के इस कार्य से, और प्रबल आंदोलन को इतनी सी बात के लिए इस प्रकार से रोके जाने पर सभी नेता, जो जेल में थे, काफी नाराज हुए। कालान्तर पश्चात् उन्हें गांधी जी की वह दूर-दर्शिता, जो उन्होंने आंदोलन रोक कर उन समय दिखलायी थी, का पूर्ण ज्ञान हुआ और उन्होंने उस समय ईश्वर को उन्हें एक ऐसा योग्य नेता प्रदान करने पर अवश्य धन्यवाद दिया होगा।

यद्यपि अधिकतर लोग यही समझते हैं, परन्तु वास्तव में फरवरी १९२२ में सत्याग्रह का स्थगित किया जाना सिर्फ चौरीचौरा कांड का वजह से नहीं हुआ था। वह तो असल में एक निमित्तमात्र हो गया था। वास्तविक कारण कुछ और ही था। सभी उच्च नेताओं के जेल में चढ़ होने के फलस्वरूप, आंदोलन में संगठन और अनुशासन का लोप हो गया था। ऐसे समय कोई अवाञ्छित तथा गैरजिम्मेदार आदमी, आंदोलन की बागडोर को थोड़े ही प्रयत्न से जिस ओर चाहता मोड़ सकता था, और इससे अनर्थ का सम्भावना थी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस-कमेटियों में उस समय उचित नेताओं की अनुपस्थिति से, अनेक ब्रिटिश सरकार के पिटू और आतंकवादी (ध्वंसात्मक कार्य में विश्वास करने वाले व्यक्ति) बुल आये थे, तथा अपने स्वार्थसाधन के लिए स्थानीय कांग्रेस और खिलाफत कमेटियों चलाने लगे थे। जनता को बरगलाने वाले उन

देश-द्रोहियों को रोकने और वहाँ से हटाने का, जिनके द्वारा आंदोलन और जन-शक्ति का भयंकर दुरुपयोग न हो, गांधी जी के पास इससे अच्छा और कोई साधन न था कि वे कुछ समय तक के लिए, जब तक पुराने नेता जेल से छूट कर नहीं आ जाते, इन आन्दोलनों को स्थगित कर दे। इसमें कोई शक नहीं कि यदि आंदोलन जारी रहता, और जनता को पथभ्रष्ट करने तथा बरगलाने वाले ये नेता उसका नेतृत्व करते, तो कई जगह भयंकर हत्याकांड हो जाते, जिन्हें सरकार को हिसात्मक ढंग से, नृशंसा-पूर्वक कुचलने का अवसर मिलता। भय का साम्राज्य फैल जाता और जनता बुरी तरह पस्तहिम्मत हो जाती। अतः १९२२ में सत्याग्रह को स्थगित करने का काम अनुकूल ही था, यद्यपि उसके स्थगित करने के और भी अच्छे ढंग को अपनाया जा सकता था।

जेल में नेहरू आदि सभी नेताओं के साथ राजनैतिक कैदियों की भौति व्यवहार किया जाता था। खाने पीने के लिये रुचि के अनुसार वस्तुएं मिलती थी। किताबें और अखबारों को पढ़ने की सुविधा थी। मित्र गोष्ठी और चर्चा चलाना नित्य का कार्य था। जेल में भी रोज दर्शकों के अपार जनसमूह का ताता लगा रहता। एक दिन जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट से खटपट हो जाने के फलस्वरूप, इन सभी व्यक्तियों को अपना पाखाना स्वयं ही उठाना पड़ा था, यद्यपि बाद में अपने उस कार्य के लिये जेलर ने उनसे क्षमा-याचना की।

पिता-पुत्र अभी तीन महीने भी साथ जेल में न रहे होंगे की नेहरू के जुर्म पर पुनः विचार करने के लिये अदालत बैठी, तथा जवाहरलाल रिहा कर दिये गये। नेहरू जी को इससे आश्चर्य हुआ, क्योंकि न तो स्वयं उन्होंने ही, न उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने ही मामले पर पुनः विचार के लिये अदालत को प्रार्थना-पत्र दिया था। पिता को अकेले जेल में छोड़ कर बाहर आने में नेहरू जी को काफी कष्ट हुआ।

जेल से छूटते ही नेहरू जी महात्मा गांधी से मिलने अहमदाबाद पहुँचे, परन्तु वे पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, अतः वे उनसे साबरमती

जेल में जाकर मिले। मुकदमे के समय नेहरू जी अदालत में मौजूद थे। अदालत में गांधी जी ने तो बयान दिया था, वह लौहशलाकियों की भोंति, वहाँ उपस्थित हरेक व्यक्ति के हृदय पर अंकित हो गया था। नेहरू जी के ही शब्दों में, “हम लोग वहाँ से (अदालत से) जब लौटे तब हमारा हृदय तरंगित हो रहा था; और उनके (गांधी के) ज्वलंत वाक्यों, चमत्कारी भावों और विचारों की हमारे मन पर गहरी छाप पड़ी हुई थी।” अहमदाबाद से लौटने के पश्चात् नेहरू को मित्रों से रहित प्रयाग बहुत ही सनसान और दुःखःप्रद लगा। उनके सभी दिल्ली दोस्त जेल के सीखचों के अन्दर बन्द थे। अतः उन्होंने अपना ध्यान कांग्रेस के संगठन कार्य में लगाया, तथा वे गांधीजी के अधूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये दूनी शक्ति से कार्यक्षेत्र में जुट गये। उन्होंने प्रयाग में विदेशी चखों के बहिष्कार सम्बन्धी आन्दोलन में टिलचस्पी ली। सत्याग्रह स्थगित कर दिये जाने के पश्चात् भी आन्दोलन का यह कार्य चालू था। नेहरू जी ने प्रयाग के समस्त व्यापारियों को एक संघ के रूप में संगठित कर, उनसे विदेशी वस्त्र खरीदकर न बेचने की प्रतिज्ञा करायी। उक्त संध ने अपने इन वादे को पूर्ण न किया। फलस्वरूप अपना वादा तोड़ने वाले इन व्यापारियों की दुकानों के आगे पिकेटिंग तथा प्रदर्शन आरम्भ हुआ।

नेहरू के इन कार्यों के फलस्वरूप सरकार ने उन्हें स्वतंत्र रहने देना शासन के लिये हितकर न समझा, अतः दूसरी बार फिर वे गिरफ्तार हो गये। नेहरू जी पर धमका देने, और बलपूर्वक रुपया ऐठने आदि के झूठे दोष लगाये गये, फलस्वरूप १७ मई को एक वर्ष नौ महीने का कठिन कारावास उन्हें दिया गया। ५० नेहरू की ओर से किसी भी प्रकार की सफाई पेश नहीं की गयी, केवल अदालत के समक्ष उन्होंने अपना लिखित बयान पेश किया। पंडित जी ने अपने वक्तव्य में सरकार की पोल खोलते हुये, न्याय का ढोंग रचने वाली अदालतों द्वारा किये जानेवाली सत्ता के दुरुपयोग का चित्र खींचा था। “जेल हमारे लिये निःसन्देह एक आश्रय-स्थल और पवित्र तीर्थ स्थान बन गया है।”... .. “स्वराज्य की लड़ाई में

भारत की सेवा करना हमारे लिये अत्यन्त गौरव का विषय है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ऐसे नेता के आधीन होकर, मातृभूमि की सेवा दूने सौभाग्य का विषय है। ओह ! प्यारे देश के लिये कष्ट भेलना, इससे और कौन बड़ा सौभाग्य एक भारतवासी को प्राप्त हो सकता है। यह कितनी महान बात होगी कि इस उच्च ध्येय की पूर्ति के लिये मेरे जवन का बलिदान हो जाये, अथवा वह विराट् स्वप्न स्वयं ही पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो जाये।”

सजा हो जाने पर करीब ६ हफ्ते बाद, नेहरू जी दूसरी बार जेल पहुँचे और वहाँ अपने पिता से मिले। उस समय जवाहरलाल जी के दो चचेरे भाई भी वही थे। इन चारों व्यक्तियों को जेल में एक अलग सायबान दिया गया। उन्हें एक बैरक से दूसरे बैरक में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। बाहर के सम्बन्धियों को उनसे आकर मिलने की इजाजत थी, तथा उचित मात्रा में समाचार पत्र और पुस्तकें भी मिलती थी। जवाहरलाल जी नित्य सुबह अपने सायबान को धोकर साफ करते, तथा अपने और पिताजी के वस्त्र साफ करते थे। मित्रों से वार्तालाप और चर्चा क़ातने में समय अच्छी तरह व्यतीत हो जाता था। कुछ दिनों तक उन्होंने वहाँ आये अपढ़ स्वयंसेवकों को शिक्षा देने का भार भी अपने उपर ले लिया था, परन्तु इस प्रकार की स्वतंत्रता में बन्धन लगा दिये जाने के फलस्वरूप बाद में यह कार्यक्रम ठप्प हो गया।

नेहरू जी जिस बैरक में रखे गये उसमें ५० कैदी और थे। सभी व्यक्ति नेहरू जी के परिचित थे; परन्तु फिर भी वह कौलाहलपूर्ण वातावरण उनके स्वभाव के विपरीत था, और वे एकांत चाहते थे। फलस्वरूप उनका एकांतप्रिय मन उन्हें बैरक के बाहर खुले अहाते में खींच लाता। अहाते में लेटे-लेटे वे अनन्त आकाश में उड़ते कुछ अकेले पर स्वतंत्र बादलों को देखा करते। वर्षा की मृदुल झड़ी उनके सतत हृदय को राहत देती। कुछ दिनों पश्चात् उनपर अधिक सख्ती की जाने लगी। उन्हें ६ अन्य व्यक्तियों के साथ—उरुडन जी, महादेव देसाई, बालकृष्ण

शर्मा, जार्ज जोसेफ और देवदास गांधी आदि के साथ—एक अलग छोटे बैरक में रखा गया। यह स्थान छोटा था परन्तु नेहरू जी को मनोनुकूल एकांत था। अब उन लोगों को समाचारपत्र भी देना बंद कर दिया गया था।

अखबार न मिलने के कारण नेहरू जी को भारत और संसार के अन्य राष्ट्रों में घटित होने वाले समाचारों का कुछ भी पता न चलता था, पर तब भी बाहर की महत्वपूर्ण खबरे निजी पत्रों और मुलाकातों द्वारा जेल में मिल ही जाती थी। उनके द्वारा नेहरू जी को यह ज्ञात हुआ कि बाहर जनता में कांग्रेस का आंदोलन शिथिल पड़ गया है। गांधी के प्रभावशाली खुले स्वर का, उनके जेल में होने कारण—“वह चमत्कारिक समय जैसे गुजर गया था, और कामयाबी धुंधले भविष्य में दूर हटती हुई मालूम पड़ने लगी।” नेहरू जी ने यह भी सुना कि बाहर कांग्रेस में दो दल हो गये हैं—परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। पहला दल, जिसके नेता स्वयं मोतीलाल जी तथा देशबन्धुदास थे, असहयोग और कांग्रेस-कार्यक्रम में परिवर्तन करके काउंसिल में जाने, और उनपर कब्जा करने के पक्ष में था, जब की दूसरा दल उसका पूर्ण विरोधी था और पुराने कार्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहता था; जिसके नेता श्री राजगोपालाचार्य थे। उस समय गांधी जी जेल में थे, अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर उनसे परामर्श लेने का कोई सवाल ही नहीं था। फलस्वरूप उस समय के अधिकतर नेता किर्तव्यविमूढ़ हो गये थे। नेहरू जी के शब्दों में “आंदोलन के जिन सुन्दर आदर्शों ने हमें, ज्वार की लहरों की चोटी पर बैठे हुए की तरह आगे बढ़ाया था, वे छोटे छोटे भागड़ों और सत्ता प्राप्त करने की साजिशों के फलस्वरूप दूर उछलते जाने लगे।” अतः मन ही मन बाहर की इन कार्यवाहियों से असंतुष्ट जवाहर, जेल में होने के कारण, उस विषय में हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे।

लखनऊ-जेल का सुपरिन्टेण्डेंट एक अंग्रेज कर्नल था, जो कभी-कभी जवाहरलाल की बैरक से गुजरता, और उन्हें हमेशा पढ़ने में दत्तचित्त

देखता था। उनका इस प्रकार हरदम पढ़ना शायद उसे ज़ेचा नहीं; अतः एक दिन उसने उनसे इतना पढ़ने की 'बुरी लत' के बारे में एक बार प्रश्न भी किया। उसने स्वयं अपना पढ़ना १२ वर्ष की ही अवस्था में छोड़ दिया था; और शायद इससे उसे इतना 'लाभ' हुआ कि उसके मन में इन लोगों की तरह 'अशांति उत्पन्न करने वाले विचार' कभी आये ही नहीं। शायद इसी 'गुण' से प्रसन्न हो ब्रिटिश सरकार ने इनाम स्वरूप उसे युक्त-प्रातीय जेलों का इन्स्पेक्टर जेनरल बना दिया था।

जेल के अधिकारियों की यह बराबर कोशिश रहती कि नेहरू आदि राजनीतिक कैदियों को अन्य सामान्य गैरराजनीतिक कैदियों से अलग रखा जाये, जैसे भले आदमियों को बुरों की सोहबत से दूर रखने का प्रयत्न किया जाता है। पर तो भी 'ये बुरे आदमी' उन अभागों मामूली कैदियों से कभी कभी मिल लिया करते, और उनके सुख दुःख की कथा सुनते और समझते। उन दिनों जेलों में होने वाली मारपीट, जोरों की रिश्तखोरी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से नेहरू जी का हृदय दुःखित होता था। उन दिनों जेल के नियम तोड़ने के लिए कठोर दण्ड दिये जाते थे। एकबार एक छोटे लड़के को जेल का नियम उल्लंघन करने के अपराध के बेटों से मारने की सजा दी गयी थी। उस लड़के की आयु १५-१६ वर्ष की रही होगी। वह अपने को 'आजाद' कहता था। दण्ड देते समय उसे नंगा करके टिकटी से बाँध दिया गया था। जैसे-जैसे उसे खाल उधेड़ने वाली कड़ी बेल की मार पड़ती, वह 'महात्मा गांधी की जय' चिल्ला उठता था। हर बेल पर वह लड़का यही नारा लगाता; अन्त में कड़ी मार की चोट से वह बेहोश हो गया। आगे चल कर वही लड़का आतंकवादी क्रान्तिकारीदल का प्रसिद्ध नेता, श्री चन्द्र शेखर 'आजाद' के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उसके वीरतापूर्ण कार्यों से सम्पूर्ण ब्रिटिश शासन एक बार थर्रा उठा।

सन १९२३ की जनवरी में, जवाहरलाल नेहरू जेल से अन्य

राजनैतिक कैदियों के साथ छोड़ दिये गये । जेल के फाटक से बाहर निकलते ही उन्होंने पिंजड़े से स्वतंत्र पक्षी की भाँति एक बार स्वच्छ वायु में साँस ली और प्रकृति के सुखदायी दृष्यों को देखा । घर लौटने पर सब को सकुशल देख कर वे प्रसन्न हुए और कुछ दिनों के विश्राम के पश्चात् फिर राष्ट्रीय आंदोलन में लग गये ।



कांग्रेस में सैद्धान्तिक मतभेद

सरकार को क्रूर, दमनपूर्ण दृष्टि के पहली बार शिकार होकर, तथा कठिन कारागार से मुक्त होकर जब नेहरू जी बाहर आये, उस समय उनका हृदय आनन्दातिरेक में उछल रहा था, परन्तु यह सब भाव थोड़ी ही देर तक रहा क्योंकि कांग्रेस-राजनीति की दशा काफी निराशाजनक थी। “ऊँचे आदर्शों की जगह पड़यंत्र होने लगे थे, और कई गुट घुसित तरीकों में कांग्रेस-तंत्र पर अधिकार करने के प्रयत्न में लगे थे। अधिकार-लिप्सा की छाया नेताओं पर भी पड़ रही थी। उचित नेतृत्व की अनुपस्थिति में जनता भी स्वातंत्र्य-संग्राम से विरक्त हो गयी थी, तथा असहयोग आन्दोलन शिथिल हो गया था।”

स्वयं कांग्रेस में ही उस समय दो ढल हो गये थे; और दोनों ही अपनी नीति के अनुसार देश के राष्ट्रीय विचारधारा का संचालन करना चाहते थे। सरकार की सत्ता से संवर्प करने के स्थान पर वे परस्पर की कूटनीति में ही व्यस्त थे। श्री चितरंजन दास और पं० मोतीलाल नेहरू के अथक परिश्रम से स्वराजिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। यद्यपि दास वाचू के ही समापतित्व में गया-कांग्रेस हुई थी, फिर भी काउन्सिल प्रवेश के इच्छुक सदस्यों ने मुँह की लायी थी; परन्तु उससे स्वराजिस्ट चुप न हो गये और वे एक दूसरे के ही विरुद्ध राजनैतिक शतरंजी चाल खेलने में व्यस्त थे। देश के ये परिवर्तनवादी नेता आरम्भ से ही सिन-फोन आन्दोलन से प्रभावित थे। वे लोक समाजों में जाकर वैधानिक ढंग से, तथा अपनी अड़गे की नीति द्वारा शासन-सत्ता को अधिकार में करना चाहते थे; परन्तु उस समय गांधी जी के तर्कों ने उन्हें ऐसा

करने से रोक दिया था। उनके अनुसार असहयोग आन्दोलन को तथा उसके कार्यक्रम के रचनात्मक महत्व को जनता अच्छी प्रकार समझ सकती है। काउंसिल के चुनाव में आस्था, और वहाँ जाकर फिर सरकार से संघर्ष के विरोधात्मक तरीके को अपढ़ जनता पूर्णरूप से नहीं समझ सकती, और वह गुमराह हो सकती है, फलस्वरूप उससे आन्दोलन की शक्ति काफी क्षीण हो जायेगी। इसके अतिरिक्त काउंसिल की निःसार और आडम्बरपूर्ण सभाओं तथा वहाँ के वक्ताओं से देश को कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे वहाँ जाकर सत्ता और वातावरण की मोहकता से वशीभूत नेता पय-भ्रष्ट हो सकते हैं। नेहरू जी स्वयं काउंसिल प्रवेश के निष्कुल खिलाफ थे, क्योंकि मेम्बरों को काउन्सिल-भवन में कदम-कदम पर समझौता करने के लिए मुकना पड़ता और फलस्वरूप सिद्धान्त और लक्ष्य का बलिदान करना पड़ता। वे स्वयं अपरिवर्तनवादियों के रचनात्मक कार्यक्रम को अधिक पसन्द करते थे, जिसका इस समय प्रधान उद्देश्य जनता से सम्पर्क स्थापित करना तथा सामाजिक सुधार था।

गांधी जी के कारागार में होने के फलस्वरूप ये परिवर्तनवादी नेता उनकी चेतावनी और पूर्व संकेतों को भूल गये थे। उन्होंने अपना अलग दल कायम कर लिया तथा काउंसिल की सदस्यता के लिए खड़े भी हुए। कांग्रेस के ये दोनों दल एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते, और उनके अधिवेशनों का प्रमुख विषय प्रायः वादविवाद और एक दूसरे के प्रति आक्षेप ही हुआ करता। पं० नेहरू ने स्वयं ही सन् १९२३ में युक्तप्रान्तीय कांग्रेस को तत्कालीन परिस्थिति की बड़ी सुन्दर मीमांसा की है। “हमारी शक्ति कुछ ही दिन पहले के साथियों से, जो कि अब विरोधी दल में थे, लड़ने-भिड़ने और शतरंजी चाल चलने में लग गयी। . . . इस प्रकार धीरे-धीरे अहिंसात्मक असहयोग के मूल गुणों का पतन होने लगा, और बहुत से लोगों की दृष्टि में वह केवल मिना सत का छिलका रह गया।”

पं० जवाहरलाल जी दोनों दलों के बीच बढ़ती हुई इस खाई को

देखकर क्रिकर्तव्यविमूढ़ हो गये। उनके समक्ष दो ही मार्ग थे। या तो वे अन्य नेताओं की भोंति त्वयं भी ओख मूँद कर किसी एक दल में सम्मिलित हो जाते, अथवा दोनों दलों के बीच शान्ति और समझौते के बीजारोपण का प्रयत्न करते। अन्त में उन्हें दूसरा पथ हाँ श्रेयस्कर लगा और उसके अनुसार कार्य करने में वे सलग्न भी हो गये; परन्तु इस कार्य में उन्हें कोई विशेष सफलता न मिली।

उन्हीं दिनों कांग्रेस की नयी नीति के अनुसार, देश के विभिन्न भागों की म्यूनिसिपैलिटियाँ में समाज-सेवा के उद्देश्य से, कांग्रेस ने अपने सदस्य भेजे। त्वयं प्रयाग-बोर्ड के चेयरमैन नेहरू जी चुने गये। कर्म-योगी नेहरू कार्य करने के इस नये वातावरण और विस्तृत क्षेत्र को पाकर काफी प्रसन्न हुए, और उन्होंने बोर्ड की उन्नति के लिए काफी परिश्रम भी किया। इसके अतिरिक्त अब वे प्रान्तीय कांग्रेस-मन्त्रों के अलावा, अखिल भारतीय कांग्रेस के भी मन्त्रों चुन लिए गये थे, अतः उन पर काफी कार्य-भार आ पड़ा था; फलस्वरूप इन विविध कार्यों की वजह से उन्हें १५-१५ घण्टे कार्य करना पड़ता था। इन कार्यों से भारग्रस्त होते हुए भी नेहरू जी ने दोनों दलों को निकट लाने के अपने प्रयत्न को छोड़ नहीं दिया।

कांग्रेस में विभेद की यह स्थिति इस समय और भी गम्भीर हो गयी थी। १९२२ की गया-कांग्रेस के अव्यक्त की हेसियत से परिवर्तन-दल के नेता देशबन्धु दास १९२३ में अखिल भारतीय कांग्रेस के भी अव्यक्त थे। यद्यपि उनका विरोधी दल अधिक प्रभावशाली था परन्तु कांग्रेस का बहुमत अपरिवर्तनवादी ही था। १९२३ की गर्मियों में, बम्बई की कांग्रेस कमेटी की बैठक में, दोनों दलों की यह आपसी खींच-तान अपनी सीमा पर पहुँच गया। इस बैठक में कांग्रेस-महासभा की समिति ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसके द्वारा उसने जनता से यह अपील की कि वे काउंसिलों का पूर्ण बहिष्कार करें; और इस नीति की अवहेलना करने वालों को वोट न दे। महासभा की नीति स्पष्ट थी और उसकी दृष्टि में काउन्सिलें विदेशी शासन-सत्ता की पुष्टि की साधन मात्र थी। त्वाराजिस्टों

पर यह प्रत्यक्ष आक्रमण था, फलस्वरूप देशबन्धु दास ने नाराज होकर अव्यक्त-गुद से स्तीफा दे दिया। कांग्रेस कैम्प में खलबली मच गयी किंतु नेहरू तथा मौलाना आजाद के प्रयत्न से अप्रैल तक दोनों ओर से काउन्सिल-आन्दोलन स्थगित कर देने की शर्त पर समझौता हो गया। कमेटी ने एक प्रस्ताव द्वारा, पंडित जी और मौलाना साहब को इस प्रशंसनीय कार्य के लिए बधाई भी दिया। परन्तु, प्रयाग के इस समझौते द्वारा दोनों दलों में स्थायी संधि न हो सकी। दोनों ही समय की गति और अवसर देख रहे थे।

इन्हीं दिनों कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने एक अलग गुट बनाया, जिसका उद्देश्य इन दोनों दलों में किसी प्रकार शान्ति-स्थापन कराना था। इन्हे लोग मध्यवर्ती (Centralists) कहते थे। इन लोगों की दृष्टि में दोनों ही दल के नेता और सदस्य श्रद्धेय और विचारवान थे; इसलिए व कांग्रेस का कार्यक्रम स्थगित रखते हुए ऐसा मार्ग ढूँढ़ रहे थे, जिससे दोनों दलों का निकट सम्पर्क बना रहे। पं० जवाहरलाल भी इसी तीसरे दल के अनुयायी थे।

ता० २५ से २८ मई तक बम्बई में अखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुआ। “यह दृष्टि में रखते हुए कि कांग्रेस के बहुत से प्रभावशाली सदस्यों का विचार सरकारी काउन्सिल-प्रवेश के पक्ष में है, और कांग्रेस का आधुनिक मतभेद उसके प्रभाव को कम कर रहा है, यह कमेटी कांग्रेसजनों ने संगठन और एकता आवश्यक समझती है, और इसलिए निश्चित करती है कि गया-प्रस्ताव के अनुसार काउन्सिल के बहिष्कार के लिए कोई विशेष आन्दोलन न किया जाये।”

इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर अग्रविर्तनवादियों ने कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। उनके विचार से यह प्रस्ताव उनके सिद्धान्तों के विपरीत था, और इसलिए इस प्रस्ताव की उपस्थिति में व कार्य करने में

असनर्थ थे । एक नया कार्यकारिणी की रचना हुई जिसके सभापति डा० अंसारी और मंत्री पं० जवाहरलाल बनाये गये ।

उपर्युक्त प्रस्ताव नवीकृत अवश्य हुआ; परंतु कुछ प्रांतों ने, जहाँ अपरिवर्तनवादियों का अधिक प्रभाव था, कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय की इस आज्ञा को मानने में इनकार कर दिया । वंदे ने इन कार्यों के विपरीत कार्य होने रहे । फलस्वरूप इस दशा पर पूर्ण रूप में विचार करने के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक २-१० जुलाई को नागपुर में हुई । इसने कार्यकारिणी के इन मध्यवर्ती (Centralists) सदस्यों ने अपने आदेशों का उल्लंघन करनेवाले प्रांतों की निंदा की, और उनके सदस्यों को दण्ड देने का एक प्रस्ताव उपस्थित किया, परंतु वह सर्वसम्मति में पास न हो सका । अतः पं० जवाहरलाल तथा उनकी कार्यकारिणी के अन्य सहयोगियों को त्यागपत्र देना पड़ा, तथा कार्यकारिणी के पुराने अपरिवर्तनवादी सदस्यों ने फिर से कार्यभार सम्हाला ।

सितम्बर के महाने में अखिल भारतीय कांग्रेस-महासभा का विशेष अधिवेशन दिल्ली में हुआ । उस अधिवेशन में स्वराजिस्टों को काउंसिल के लिए खड़े होने की आज्ञा मिल गयी और दोनों विरोधी दलों ने फिर से समझौता हो गया । दिल्ली-अधिवेशन में, कांग्रेस के शासन-विधान में सुधार के लिए एक कमेटी नियुक्त हुई, जिसके पं० जवाहरलाल जी सचिव नियुक्त हुए । आप सत्याग्रह और अकाली परिस्थिति के सम्बन्ध में नियुक्त समितियों के भी सदस्य थे ।

नेहरू और नामा-आन्दोलन

सन् १९२३ में पंजाब में सिक्खों ने एक सुधारवादी, अकाली आंदोलन की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य गुस्ठारों से बद-चलन महंतों को निकाल कर उनका प्रबंध योग्य हाथों में देना था। सरकार भारत-व्यापी, कांग्रेसी आंदोलन से पहले ही तत्त थी, जब उसने पंजाब के आकाश पर अशान्ति के एक नये प्रकार के काले बादल देखे तब उसने प्रबल भ्रंभावट की तरह उसे पूर्ण नष्ट कर देने का संकल्प किया। इन अहिंसात्मक अकाली सत्याग्रहियों का वर्तमानपूर्वक दमन किया जाने लगा।

उन्हीं दिनों की एक घटना ने, जिसका इस अकाली आंदोलन से कोई सम्बन्ध न था, नेहरू को सिक्खों के दुख-दर्द के समीप ला खड़ा किया। अंग्रेजों ने नामा-रियासत के जनप्रिय महाराज को गद्दी से उतार कर, रियासत की व्यवस्था के लिए, एक ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया था। सिक्खों ने इसका विरोध किया तथा जैतो नामक स्थान में अखंड पाठ आरम्भ करने का प्रयत्न करने लगे जिसे अंग्रेजों ने रोका, फलस्वरूप शासकों के इस कार्य के विरोध के लिए सिक्खों ने अपने प्रदर्शनकीरी जत्थे जैतो मेजना आरम्भ किया। पुलिस इस कार्य के लिए सत्याग्रहियों को नृशंसता के साथ मारती और गिरफ्तार करती। पत्रों द्वारा जवाहर लाल जी का इस आन्दोलन की ओर ध्यान गया, अतः वे इसका निरीक्षण करना चाहते थे।

कांग्रेस के दिल्ली-अधिवेशन के पश्चात् ही नेहरू जी को उनकी इच्छा के अनुरूप ही, अकालियों के एक दूसरे जत्थे का जो जैतो की ओर

जा रहा था, स्थिति निरीक्षण के लिए आमंत्रण मिला। नेहरू जी अपने दो सहयोगियों—आचार्य गिबवानी और श्री के० सन्तानन—के साथ जैतो के लिए रवाना हुए। जैतो पहुँचने पर उक्त जत्थे को पुलिस ने रोका, तथा साथ ही नेहरू तथा उनके अन्य दो साथियों को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त नामा रियासत-स्थित शासक का आज्ञापत्र मिला, जिसके अनुसार उन्हें वह स्थान तत्काल छोड़ देने का आदेश दिया गया था। नेहरू जी ने वापस लौटने में अपनी असमर्थता प्रकट की। फलतः उन्हें उनके साथियों के साथ तुरन्त ही गिरफ्तार कर लिया गया। दो तीन दिवस तक उन्हें नामा-जेल की एक गंदी कोठरी में रखा गया। उन पर तथा उनके उन सहयोगियों के ऊपर दो आरोप लगाये गये थे। पहला आज्ञा भंग का तथा दूसरा पडयन्त्र का। नामा की अदालतों के कार्यक्रम अव्यवस्थित तथा विचित्र प्रकार के थे। द्वितीय प्रकार के अभियोग को सिद्ध करने के लिए सिर्फ तीन ही व्यक्ति पर्याप्त न थे; अतः उन लोगों के साथ एक अपरिचित सिक्ख को भी गिरफ्तार कर, सम्मिलित पडयन्त्र वे अभियोग में बसीटा गया था। इसी बीच एक दिन नामा के ब्रिटिश ऐडमिनिस्ट्रेटर की ओर से, जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उन लोगों के बार्ड में उपस्थित होकर कहा कि यदि आप लोग अपने कार्यों पर दुःख प्रकट कर क्षमा याचना करें, और बिना आज्ञा नामा में फिर न आने का वचन दें, तो आप लोगों पर से मुकदमा उठा कर आपको स्वतंत्र किया जा सकता है। नेहरू जी ने उत्तर दिया, हम लोगों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके लिए हम दुःख प्रकट करें; बल्कि हम लोगों के प्रति किये गये अपने दुर्व्यवहारों पर नामा-शासक को खेद प्रकट करना चाहिये।

गिरफ्तारी के पश्चात् न्याय का ढोंग दो सप्ताह तक होकर समाप्त हुआ। नेहरू जी ने मुकदमे के समय अपनी और अपने मित्रों की किसी प्रकार की पैरवी किये बिना सिर्फ एक लिखित बयान अदालत को दिया। अंत में अवज्ञा के लिए ६ महीने, तथा पडयन्त्र के लिए १८ महीने का कारावास दंड नेहरू जी को तथा उनके साथियों को दे दिया गया। नेहरू जी

के गिरफ्तार होने पर आशंकित पिता ने वायसराय को एक तार दिया तथा पुत्र से मिलने की आज्ञा माँगी । आज्ञा मिलने के पश्चात् वे नाभा-जेल में जाकर पुत्र से मिले । पुत्र के सविनय अनुरोध से, तथा वहाँ रहना विशेष लाभप्रद न समझकर वे एक वकील, कपिलदेव मालवीय को वहाँ छोड़ कर प्रयाग लौट आये । जवाहरलाल जी को अपने सहयोगियों के साथ सजा तो मिल गयी, पर न्यायालय द्वारा हुए अपने विरुद्ध फैसलों की प्रतिलिपियों अनेक बार माँगने पर भी न मिली ।

एक दिन शाम को जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने उन्हें बुलाकर नामा शासक का आदेश पत्र दिखलाया, जिनमें उन लोगों की सजाये स्थगित कर दी गयी थी, साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया गया था कि बिना आज्ञा के वे कभी भी नामा में पदार्पण न करें । उन दोनों आज्ञाओं की प्रतिलिपि माँगने पर भी उन्हें न मिली । इसके पश्चात् नेहरू जी अपने साथियों सहित स्टेशन मेज दिये गये ।

प्रयाग लौटने के बाद नेहरू तथा उनके वे दोनों मित्र विषम ज्वर से ग्रसित हुए । नेहरू जी तो चार सप्ताह बाद स्वस्थ हो गये, परन्तु उनके वे दोनों मित्र काफी दिनों तक खाट पकड़े रहे ।

उन्हीं दिनों जब पं० जवाहरलाल नेहरू नामा में थे उन्हें सूचना मिली थी की वे युक्त प्रान्तीय कांग्रेस के समापति मनोनीत हुए हैं । दुर्भाग्य-वश कांग्रेस के अधिवेशन के दिन ही पं० नेहरू बीमार पड़ गये और उनकी अनुपस्थिति में ही, उनके द्वारा लिखित भाषण पढ़ा गया । इसके पूर्व पं० नेहरू प्रांतीय कांग्रेस के मंत्री-पद पर कार्य कर रहे थे ।



राजनैतिक जीवन और सार्वजनिक सेवा

दिसम्बर १९२३ में मौलाना मुहम्मद अली के सभापतित्व में अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा का वार्षिक अधिवेशन कोकनाडा (दक्षिण) में हुआ । मौलाना मुहम्मदअली के अनुरोध से, अपनी इच्छा के विपरीत भी नेहरू जी को मंत्री-पद ग्रहण करना पड़ा । अपरिवर्तनवादियों ने अपनी सारी शक्ति संगठित करके, एक बार पुनः देश को पुराने असहयोगी कार्यक्रम पर वनाये रखने की चेष्टा की; किन्तु वे विफल हुए तथा विजय स्वराजिस्टों के हाथ लगी । इस अस्थिर परिस्थिति में नेहरू जी का मंत्रीपद के लिए अनिच्छा रखना स्वाभाविक ही था, परन्तु मुहम्मद-अली के आग्रह की वे उपेक्षा भी नहीं कर सकते थे ।

मौलाना साहब इस्लाम के कट्टर भक्त तथा धार्मिक प्रकृति के थे, जब की नेहरू जी परम नास्तिक और धार्मिक रुढ़ियों के विरोधी । कभी-कभी धर्म विषयक बातों को लेकर उनकी और मौलाना की छोटी-मोटी झड़प भी हो जाती थी, परन्तु इतने पर भी वे नेहरू जी से स्नेह करते तथा उन्हें सहीमाने में एक असली 'मजहबी आदमी' मानते थे ।

कोकनाडा-कांग्रेस में हिन्दुस्तानी-सेवा-दल की नींव पड़ी । कांग्रेस स्वयंसेवकों में सैनिक-अनुशासन तथा संगठन का अभाव काफी पहले से कुछ नेताओं को खल रहा था । डा० नारायण सुब्बाराव हार्डकर के आग्रहपूर्ण लगन तथा नेहरू जी के सहयोग से, कुछ नेताओं का 'अहिंसा के सिद्धांत का शत्रु' समझ कर विरोध करते रहने के पश्चात् भी, इसे शक्तिपूर्ण सैनिक अनुशासन के आधार पर संगठित किया गया । इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय स्वयंसेवक कान्फ्रेंस भी हुई

जिसके समाप्ति नेहरू जी ही हुए; तत्पश्चात् वे इसके प्रथम अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए ।

दक्षिण के इस कांग्रेस-अधिवेशन के पश्चात् नेहरू जी प्रयाग पहुँचे । इन्हीं दिनों प्रयाग में ६ वर्ष बाद आने वाले कुम्भी-स्नान का पर्व आ उपस्थित हुआ था । राष्ट्र के कोने-कोने से धर्मप्राण हिन्दू स्नान के उद्देश्य से प्रयाग में एकत्रित होने लगे । नदी के तीव्र बहाव तथा खतरे की वजह से सरकार ने संगम-स्नान पर रोक लगा दिया । इस धार्मिक हस्तक्षेप में वातावरण कुछ गरम हो चला था, तथा सम्पूर्ण हिन्दू जनता सरकार के इस प्रकार के व्यवहार से क्रुद्ध थी । जनता की ओर से मालवीय जी ने स्वयं प्रार्थना-पत्र सरकार की सेवा में भेजा था, परन्तु उस पर कोई विचार न हुआ, फलस्वरूप गंगा के कगारों पर उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ सत्याग्रह करने का निश्चय किया । अहिंसात्मक सत्याग्रही की भोंति नेहरू जी, मालवीय जी तथा उनके अनेक सहयोगियों के साथ शांतिपूर्वक उस कड़ी धूप में चार घण्टे तक बालू पर बैठे रहे । बुडसवारों का निर्दयतापूर्ण अशिष्टता, तथा वातावरण की अकर्मण्य गम्भीरता से उग्र कर, वे उन बोंस के घेरे पर कांग्रेस का झण्डा लेकर चढ़ गये जिन्हें स्नानार्थियों को रोकने के लिए बनाया गया था । उन्होंने बलपूर्वक घेरे के कुछ तल्ले और बल्लियों उखाड़ डाले और जनता के लिए एक छोटा सा प्रवेश मार्ग बना दिया । अनेक व्यक्तियों के साथ उन्होंने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगायी । पुलिस का सब प्रयत्न और परिश्रम व्यर्थ ही रहा वह उन्हें रोकने में असमर्थ रही ।

सन् १९२४ में गांधी जी अत्यधिक अस्वस्थता के फलस्वरूप कारागार से मुक्त कर दिये गये । वे स्वास्थ्य-लाभ के लिए बंबई के रमणोय समुद्र-तट जूहू पर ठहरे हुए थे । काफी दिन के पश्चात् अपने प्रिय नेता से मिलने के लिये पिता और पुत्र—पं० मोतीलाल तथा जवाहरलाल जी बम्बई पहुँचे । देश की राजनैतिक समस्याओं पर गांधी जी के विचार, तथा उनके आगे के कार्यक्रम के बारे में जानने के लिए दोनों ही व्यक्ति बहुत

उत्सुक थे । स्वराजिस्टो के अधिनायक पं० मोतीलाल जी का बम्बई आने का एक यह उद्देश्य भी था, कि वे अपने दल के कार्यक्रम और विचारों को उन्हें बतलाकर अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करे, और यदि सक्रिय सहयोग नहीं तो कम से कम निष्क्रिय सहानुभूति अवश्य ही प्राप्त करे; परन्तु वे अपने इस कार्य में सफल न हो पाये और निराश होकर लौटे । गांधी जी को काउन्सिल में प्रविष्ट इन स्वराजिस्ट मेम्बरों के कार्य में विशेष आस्था न थी । उनके अनुसार काउन्सिल में विद्वतापूर्ण लच्छेदार भाषण देकर, तथा वहाँ सत्ता का विरोध कर और वजट को ठुकराकर, न तो वे सरकार का कुछ बिगाड़ ही सकते हैं न सही अर्थों में जनता और राष्ट्र की सेवा ही कर सकते हैं । १९२४ में अनेक प्रान्तों की काउन्सिलों में इन मेम्बरों ने ऐसा ही किया भी था, परन्तु बार-बार किये जाने वाले इन बासी और बेकार के कार्यों से अंत में जनता ऊब गयी और निराशा से उनकी ओर से दृष्टि फेर लिया ।

दिसम्बर १९२४ में कांग्रेस का अधिवेशन गांधी जी के सभापतित्व में बेलगोवा में हुआ । नेहरू जी अब की बार भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री चुने गये । यूरोप-यात्रा के दो वर्ष छोड़ कर नेहरू जी काफी दिनों तक कांग्रेस के स्थायी प्रधानमन्त्री रहे हैं, और आज तो आप राष्ट्र के ही प्रधान मंत्री हैं । इस पद पर रह कर उन्होंने योग्यता से अपना कार्य सम्पन्न किया तथा कांग्रेस-कार्यालय को एक जीती जागती वस्तु बना दिया । वे परिश्रम और लगन से अपना कार्य करते तथा प्रेम-पूर्वक अपने सहयोगियों से भी खूब काम लेते थे ।

इन्हीं दिनों हिन्दू और मुसलमानों के बीच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही कटुता अपनी सीमा पर पहुँच चुकी थी । आपसी घृणा के फल-स्वरूप, बड़े बड़े शहरों में पशुता और क्रूरता का नग्न ताण्डव नृत्य हो रहा था । एक ही देश के दो मजहबों में बँटें इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे । बेबुनियादी बातों पर उठने वाली इस आग को लगाने वाली, देश की एक तीसरी ही निकम्मी और नमकहराम ताकत

थी, जो प्रायः शासकों के टुकड़े पर पल रही थी। उसके दुष्प्रयत्न से सम्पूर्ण भारत साम्प्रदायिकता की वहि में घबक उठा, कांग्रेस के शीतल छिड़काव का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अंग्रेज-सरकार की यह नयी फूट की नीति काफी सफल रही, और उनके जाने के बाद भी इस दुर्नीति ने भारत के दिल के दो टुकड़े कर के ही दम लिया। भारत की अविभाज्य आत्मा ने उस समय इसको प्रोत्साहन देने वाले हिन्दू-मुसलमान नेताओं पर लानत भेजी।

साम्प्रदायिक अग्नि के उत्पन्न होने का एक कारण, हमारा अनिश्चित राजनेतिक पथ और सामाजिक पृष्ठभूमि का अभाव भी था। नेहरू जी के ही शब्दों में, “हमारी आजादी की लड़ाई में स्पष्ट आदर्शों और व्ययों की कमी ने साम्प्रदायिकता का जहर फैलाने में मदद की। जनता को स्वराज्य की लड़ाई का अपने प्रतिदिन के कष्टों से कोई सम्बन्ध दिखायी नहीं दिया। वे जगत् अपनी सहज बुद्धि से प्रेरित होकर खूब लड़े; लेकिन वह हथियार इतना कमजोर था कि उसे आसानी से कुण्ठित किया जा सकता था; और दूसरी तरफ अन्य (प्रतिक्रियावाद के) कामों के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता था....प्रतिक्रिया के समय साम्प्रदायिक नेताओं को इस काम में कोई रुचिकल भी नहीं पड़ी। वे जनता की इन्हीं भावनाओं को धर्म के नाम पर उभाड़ कर उसका इस्तेमाल करते रहे।” इस काम में अवोध जनता की उन्हें काफी सहानु-भूति भी मिली।

कांग्रेस के कुछ मुसलमान नेताओं ने, जनता में इन सम्प्रदायवादी नेताओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से, नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी नामक एक दल भी बनाया, परंतु अपनी लिबरल नीति के फलस्वरूप इस विषय में वह सरया कोई प्रशंसनीय कार्य न कर पायी।

हिन्दू-मुसलिम के इस साम्प्रदायिक गहन प्रश्न को लेकर, १९२० से १९२६ तक अनेक ‘एकता सम्मेलन’ हुए, जिसमें इस प्रश्न को किसी भी प्रकार हल करने का प्रयत्न किया गया। १९२४ में गांधी जी के २१

दिन के अनसन के अवसर पर, मौ० मुहम्मद अली की अध्यक्षता में दिल्ली में हुए कांग्रेस-सम्मेलन में भी यही प्रश्न प्रधान था, परंतु इस सम्मेलन से कोई विशेष लाभ न हो सका ।

दिल्ली का एकता-सम्मेलन मुश्किल से समाप्त हुआ था कि अन्य स्थानों की देखा-देखी प्रयाग में भी दंगा आरम्भ हो गया । नेहरू जी अन्य साथियों के साथ प्रयाग पहुंचे, परंतु तब तक दंगा समाप्त हो चुका था । अपने ही क्षेत्र में, अपनी ही नाक के नीचे हुए इस घृणित कांड को देख कर नेहरू जी को अत्यंत चोभ हुआ, और वे कई दिन तक अनमने और कुछ खीचे-खीचे से फिरते रहे । सचमुच यह चिराग तले अंधेरा था ।



यूरोप-यात्रा

सन् १९२६ में श्रीमती कमला नेहरू का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब हो गया, तथा उनकी रूग्णावस्था संदेहात्मक हो गयी। स्थानीय डॉक्टरों की राय उनका इलाज स्विट्जरलैंड में कराने की हुई। प्रकृति के भव्य उपहारों से पूर्ण उस प्रदेश में अवश्य ही उनकी प्रिय पत्नी स्वस्थ हो जायेगी, ऐसा नेहरू जी का विश्वास था। अस्तु मार्च सन् १९२६ में उन्होंने वेनिस की यात्रा आरम्भ की, वहाँ से वे स्विट्जरलैंड पहुँचे। कमलादेवी का उपचार विशेषतः जिनेवा और मोण्टाना के पहाड़ी सेनिटोरियम में हुआ। प्रवासी नेहरू वहाँ भी भारतीय परिस्थिति पर विचार करते और स्वाध्याय में तन्मय रहा करते थे। इस बार यूरोप में वे करीब १ साल नौ महीने ठहरे। उनके जीवन का यह थोड़ा समय काफी आनंद और शांति से बीता।

पत्नी के स्वास्थ्य-लाभ के पश्चात् पण्डित जी ने परिवार-सहित यूरोप के भिन्न-भिन्न देशों का पर्यटन किया, तथा अनेक निर्वासित क्रांतिकारी भारतीय नेताओं एवं प्रमुख विदेशी व्यक्तियों से मिले, जिनमें से कुछ व्यक्तियों की स्पष्ट छाप भी उन पर पड़ी।

इन्ही दिनों नेहरू जी ने भारतीय क्रांतिकारी श्याम जी वर्मा से मेंट की, जो अपनी रूग्ण गुजराती पत्नी के साथ जिनेवा के एक भवन की सबसे ऊँची मंजिल पर रहते थे। पैसा होते हुए भी उनका जीवन काफ़ी अव्यवस्थित, गरीबी ढंग का था। वे हर एक व्यक्ति को, जो उनसे मिलने आता था उसे ब्रिटिश मेदिया समझ कर संदेहात्मक दृष्टि से देखते थे।

इसके अतिरिक्त स्विटजरलैंड में वे राजा महन्द्रप्रताप से भी मिले, जो एक अर्जाव सी आधी फौजी पोशाक पहने, निहायत आशावादी ढंग में बातचीत करते थे ! उन्होंने योरोप के कुछ देशों में 'आनन्द-समाज' की स्थापना की थी, तथा अपने को 'मनुष्य जाति का सेवक' कहते थे । लम्बे अरसे से निवासित जीवन व्यतीत करने के बाद स्वतंत्रता के पश्चात् वे भारत लौटे ।

नेहरू जी पेरिस में, भारतीय स्वतंत्रता की पक्षपाती, तथा साम्राज्यवादी भावना की विरोध बूढ़ी मैडम कामा से भी मिले । संघर्षों ने उन्हें जर्जर तथा विक्षिप्त सा बना दिया था । जीवन के प्रति अब उनकी कोई विशेष आस्था न रह गयी थी । वे काफी डरावनी सी दीखती थीं ।

इसके अतिरिक्त बर्लिन में वे मौलवी बरकतउल्ला, इटली में मौलवी उवेदुल्ला, आदि से भी मिले । बर्लिन में ही उनकी कुछ अन्य क्रांतिकारी नवयुवकों से भी मेंट हुई, जो युद्ध के पूर्व वहाँ पढ़ते थे तथा युद्ध काल में भारतीय-स्वातंत्र्य और राष्ट्रीयता के विचारों से प्रभावित हो, युद्ध के पश्चात् भारत को स्वतंत्रता देने की शर्त पर, जर्मनी की मदद करने के लिए तैयार हो गये थे । वहाँ उन्होंने इसके लिए एक हिंदुस्तानी युद्ध कमेटी भी बनायी थी, जिसके अध्यक्ष-पद के लिए अमेरिका में निवासित जीवन व्यतीत करने वाले क्रांतिकारी भारतीय नेता लाला हरदयाल को उन्होंने आमंत्रित किया था । युद्धांत के पश्चात् यह कमेटी टूट गयी तथा इसके सदस्यों को जर्मनी के शासक सदेह की नजर से देखने लगे थे । भारत के सुविख्यात निवासित क्रांतिकारी वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय तथा मानवेन्द्रनाथ राय की विद्वत्ता का नेहरू जी पर काफी प्रभाव पड़ा ।

नेहरू जी जिनेवा में कई बार, प्रसिद्ध साम्राज्यविरोधी फ्रेंचविद्वान रोम्यो रोला से मिलने विलाओल्पा गये । रोम्योरोला गांधी जी के भक्त तथा भारतीय स्वतंत्रता के सच्चे आकांक्षियों में से थे । प्रथम मिलन के

समय नेहरू जी ने गाँधी जी से प्राप्त अपने सम्बंध के एक परिचय-पत्र को उन्हें दिखलाया था ।

नेहरू जी के स्विटजरलैंड पहुँचने के कुछ दिन पश्चात ही, पूँजीपतियों के अत्याकार से तंग आकर इंग्लैंड के मजदूरों ने आम हड़ताल की । स्वभाविक था कि एक पददलित देश के नेता की सहानुभूति उन शोषित-शापित शत-शत श्रमजीवियों से हो । पूँजीपति सरकार ने मजदूरों के 'अनैतिक आंदोलन' तथा उनकी माँगों को, 'शांतिके खिलाफ' कहकर बुरी तरह कुचल डाला । इसके कुछ महीने पश्चात नेहरू जी इंग्लैंड पहुँचे तथा उन्हें वहाँ के एक अशांतिग्रस्त प्रदेश की खान के मजदूरों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । खान में काम करनेवाले मर्दों, औरतों और बच्चों के पीले और पिचके हुए गाल, तथा घँसा हुई आँखों में तिरती हुई भूख और आह ने दुनिया के हर पूँजीवादी देश की तस्वीर उनकी आँखों के परदे पर खींच दी । पूँजीपतियों के टुकड़ों से पली हुई अदालतों और पुलिस द्वारा किये गये नृशंस अत्याचारों से अस्त उन मजदूरों की भयभीत आँखों में, दुनिया के हर देश के मजदूरों की गर्वा वीती जिंदगी के बीच उन्हें एक अजीब साम्य दिखलाई दिया । इस नयी दुनिया की पहली मलक ने नेहरू की आत्मा तक कंपा दी । ✓

सन् १९२६ के दिसम्बर में नेहरू जी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में थे, और वही उन्हें यह मालूम हुआ कि ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में दलित जातियों का एक सम्मेलन होने वाला है । नेहरू जी उस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि की हेसियत से जाने के लिए तैयार हो गये । ब्रुसेल्स की कांग्रेस १९२७ की फरवरी में आरम्भ हुई । इसके सभापति ब्रिटिश मजदूर नेता जार्ज लेन्सवरी थे । इस संगठन का उद्देश्य साम्राज्यवाद के कठिन पंजे से ग्रसित राष्ट्रों तथा वर्गों को मुक्त करना था । फलस्वरूप इसमें सभी राष्ट्रों के वामपक्षी नेता और प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे । नेहरू जी ने पहले पहुँच कर सम्मेलन की अंतरंग गोष्ठियों तथा विषय निर्धारणा समितियों में भी भाग लिया । अखिल भारतीय कांग्रेस महा-

सभा के प्रतिनिधि होने के कारण वहाँ आप विशेष रूप से सम्मानित किये गये। विषय निर्धारिणी समिति के सदस्य तो नं.हू जी थे ही, साथ ही नियमानुसार एक बैठक में वे सभापति भी बनाये गये। अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस के पोंच सम्मानित सभापति बनाये गये थे जिनमें पं० नं.हू भी एक थे। शेष चार सभापति थे इस्टीन, रोम्यो रोला, श्रीमती सनयात सेन तथा लेन्सवरी। यह भी प्रस्ताव किया गया था कि पंडित जी तीन मंत्रियों में से भी एक चुने जाये, परन्तु आपने इसमें अपनी असमर्थता दिखलाते हुए अस्वीकार कर दिया था।

इस सम्मेलन में जावा; हिन्द-चीन, फिलिस्तीन, सीरिया, मिश्र, उत्तरी अफ्रिका आदि के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। कम्यूनिरटों तथा समाजवादी विचारधाराओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे; परन्तु इन सब विचारधाराओं के बीच भी सम्मेलन ने अपना दृष्टिकोण स्वतंत्र रखा। पं० जवाहरलाल ने इस कांग्रेस के मंच से भारत की सच्ची अवस्था का परिचय कराने, और दलित राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया। आपने भारत की स्वतंत्रता तथा उन्नति सम्बन्धी कई प्रस्ताव भी सम्मेलन में उपस्थित किये, जिसकी पूरी रिपोर्ट भारत आकर आपने कांग्रेस महासभा को दिया। सम्मेलन में अपने राष्ट्र के जन-आंदोलन के प्रति सासारिक सहानुभूति प्राप्त करने, साम्राज्यवाद का विरोध करने, और भारत तथा चीन के बीच मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने के संबंध में भी कई प्रस्ताव आपने पास कराये।

इस कांग्रेस के भंडा कैम्प में भारत का तिरंगा भंडा भी लहराता था। पं० जी ने महान दूरदर्शिता और विद्वत्ता के साथ दलित राष्ट्रों की गोष्ठी में भारतीय प्रेम का बीजारोपण किया और उन्हें यह समझाने का प्रयत्न किया कि भारत की मुक्ति से ही संसार के दलितवर्ग, विशेषतः एशिया की मुक्ति सम्भव है। भारत ही साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा अड्डा है, और जब तक भारत में उसका नाश नहीं होता संसार के बहुत से भागो, प्रधानतः एशिया को स्वतंत्रता की स्वच्छ वायु में साँस लेने का

त्वप्न देखना एक मृगतृष्णा ही होगी। नेहरू जी ने कुछ दिन ब्रुसेल्स में रह कर कोलोनीज़ (ब्रिटिश और फ्रेंच उपनिवेश) और अन्य परतंत्र राष्ट्रों की समस्याओं का अध्ययन किया और पश्चिम के असंतुष्ट श्रम-जीवियों का अदम्य संघर्ष देखा। वे यद्यपि इन समस्याओं के बारे में पहले से भी बहुत कुछ जानते थे पर इन आंदोलनकारियों के सम्पर्क में आने में उन्हें और भी बहुत सी नयी बातें मालूम हुईं। इस सम्मेलन की साम्राज्य विरोधी कार्यवाहियों से फ्रांस और इंग्लैण्ड की सरकारें असंतुष्ट थीं, अतः उनके बहुतेरे गुप्तचर उसका कार्यवाहियों में अनेक रूप धर कर उपस्थित रहते थे, जो वहाँ की घटनाओं तथा समाचारों को अपने राष्ट्र तक पहुँचाते रहते थे।

इस संघ की एक बैठक कोलोन में भी हुई जिसमें नेहरू जी ने भाग लिया। बाद में यह संघ दिन प्रति दिन कम्युनिज्म की ओर झुकता गया और अन्त में ऐसा हो गया कि जिन लोगों का पूर्वावाद या उसके प्रतिनिधियों से थोड़ा सा भी सम्पर्क रहता उससे संघ अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेती थी। नेहरू जी इस संघ के कई वर्ष तक सदस्य रहे, पर सन् १९३१ में भारतीय कांग्रेस और सरकार के बीच दिल्ली में जो समझौता हुआ और उसमें नेहरू जी ने जो हिस्सा लिया, उससे संघ ने नेहरू जी पर असंतुष्ट होकर उन्हें अपनी सदस्यता से पृथक् कर दिया। यहाँ तक कि उसने नेहरू जी को अपनी परिस्थिति, जिनके वर्षाभूत होकर उन्हें ऐसा करना पड़ा, स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं दिया।

१९२७ के ग्रीष्म में पं० मोतीलाल जी सपरिवार यूरोप गये तथा वेनिस में अपने पुत्र से भेंट की। इसी बीच नेहरू जी को संवित हस की विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध रखने वाला सना को ओर ने, हसी स्वतंत्रता के दसवीं वर्ष गौठ के अवसर पर, सपरिवार हस आने का आमंत्रण मिला। निर्मङ्गण पाकर 'किसान और मजदूरों के अपने राज्य' को देखने का लोभ वे संवरण न कर सके; तथा नवम्बर में सपरिवार वे हस की राजधानी मास्को पहुँच गये। स्वतंत्रता के इन कुछ वर्षों के बीच

ही रूस में हो जाने वाले इस महान परिवर्तन को देखकर वे काफी प्रसन्न हुए । पं० मोतीलाल पर भी इसका काफी असर हुआ । नये रूस में जार के गगनचुम्बी प्रासादों में मजदूर-संघों के कार्यालय खुल गये थे । मास्को के सबसे बड़े गिरजेघर पर लिखा था “धर्म मनुष्यों के लिए अफीम है ।” बड़े और छोटे कार्य करने वाला में कोई भेद न था और सभी ‘साथी’ कहकर सम्बोधित किये जाते थे । सभी बड़ी फैक्टरियों सरकार के अधीन थी । आज से कुछ साल पहले के पूँजीवादी रूस का ढोंचा अब एक दम ही परिवर्तित हो गया था ।

वहाँ पंडित जी को मास्को जेल देखने का भी अवसर मिला । रूस में कारागार का उद्देश्य दंड न होकर सुधार है । वहाँ मानवीय भावनाओं को महत्व दिया जाता है । मद्रास में होने वाले राष्ट्रीय महासभा का वार्षिक अधिवेशन निकट होने के कारण, मास्को में ३-४ दिन रहकर नेहरू-परिवार अपनी जन्मभूमि भारत लौट्य ।



भारत की राजनैतिक-स्थिति तथा साइमन कमीशन

सोवियत रूस की दुग परिवर्तनकारी महान उन्नति देखकर नेहरू जी का उसकी ओर विशेष आकर्षण हुआ। उसके सिद्धांतों, जिस पर वह राष्ट्र आधारित था, का अध्ययन करने के लिए उन्होंने साम्यवादी पुस्तकों का अध्ययन आरम्भ किया। अभी तक उन्हें उसके सिद्धांत और क्रियात्मक पहलू पर विशेष विश्वास न था। वे उसे केवल एक उच्च तथा काल्पनिक आदर्शवाद ही समझते थे। रूस में जाकर उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनके विचार-जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मजदूर और किसान का संगठन स्वतंत्रता-युद्ध की दृष्टि से अब उनके लिए विशेष मूल्यवान हो गया था। उन्हें अब मशीन से घृणा न रह गयी थी, और वे साम्यवाद-संचालित फैक्ट्रियों में मशीन के उपयोग को लाभकारी मानते थे। “मशीन औजार है; भले और बुरे दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।”

विदेशों में घूम कर और दलित राष्ट्रों के प्रतिनिधियों एवं राजनीति शास्त्र के दिग्गज विद्वानों से मिलकर उनका अंतराष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा अनुभव विस्तृत हो गया था। अब वे राजनैतिक स्वतंत्रता का पहला कदम आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता समझने लगे थे। उनके दृष्टिकोण से, अन्तराष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता होना आवश्यक था, और साथ ही जनसमुदाय की शक्ति और सम्मति प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक था कि स्वराजी कार्यक्रम में मजदूरों और किसानों का सक्रिय सहयोग हो।

नेहरू की पारदर्शी दृष्टि ने विश्व के राजनैतिक वातावरण के बीच

से उठते हुए भविष्यगत महायुद्ध की घनी घटाओं को देख लिया था । अतः मद्रास-अखिलभारतीय कांग्रेस-कमेटी के अधिवेशन में उन्होंने दो प्रस्ताव रखे-भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और भावी युद्ध के वज्रपात से भारत की रक्षा । बिना किसी विरोध के ये दोनों ही प्रस्ताव एक स्वर से मान लिये गये; यद्यपि उस समय कांग्रेस ने इन प्रस्तावों के तात्त्विक महत्त्व तथा इसमें छिपे मूलभाव को नहीं समझा था ।

कांग्रेस के इस मद्रास-स्थित अधिवेशन के अवसर पर वहाँ 'अ-भारतीय प्रजातांत्रिक कांग्रेस' तथा 'हिंदुस्तानी सेवादल' के वार्षिक अधिवेशन भी हुए थे । नेहरू जी ही इन दोनों अधिवेशनों के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे ।

मद्रास-कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके, कार्य-कारिणी को आज्ञा दी कि वह भिन्न-भिन्न राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक दलों के नेताओं से परामर्श करके, मौलिक अधिकारों की घोषणा के आधार पर एक राष्ट्रीय शासन-विधान तैयार करे, और मार्च के महीने तक सर्वदल-सम्मेलन दिल्ली में बुलाकर अपने कार्य को उसके समक्ष उपस्थित करे ।

कांग्रेस का निमंत्रण स्वीकार कर सभी दलों की एक बैठक दिल्ली में हुई । इसी समय मुस्लिम लीग ने ५ शर्तें उपस्थित की, और किसी भी समझौते पर विचार करने के पूर्व इनकी मान्यता चाही । इस आधार पर अन्य छोटे और साम्प्रदायिक दलों ने भी अपनी मांगें उपस्थित की, फलस्वरूप दिल्ली का अधिवेशन विशेष सफल न हो सका । मुस्लिम मांगों के आधार पर दो समितियों, सिन्ध-विच्छेद और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रश्नों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गयी । मई के महीने में फिर सम्मेलन की बैठक बुलाई गयी । इस बीच हिंदूमहासभा मुस्लिम मांगों के विरोध में कई प्रस्ताव पास कर चुकी थी, और परिस्थिति पहले से कहीं विशेष उलझ गयी थी, साथ ही नियुक्त समितियों ने भी अब तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी । सम्मेलन की असफलता की ही अधिक आशंका थी । मन्मई के भिन्न-भिन्न दलों के कुछ प्रतिनिधियों की एक

कमेटी इसी 'सर्वदल-सम्मेलन' के तत्वावधान में बनायी गयी। इसका उद्देश्य सभी साम्प्रदायिक दलों, तथा राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए एक जनतन्त्रात्मक विधान का निर्माण करना था। इस कमेटी के अध्यक्ष पं० मोतीलाल नेहरू थे अतः इसकी रिपोर्ट, 'नेहरू-कमेटी' की रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट को सफल तथा कार्यात्मक बनाने के लिए जवाहरलाल जी ने जितना उद्योग किया, उसका उल्लेख स्वयं कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किया है।

यह सब होते हुए भी जवाहरलाल जी इससे पूर्णतः संतुष्ट न हो सके। जहाँ तक साम्प्रदायिक समस्याओं का संबंध था, वे रिपोर्ट के साथ थे, किंतु उनकी दृष्टि में देश के हित के विचार से औपनिवेशिक स्वराज्य को भारत के भारी शासन विधान का आधार बनाना सर्वथा अनुचित था। उनकी धारणा थी कि सामयिक नीति और वास्तविकता के अनुसार भी, पूर्ण स्वतंत्रता ही देश का लक्ष्य होना चाहिए। उसी धारणा के अनुसार उन्होंने लखनऊ-सर्वदल-सम्मेलन के अधिवेशन में मालवीय जी के प्रस्ताव का विरोध करते हुए, निर्भीकता के साथ पूर्ण स्वतंत्रतावादियों की कार्यवाहियों को ओर से भाषण करते हुए घोषणा की थी कि हम लोग इस प्रश्न पर सम्मेलन की कार्यवाहियों से पृथक् रहेंगे।

इन्हीं पूर्ण स्वतंत्रतावादियों की नयी समिति का नाम 'इन्डिपेन्डेन्स लीग' पड़ा। लीग ने ३-४ नवम्बर को दिल्ली की अनेक बैठकों में अपना विधान निर्माण किया, और देश भर में पूर्ण स्वतंत्रता का आन्दोलन करने का कार्यक्रम बनाया। अग्निवास अयंगर लीग के सभापति निर्वाचित हुए और पं० जवाहरलाल मंत्री। दिसम्बर सन् १९२८ में अ० भा० कांग्रेस महासभा का अधिवेशन पं० मोतीलाल की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। पं० जवाहरलाल जी इस सम्मेलन में भी अपने पूर्ण स्वतंत्रतावादी सिद्धान्त पर अटल रह तथा पिता के विरुद्ध खड़े हुए। महात्मा गान्धी ने जिस समय कलकत्ता-कांग्रेस के समक्ष नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट पर अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव रखा था, उस समय जवाहरलाल जी

अनुपस्थित थे। यद्यपि प्रस्ताव पर उनके दल ने सम्मति दे दी थी, परन्तु नेहरू जी को उससे शान्ति नहीं हुई। गोंधी जी ने स्वयं नेहरू जी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि “पूँजीवादी आर्थिक-चक्र में पिसे मजदूरों को देख नेहरू का दिल भर आता था: और फिर एक नवीन जीवनी शक्ति के साथ वे उनको स्थिति सुधारने के लिए फिर से अपने कार्य में जुट जाते थे।” नेहरू-कमेटी द्वारा बनाये हुए नये विधान के मौलिक अधिकारों में, व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा रियासतों के जिन अधिकारों की गारंटी दी गयी थी, उसे नेहरू जी बहुत ही नापसंद करते थे: और उसी के फलस्वरूप नेहरू जी तथा सुभाष बाबू ने ऐसी संस्था से, जो इन आधारों पर सर्वहारा जनता के अधिकारों के साथ अपने नये विधान में विश्वासघात करने जा रही थी, सम्बन्ध तोड़ लेना चाहा था।

समस्त विरोधों और कठिनाइयों को सहते हुए भी, अंत में कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि यदि आज से एक वर्ष के भीतर, ३१ दिसम्बर सन् १९२६ तक ब्रिटिश सरकार ने नेहरू-रिपोर्ट के आधार पर औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वचन न दिया तो कांग्रेस देश में पूर्ण स्वाधीनता घोषित कर देगी; सरकार को टैक्स न देने का आन्दोलन आरम्भ कर देगी। उक्त निश्चित समय के पूर्व तक कांग्रेस देश को आनेवाली लड़ाई के लिए तैयार करेगी।

इस बीच कांग्रेस की आशा के विपरीत साइमन-कमीशन भारत की राजनैतिक स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए देश भर में दौरा कर रहा था। सरकार ने नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट तथा कांग्रेस के प्रस्ताव पर बिल्कुल ध्यान न दिया। फलस्वरूप कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निश्चय किया। कमेटी ने एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया कि “यह दृष्टि में रखते हुए कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार की अवहेलना करके एक कमीशन नियुक्त किया है, यह कांग्रेस यह निश्चित करती है कि इस परिस्थिति में

भारत के लिए केवल एक ही मार्ग शेष है, और वह है प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक समय कमीशन का बहिष्कार करना ।”

कांग्रेस को इस कार्य में काफी सफलता मिली । इस कार्य में नरम दल वालों ने भी कांग्रेस का साथ दिया । जहाँ-जहाँ कमीशन गया वहाँ वहाँ विरोधी जन-समूहों ने काले भंडे के साथ ‘साइमन लौट जाओ’ (*Siman go back*) की बुलंद आवाज से उसका स्वागत किया । कमीशन के मेमबर इस प्रदर्शन में इतना घबड़ाये कि कभी-कभी रात के अंधेरे दामन को चीर, स्वप्न में भी सहूलों कण्ठ से निकली यह आवाज उन्हें अपना पीड़ा करती हुई मालूम होती ।

कभी-कभी भीड़ द्वारा अपने प्रभु अंग्रेज साहबों के प्रति की गयी इस गुस्ताखी से चिढ़कर, पुलिस, सत्याग्रहियों की पीठ और सिरों पर अपने दो चार सघे हाथ दिखला देती । कांग्रेस प्रदर्शनकारियों पर लाठियों का इस प्रकार अनुचित और खुला प्रहार साइमन-कमीशन के दौरे के समय पहली बार हुआ था । लाहौर में इस प्रकार के एक नृशंस कार्य ने देश के कोने-कोने में घृणा और क्रोध की एक लहर दौड़ा दी । लाहौर में साइमन-विरोधी प्रदर्शन लाला लाजपतराय के नेतृत्व में हुआ । एक नौजवान अंग्रेज अफसर ने इससे खीझकर उनकी छाती पर कई डंडे लगाये । सम्पूर्ण हिन्दुस्तान प्रतिशोध की अग्नि से उबल पड़ा । वच्चा-वच्चा यह सोचने लगा, हाय ! हम कितने असहाय और कमजोर हैं कि अपने नेताओं के सम्मान की रक्षा तक नहीं कर सकते । लालाजी को शारीरिक चोट कम न लगी थी, परन्तु उससे भी अधिक मानसिक चोट लगी थी, इसलिए नहीं कि उनका अपमान हुआ था, बल्कि इसलिए कि उनपर किये गये प्रहार में राष्ट्रीय अपमान रो-रो कर अपनी आत्मकथा कह रहा था, और इसी चोट ने लालाजी को गुलाम देश से हमेशा के लिए उठा लिया । अपने दिल से उठती आह को दबाकर उस समय उन्होंने कहा था, “मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक-एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी” सचमुच इस कथन में कितनी सत्यता थी ।

सत्ताधारियों की इस चोट ने हिन्दुस्तान के सोये स्वाभिमान को झकझोर कर जगा दिया। गांधीजी के प्रयत्न से वर्षों से सोयी हिंसा अँगड़ाई लेकर उठ बैठी। राष्ट्र को अपमानित करने वाले अंग्रेजों को दण्ड देने वाले, क्रांतिकारी सरदार भगतसिंह का नाम पंजाब के घर-घर में गूँज उठा। शहरों और सुदूर गाँवों में माता अपने नवजात शिशुओं को भगतसिंह की वीरता के गीत सुनाने लगी; लोगो को लगा कि अपने हिंसात्मक कार्यों से भगतसिंह ने भारत के सम्मान की रक्षा की है। यद्यपि भगतसिंह के कार्य भूल गये, परन्तु देश की चेतना और उत्साह के लिए उसका नाम एक प्रतीक सा बन कर हर हिन्दोस्तानी के दिल और दिमाग पर छा गया।

साइमन-कमीशन के विरोध में नेहरू जी के प्रयत्न से प्रयाग में भी ३ फरवरी को सफल हड़ताल हुई। पानी बरसते रहने पर भी सार्वजनिक सभा के अवसर पर वहाँ काफी भीड़ रही। नेहरू जी का कार्यक्रम इस सबंध में प्रयाग तक ही सीमित न रहा, वरन प्रात के भिन्न-भिन्न नगरों में कमीशन का बहिष्कार सफल बनाने में भी उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया।

कमीशन के सक्रिय बहिष्कार करने में ही नेहरू जी को जीवन में सर्व प्रथम लखनऊ में पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा। साइमन कमीशन का आगमन लखनऊ में भी होने वाला था। सरकार चाहती थी कि लखनऊ में इसका बहिष्कार सफल न हो सके, पर कांग्रेसी नेतागण इस कार्य के लिए अपनी शक्ति सगठित कर रहे थे। २६ नवम्बर को अपार जन-समूह ने जुलूस में शामिल होकर सरकार को और भी शक्ति-कर दिया। अधिकारियों ने २८ नवम्बर को होने वाले जुलूस में जनता को भय दिखलाकर निरुत्साह करने की ठान ली। ता० २८ को पुलिस ने गोलियों और लाठियों का प्रयोग निहत्थे जुलूस पर किया, और बहुतों को इससे चोट आयी। इसी समय नेहरू जी भी लखनऊ पहुँच गये।

ता० २९ के दिन दो सभाये होनी निश्चित हुई थीं। बड़ी सभा अमीनुद्दौला पार्क में; और दूसरी मुहल्ला नरही की छोटी सभा हजरतगज

के पास । पं० नेहरू कई सहकारियों के साथ मुहल्ला-सभा में उपस्थित थे । उस दिन अधिकारियों ने 'जुलूस से सड़के रुक जाती है' घोषित करके उस पर प्रतिवध लगा दिया था । फलस्वरूप अधिकारियों को इस तरह की शिकायत का मौका न देने की गरज से, 'नेहरू जी ने सोलह-सोलह की टोलियों में बड़ी सभा में जुलूस मेजने का निश्चय किया । पहली टोली के नायक स्वयं जवाहरलाल जी दल के आगे तिरंगा झंडा लिए हुए चल रहे थे । थोड़ी दूर से एक दूसरा दल पं० गोविन्दवल्लभ पंत के नेतृत्व में आ रहा था । पुलिस भी अपने प्रमुखा की आज्ञा से मुस्तैदी पूर्वक इन दलों की रोक-थाम कर रही थी, और उधर जनता की अपार भीड़ उस संघर्ष को देखने के लिए उमड़ पड़ रही थी ।

पं० जवाहरलाल का दल मुश्किल से २०० कदम आगे बढ़ा होगा कि उसे सहसा पीछे से आने वाले घोड़ों के टापों की आवाज चुनायी दी । क्षण भर बाद ही दो-तीन दर्जन पुलिस घुड़सवार उस स्थान पर आ पहुँचे, और वेदर्दी के साथ उस झुण्ड को तितर-बितर करने के लिए उन पर लाठियों की वर्षा करने लगे ; यहाँ तक कि भागते हुए व्यक्तियों का भी पीछा किया गया और उन्हें लाठियों से मार-मार कर गिरा दिया गया ।

सड़क के बीच एक स्थान पर नेहरू जी को अविचल खड़ा देख कर एक सवार उनकी ओर झंडा घुमाता हुआ बढ़ा । अपमान और क्रोध की ज्वाला से दग्ध-हृदय नेहरू ने उसकी ओर देखकर ललकारते हुए कहा— "मारो ! मारो ।" और दासता का वह प्रतीक स्वतन्त्रता के उस पुजारी के सुकोमल पीठ पर अपनी पाशविक शक्ति से पिल पड़ा । झंडों की मार से जवाहरलाल जी को चक्कर आ गया, परन्तु वे स्वयंसेवकों को साहस बँधाते हुए और अपने ऊपर हुए अत्याचार को सहन करते हुए घटना-स्थल पर खड़े रहे । यह निश्चय ही अहिंसात्मक संघर्ष का एक बड़ा ही दारुण दृश्य था, जब कि पुलिस को अपने ऊपर हमला होने का कोई भय नहीं था पर वह सब तरफ भीषण आक्रमण करके अंधाधुन्ध लाठियों बरसा सकती थी ।

इस दर्दली घटना के पश्चात् ही पुलिस पीछे हट गयी और उस जुलूस को आगे न बढ़ने देने के उद्देश्य में बेरा बाँव कर सड़क रोक ली। कड़ी चोट से अल्ल स्वयंसेवक फिर उसी स्थान पर जुट गये। इतने में ही कठिन नार का सामना करने के पश्चात् पं० गोविन्दवल्लभ पन्त का जुलूस भी वहीं पहुँच गया। अपार दर्शकों की अथाह भीड़ में असंतोष बढ़ते देख कर, शांति-भंग की आशंका से अधिकारियों ने उस जत्थे को अपनी राह चले जाने देना ही उचित समझा; अतः उनका रास्ता छोड़ दिया गया।

दूसरे ही दिन, ता० ३० को साइमन-कमीशन का आगमन होनेवाला था। कल की घटना से लखनऊ के निवासियों में उत्तेजना बढ़ गयी थी, अतः वे स्वयं स्टेशन पर टिब्बियों के ढल से उपस्थित हो रहे थे। स्वयं जवाहरलाल जी भी करीब नौ बजे सड़क-वल स्टेशन की ओर रवाना हुए। इस विराट जुलूस का नेतृत्व श्री जवाहरलाल तथा श्री गोविन्दवल्लभ पन्त कर रहे थे। जुलूस जाकर स्टेशन के सामने के एक मैदान में शांति से खड़ा हो गया। अचानक दूर से धुड़सवारों का काफी लम्बा ढल बढ़ता हुआ आया, तथा उन्हें तितर-बितर करने के लिए उन पर बेदर्री से लाठी-प्रहार करने लगा। जवाहरलाल लाठियों के इस प्रहार से तिलमिला उठे और उनकी आँखों के आगे अंधेरा छाता सा मालूम हुआ। स्वयंसेवकों की पंक्तियाँ धीरे-धीरे पीछे हटने लगीं परन्तु हठी जवाहर अकेले ही वहाँ डटे रहे। अंत में कुछ स्वयंसेवकों ने अचेतावस्था में उन्हें वहाँ से हटाया। पं० गोविन्दवल्लभ पन्त पर तो जवाहरलाल जी से भी अधिक मार पड़ी थी।

साइमन-कमीशन आया और काले भएडों तथा 'साइमन लौट जाओ' के नारों के बीच, साम्राज्यवादी पुलिस का निहत्यो पर यह 'धीरता पूर्ण प्रहार' देखता हुआ बहुत दूर से ही निकल गया।

सरकार के निरंकुश दमन से बहिष्कार-आन्दोलन को जितनी शक्ति

(८५)

मिली उसका प्रत्यक्ष प्रमाण लखनऊ का यह कांड था । पं० जी को डंडा का शिकार बनाकर सरकार ने बहिष्कार-आन्दोलन को लोगों की दृष्टि में दूना ऊँचा कर दिया और देश में अपने प्रति विरोध बढ़ा लिया । देश के राजनैतिक वातावरण को इससे और भी प्रोत्साहन मिला ।



जननेतृत्व

जब से ५० जवाहरलाल नेहरू योरोप से लौट कर आये, तभी से देश के विभिन्न प्रान्तों ने उन्हें अपनी कान्फ्रेन्सों में समापति बनाकर सम्मानित किया था । १९२८ में संयुक्तप्रान्त, पंजाब, दिल्ली, केरल आदि प्रान्तों के समापति-पद पर वे आसीन हुए, तथा अधिवेशन में उपस्थित अपार जनता को राष्ट्रीय आन्दोलन और उसके क्रियात्मक महत्व का संदेश पहुँचाया ।

राजनीतिक दृष्टि से १९२८ का साल एक भरा-पूरा साल था । देश भर के सभी वर्गों में—कारखानों के मजदूरों और किसानों में भी, मध्यम वर्ग के नौजवानों और पढ़े लिखे लोगों में भी—एक नये जीवन की लहर—जन-जागृति व्याप्त थी । एक नयी प्रेरणा, एक नयी जिन्दगी से सम्पूर्ण राष्ट्र चेतन हो उठा था । पश्चिमी देशों, विशेषतः रूस का सतर्क निरीक्षण करने के पश्चात्, नेहरू जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि राष्ट्रीय आन्दोलन की सफलता के लिये देश के आर्थिक तथा सामाजिक तत्वों पर ध्यान देना तथा उसे अपनी ओर मिलाना आवश्यक है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने सम्पूर्ण हिन्दुस्तान का दौरा भी किया, तथा भाषणों के द्वारा अपना संदेश सर्वहारा वर्ग तक पहुँचाने का प्रयत्न किया । हर स्थान पर उन्होंने राजनैतिक आजादी और सामाजिक स्वाधीनता पर जोर दिया, और यह कहा कि राजनैतिक आजादी सामाजिक स्वाधीनता की सीढ़ी है, अर्थात् आर्थिक स्वाधीनता के लिये राजनैतिक आजादी आवश्यक है । इसके अतिरिक्त नेहरू जी अपने भाषणों में भारत की प्राचीन संस्कृति और गौरव पर विशेष आस्था प्रकट कर उन्हें फिर से स्थापित करने पर जोर देते थे । वे जनता को बतलाते थे कि विदेशी सरकार ने

राष्ट्र को क्या क्या भौतिक और आध्यात्मिक हानि पहुँचायी है। बृटिश साम्राज्यवादी पूँजीपतियों के शोषण, तथा भारतीयों के प्रति किये जाने वाले अत्याचारों का नंगा चित्र खींचकर, वह जनता जनार्दन से अपील करते कि हमारी कौमी इज्जत का तकाजा है कि हम आजाद हो, और इस ध्येय की पूर्ति के लिये यह आवश्यकता है कि हम लोग मातृ-भूमि की वेदी पर हँसते-हँसते बलि हो जावें।

इन्ही दिनों किसानों में भी एक नवीन प्रकार की जाग्रिति हो रही थी। विशेषतः यह नयी करवट अवध और संयुक्तप्रान्त ने ली थी, जहाँ अपने ऊपर होने वाले जमींदारों के अत्याचारों का विरोध करने के लिये किसानों की बड़ी बड़ी सभाएँ तथा सगठन होने लगे थे। लोग यह महसूस करने लगे थे कि अवध के जोत सम्बन्धी कानून ने किसानों को उनकी आशा के विपरीत भूमि पर अत्यन्त अल्प हक दिये हैं, उससे उनमें असन्तोष की वृद्धि हो गयी थी। मालगुजारी के प्रश्न पर गुजरात के किसानों ने तो एक बड़े पैमाने पर सघर्ष ही आरम्भ कर दिया था। कृषकों का यह सफल सघर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में हुआ प्रसिद्ध बारडोली का सत्याग्रह था। इस आन्दोलन में किसानों की विजय हुई तथा उनकी मालगुजारी में वृद्धि का प्रश्न सरकार ने छोड़ ही दिया। इस आन्दोलन तथा उसकी सफलता का हिन्दुस्तान की नव जाग्रिति पर बड़ा अच्छा असर पड़ा, विशेषतः किसानों के लिये बारडोली आशा, शक्ति, और विजय का प्रतीक बन गया। इस के पश्चात् ही युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने नेहरू जी के प्रस्ताव को मान्यता देते हुए 'जमींदारी प्रथा दूर होनी चाहिये' की घोषणा की। १९२६ में कांग्रेस के बम्बई-अधिवेशन में भी संयुक्तप्रान्त के इस प्रस्ताव ने मान्यता प्राप्त की।

१९२८ के व्यस्त वर्ष में अन्य आन्दोलन तथा जाग्रिति की भाँति, नौजवानों के आन्दोलन ने भी जोर पकड़ा। हर जगह युवक-संघ स्थापित हो रहे थे, तथा युवक-कान्फ्रेंसें की जा रही थी। युवकों में इस नयी चेतना का उदय कुछ तो धार्मिक आधारों तथा कुछ क्रान्तिकारी राजनैतिक विचार

धारा को लेकर हो रहा था। परन्तु इस नव-जागृति का आधार कुछ भी रहा हो, और उनका नियंत्रण किसी के हाथ में भी रहा हो, वे हिन्दुस्तान की तत्कालीन नवचेतना की प्रतीक थी। युवकों की ऐसी सभाये आमतौर पर तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर विचार करती थी, और साधारणतः उनका मुकाब इसी ओर होता था कि मौजूदा व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन कर देना आवश्यक है। प० जवाहरलाल जी ने युवक-आन्दोलन में भी विशेष रूप से भाग लिया, और कम से कम युक्त-प्रान्त के युवक-आन्दोलन के तो वे कर्णधार ही थे। यूरोप में युवकों की कर्तव्य-शक्ति देख कर, उन्हें विश्वास हो गया था कि देश की आजादी युवकों के हाथों ही स्थापित हो सकती है। युवकों का नया और जोशीला खून ही आदर्श के नाम पर बड़े बड़े त्याग कर सकता है। संसार की बहुत कुछ प्रगति का श्रेय युवकों को भी है। अतः प० जी ने सोशलिस्ट-युवक-कांग्रेस, बंगाल विद्यार्थी-परिषद्, और बर्मा-प्रान्तीय-युवक-संघ के अनुरोध पर, उनके वार्षिक अविवेशनों में समापति का पद ग्रहण कर, भारत के कोटि कोटि युवकों तक अपना संदेश पहुँचाया, और उनके सामने उनके कर्तव्य की तथा एक अनुपम कार्यक्रम की पृष्ठभूमि उपस्थित किया।

किसानों और मध्यवर्गीय युवकों की भोंति, इन्हीं दिनों मजदूर-संघों में भी काफी हलचल बढ़ गयी थी। सात-आठ साल पहले कायम हुई आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अब पहले से अधिक संगठित हो गयी थी, तथा उसके मेम्बरों की संख्या भी अब काफी अधिक हो गयी थी। वर्ग-चेतना (Class consciousness) की वृद्धि के फलस्वरूप औद्योगिक शहरों में अक्सर हड़तालें हो जाती थी। कपड़े की मिलों और रेलों में काम करने वाले मजदूर अधिक संगठित थे।

परन्तु इन मजदूर-संगठनों में अनेक दोष भी थे। अपनी जातीय प्रवृत्ति के अनुसार, हिन्दुस्तान के मजदूर-संघों को कायम होते देर न हुई कि वे एक दूसरे से ही होड़ लेने वाले तथा दुश्मनी रखनेवाले दलों में बँट गये। इनके विशेषतः दो दल हो गये। एक दल, जो 'दूसरी इन्टरनेशनल' के

पक्ष में था, तथा मजदूर-स्वार्थ-संघर्ष में दूसरे दल की अपेक्षाकृत सुधारवादी नरम मार्ग अपनाना चाहता था, के नेता श्री एन. एम. जोशी थे। दूसरा दल, जो कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर विशेष मुकाबला हुआ था, खुल्ला क्रान्ति द्वारा आमूल परिवर्तन के पक्ष में था। इन दोनों के बीच में कई किस्म की राये थी जिनमें मात्रा का मेद था, और जैसा कि आम जनता के संगठन में होता है, इसमें कुछ अवसरवादी व्यक्ति भी आ चुके थे।

नेहरू जी ने अन्य आन्दोलन की भाँति मजदूर-आन्दोलन में भी भाग लिया। ऐसे उत्साही तथा यशस्वी कार्यकर्ता को पाकर आन्दोलन को बल प्राप्त हुआ। मजदूर-कांग्रेस ने सन् १९२८ में नेहरू जी को अखिल भारतीय-मजदूर-संघ का समापति निर्वाचित किया। नेहरू जी के कार्य ने एक कड़ी बन कर कुछ समय के लिए अखिलभारतीय कांग्रेस-महासभा तथा मजदूर-संघ को परस्पर जोड़ दिया। पहली नवम्बर १९२६ को नागपुर में नेहरू जी की अध्यक्षता में मजदूर-संघ का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसके लगभग दो महीने पूर्व संयुक्त-प्रार्थीय मजदूर-संघ की सभा पंडित जी की अध्यक्षता में कानपुर में हुई थी।

देश-न्यायी मजदूर-आन्दोलन तथा हड़तालों से त्रस्त ब्रिटिश-पूँजीवादी सरकार ने अपना अनैतिक दमन-चक्र इस पर भी चलाने का निश्चय किया। बड़े-बड़े अंग्रेज मिल-मालिकों की इससे अत्यधिक हानि हो रही थी अतः इंग्लैंड की उच्चवर्गीय जनता में काफी असंतोष फैला था। फल-स्वरूप सरकार ने मेरठ षड़यन्त्र का झूठा दोषारोपण बढ़ कर, न्याय का ढोंग रचने के लिए देश के सम्पूर्ण मजदूर-नेताओं को अदालत के सामने पकड़ भेजवाया; यह मुकदमा करीब साढ़े चार साल चला। मेरठ के इन निर्दोष मुल्जिमों की मदद के लिए कांग्रेस ने पं० मोतीलाल के समापतित्व में एक जाच-कमेटी नियुक्त की। डा० अंसारी तथा जवाहरलाल जी भी इसके मेंबर थे। अपने इन निर्दोष माइनों की रक्षा के हेतु वे जनता के पास जाकर धन की याचना करते, तथा स्वयं भी जी जान से अभियुक्तों की पैरवी तथा अन्य कानूनी मदद करते।

राष्ट्रपति जवाहरलाल

धीरे धीरे गरमी और बरसात की ऋतु बीत कर ज्योंही शरद-ऋतु आयी, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों, कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुनने के कार्य में लग गयी। इस समय देश की राजनैतिक परिस्थिति विषम हो रही थी। कलकत्ता-कांग्रेस की घोषणा, कि नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यदि सरकार अपना शासन-सूत्र नहीं संचालित करती, तथा एक वर्ष के भीतर देश को औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं दे देती तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य-आन्दोलन के लिए कटिबद्ध हो जायेगी, की अवधि समाप्त हो चली थी, तथा सरकार ने इसे गीदड़-धमकी समझ कर इसकी और कोई ध्यान न दिया था। कांग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार अग्रे पूर्ण स्वराज्य-आन्दोलन आरम्भ होने ही वाला था। ऐसे संकट-काल में, राष्ट्र की विषम परीक्षा के समय, देश के नेतृत्व के काटों का ताज किसे पहनाया जाय यह प्रश्न सभी के समक्ष था। प्रान्तीय कमेटियों एक मत से अपने अडिग सेनानी गोंधी को अपने नेतृत्व की बागडोर देने को तैयार थीं; परन्तु गोंधी जी ने इसे मंजूर न किया। वे चाहते थे कि इस अवसर पर यह पद किसी ऐसे नवयुवक नेता को देकर सम्मानित किया जाये, जिस पर देश के जन-समुदाय तथा सभी दलों का पूर्ण विश्वास हो, तथा जिसके आगमन से युवक वर्ग में विशेष उत्साह, उत्तरदायित्व तथा आत्मगौरव के भाव का उदय हो। फलस्वरूप उन्होंने जवाहरलाल जी का नाम प्रस्तावित किया। उनके अनुरोध पर कांग्रेस ने लाहौर-अधिवेशन तथा अगले वर्ष के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा का राष्ट्रपति ४० वर्षीय नवयुवक नेहरू जी को निर्वाचित किया। गोंधी जी के उस

समय के व्यक्त विचारानुसार पं० जवाहरलाल नेहरू “स्फटिक मणिवत् पवित्र हैं, उनकी सत्यशीलता सन्देह से परे है, वे अहिंसक और अनिन्दनीय योद्धा हैं, राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित होगा।” नेहरू जी की जन-सेवाओं, तथा मजदूर, किसान और दुबकों का अदम्य उत्साह से नेतृत्व को देखकर गाँधी जी को उनकी गम्भीरता और धैर्यशीलता में पूर्ण विश्वास था, वे कांग्रेस के सभापति-पद के लिए उन्हें पूर्ण रूप से योग्य समझते थे। दिवान चम्पनलाल के शब्दों में उन दिनों “पं० जवाहरलाल जी साहस, चातुर्य और लावण्य की प्रतिमूर्ति जान पड़ते थे। कोई भी संस्था उनसे बढ़कर सभापति पाने की आशा नहीं कर सकती, और कोई भी कार्यवाहियों इतनी योग्यता से सम्पादित नहीं हो सकती थी।”

लाहौर-कांग्रेस के अधिवेशन का दिवस नजदीक आता जा रहा था। इस बीच घटनायें एक-एक कर के ऐसी घटती जा रही थीं, जिनसे मालूम होता था कि वे अपनी अज्ञात ताकत से खुद ही आगे बढ़ती जा रही हैं। हर व्यक्ति को यही मालूम होता था कि वह किसी बड़ी मशीन के अन्दर, जो बेरोक आगे बढ़ी जा रही है, सिर्फ एक पुरजे की तरह काम कर रहा है।

हिन्दुस्तान के भाग्य-सूर्य की बढ़ती हुई इस प्रखरता को रोकने की गरज से ब्रिटिश सरकार ने लार्ड इर्विंग को वायसराय बनाकर भारत भेजा था। इर्विंग ने चालाकी भरे शब्दों में शासन-सुधार का आश्वासन देकर सभी दलों के नेताओं की एक गोलमेज-काफ़ेस बुलायी। इर्विंग की यह घोषणा काफी कूटनीति पूर्ण थी, जिसका मतलब ‘बहुत कुछ’ और ‘कुछ भी नहीं’ दोनों ही लगाया जा सकता था। गोलमेज-काफ़ेस के निमंत्रण पर अनंक आशा लेकर कांग्रेस के गरम दल की ओर से गाँधी जी, पं० मोती लाल नेहरू तथा विठ्ठल माई पटेल, और नरम दलकी ओर से सर तेज बहादुर सप्रू आदि दिल्ली में उपस्थित हुए। सभी दलों के नेताओं की सर्व सम्मति से एक संयुक्त प्रस्ताव, कुछ अनिवार्य शर्तों के साथ वायसराय के समक्ष उपस्थित किया गया, जिसमें कहा गया था कि ये वे कम

से कम शक्त हैं, जिनके अमान्य होने पर सरकार और कांग्रेस का कोई भी सम्बन्ध न रहेगा। सभी दलों की एकता और एक स्वर सहमति की प्राप्ति के लिए, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को निर्मित करते समय तथा हस्ताक्षर करते समय, अपने सिद्धान्त पर भी आघात कर काफी नीचे गिरना मंजूर कर लिया था, इससे कांग्रेस के कुछ सदस्य नाराज भी थे। इस प्रस्ताव में स्वाधीनता की माँग को कांग्रेस द्वारा त्याग देना, चाहे सिर्फ कल्पना में और सिर्फ थोड़ा देर के ही लिए क्यों न हो, एक गलत और खतरनाक बात थी। जनता के समक्ष उसका मतलब यह हो सकता था कि कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता की बात, और कलकत्ता-कांग्रेस की महत्वपूर्ण घोषणा एक चाल मात्र थी, तथा शेर की लाल आँदों उनके कुछ सम्मानित नेता उसके आधार पर सरकार से निकट भविष्य में सौदा करना चाहते थे। वह कोई ऐसी सारभूत चीज न थी जिसके बिना जनता का परतन्त्र देश की वंद और गंदी हवा में सोंस लेना ही मुश्किल हो। नेहरू जी ने इस चीज को समझा और उन्होंने तथा सुभाष बाबू ने ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। इसके कारण ही नेहरू जी ने कांग्रेस के निर्वाचित समापति-पद से भी पद-त्याग कर देने की बात सोची, परन्तु अंत में गाँधी जो आदि नेताओं के अनुरोध से वे पद पर आसीन रह तथा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिया। इतना होने पर भी वायसराय ने प्रस्ताव को कोई विशेष महत्व न दिया। फलस्वरूप लाहौर-कांग्रेस के कुछ ही दिन पूर्व कांग्रेस और सरकार के बीच में समझौते का कोई आधार ढूँढ़ने की आखिरी कोशिश की गयी। तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विंग के साथ एक मुलाकात का इन्तजाम किया गया। इस मुलाकात में गाँधी जी और प० मोतीलाल जी कांग्रेस का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए उपस्थित थे, इसके अतिरिक्त जिन्ना, पटेल; तथा नरम दल की ओर से सर तेजबहादुर सप्रू आदि नेता भी उपस्थित थे। इस मुलाकात का कोई नतीजा न निकला और यह पाया गया कि दो प्रधान पार्टियों, सरकार और कांग्रेस, एक दूसरे से बहुत फासले पर खड़ी थीं। अतः अब इसके

सिवा कोई रास्ता न रहा कि कांग्रेस अपना कदम आगे बढ़ाये। कलकत्ते में दी हुई एक साल की अवधि खतम हो गयी थी, अब कांग्रेस का आदर्श हमेशा के लिए स्वाधीनता-घोषित करना था, और उसे प्राप्त करने के लिए जतरी कार्रवाइयों करनी थी।

२४ दिसम्बर २६२६ को भारतीय कांग्रेस का ४४ वीं वार्षिक अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में, रावी नदी के तट पर हुआ। इसके एक वर्ष पूर्व जिस स्थान पर पिता बैठा था उसी सम्मानित स्थान पर आज योग्य पुत्र आसीन हुआ था। जनता के सामने दृढ़ पिता ने सगर्व कहा था “जो काम पिता पूर्ण न कर सका उसे पुत्र पूरा करेगा।” निश्चय ही उनका संकेत भारत के भारी स्वराज्य की ओर था। वास्तव में जवाहर लाल जी ने ऐसा ही किया। कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, मंच से पं० मोतीलाल जी के समय नहीं, वरन् पं० जवाहरलाल जी की अध्यक्षता में, रावी के तट पर हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, रावी की गम्भीर लहरें, उसका गहरा नीला पानी इसके साक्षी हैं।

लाहौर-कांग्रेस का अधिवेशन पं० जवाहरलाल की अध्यक्षता में धूमधाम से सम्पन्न हुआ, जिसमें देश भर के हजारों नेता, प्रतिनिधि और दर्शक उपस्थित थे। कांग्रेस के उस सजे-सजाये विशाल मंडप और उस सम्पूर्ण क्षेत्र का नाम ‘लाजपत राय नगर’ था।

कलकत्ता-कांग्रेस के अवसर पर पं० मोतीलाल नेहरू की सवारी ३४ श्वेत अश्वों की गाड़ी पर निकली थी, परन्तु पं० जवाहरलाल की सवारी उनकी इच्छानुसार एक श्वेत अश्व पर निकली। ‘वन्दे मातरम्’ की गगन-भेदी ध्वनि में राष्ट्रपति जवाहरलाल घोड़े पर सवार हो चले। उनके पीछे प्रधान सेनानायक सरदार मंगल सिंह भी उसी रंग के अश्व पर आसीन थे। अपार जन-समूह ने अपने राष्ट्रनायक नेहरू का आल्हाद पूर्ण अपूर्व स्वागत किया। स्वयं पिता ने पुत्र पर फूलों की वर्षा की, तथा माता ने हार्पतिरेक में रूपों की वर्षा की। सभा-मवन के द्वार पर नव

युवक राष्ट्रपति को पुष्पहार पहनाया गया, वहीं उन्होंने स्वर्गीय लाला लाजपत राय की पत्नी से भेंट किया ।

सभा-भवन में पं० मोतीलाल ने हिन्दी में भाषण करते हुए, कांग्रेस-अध्यक्ष-पद पं० जवाहरलाल जी को प्रदान किया । उस समय विनोद पूर्वक मीठी हँसी और करतल ध्वनि के बीच उन्होंने कहा था, मैं नये अध्यक्ष महोदय को यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अत्यन्त नियमशील रूप से उनके आदेशों का पालन करूँगा । उस समय, 'राष्ट्र नायक जवाहर लाल चिर आयु हो' और 'वन्दे मातरम्' की जय-ध्वनि के बीच युवक शिरोमणि पं० नेहरू ने समापति का आसन ग्रहण किया । श्रीमती सरोजनी नायडू ने उन्हें फूलों की माला पहनाई ।

२६ दिसम्बर को कांग्रेस के इस महाअधिवेशन का पहला दिन था । लाखों व्यक्तियों के जन-समूह के बीच जवाहरलाल जी ने कांग्रेस का तिरंगा राष्ट्रीय झंडा लहराया । कांग्रेस-स्वयंसेवक-सेना के प्रधान, सरदार मंगल सिंह ने सैनिक ढंग से उनका अभिवादन किया ।

पं० जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा:—“मैंने अभी भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया है । यह भारत की स्वतंत्रता का चिन्ह है और भारत की एकता की निशानी है । याद रखिये जब एक बार यह झंडा फहराया जा चुका, तो यह तब तक न गिरने पाये जब तक देश का एक मनुष्य भी जीवित है ।... जिस झंडे के नीचे आप लोग यहाँ खड़े हैं वह किसी सम्प्रदाय का नहीं, बल्कि सम्पूर्ण देश का झंडा है । आज इस झंडे के नीचे जो लोग खड़े हैं, वे न तो हिन्दू हैं और न तो मुसलमान, बल्कि सब भारतीय हैं । भारत की स्वतंत्रता ही सब भारतीयों का प्रधान लक्ष्य है ।”

२६ दिसम्बर को इसी कांग्रेस के अधिवेशन में करतल ध्वनि के बीच उठकर उन्होंने अपना लिखित भाषण पढ़ा:—“गत ४४ वर्षों से यह राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) भारत की स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है । इस बीच महासभा ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावनाये भरी हैं,

और उन्हें गहन निद्रा से जगाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को आगे बढ़ाया है तथा उसे शक्तिशाली बनाया है। हम अपनी शक्तियों, और निर्वलताओं को भली भौति जानते हुए, अपने राष्ट्र के भविष्य को कुछ आशा और आशंका की दृष्टि से देख रहे हैं।”

“आज हमारे समक्ष गर्भार राष्ट्रीय प्रश्न और समस्याएँ उपस्थित हैं। संसार एक उथल-पुथलकारी दिशा में है, और उसी के परिवर्तन के फलस्वरूप एक नवयुग का उदय होने वाला है।”

“भविष्य के संबंध में कुछ कहना कठिन है, पर फिर भी हम थोड़े-बहुत निश्चित के साथ यह कह सकते हैं कि एशिया और भारतवर्ष संसार की भावी नीति निर्धारित करने में एक निर्णायक का कार्य करेंगे। यूरोपीय साम्राज्य के इने-गेने दिन ही रह गये।.. .. हमारे समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक और आर्थिक समानता का है। भारत को, यह समस्याएँ हल करने के लिए आवश्यक साधन ढूँढ़ने हैं। जब तक वह ऐसा नहीं कर लेता तब तक उसका राजनैतिक तथा सामाजिक संगठन सुदृढ़ नहीं हो सकता...।”

“मुझे धर्म और साम्प्रदायिकता से कोई प्रेम नहीं है। मुझे यह समझने में कठिनायी होती है कि राजनीतिक और आर्थिक अधिकार क्या किसी धर्म या वर्ग के मानने पर निर्भर होने चाहिए ..।”

इसके पश्चात् राष्ट्रपति नेहरू ने ब्रिटिश शासकों की अनीति और प्रतिज्ञा-भंग की ओर संकेत करते हुए कहा, कि उनके वादे तथ्यहीन, निम्नकोटि के तथा अस्पष्ट हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वे अपने को बाध्य नहीं समझते। औपनिवेशिक स्वराज्य केवल भ्रम-जाल है। दस वर्ष के लिए किये गये शासन-सुधारों से भारतीय जनता का बोझ पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया है। आज हमारे समक्ष केवल एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वाधीनता का। हम संकुचित राष्ट्रीयता या स्वाधीनता नहीं चाहते। हमारी इस पूर्ण स्वाधीनता का उद्देश्य अन्य राष्ट्रों से पृथक्

रहना नहीं है। हमारी पूर्ण स्वाधीनता का अर्थ ब्रिटिश साम्राज्य से संबंध विच्छेद करना है।”

“मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मैं सोशलिस्ट और रिपब्लिकन समाजवादी हूँ, मेरा विश्वास राजाओं, जमींदारों और पूँजीपतियों की सत्ता में नहीं है। हमारी ३ मुख्य समस्याएँ हैं; अल्प संख्यक जातियों, देशी राज्य और श्रमजीवी (मजदूर और किसान)। हमें अल्प संख्यक जातियों को अपने शब्दों और कार्यों से यह दृढ़ विश्वास करा देना चाहिए कि उनकी सभ्यता और संस्कृति की यहाँ पूरी रक्षा होगी। देशी रियासतें सम्पूर्ण राष्ट्र की उन्नति में बाधक हैं... . ब्रिटिश शासकों ने अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए इन राजाओं का सृजन किया है। तीसरी समस्या श्रमजीवियों की देश की सबसे बड़ी समस्या है। भारत के किसानों और मजदूरों की दशा जब तक न सुधरेगी तब तक देश की दशा सुधरनी भी असम्भव है।”

“हम अपने छोटे-छोटे झगड़े भुलाकर राष्ट्रीय कार्य-क्रम को पूरा करने में लग जायें। देश-भक्ति और देश-सेवा का पुरस्कार है यातना, कारागार और मृत्यु। परन्तु इससे आपको इतना संतोष होगा कि आपने अपना थोड़ा सा कर्तव्य-पालन करके प्राचीन भारत को, जो सदा दुबा है, मुक्त किया, और मानव-समाज को दासता से छुड़ाने में सहयोग दिया।”

दूसरे दिन कांग्रेस के खुले अधिवेशन में महात्मा गांधी ने 'भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव उपस्थित किया। पं० मोतीलाल ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। अल्प विरोध के पश्चात् भी वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। इसके पश्चात् कांग्रेस में एक नयी आशा-वादिता और दृढ़ता दिखलायी देने लगी।

सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन

पं० जवाहरलाल द्वारा लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा के पश्चात् भारतीय कांग्रेस एक नये प्रयत्न और संघर्ष के लिए तैयार हुई, जो पहले के सभी आन्दोलनों की अपेक्षा अधिक गम्भीर तथा अभूत-पूर्व था। भारत की राष्ट्रीय मॉर्गो में पहले स्वशासन, आत्मनिर्णय तथा उत्तरदायी शासन या औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करने की बातें प्रधान थी, पर लाहौर-कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता तथा उसकी प्राप्ति के लिए सरकार से अहिंसात्मक युद्ध की जोरदार घोषणा की गयी थी, जिससे जनता में एक नवीन लक्ष्य के लिए, एक नवीन आशा-लाहर और आकांक्षा का संचार हुआ। सम्पूर्ण देश नवीन जाग्रिति के उत्ताल तरगाधातों से आन्दोलित हो उठा, राष्ट्र ने एक नये व्रत और संकल्प के साथ संघर्ष की तीसरी अवस्था में प्रवेश किया।

राष्ट्रपति नेहरू ने जनता-जनार्दन को स्वतंत्रता के इस नवीन संग्राम में सम्मिलित हो, अपना सहयोग देने के लिए आह्वान किया। कांग्रेस ने स्वतंत्रता-दिवस मनाने के लिए २६ जनवरी तिथि निश्चित की। उस दिन बहुसंख्यक देश-वासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता के युद्ध में सहयोग देने की पवित्र शपथ ली। कोटि-कोटि कंठ एक साथ फूट पड़े, “भारत के हित के लिए, बलिदान और आत्मत्याग के महान स्फूर्तिदायक उदाहरणों को सामने रखते हुए, हम स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा को दुहराते हैं, और भारतवर्ष जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक अपनी लड़ाई जारी रखने का निश्चय करते हैं।”

गांधी जी को इस दिवस के प्रदर्शन से आवश्यक बल मिला, और

जनता की नाड़ी ठीक तरह से पहचानने के कारण उन्होंने समझ लिया कि संघर्ष और आन्दोलन के लिए यह समय अनुकूल है। भारतीय अब पहले से अधिक अनुशासित, संयमित और दृढ़ प्रतिज्ञा हो गये थे, और पूर्ण रूप से अहिंसा के महत्व को समझने लगे थे। इधर नेहरू जी जन-समुदाय के सन्त आन्दोलन के आर्थिक पहलू पर चोर देते हुए, उसके महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यक्रम तथा उससे लाभ पर प्रकाश डाल रहे थे, जिससे किसान और अन-जीवियों ने भी एक नवीन शक्ति और उत्साह से उनका साथ देने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त इस बार के आन्दोलन में बहुसंख्यक महिलाओं ने भी भाग लेना निश्चित किया था। विध्वंसार्थी आर्थिक नर्दी और उनके अनित्यकारी प्रभाव से जनता शानकों के प्रति और भी असन्तुष्ट हो गयी थी। इन सभी कारणों ने आन्दोलन को विशेष शक्ति प्रदान किया।

इस विकट परिस्थिति में असन्तुष्ट जनता, जिसने परतंत्रता का जुआ अपने कंवे से फेंक देने का निश्चय कर लिया था, तथा शासकों में भयंकर संघर्ष आरम्भ हुआ। एक ओर शक्तिशाली सरकार अपने नवान्दोलन के नाय तैयार थी, और दूसरी ओर गांधी और नेहरू के अहिंसात्मक चेष्टा अपने अमूल्य प्राणों की बाजी लगाये हुए छापी खोले खड़े थे।

सरकार शीघ्र ही संकट की गुरुता समझ गयी और वह उसके निवारण के प्रयत्न में लग गयी। उसने गांधी जी को समझाने बुझाने की प्रयत्न किया, और वह फिर अत्यन्त घाटे और दिखावे देकर कांग्रेस को बन्धे की तरह बहलाने की कोशिश करने लगी। 'परन्तु स्वतंत्रता के बीर सेनानी कांग्रेसी अब उन सूटी मृग-मरीचिका के पीछे पड़ने वाले नहीं थे, उन्हें उन सूटी बातों का काफी अनुभव हो चुका था। आन्दोलन बढ़वाने की भांति द्रुत गति से बढ़ता जा रहा था, लगता था उसकी विशाल जिद्द वृद्धि साम्राज्यवाद को चाट कर ही दम लेगी।'

अन्य बातों के अतिरिक्त ननक-मंग करना इन आन्दोलन का प्रमुख अंग था। सरकार ने ननक पर कर लगा दिया था। इसमें उमका

उद्देश्य भारत के चीथड़े लपेटे दरिद्रनगरण के झोपड़ों से भी बलपूर्वक पैसा खींच लाने का था। इससे ब्रुत होकर निकली झोपड़ों के आहों की आग सारे हिन्दुस्तान के दिल को जलाने लगी। गांधी ने कानून-भंग कर जनता को स्वयं नमक बनाने का आदेश दिया। नदियों की भीति कोटि-कोटि पग समुद्र की ओर उस आजा-पूति के लिए बढ़ चले। गांधी जी ने स्वयं सावरमती-आश्रम से दाण्डी की नमक-कर-भंग करने की ऐतिहासिक यात्रा आरंभ की। अपार जन-समूह सरकार के नियमों की सविनय-अवज्ञा करने के लिए उनके साथ चल पड़ा।^१

इधर गांधी जी की अनुपस्थिति में, सरकार के बढ़ते हुए क्रोध तथा नेताओं के प्रति वक्र-दृष्टि को देखकर, अहमदाबाद में अ० मा० कांग्रेस महासभा की बैठक हुई। इसमें सभा ने सभी मुख्य नेताओं की शीघ्र ही गिरफ्तारी की आशंका प्रकट की, तथा गिरफ्तारी के पश्चात् कांग्रेस के बचे हुए सदस्यों का क्या कार्य होगा तथा वे किस प्रकार आन्दोलन को संगठन करेंगे इसे निर्धारित किया। इस प्रकार अंतिम तैयारी कर के कांग्रेस-कमेटी के प्रत्येक सदस्य ने अनिश्चित काल के लिए एक दूसरे से विदा मागी। इस समय सभी के हृदय में देशभक्ति की लहरें हिलोरे ले रही थी। सभी नेताओं ने युद्ध में जाते हुए सैनिकों की भांति अपने-अपने क्षेत्रों के आन्दोलन-संचालन के लिए एक दूसरे से विदा लेकर प्रस्थान किया; दूसरे शब्दों में, जैसा कि श्रीमती सरोजनी नायडू ने कहा है, “जेल-यात्रा के लिए विस्तर बंधने को जल्दी-जल्दी चल दिये।”

६ अप्रैल १९३० को, जलियाँवाले बाग की घटनाओं के प्रतिवर्ष ननाये जाने वाले स्मरण-पर्व के दिन, गांधी जी ने सर्वप्रथम दांडी में समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक-कानून-भंग किया। इसके तीन चार दिनों बाद सम्पूर्ण कांग्रेस-संगठनों को अपने-अपने क्षेत्रों में नमक-कानून तोड़ने की आज्ञा दे दी गयी। हर एक प्रांत में सविनय-अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ हो गया था। ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने बिजली का चदन दबा दिया हो। सम्पूर्ण देश में—शहरों और गाँवों के कोने-कोने में

—नमक-कर-भग-आन्दोलन बड़वाग्नि की तरह फैल गया । गांधी जी की इस अद्भुत नेतृत्व-शक्ति का ध्यान कर सचमुच आश्चर्य होता है । नेहरू जी के शब्दों में, “हमे ताज्जुब होता था कि इस व्यक्ति (गांधी जी) में लोगों पर असर डालने और उनसे संगठित रूप में काम लेने की कितनी अद्भुत सक्ति तथा शक्ति है ।”

नेहरू जी भी अपने प्रान्त, युक्तप्रान्त में जनता को नमक-कर-भग करने के लिए उत्साहित करने लगे । भारतीय संग्राम के इस दौर में नेहरू-परिवार के आत्मत्याग बड़ी वीरता से हुए । उनके पिता, उनकी माता, पत्नी और बहनें सब राष्ट्रीय संग्राम की प्रथम पक्ति में थी । उन्हें जेल हुई, वे लाठी प्रहारों की चपेट में आये, उनके सामान नीलास हुए तथा कितने ही प्रियजन ससार से उठ गये; परन्तु फिर भी उन लोगों ने संग्राम जारी रखा ।

गांधी जी द्वारा प्रयुक्त शब्दों में, “दानवीय सरकार” अब अपनी पूर्ण क्रूरता के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन पर टूट पड़ी थी । उसने कांग्रेस को एक गैरकानूनी सस्था घोषित कर दिया और कांग्रेस का धन-कोष जब्त कर लिया । जनता के समस्त नागरिक-अधिकार समाप्त हो गये; और अत्यन्त कठोर कानूनों (आर्बिनेन्सो) का शासन आरम्भ हुआ ।

पं० जवाहरलाल नेहरू भी अधिक दिन तक स्वतंत्र न रह सके, और १४ अप्रैल १९३० को, जब वे रेलगाड़ी से रायपुर की एक कांग्रेस में शामिल होने के लिए जा रहे थे, गिरफ्तार कर लिए गये । उसी दिन जेल में उनपर मुकदमा चला और नमक-कानून-भग करने के अपराध में उन्हें ६ मास के कारावास का दंड हो गया । उन्हें अपने गिरफ्तार होने का आभास पहले ही लग गया था, अतः उन्होंने अपने पिता को कांग्रेस का स्थानापन्न अव्यक्त नियुक्त कर दिया था ।

सहसा ५ मई को गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गये । उनकी गिरफ्तारी के बाद समुद्र के पश्चिमी किनारे पर नमक के कारखानों और गोदामों पर धावे किये गये । उस समय पुलिस ने जिस बेरहमी से

आंदोलनकारियों का दमन किया, उसने समस्त भारतीयों के विद्रोही हृदय में विदेशी शासकों के प्रति घृणा का बीज और मो गहरा बो दिया ।

३० जून को बम्बई से लौटने पर ५० मोतीलाल जी भी गिरफ्तार कर लिए गये, तथा उन्हें ६ महीने की सजा दे दी गयी । जवाहरलाल के साथ ही मोतीलाल जी भी नैनी-जेल में रखे गये । इस बार जवाहरलाल जी को जेल की एक ऐसी तग और गदी कोठरी में रखा गया था, जो 'कुत्ताघर' के नाम से प्रसिद्ध थी । पहले इसमें खास तौर पर खतरनाक कैदी रखे जाते थे, और अब भी एक खास प्रकार के 'खतरनाक कैदी' से उसे आबाद किया गया था, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उलटने के 'कुचक्र' में लगा था । उन्हें अन्य कैदियों के सम्पर्क से हमेशा दूर रखा जाता था जिससे कहीं वे उन्हें 'वरगलाने' में सफल न हो ।

नेहरू जी इस जीरव और एकान्त समय को काटने के लिए निवाड़ बुनते, सूत कातते तथा सुबह, मुँह अँधेरे ही उठ कर कसरत करते एवं दौड़ कर जेल के अहाते का चक्कर लगाते थे । पिता के आगमन के पश्चात् उनका एक दैनिक कार्य उनकी तन-मन से सेवा करना भी हो गया था ।

यरवदा-सन्धि-धर्चा तथा करबंदी-आन्दोलन

कांग्रेस और सरकार के बीच बढ़ती हुई तनातनी को देखकर, तथा एक पत्र-प्रतिनिधि के समक्ष गिरफ्तारी के पूर्व दिया हुआ मोतीलाल जी का बयान पढ़ कर, जिसमें यह संभावना प्रकट की गयी थी कि सरकार यदि कांग्रेस की कुछ शर्तें मान ले तो कांग्रेस सत्याग्रह को वापस ले सकती है; सर तेजबहादुर सप्रू तथा जयकर साहब कांग्रेस और सरकार के बीच सुलह कराने का प्रयत्न करने लगे। उसके लिए उन्होंने तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विङ्ग से पत्रव्यवहार किया तथा इसी उद्देश्य से गांधी जी से मिले भी। २७ जुलाई को इसी उद्देश्य से श्री सप्रू और जयकर महोदय नैनी-जेल में पिता-पुत्र से उनकी इस विषय में राय जानने के लिए मिले, परन्तु दोनों ही व्यक्तियों ने बिना गांधी जी से मिले और उनकी राय जाने अपना कोई निश्चय प्रकट करने में असमर्थता प्रकट की।

वायसराय की सहमति तथा सर सप्रू के अनुरोध पर जवाहरलाल जी, मोतीलाल जी तथा डा० सैयद महमूद यरवदा-जेल जाकर गांधी जी से इस विषय पर परामर्श करने को तैयार हो गये। १० अगस्त को एक स्पेशल ट्रेन से ये तीनों व्यक्ति पूना के यरवदा-जेल में पहुँचाये गये। इस भय से कि कहीं गांधी जी के पास रहने से उन लोगों का मस्तिष्क फिर न जाये, और वे सरकार के विरुद्ध नये प्रकार के षडयंत्र की बातचीत न करने लगे, उन्हें गांधी जी की बैरक से अलग ही रखा गया। पं० मोतीलाल जी इससे बहुत ही नाराज हुए थे, तथा उन्होंने समझौते की किसी भी बात पर वार्तालाप तथा विचार करने से साफ इन्कार कर दिया था, परन्तु

बहुत अनुरोध के पश्चात् उन्होंने इस विषय पर अपने साथियों से वार्तालाप करना मंजूर कर लिया ।

उन दिनों सरदार पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू तथा जयराम दास दौलत राम आदि नेता भी यरवदा-जेल में हों थे । इन सभी व्यक्तियों ने सम्मिलित रूप से इस विषय पर विचार किया, तत्पश्चात् अपनी वे कम से कम शर्तें सरकार के समक्ष भेजी जिनकी मान्यता पाये बिना असहयोग-आंदोलन बढ़ होना असम्भव था । सरकार ने उन शर्तों पर विशेष ध्यान न दिया फलस्वरूप आंदोलन जारी रहा, तथा सर सप्रू एवं जयकर साहब के सभी किये कराये प्रयत्न पर पानी फिर गया । १६ अगस्त को ये तीनों व्यक्ति फिर नैनी-जेल को लौट गये ।

जेल के गंदे वातावरण तथा अत्यधिक शारीरिक और मानसिक श्रम के फलस्वरूप पहले से ही खराब प० मंतीलाल जी का स्वास्थ्य और भी गिर गया, अतः ८ सितम्बर को दस समाह के पश्चात्, जर्जरित काय उस बूढ़े सिंह को जेल के पिंजड़े से मुक्त किया गया । इसके एक मास पश्चात् ६ महीने का दण्ड पूर्ण हो जाने के कारण, प० जवाहरलाल जी भी छोड़ दिये गये ।

कोई भी आंदोलन देश के कृषकों के सहयोग के बिना पूर्ण सफल होना कठिन था । जेल से मुक्त होने के पश्चात् नेहरू जी ने इस ओर ध्यान दिया । उन्होंने कृषकों के बीच जाना तथा उन्हें आंदोलन के लिए तैयार करना आरम्भ कर दिया । युक्तप्रात में इस नये उमड़ते संघर्ष का आर्थिक आधार कर-बन्दी-आंदोलन रख कर उन्होंने कृषकों को पूर्ण रूप से अपनी ओर कर लिया था । कर-बन्दी-आंदोलन से अपने ही देश-भाइयों, किसान तथा जमींदार वर्ग, के बीच बढ़ने वाले द्वेष तथा घृणा को रोकने, तथा इस विषम परिस्थिति से वर्ग-संघर्ष की भीषण आग कांग्रेस के भीतर न लगाने देने के उद्देश्य से नेहरू जी ने किसान और जमींदार दोनों को ही कर न देने के लिए उत्साहित किया ।

नेहरू जी ने घूम-घूम कर गाँवों में इस विषय का सन्देश पहुँचाया

तथा किसानों को इस कर-बंदी-आंदोलन के लिए संगठित किया। नेहरू जी ने प्रयाग में भी किसान प्रतिनिधियों की एक बृहत् सभा की, तथा इस सदेश को उन तक पहुँचाते हुए अपना भाषण दिया। इस सभा में विभिन्न गाँवों के १६०० प्रतिनिधि मौजूद थे। उस सभा के पश्चात् एक और ग्राम-सभा में भाषण देकर जब वे तथा उनकी पत्नी, पिता को देखने के लिए मोटर द्वारा शीघ्रतापूर्वक अपने निवास-स्थान को लौट रहे थे, उसी समय उनकी मोटर रोक कर उन्हें (जवाहरलाल जी को) फिर से गिरफ्तार कर लिया गया; और अपनी रिहाई के ठीक एक सप्ताह बाद फिर वे अपने उसी चिर-परिचित नैनी-जेल में सरकार की कृपा से पहुँचा दिये गये। न्याय का ढोंग करनेवाली स्वेच्छाचारी सरकार ने उनके भाषण को आपत्तिजनक करार कर उन्हें इस बार २ साल की सजा दे दी।

नेहरू जी की इस गिरफ्तारी से कर-बंदी-आंदोलन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। जो किसान पहले इसे आरम्भ करने से डरते थे उन्होंने भी अपने प्रिय नेता को जेल की सींखचों के अन्दर देखकर, क्रोध से उन्मत्त हो पूर्ण शक्ति से इस आन्दोलन को आरम्भ कर दिया।

जब दृष्ट ५० मोतीलाल को पुत्र की गिरफ्तारी की सूचना मिली तब उन्हें काफी कष्ट हुआ, और उसी समय उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा कि “मैंने यह निश्चय कर लिया है कि अब मैं भी बीमार की तरह पड़ा न रहूँगा। अच्छा बन कर मैं अब एक नौजवान की तरह कार्य करूँगा तथा इस प्रकार बीमारी को आत्मसमर्पण न करूँगा।” उनकी इच्छानुसार १४ नवम्बर को देश भर में जवाहरलाल जी की वर्ष गाँठ एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनायी गयी; सार्वजनिक सभाओं में जवाहरलाल के भाषण के वे अंश पढ़े गये जिन पर आपत्ति कर उन्हें सजा दी गयी थी। सरकार को इन सभाओं में भी षड़यन्त्र की अनोखी गंध मालूम पड़ी, फलस्वरूप उनमें उपस्थित जनता पर पुलिस के क्रूर अत्याचार हुए, गिरफ्तारियों का एक बार फिर बाजार गर्म हो गया।

इन आन्दोलनों के फलस्वरूप राजनैतिक कैदियों पर जेल में अत्याचार

बढ़ गये। जेल के अधिकारी उनसे कठिन से कठिन तथा गंदा से गंदा कार्य लेते, उन्हें कुत्तों को भी न दिये जाना वाला भोजन देते। वेत की मार तथा जेल के अन्य क्रूर तरीकों द्वारा उन्हें यातना पहुँचायी जाती, तथा उनसे यह प्रतिज्ञा कराने का प्रयत्न किया जाता कि छूटने के पश्चात् वे इस प्रकार के किसी भी राजनैतिक आन्दोलन तथा संगठन में भाग न लेंगे। कार्यकर्त्ताओं पर होने वाले इन अत्याचारों की खबर सुनकर सभी कांग्रेसी नेता बड़े दुःख तथा चिन्तित थे। इन अत्याचारों के विरोध में पं० जवाहरलाल जी ने तथा उनके कुछ अन्य साथियों ने ७२ घंटे का अनसन किया, फलस्वरूप डर कर युक्तप्रान्तीय सरकार ने जेलों में राजनैतिक कैदियों को बेंत न लगाये जाने, तथा दुर्व्यवहार न करने की आज्ञा मेजी।

पति के गिरफ्तार होने के पश्चात् से ही बीमार कमला देवी ने भी सत्याग्रह-आन्दोलन में विशेष रूप से भाग लेना आरम्भ कर दिया था। वे दिन भर धूप में दूकानों के समक्ष पिकेटिंग करती तथा महिला-संगठन के लिए कार्य करती थी। फलस्वरूप सत्ता से मदान्व सरकार ने महिलाओं को भी गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया। देश-भक्ति का गीत गाती वे महिलाये प्रसन्नतापूर्वक जेल जाती थी। श्रीमती कमला नेहरू की गिरफ्तारी के समय वहाँ उपस्थित एक पत्रकार ने जेल-यात्रा के पूर्व उनसे अपना सदेश माँगा, तब उन्होंने अपने स्वभावानुकूल ही प्रसन्नतापूर्वक कहा—“आज मुझे असीम प्रसन्नता है, तथा इस बात का गर्व है कि मैं अपने पति के पद-चिन्हों पर चल रही हूँ, मुझे आशा है कि आप लोग इस ऊँचे झंडे को नीचे न झुकने देंगे।”

बीमार पं० मोतीलाल ने जब इस समाचार को सुना तो उन्होंने मर्माहत हो उसी समय प्रयाग के लिए प्रस्थान कर दिया; वे पं० जवाहरलाल जी से जेल में मिले। पिता के गिरे हुए स्वास्थ की यह गम्भीर दशा को देखकर पं० जवाहरलाल अत्यन्त चिन्तित हुए।

उन्हीं दिनों जब हमारे देश के राष्ट्रीय नेता और कार्यकर्त्ता जेलों में

सड़ रहे थे, हमारे ही देश के कुछ उच्चश्रेणी के नरमदलीय नेता, लन्दन की गोलमेज कांफ्रेंस में, ब्रिटिश शासकों के 'सहयोग' से, भारत के लिए एक नये शासन-विधान के निर्माण की बात सोच रहे थे। जब भारत के सब सच्चे तथा त्यागी नेता जेल में थे, कुछ प्रतिक्रियावादी नेता अपने को देश और जनता का वास्तविक प्रतिनिधि बतलाकर, अपने निजी स्वार्थों की रक्षा के निमित्त देश भक्ति की ऑड लेकर, ब्रिटिश-शासन बनाये रखने के लिए लन्दन में शासकों से मिल कर देश के विरुद्ध कुचक्र रचने में सलग्न थे। परन्तु चतुर ब्रिटिश-शासक जानते थे कि नेहरू तथा गंधी की सहमति के बिना उनकी नये विधान बनाने और उसके लागू करने की सब चालें व्यर्थ हो जायेगी, अतः उन्होंने कुछ नरम रुख अख्तियार कर कांग्रेस-कार्यसमिति के कुछ व्यक्तियों को छोड़ना आरम्भ कर दिया, जिससे वे इस नई दिशा तथा गोलमेज-परिषद की बातों पर पूर्ण रूप से विचार कर सकें, तथा इस 'शुभ' कार्य में सरकार का साथ दे सकें।

१९३१ की जनवरी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इसी विषयक घोषणा पर विचार करने के लिए कांग्रेस-कार्यसमिति की बैठक हुई, जिसमें पं० मोतीलाल जी की इच्छानुसार यह तय हुआ कि कांग्रेस इस झूठी मृग मरीचिका में पड़कर सरकार के विरुद्ध छेड़ी गयी अपनी लड़ाई को बंद न करेगी।

२६ जनवरी को राष्ट्र भर में स्वतंत्रता-दिवस का प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया। सम्पूर्ण देश में सभाये की गयी तथा उनमें स्वाधीनता के प्रस्ताव का जोरो के साथ समर्थन किया गया। उस दिवस के इन प्रस्तावों को 'स्मारक प्रस्ताव' भी कहते हैं।

पं मोतीलाल का देहावसान

२६ जनवरी के उस महादिवस के दिन, पिता की हालत चिन्ता-जनक होने के कारण, पं० जवाहरलाल ६ महीने का बंदी जीवन बिताने के पश्चात् सरकार द्वारा छोड़ दिये गये । २६ दिन का जेल जीवन व्यतीत करने के पश्चात् श्रीमती कमला नेहरू भी मुक्त कर दी गयी ।

२६ जनवरी को ही गाँधी जी भी पूना के प्रसिद्ध यरवदा-जेल से सरकार की नयी घोषणा के विषय में विचार करने के लिए, अन्य कार्य समिति के मेम्बरो के साथ छोड़ दिये गये । बम्बई में, छूटने के पश्चात् अपने दर्शन करने के लिए आये एक विशाल जनसमूह के समक्ष भाषण देने के पश्चात् वे अस्वस्थ पं० मोतीलाल को देखने प्रयाग पहुँचे । पं० मोतीलाल जी उनके आगमन, तथा जीवन-यात्रा समाप्त करने के पूर्व एक बार उनके दर्शन, एवं अन्तिम बार उनसे वार्तालाप करने के लिए आतुरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । गाँधी जी के आगमन पर उन्हें अत्यन्त प्रसन्नता हुई । देश के सभी बड़े बड़े नेता, युक्तप्रान्त के उस नर पुंगव के अन्तिम दर्शन तथा परामर्श के लिए आने लगे । इन मिलने वालों का, बोलने में असमर्थ होने के कारण, वे आँखों की एक स्वर्गीय चमक से ही स्वागत करते । सताप में डूबे जवाहरलाल पिता को निर्निमेष, भाव शून्य आँखों से देखते रहते । उन्हीं के शब्दों में “एक जर्जरित सिंह की तरह, जिसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया हो, वे बैठे थे, लेकिन उस हालत में भी उनकी शान शैरो जैसी ही थी ।”

मोतीलाल जी धीमे स्वर से अपने मित्रों से बात करते । परन्तु जब वे

थोले न पाते तब अपने मन के भाव कागज पर लिख कर व्यक्त करते थे । उस समय उन्होंने महात्मा जी की ओर देग्व कर कहा था, “महात्मा जी मैं जा रहा हूँ, और स्वराज्य न देख सकूँगा । पर मैं जानता हूँ कि आपने स्वराज्य प्राप्त कर लिया है और शीघ्र ही उसका उपयोग करेंगे ।” मोती लाल जी के अन्तिम विचार भी भारतीय स्वतंत्रता विषयक ही थे ।

पिता की हालत चिन्ताजनक होने पर, डाक्टरों की राय से एकसरे कराने तथा विधिवत उपचार करने के लिए जवाहरलाल उन्हें लेकर लखनऊ पहुँचे । गाँधी जी उस समय भी उन लोगों के साथ थे । ६ फरवरी को प० मोतीलाल नेहरू ने इस मौक्तिक जगत से प्रयाण कर दिया । उसी दिन शव, विधिवत् राष्ट्रीय झंडे से लपेट कर प्रयाग लाया गया । अन्येष्टि क्रिया सम्पन्न करने के लिए उनकी गंगा-यात्रा के अवसर पर लाखों व्यक्ति अपनी अन्तिम श्रद्धान्जलि अर्पित करने के लिए उपस्थित थे । [जाड़े के दिन थे, सव्या का अन्धकार मुख पर कालिल लगाए सिसक रहा था ! चिर शान्ति की गोद में चिता की ऊँची ऊँची लपेटों ने उस पवित्र शरीर को भस्म कर दिया, उस स्थान पर बची रह गयी थोड़ी सी राख, जो पुत्र के लिए, सवधियों के लिए तथा सम्पूर्ण भारत के लिए कर्मठता, साहस और त्याग की दिव्य विभूति हो गयी थी । क़ातर गाँधी ने रोकर, अपने अभिन्न मित्र के प्रति उस दिन अपार जन-समूह ने बीच कहा था “मोतीलाल जी के चले जाने से मैं एक विधवा स्त्री की मोंति पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ ।”

१ किसी देश के नेताओं का बलिदान विफल नहीं होता । उनका अवसान राष्ट्रीय स्वतंत्रता के राजपथ पर स्थित मील के पत्थरों सा होता है, जिस पर विश्वास के साथ दृढ़ कदम बढ़ाती हुई कोटि-कोटि विद्रोही जनता, एक दिन अपने अमीष्ट लक्ष्य पर अवश्य पहुँच जाती है; और उसके पश्चात् पीछे मुड़ कर वह बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ उन अपने आप में सजीव पत्थरों की ओर देखती है, जिसने उन्हें ठीक ठीक राह बतलायी, और अत तक घुटते हुए दम से उनका नेतृत्व करते हुए उन्हें आशा और दिलासा दिलायी ।

गाँधी-इर्विङ्ग-पैक्ट और उसके पश्चात्

सरकार और लिबरल नेताओं के अनुरोध से, तथा देश की असहयोगी जनता को आन्दोलन की क्लान्ति से कुछ समय के लिए राहत देने के विचार से, गाँधी जी ने तत्कालीन वायसराय इर्विङ्ग से मिलकर शान्ति-शर्तों पर वार्ता करने की अपनी सहमति दे दी, यद्यपि उन्हें इससे विशेष लाभ की आशा न थी।

गाँधी जी इस विषय पर वायसराय से वार्तालाप करने दिल्ली पहुँचे। वे कई बार इर्विङ्ग महोदय से मिले परन्तु समझौते के विषय में कुछ निश्चय न हो पाता था। इर्विङ्ग महोदय असहयोग तथा सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन के विपक्ष में थे, और उसे पूर्णतः बंद कर देने का वादा कराना चाहते थे, जब की गाँधी जी स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि वे सविनय अवज्ञा-आन्दोलन हमेशा के लिए बन्द कर देने के लिए तैयार नहीं हो सकते। हाँ! सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाने पर वे उसे स्थगित अवश्य कर देंगे। वायसराय महोदय इससे सहमत न थे।

एकाएक गाँधी-इर्विङ्ग-वार्तालाप का क्रम टूट गया तथा इर्विङ्ग ने इस विषय में आगे बात करने से इन्कार कर दिया। कार्यकारिणी के मेम्बरों को पूर्ण रूप से यह विश्वास हो गया कि सरकार और कांग्रेस के बीच अब समझौता होना असम्भव है। अतः कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गयी, जिसमें यह निश्चय किया गया कि गाँधी जी की इस विषय में असफलता के पश्चात् वे लोग अपने-अपने प्रान्तों में किस प्रकार भावी आन्दोलन का संगठन तथा संचालन करेंगे। उन्होंने भावी कार्य की रूपरेखाओं और सविनय-अवज्ञा पर विचार विनिमय किया। कार्यकारिणी द्वारा इतनी जल्दी

इस विषय पर निश्चय करने का प्रधान कारण यह भी था कि सभी व्यक्ति यह पूर्ण रूप से जानने थे कि गाँधी-इर्विङ्ग-बाता की असफलता घोषित होने के साथ ही वे सभी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। ऐसी अवस्था में जनता तक उनके भारी कार्यक्रम का संदेश जल्द से जल्द पहुँचा देना आवश्यक था।

परन्तु कार्यसमिति की धारणा के विपरीत, ४ मार्च की रात को गाँधी जी वायमगव के यहाँ बुलाये गये और वे जब वहाँ से लौटे तब समझौता हो गया था। सविनय-आन्दोलन स्थगित कर देने का उन्होंने वादा कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू उस समझौते की शर्तों को कांग्रेस की नीति के विपक्ष में समझकर इसके बहुत खिलाफ थे, परन्तु गांधीजी के समझाने पर वे वेमन से मान नये। उन्होंने नेहरू जी को बतलाया कि इस समझौते से कांग्रेस की नीति—पूर्ण स्वराज्य पर कोई आघात नहीं हुआ है।

समझौते के फलस्वरूप असहयोग तथा अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले कैदी छोड़ दिये गये। परन्तु गांधीजी के बहुत परिश्रम के पश्चात् भी सरकार आतंकवादी कैदियों को छोड़ने तथा उनकी मजा घटाने के लिए गर्जी न हुई। गांधीजी के विरोध के पश्चात् भी भगतसिंह आदि क्रांतिकारियों को फाँसी दे दी गयी।

समझौते के कुछ दिन पश्चात् ही अ० मा० कांग्रेस महासभा का अधिवेशन कराची में वल्लभभाई पटेल के समापतित्व में हुआ। कराची के मुख्य कार्यक्रम में दिल्ली-समझौता को मान्यता देने, तथा गोलमेज परिषद् के विषय में विचार-विनिमय करने का प्रस्ताव था। कार्य-समिति ने इसे पास कर दिया। नेहरू जी के लिए यह कठिन अवसर था, वे दिल्ली-समझौते को आपत्ति-जनक तथा गोलमेज काफ़ेस को बेकार समझते थे, परन्तु गांधी जी की आज्ञा से अनेक मानसिक संघर्षों के पश्चात् भी अंत में उन्होंने उस पर अपना हस्ताक्षर कर ही दिया।

इन प्रस्तावों के अतिरिक्त नेहरू जी ने कराची-कांग्रेस के कार्यक्रम में गांधी जी की अनुमति से, कांग्रेस की आर्थिक नीति संबंधी एक नव

प्रस्ताव भी जोड़ दिया था। यह प्रस्ताव कांग्रेस में एक नये दृष्टिकोण—सामाजिक अर्थ-व्यवस्था के सिद्धांत की दिशा में एक सूक्ष्म संकेत—का प्रवेश करा रहा था। अब तक कांग्रेस सिर्फ राष्ट्रीयता की ही दिशा में सोचती थी और आर्थिक प्रश्नों से बचती आ रही थी; परंतु इस प्रस्ताव द्वारा उसकी आर्थिक तटस्थता की नीति बनी न रह सकी। सरकार इस प्रस्ताव को भी आशंका और असंतोष की दृष्टि से देखती थी, परंतु उसने इसपर कोई विशेष आपत्ति नहीं प्रकट की।

इन सब कार्यों के यथा विधि सम्पन्न हो जाने के पश्चात् अब कांग्रेस का अन्तिम कार्यक्रम अगले वर्ष के लिए कार्यसमिति के सदस्य निर्वाचित करना था। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्य संख्या में कम निर्वाचित होने के कारण काफी नाराज हुए। इन विरोधी मुसलमानों ने इस विषय को लेकर कांग्रेस का साथ जोड़ दिया तथा 'मजलिसे अहरार' (आत्म-सम्मान रखनेवाली संस्था) नामक एक संस्था का निर्माण किया, जिसका एक धुंधला सा आर्थिक दृष्टिकोण था। आगे चल कर इस संस्था ने देशी राज्यों के मुसलमान-आंदोलन, खासकर काश्मीर में काफी काम किया, जिसका अजीब सा बुला-मिला एक आर्थिक और साम्प्रदायिक आधार था। कांग्रेस से 'अहरार' पार्टी के रूप में कुछ लोकप्रिय मुसलिम नेताओं का कट कर अलग हो जाना पंजाब में कांग्रेस के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ।

इन्हीं दिनों जब करोंची-कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कानपुर में हिन्दू-मुसलिम टंगा आरम्भ हुआ। इसे बन्द करने के उद्योग में रत, कांग्रेस के एक कर्मठ सदस्य श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की कुछ साम्प्रदायिक व्यक्तियों ने हत्या कर दी। इस घटना ने करोंची में, युक्तप्रातीय कांग्रेस के सदस्यों के हृदय को शोकाकुल कर दिया, परन्तु फिर भी हर एक व्यक्ति को उनके कार्य पर अभिमान भी था कि वे एक निश्चित व्यय, हिन्दू-मुस्लिम-एकता तथा प्रेम, के लिए अपना प्राण देने में भी पीछे न हटे।

गांधी-इर्विङ्ग-पैकट के पश्चात् भी कांग्रेस के समस्त हमेशा यह प्रश्न

उपस्थित रहता था कि गांधी जी गोलमेज-कान्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए इङ्गलैंड जाये या नहीं, क्योंकि उससे कुछ विशेष फल-प्राप्ति की आशा लोगों को बहुत कम थी। दूसरे ब्रिटिश सरकार की ओर से यह बराबर संकेत किया जाता था कि प्रथम गोल-मेज-कान्फ्रेंस ने हिन्दुस्तान के नये विधान की रूप-रेखा निश्चित कर ही दी है, अब तो कांग्रेस को सिर्फ जाकर उस नवीन चित्र को मोटी-मोटी रेखाओं में रंग भरना ही शेष रह गया है, जब कि इसके ठीक विपरीत कांग्रेस की निगाह में अभी तो उसे कोरे कागज पर विधान का पूरा नक्शा ही बनाना बाकी था। यद्यपि गांधी जी ने दिल्ली-समझौते में भारत के लिए संघ-शासन पूर्णतः मंजूर कर लिया था, परन्तु वे उस प्रकार के संघीय विधान को ग्रहण करने के लिए तैयार न थे जिसे पहला गोल-मेज-कान्फ्रेंस ने बनाया था, तथा जिसे बलपूर्वक सरकार भारत पर लादना चाहती थी। करोंची-कांग्रेस में भी यह साफ तौर से निश्चित हो गया था कि भारत की जनता तथा उसकी प्रतिनिधि संस्था कांग्रेस वही विधान मंजूर करेगी, “जिसमें उन्हें फौज, वैदेशिक मामलों, राजस्व तथा आर्थिक नीति पर अधिकार दिया गया हो, और भारत को विदेशों की ऋण-पूर्ति करने के पहले अपने देश से दिये गये कर्ज को जॉच करने का पूर्ण हक हो। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों सम्बन्धी प्रस्ताव में भी उसने यह दिग्दर्शित कर दिया था कि वह क्या क्या राजनैतिक और आर्थिक परिवर्तन मौजूदा भारतीय स्थिति में चाहती है। कांग्रेस के विधान सम्बन्धी ये प्रस्ताव तथा उसकी मांगें सरकार की तत्कालीन नीति के विरुद्ध थीं। शासक और शासितों के दृष्टि-कोण में बहुत अधिक अन्तर था। इन सब कारणों के फलस्वरूप आशावादी गांधी जी को भी कान्फ्रेंस की सफलता में संदेह ही था।

कुछ ऐसी अवस्थायें भी थी जिनके भविष्य में, उपस्थित हो जाने पर कांग्रेस का गोल-मेज-परिषद में भाग लेना ही असम्भव हो सकता था। प्रथम तो यह कि कांग्रेस कान्फ्रेंस में तभी भाग लेने को तैयार थी जब सरकार कांग्रेस को परिषद में अपने दृष्टि-बिंदु पूर्णतः उपस्थित करने का

अवसर देने का वादा करे । इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान में ही कुछ ऐसी राजनैतिक परिस्थिति उत्पन्न हो सकती थी, जिसकी तत्कालीन स्थिति में कुछ-कुछ सम्भावना भी थी, जिससे कांग्रेस को सरकार से मेल का ध्येय पूर्ण रूप से त्याग देना पड़ता ।

बंगाल, युक्त-प्रात तथा सीमाप्रात की परिस्थिति कुछ विषम थी । बंगाल में पुलिस तथा अन्य नौकरशाही वर्ग अब भी जनता पर अपने अधिकार-मद में प्रमत्त हो अत्याचार करने में लिस थे । युक्तप्रात में कर-बंदी-आंदोलन स्थगित हो जाने के पश्चात भी प्रान्तीय सरकार लगान और मालगुजारी की छूट के सवाल पर बराबर टाल-मटोल कर रही थी; तथा जवर्दस्ती बकाया लगान की वसूली आरम्भ हो गयी थी । गांधी जी के विरोध तथा लिखा-पढ़ी के बावजूद भी हजारों किसानों की भूमि बेदखल तथा कुर्क की जा रही थी । इस समय जवाहरलाल जी अस्वस्थ होने के कारण लंका में विश्राम ले रहे थे । भारत के इन राजनैतिक प्रश्नों से वे अत्यन्त चिंतित थे तथा उस अस्वस्थावस्था में भी उनकी आत्मा भारत शीघ्र ही पहुँचने के लिए छुटपटा रहो थी । इसके अतिरिक्त सीमाप्रान्त में अण्डुल गम्फार खों के नेतृत्व में बढ़ती हुई अहिंसात्मक जाग्रति को भी सरकार संदेह की निगाह से देख रही थी, तथा विभिन्न आर्डिनेन्सों द्वारा उनकी प्रगति को दबाना चाहती थी ।

इन सब सवालों के अतिरिक्त एक और बड़ा प्रश्न भी कांग्रेस के समक्ष था, और वह था सरकार की साम्प्रदायिक नीति । कांग्रेस यह पूर्णतः जानती थी कि सरकार गोलमेज-परिषद में साम्प्रदायिक स्वार्थ को अन्य विषयों से अधिक महत्व देगी, जो राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए घातक था ।

१९३१ की गर्मियों में सरकार ने कांग्रेस पर यह दोषारोपण लगाना भी प्रारम्भ कर दिया कि कुछ प्रातीय-कांग्रेस-कमेटियों दिल्ली-समझौते के विरुद्ध कार्य कर रही हैं; उधर कांग्रेस भी सरकार के विरुद्ध समझौता तोड़ने का आरोप लगाती थी । इस प्रकार संघर्ष मानो उस समय हिन्दु-स्ताम की तत्कालीन परिस्थिति में ही छिपा हुआ था, और वह

किसी प्रकार के लुभावने शब्दों या समझौतों से दूर नहीं किया जा सकता था ।

दिल्ली-समझौता-भंग करने के प्रश्न को लेकर गांधी जी तथा जवा-हरलाल ३ बार शिमला में वायसराय से बातचीत करने गये । उनका विचार शिमला में वायसराय से इस विषय में फिर से समझौता करने के पश्चात् ही गोलमेज-काफ्रेस में भाग लेने को था अन्यथा नहीं । समझौते की सम्भावना न होते हुए भी अन्त में समझौता हो ही गया । फलस्वरूप गांधी जी ने गोलमेज-काफ्रेस में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से उपस्थित होने के लिए इङ्गलैंड की ओर प्रस्थान किया । उनके साथ कार्यसमिति की एक अन्य सदस्या श्रीमती सरोजनी नायडू भी, भारतीय महिला प्रतिनिधि के रूप में आमन्त्रित होकर गयी थी ।



गोलमेज-परिषद की असफलता तथा उसके पश्चात्

यद्यपि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि की हसियत से गोलमेज-परिषद में भारत के लिए एक सर्वहितकारी नया विधान पास कराने, तथा कांग्रेस और सरकार के बीच की खाई पाटने गये अवश्य परन्तु वे सफल न हो सके। वहाँ तो ब्रिटिश सरकार का इरादा एवं कार्यपद्धति परिषद के उद्देश्य को गौण रख, और वे मतलब की छोटी-छोटी बातों में उन्हें फसा कर, मूल और असली सवाल पर विचार करने के काम को टालना था। यदि विषय कभी असली सवाल की ओर मुड़ भी जाता तो सरकार उसके बारे में गोल-मोल उत्तर देती थी। सरकार अपनी साम्राज्यवादी कूटनीति का इस्तेमाल परिषद की कार्यवाही में भी कर, फूट द्वारा राष्ट्रीय-आंदोलन की प्रगति को रोकना, तथा कांग्रेस की सार्वजनिक मांगों को दबाना चाहती थी। उसे इसमें पूर्ण सफलता भी मिली। कांग्रेस के ज्यादातर हिन्दुस्तानी मेम्बर इस फंके हुए चारे के विनाशकारी परन्तु लुभावने सरकारी जाल में फँस गये। इसके अतिरिक्त परिषद में हिन्दुस्तान के विभिन्न सम्प्रदाय एवं वर्ग के जो प्रतिनिधि बुलाये भी गये थे, उनमें से अधिकतर राजनैतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रीय उन्नति के सबसे ज्यादा विरोधी दलों के थे। ये लोग हिन्दुस्तान में ऐसे स्वार्थ रखने वालों के प्रतिनिधि थे जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद से बँधे हुए थे, एवं अपनी तरक्की तथा रखवालों के लिए उन्हीं का भरोसा भी रखते थे। राजनैतिक दृष्टि से वे हर किस्म की प्रगति के विरोधी थे और उनकी दिलचस्पी केवल एक बात में थी, किसी प्रकार इस कांग्रेस में अपने तथा अपने वर्ग के फायदे के लिए कुछ सुविधायें प्राप्त कर सकें। उन्होंने

• खुल्लम-खुल्ला यह प्रचारित भी कर दिया था कि जब तक उनकी साम्प्रदायिक मूर्खों पूरी न होगी वे स्वराज्य लेने के लिए भी उत्सुक न होंगे। इन्सान की गुलामी की तवारीख में यह एक अजीब दुख भरा मज़मा था। एक गुलाम जाती किस हद तक गिर सकती है, उसके मानसिक स्तर का किस हद तक पतन हो सकता है, और वह साम्राज्यवादियों के खेल में किस तरह शतरंज का मोहरा बन सकती है, इसे देख और सुन कर ओख और कान दोनों बन्द कर लेने की इच्छा होता था। ब्रिटिश-शासन की भेद-नीति के एक इशारे पर, वर्गीय तथा साम्प्रदायिक नारों की ओड़ में राष्ट्रीय हित का बलिदान करने में भी नहीं चूका जा रहा था। नेता कहे जानेवाले पाखंडी बड़ी आसानी के साथ राष्ट्र को वास्तविक हित की बातों से हटा कर एक दूसरे की कोशिशों को बेकार करने के कामों में लगा रहे थे। अवसरवादिता के जाम का दौरा दौरा था; ऐसा मालूम पड़ता था कि हिन्दुस्तान के नये शासन-विधान में शिकार के तप में मानवता का जो विचित्र शव फेंका जाने वाला था, उसकी फिराक में भिन्न-भिन्न गिरोह भूखे मेड़िये की तरह घात लगाये फिर रहे हैं। हिन्दुस्तान की कोटि-कोटि भोली जनता के इन 'प्रतिनिधि' नेताओं ने, अपने देश के प्राचीन आदर्शवाद और त्याग की दुर्लभ मलय-समीर को छोड़ कर, स्वार्थ की गंदी और दम घुटाने वाली हवा को ग्रहण किया था।

गांधी जी के अनेक प्रयत्न के पश्चात् भी ब्रिटिश-शासकी-शतरंजी चालों में उलझी कान्फ्रेन्स व्यर्थ ही रही। साम्राज्यवादी शासन-सत्ताधारियों ने यह साबित कर दिया कि अभी तक उनमें सिर्फ अपने साम्राज्य को कायम रखने की ही ताकत नहीं है, वरन कुछ दिनों तक और साम्राज्यवादी परम्परा को चला ले जाने के लिए चालाकी और कूटनीति भी उनके पास मौजूद है। लंडन में हिन्दुस्तान के लोग असफल रहे, यद्यपि न तो काफ़्रेस का सही माने में उनके द्वारा प्रतिनिधित्व ही हुआ था, और न तो उसकी ताकत से हिन्दुस्तान के खून की गर्मी और ताकत का सही

अन्दाज ही लगाया जा सकता था; परन्तु फिर भी अंग्रेजों का मतलब, सिद्ध हुआ और कांग्रेस की असफलता से हिन्दुस्तान की बदनामी ही हुई। अंग्रेजों को दुनिया के सामने यह कहने का मौका मिला कि हिन्दुस्तान अभी आपसी मजहबों लड़ाई से ही मुक्त नहीं है। वे अयोग्य हैं और अपने हित के लिए उन्हें 'शुभ चिन्तक' विदेशी-शासन में रहना आवश्यक है। "उन्हे स्वतंत्रता या अन्य विशेष सुधार देना, असम्भव बंदर के होंथों खूबसूरत मोती की माला नष्ट कराना है।" नेहरू जी के शब्दों में—“वह कांग्रेस जहाँ साजिशों, मौकापरस्ती और जालसाजियों का बोलबाला था, हिन्दुस्तान की असफलता नहीं कहला सकती। वह तो ऐसी बनायी ही गयी थी जिससे असफल होती।” यह हिन्दुस्तान की अपनी हार नहीं थी। मचमुच, हिन्दुस्तान के लोगों के लिए सफलता या असफलता खुद हिन्दुस्तान में होने वाली राजनीतिक घटनाओं से हो सकती थी; भारत में जो दृढ़ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वह लंदन में होने वाली-चालबाजियों से ठण्डा नहीं हो सकता था।

जब की लंदन में हिन्दुस्तानियों के सहयोग से उनके लिए एक नये और हितकारी विधान का स्वागत भरा जा रहा था, भारत में गांधी-इर्विङ्ग पैक्ट के विरुद्ध भारतीय नेताओं पर सम्झौते विरोधी कार्य करने का झूठा दोषारोपण कर, कुचक्रपूर्ण अत्याचार करने से सरकार बाज न आ रही थी। भारतीय जनता की किसी प्रकार की मॉग चाहे वह रोटी, कपड़ा, आवास के लिए ही क्यों न हो, संदेह की दृष्टि से देखी जाती थी, और सरकार को उनमें राजनीतिक कुचक्रों की वृद्धि आती।

पहले ही कहा जा चुका है कि किसानों में १९२१ से ही जाग्रति का आगमन होने लगा था। कांग्रेस के सहयोग से और भी संगठित हो वे अपनी मांगों सरकार के समक्ष रखने, और दो एक बार तो उन्हें प्राप्त करने में सफल भी हो चुके थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रधान मंत्री तथा कार्यसमिति के एक सदस्य की हसियत से पं० जवाहरलाल किसान-आंदोलन के काफी सम्पर्क में आ चुके थे। किसान-संगठन

के उद्देश्य से उन्होंने कई बार देश के विभिन्न भागों में दौरा भी किया था ।

राष्ट्र के अन्य भागों की अपेक्षा युक्तप्रात, विशेषतः प्रयाग के किसानों में विशेष जाग्रति थी तथा वे अधिक संगठित थे । १९३० में सर्वप्रथम प्रयाग-किसान-कमेटी को ही कर-उदी-आंदोलन आरम्भ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था ।

१९२६ की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा । अन्य धंधों की तरह कृषि के क्षेत्र में भी इसका काफी बुरा असर पड़ा । किसानों पर कर्ज बरसाती पानी की तरह बढ़ने लगा और वे दाने-दाने को मोहताज हो गये । धरती के उन लालों को, जो छाती फाड़कर सारी दुनिया का पेट भरते थे; स्वयं पेट के लाले पड़ना पड़ा ।

१९२६ और ३० में सरकार द्वारा नियुक्त प्रातीय बैंकिंग जॉन्च कमेटी ने अंदाज लगाया था कि (वर्मा सहित) हिन्दुस्तान का कृषि सम्बन्धी कर्ज ८६० करोड़ रुपया था । इसके अतिरिक्त रुपये का अनुपात जबर-दस्त विरोध करने के पश्चात् भी १६ पैसे के बजाय १८ पैसे कर देने से किसानों का कर्ज १२½ प्रतिशत या लगभग १०७ करोड़ बढ़ गया था ।

गांधी जी तथा पं० नेहरू आदि नेताओं का, तत्कालीन परिस्थिति देखते हुए, यह प्रस्ताव था कि सब मौसमी कास्तकारों के लिए ५० प्रतिशत ग्राम छूट होनी चाहिए, और जिन कास्तकारों की हालत विशेष चिंता जनक हो उनको इससे भी ज्यादा छूट दी जाये । परन्तु तत्कालीन युक्त प्रातीय गवर्नर ने इस प्रस्ताव को 'अमान्य' कर दिया, फलस्वरूप छूट नाम मात्र की दी गयी । जो किसान बाकी लगान न दे पाता था उसपर बल प्रयोग की मशीन, कानूनी और गैर कानूनी दोनों ढंग से, चलने लगी । जमीन की बेदखली, कृषकों की बेइज्जती तथा मारपीट प्रतिदिन की घटना हो गयी ।

यह सब देख कर प्रातीय कार्यकारिणी बहुत ही कठिन स्थिति में पड़ गयी थी । यह जानते हुए भी कि कृषकों के साथ अत्याचार हो रहा है,

गांधी-इर्विङ्ग-पैक्ट से बड़े कांग्रेस के कर्मठ नेता कुछ नहीं कर पाते थे । हजारों की संख्या में वे धरवार कर दिये गये भोले-भाले किसान अपनी आप-बीता अपने दुख-सुख में साथ देने वाले नेताओं को रो-रो कर सुनाने के लिए प्रयाग दौड़े आते थे । मावुक पं० नेहट्ट के जिंगर का जल्म जमींदारों के कारिन्दों से मार खाये किसानों की चोट का निशान देख कर फिर से हरा हो जाता था । वे अपनी असहायता पर रोने लगते और उनकी तगियत होती को वे इस बेइन्साफ दुनिया से बहुत दूर भाग जाये, जहाँ उन्हें अपने निर्दोष भाइयों की यह दुर्दशा देखने को न मिले । पर वे कर ही क्या सकते थे ?

शासक और शासित के जिस संघर्ष को गांधी जी के आगमन तक ढालने का नेताओं की ओर में बराबर प्रयत्न हो रहा था, वह तत्कालीन परिस्थिति तथा सरकारी नीति के फलस्वरूप उनकी इच्छा के विपरीत तेजी में बढ़ता चला आ रहा था । भारत-सरकार का लगातार कांग्रेस की ओर लख सलत होता जा रहा था । सरकार उनकी आर्द्धिनेसों तथा दमन-चक्रों द्वारा आंदोलन को पूर्णतः कुचल देना चाहती थी ।

तनातनी बढ़ती गयी और घटनाये नेताओं के प्रयत्न की उपेक्षा करती हुई अपने आप आगे बढ़ती रही । युक्त-प्रात की सरकार के एक और काम ने दग्री हुई आग में घी का काम किया । स्थानीय अफसरों ने पर्चियों बटवाई, जिसके अनुसार यदि छूट की रकम के अतिरिक्त अन्य रकम को नीयत समय पर जमा न कर दिया गया तो वह जवरन बसूल की जाने वाली थी । इससे शातिपूर्ण समझौते का मौका खतम हो गया, और अनिवार्य संघर्ष एक के बाद दूसरा पग धरता हुआ सामने उपस्थित हो गया । अखिल भारतीय-कांग्रेस-कार्यकारिणी की सम्मति मिलने के पश्चात् नेहट्ट जी ने अपनी ग्जवृत किसान-सेना के साथ अहिंसात्मक लडाई की तैयारी आरम्भ कर दी । किसानों का कर-ग्रन्दो-आंदोलन नृशंस दमन के पश्चात् भी युक्तप्रान्त, गुजरात तथा कर्नाटक में जोर से चलता रहा ।

संघर्ष आरम्भ होने के पूर्व नेहरू जी घूम कर सम्पूर्ण आतंकग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करना चाहते थे। उन दिनों बंगाल की स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। आतंकवादियों का वहाँ विशेष प्रभाव था, फलस्वरूप छुट-पुट घटनाये हो जाती थीं, जिनका भारतीय राजनीति पर बुरा असर पड़ता था। चटगोव की आतंकवादी घटना, जिसमें एक क्रांतिकारी नवयुवक द्वारा एक मुसलमान अफसर की हत्या ने साम्प्रदायिक दंगे का रूप ग्रहण कर लिया था, के पश्चात् नेहरू जी कलकत्ता पहुँचे तथा वहाँ की स्थिति का निरीक्षण किया। वहाँ दिये गये अपने भाषण में तत्कालीन घटना की ओर इंगित करते हुए उन्होंने बतलाया की आतंकवादी क्रांतिकारियों के कार्यों से किस प्रकार राष्ट्रीय हित तथा आंदोलन की हानि हो रही है। यद्यपि उनकी देशभक्ति, बलिदान तथा साहस की नेहरू जी प्रशंसा करते थे, परन्तु फिर भी वे उनके हिंसात्मक मार्ग को भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की आत्मा के प्रतिकूल तथा अहितकर समझते थे। इसके पश्चात् एन० एस० हाईकोर के अनुरोध पर वे दक्षिण में कर्नाटक तक दौरा करने गये।

पं० नेहरू, संघर्ष के लिए तत्पर देशवासियों के जबरदस्त जोश को देखकर लौट रहे थे। लड़ाई करीब थी, नेहरू जी के हृदय में अनेक भाव उठ रहे थे। “कर्नाटक के उस दौरे ने मेरे लिए बिदाई के समारोह का रूप धारण कर लिया। मेरे भाषण बिदाई के गीत जैसे लगते थे, लेकिन उनमें सुप्त संगीत के स्थान पर रणभेरी का स्वर था।”

उन्ही दिनों सरकार ने किसान-आंदोलन के कारण एक दमनात्मक आर्डिनेन्स निकाला, जिसमें बच्चों या नाबालिक के अपराध के लिए माता-पिता या संरक्षकों को सजा देने का इन्तजाम किया गया था। बंबई में रोग-शय्या पर पड़ी प्रिय पत्नी के दुखों का भी विस्मरण कर नेहरू जी प्रयाग पहुँचे। मार्ग से भवन तक पहुँचने में उन्हें तीन सरकारी आर्डिनेन्स मिले, प्रत्येक के द्वारा उन पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाये गये थे, जिनका तात्पर्य यह था, कि वे ‘प्रयाग म्यूनिसिपल सीमा’ के बाहर न जाये, न किसी सार्वजनिक सभा में शरीक होकर भाषण आदि ही दें,

और न किसी समाचार पत्र में लेख आदि ही लिखें।' वाद में नेहरू जी को मालूम हुआ कि इसी आशय के आज्ञा-पत्र उनके अन्य कर्मठ साथियों का भी मिले थे। उन्हें यह पहले ही मालूम हो चुका था कि बंगाल तथा अन्य स्थानों की घटना से चिंतित गांधी जी इंग्लैण्ड से भारत के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, ऐसी अवस्था में वे शीघ्रातिशीघ्र अपने नेता से मिलना तथा संघर्ष के भावी कार्यक्रम को निश्चित करना चाहते थे; अतः उन्होंने दूसरे दिन सुबह ही जिला-मैजिस्ट्रेट को सूचित कर दिया "मैं आप लोगों की इच्छा के विपरीत भी अपनी इच्छानुसार ही कार्य करूँगा, इसके अतिरिक्त गांधी जी से मिलने तथा कार्यसमिति की एक बैठक में शरीक होने के लिए मैं बम्बई भी जाऊँगा।"

पं० नेहरू तथा श्री शेरवानी निश्चयानुसार बम्बई के लिए रवाना हो गये, किन्तु एक गाँव के स्टेशन के पास उनकी गाड़ी रोक ली गयी तथा वे गिरफ्तार कर लिये गये। जनवरी सन् १९३२ में नेहरू जी को २ वर्ष का कारावास दण्ड मिला, जब कि उसी अपराध में उनके अन्य साथियों को केवल ६ मास का दण्ड मिला था। इससे मालूम होता है कि उन्हें विशेष 'खतरनाक' समझ कर सरकार की उन पर विशेष 'कृपा-दृष्टि' थी।

गिरफ्तारी के दो दिन पश्चात्, नीले आस्थान और नीले समुद्र को मनहूस कैद से मुक्त हो, गांधी जी ने स्वदेश की संधी मिट्टी पर पाँव रखा, और साथ ही उन्हें मालूम हुआ कि उनके कंधे से कन्धा भिडाकर काम करने वाले उनके साथी जेल में ठूस दिये गये हैं। सरकार का दमन-नीति से उनका हृदय क्षोभ से भर गया। सम्पूर्ण देश आर्डिनेन्सों में बद्ध कराह रहा था। तत्कालीन परिस्थिति से विचलित गांधी ने वायस-राय से मिलकर उन विषयों पर बात करने के लिए उनकी आज्ञा चाही, परन्तु वह उन्हें न प्राप्त हो सकी। अब गांधी जी के समस्त सविनय-अवज्ञा आन्दोलन फिर चालू कर देने के सिवाय कोई रास्ता न था। कार्य-समिति ने सविनय-आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया। ४ जनवरी सन् १९३२

को सरकार की ओर से इसका जवाब गांधी जी तथा कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल की गिरफ्तारी के रूप में मिला, और साथ ही उसकी ओर से वह वोटन भी दवा दिया गया जिससे सारे देश ने दमन का न्यंत्र दूर श्रुत हो गया। चार नये आर्डिनेन्स जारी किये गये जिनके द्वारा मैजिस्ट्रेटों और पुलिस अफसरों को व्यापक से व्यापक अधिकार मिल गये थे। नागरिक स्वतन्त्रता की हस्ती मिट गयी थी, तथा जन और धन दोनों पर ही अधिकारी चाहे जब कच्चा कर सकते थे। तत्कालीन भारत-मन्त्री सर सैम्युअल होर ने २४ मार्च सन् ३२ को क्रान्त्य सभा ने त्वयं मंजूर किया था, "जिन आर्डिनेन्सों का हमने समर्थन कर दिया है वे बड़े ही व्यापक और सरत हैं, वे हिन्दुस्तान के जीवन की लगभग हर एक प्रवृत्ति पर अमर डालते हैं।"

अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात्, देश ने फिर एक बार प्रबल सत्याग्रह-आंदोलन तथा सरकार का दमन-चक्र घूमना आरम्भ हुआ। इकट्ठी सत्याग्रही मोड़ पर पुलिस की लाठियों को नार पड़ते। नित्य हजारों गिरफ्तारियों तथा सजाये होते। कांग्रेस तथा उससे सम्बन्धित सभी संस्थाये गैर कानूनी घोषित कर दी गयी थीं। स्वतन्त्रता के पश्चात्, अपने ऊपर किये गये अपने शासकों के अत्याचारों से उत्पन्न आक्रोश की आग की ज्वालायें नले ही बुझ जाये फिर भी उसके धधकते हुए अंगारे भारतीयों के हृदय में, साम्राज्यवाद के प्रति दृष्टा बन कर हमेशा सुरक्षित रहेंगे, और वे हिन्दुस्तान की स्वाधीनता के संकल्प की तरह गरम और कभी न बुझने वाले होंगे।

नेहरू जी तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् नेहरू जी के परिवार के लोग भी शांत न रह सके। बम्बई में रोग-शय्या पर पड़ी उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू अपनी असहायवस्था के फलस्वरूप आंदोलन में भाग न ले सकने के कारण छुटपट रही थीं; परन्तु उनकी मों और वहन आंदोलन में कूद पड़ी। श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित तथा श्रीमती कृष्णा नेहरू को आंदोलन में प्रमुख भाग लेने के कारण एक-एक

वर्ष का कारावास दण्ड मिला । अंग्रेजों द्वारा नादिरशाह की भोपख नृशसता दुहरायी जा रही थी ।

इसी समय नेहरू जी की माता के साथ एक ऐसी घटना घटी जिस पर सम्पूर्ण देश दुःख और आश्चर्य से स्तब्ध रह गया । २६ जनवरी के राष्ट्रीय समाह के अवसर पर वे प्रयाग में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं । उसी समय गुलामी के विनाशकारी नशे में मदहोश पुलिस दल ने पहुँचकर जुलूस पर लाठियों बरसायां । माता खट्परांनी सावा-तिक चोट में बेहोश हो सड़क पर गिर पड़ीं उनके मस्तक के घाव से रक्त की धारा बह चली । बाद में कुछ पुलिस अफसर ने उन्हें मूर्छितावस्था में ही आनन्द भवन पहुँचाया । गिजली की तरह यह समाचार प्रयाग में फैल गया इससे क्रुद्ध भीड़ विवक्षित हो अहिंसा का पाठ भूल गयी और उसने पुलिस पर हमला कर दिया । पुलिस ने भी जवाब में गोलियों चलाई जिससे बहुतेरे मनुष्य मरे और घायल हुए । नेहरू जी को यह दुःखद समाचार जेल में मिला । स्वयं नेहरू जी के ही शब्दों में “इस खाल में ही मुझे बड़ी बेचैनी हुई कि मेरी वयोवृद्ध निर्बल माता खून से लथपथ सड़क की धूल में पड़ी हुई हैं । मैं सोचने लगा कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या करता ? मेरी अहिंसा कहाँ तक मेरा साथ देती ? परन्तु इस घटना के कुछ दिनों पश्चात् “धीरे-धीरे वे चगी हो गईं और जग दूसरे महीने वे बरेली-जेल में मुझसे मिलने आईं तब उनके सिर पर पट्टी बंधी थी; उन्हें इस बात की प्रसन्नता तथा गर्व था की स्वयंसेवक और स्वयं-सेविकाओं के साथ उन्होंने भी वेतों और लाठियों की मार सहन की । परन्तु इस घटना के पश्चात् उनका स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिरने लगा तथा उनकी स्थिति चिन्ताजनक होने लगी ।”

की सेवा करने के माबं से प्रेरित होकर' सार्वजनिक खर्च पर फिर समुद्र पार गये, और कहा जाता है कि इनमें से कुछ ने ज्यादा सफर-खर्च मिलने के लिए कोशिश भी की। उस दिन हर एक सच्चे भारतीय को यह देख कर जलर वेदना हुई होगी कि जब उसकी मातृ-भूमि इस तरह जन्म-मरण के संघर्ष के लगी हुई है, कुछ अवसरवादी लोग हिंदोस्तान के नाम पर कालिल लगाने वहाँ पहुँचे।

किंतु इन अवसरवादी नेताओं की साजिशों से आंदोलन दबने की एवज में और भी उमड़ा, यद्यपि सरकार भी उसका पूरे जोर-शोर के साथ दमन कर रही थी। फौजी-हुकूमत तथा पुलिस-शासन का बोल-वाला था। व्यक्तिगत जन-जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर शासन का नियंत्रण था।

सरकार की हिंसात्मक मनोवृत्ति ने सत्याग्रहियों को बंदी बनाने के पश्चात् जेल में भी उनका पाँखा नहीं छोड़ा। उन्हें भीख यद्वा दाँ जाती थी, तथा सरकारी नीति के अनुसार उनसे नानुर्ली कैदियों से नी बुरा बर्ताव किया जाता था। वेतों की सजा जेल को आम सजा हो गया था। जेल में राजनीतिक कैदियों की जिंदगी उनके लिए भार बना दी जाती, तथा यद्वा दे-देकर उनसे प्रतिज्ञा कराया जाता कि वे अब आंदोलन में भाग न लेंगे। कम उम्र के नौजवानों तथा महिला कैदियों के साथ तो और भी बुरा बर्ताव होता था।

यह सब होते हुए भी न जाने क्यों जेल में जे० नेहरू के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया जाता था, परन्तु एक बार जेल की एक घटना से उन्हें विशेष कष्ट अवश्य हुआ था। एक बार उनकी माँ, पुत्री एवं पत्नी उनसे और रणजीत पंडित से मुलाकात करने जेल गये थे: वहाँ पर जेलर ने उनका अपमान किया था तथा उन्हें दंडित कर बाहर निकाल दिया था। जब नेहरू जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपनी माँ को जेल-अधिकारियों द्वारा अपमानित किये जाने की सम्भावना से बचाने के लिए आइन्दा से जेल में किसी ने भी मुलाकात न करने का निश्चय किया, और सचमुच

करीब सात महीने तक, जब तक वे देहरादून-जेल में रहे किसी से मुलाकात नहीं किया ।

प० जवाहरलाल जी जेल में 'जेल की चिड़िया' के नाम से प्रसिद्ध थे तथा उसी प्रकार जीवन भी व्यतीत करते थे । कुशासन की दुर्नीति में सच्चे ईमानदार मनुष्यों के लिए जेल ही रहने के लिए उतम स्थान है । सुप्रसिद्ध आदर्शवादी विलियम थोरे के अनुसार "जिस समय पुरुषों और स्त्रियों को अन्यायपूर्वक कारावद्ध किया जाता है, उस समय ईमानदार नर-नारियों का ग्यान जेल ही है ।" अपने जेल-जीवन में नेहरू का सम्पर्क बाहरी संसार से करीब-करीब कट सा गया था, और जेल में उनका अधिक समय पढ़ने-लिखने में ही व्यतीत होता था । जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, जो जून १९३४ में प्रारम्भ हुई और १८ महीनों में समाप्त हुई । इस पुस्तक में उन्होंने सम सामयिक भारतीय राजनीति का विश्लेषणात्मक तथा कवित्व पूर्ण ढंग से, बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । जेल से ही उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री-इन्दिरा को हजारों पत्र लिखे जो बाद में 'पिता के पत्र पुत्री को' के नाम से प्रकाशित हुए । जेल में भी वे अपने को व्यस्त रखते तथा प्रकृति के रमणीय दृश्यों के अतिरिक्त कुदरत के खुशनुमें और मासूम जीवों को देख कर अपना दिल बहलाते थे ।

इन्ही दिनों जब नेहरू जी अपना जेल-जीवन शान्ति पूर्ण ढंग से बिता रहे थे, उन्हें सितम्बर १९३२ को एक दिन ज्ञात हुआ कि उनके पूज्य नेता गांधी जी ने रेम्जे मैकडानल्ड द्वारा दलित वर्गों को साम्प्रदायिक चुनाव का अधिकार देने के विरोध में, आमरण अनशन आरम्भ कर दिया है । नेहरू जी का हृदय भविष्य की अमंगलकारी अशंकाओं से भर उठा, यद्यपि उन्हें बापू के व्यक्तित्व और कार्यों पर पूर्ण विश्वास था । परन्तु इसी समय नेहरू जी की आशा के विपरीत अप्रत्याशित ढंग से पूना में विभिन्न दलों ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसे, परिस्थिति की विपमता को समझ कर, ब्रिटिश प्रधान-मंत्री रेम्जे मैकडा-

नल्ड ने भी तुरन्त मान लिया । इस समझौते से, तथा आर्या हुई विपत्ति इस प्रकार आसानी से टल जाने से नेहरू आदि सभी नेताओं को विशेष प्रसन्नता हुई । इसके कई महीने पश्चात् १९३३ में, गांधीजी ने फिर २१ दिन का उपवास आरम्भ किया था । यद्यपि नेहरू जी को राजनीति में इस उपवास को पद्धति पर विश्वास नहीं था फिर भी वे गांधी जी के कार्यों और दूरदर्शिता को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । गांधी जी का यह उपवास भी सफुशल पूर्ण हुआ । उपवास के पहले ही दिन वे जेल से रिहा कर दिये गये, तथा उनके कहने से ६ हफ्तों के लिए सविनय-अवज्ञा-आन्दोलन भी स्थगित कर दिया गया ।

यरवदा-जेल से, और बाद में बाहर आकर भी, गांधी जी द्वारा संचालित हरिजन-आंदोलन बड़ी तीव्रता से चल रहा था । हरिजन-मंदिर-प्रवेश का प्रतिबंध दूर करने के लिए गांधी जी ने तत्कालीन धारा सभा में इस आशय का एक बिल भी उपस्थित किया, तथा उसे पास कराने के लिए काफी प्रयत्न भी किया । परन्तु भारतीय-समाज-सुधार के आंदोलन को भविष्य में अपने शोषण में हानिकारक समझ सरकार ने उसे पास न होन दिया ।

सविनय आंदोलन स्थगित करने के पश्चात् गांधी जी ने अपना ध्यान सामाजिक सुधारों की ओर लगाया, यद्यपि नेहरू आदि कुछ उग्र नेताओं को आंदोलन स्थगित कर उसकी शक्ति सामाजिक सुधार में लगा देने से काफी असंतोष भी हुआ था । इसके अतिरिक्त गांधी जी ने पूना में एक विशेष कांग्रेस बुलाई जिसमें यह निश्चय किया कि सामूहिक सविनय अवज्ञा त्रिस्तुल स्थगित कर दिया जाय, परन्तु उन्होंने व्यक्तिगत अवज्ञा की छूट दे दी थी । सभी तरह की गुप्त प्रवृत्तियों को बंद कर देने की आज्ञा दी गयी । परन्तु उस कांग्रेस में, तत्कालीन परिस्थिति, कांग्रेस के लक्ष्य तथा उसके आगामी कार्यक्रम पर प्रकाश नहीं डाला गया, जब की अंग्रेजों और अन्य अवसरवादी शक्तियों के भूठे प्रचार का मुह-तोड़ जवाब तथा अपनी नीति का स्पष्टीकरण करना आवश्यक था ।

काफ़ेस में व्यक्तिगत आंदोलन की छूट दिये जानें के साथ ही, जनता के समक्ष उसका सही उदाहरण उपरिथत करने को ध्यान में रखकर, गांधी जी १ अगस्त को गुजरात के किसानों में सविनय-अवज्ञा का प्रचार करने के लिए खाना हुए। वह फौरन गिरफ्तार कर लिए गये तथा उन्हें, जनता में शासन के प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न करने के अपराध में एक साल की सजा दे दी गयी, और वे फिर यरवदा की अपनी चिर परिचित कोठरी में पहुँचा दिये गये। वहाँ गांधी जी ने, अधिकारियों से पहले की तरह ही जेल से हरिजन-आंदोलन-संचालन करने की आशा प्राप्त करनी चाहा; परंतु सरकार ने उन्हें ऐसी आशा देने से इंकार कर दिया। फलस्वरूप वे इसके विरोध में आमरण अनशन करने के लिए कटिबद्ध हो गये। पहले तो सरकार ने मुँकी परंतु उनकी हालत चिंताजनक देखकर तथा भावी आशका का ध्यान कर उसने उन्हें छोड़ देने में ही भलाई समझा। गांधी जी की रिहाई के कुछ दिनों पश्चात्, ३० अगस्त सन् १९३३ को, माता की शारीरिक स्थिति चिंताजनक हो जाने के फलस्वरूप नेहरू जी को भी छोड़ दिया गया। जेल से मुक्त होते ही नेहरू जी शीघ्रता पूर्वक अपनी माँ की रोगशय्या के पास लखनऊ पहुँचे।

नेहरू जी जिस समय मुक्त किये गये उस समय राजनैतिक दृष्टि से हिंदुस्तान कुछ शांत था। सार्वजनिक प्रवृत्तियों का सरकार ने ज्यादातर नियंत्रण और दमन कर रखा था और उनके विरुद्ध कार्य करने वालों की गिरफ्तारियों भी जारी थी। हिंदुस्तान में उस समय की खामोशी वैसी ही मनहूस थी जैसी कि भयंकर दमन के अनुभव के पश्चात् दम-तोड़ देने वाली थकावट से आती है। यह खामोशी अक्सर तूफान आने के पहले के शांत पर सफ़ आकाश की तरह थी, जिसकी भयंकरता का ज्ञान अधावुन्ध काम करने वाली सरकार को कैसे हो सकता था।

नेहरू जी यह जानते थे कि वह मौजूदा परिस्थिति में अधिक दिन तक जेल के बाहर नहीं रह सकते, अतः उन्होंने जल्दी-जल्दी बाहर के

काम निवटा देना ही आवश्यक समझा । वे फिर जेल जाने के पूर्व एक बार गांधी जी तथा बहुत दिनों से बिछुड़े अपने अन्य सहयोगी साथियों से मिलकर मौजूदा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर विचार कर लेना, तथा उसके अनुसार अगला राष्ट्रीय कार्यक्रम निश्चित कर लेना चाहते थे । इसके अतिरिक्त उनकी बहन कृष्णा नेहरू भी एक साल तक जेल में रहकर छूट चुकी थी, तथा उनकी सगाई भी हो गई थी । अतः नेहरू जी जेल जाने के पूर्व जल्दी ही उनका विवाह कर देने के लिए भी चिन्तित थे ।

माता के स्वास्थ्य में संतोषजनक परिवर्तन देखकर तथा उनकी परिचर्या की पूर्ण व्यवस्था कर नेहरू जी गांधी जी से मिलने पूना गये । वहाँ उन्होंने विभिन्न विषयों पर गांधी जी तथा अपने अन्य सहयोगियों से बातचीत की । वहाँ रहकर उन्होंने प्रतिक्रियावादी शक्तियों तथा लिबरल नेताओं की अवसरवादी नीति का भी पूर्णतः अध्ययन किया ।

सितम्बर १९३३ के मध्य में करीब एक हफ्ता बँवाई और पूना में व्यतीत करने के पश्चात् नेहरू जी लखनऊ लौट आये । माता का स्वास्थ्य पहले से अधिक सुधर गया था । खुद अस्वस्थ होते हुए भी उनकी प्रिय पत्नी कमला भी माँ की सेवा तथा परिचर्या करने लखनऊ आ गयी थी । उनकी बहने भी सप्ताह के अंतिम दिनों में अपनी माँ का देखने एक बार लखनऊ अवश्य आती थीं । नेहरू जी वहाँ करीब २-३ सप्ताह रहे । वे प्रतिदिन दोनों समय माँ को देखने अस्पताल जाते थे तथा अपने खाली समय में विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए लेख आदि तैयार करते थे ।

कुछ दिनों पश्चात् पं० नेहरू माता की इच्छानुसार उन्हें लेकर प्रयाग वापस लौटे । सगाई हो जाने के फलस्वरूप अपनी बहन कृष्णा नेहरू का विवाह अपने फिर जेल जाने से पूर्व ही कर देने के उद्देश्य से, 'सिविल मैरेज ऐक्ट' के अनुसार बड़ी ही साधारण रीति से उन्होंने उसे भी सम्पन्न किया । बहन की शादी हो जाने के पश्चात् वे काशी पहुँच कर अपने

रुग्ण मित्र श्री शिवप्रसाद गुप्त से मिले । इसी अवसर पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उन्हें एक सम्मान-पत्र भी प्रदान किया । उन्होंने वहाँ हिन्दी के सच्चे शुभाकांक्षी की तरह कहा था, “हिन्दी-साहित्य का भूतकाल बड़ा गौरवमय था, लेकिन वह सदा उसी के बल पर जिन्दा नहीं रह सकती ।” मुझे पूरा यकीन है कि हिन्दी का भविष्य भी काफी उज्ज्वल है, और मैं यह भी जानता हूँ कि किसी दिन देश में हिन्दी के अखबार एक जबरदस्त ताकत बन जायेंगे, लेकिन जब तक हिन्दी के लेखक और पत्रकार पुरानी रूढ़ियों से अपने को बाहर नहीं निकालेंगे, और आम जनता के लिये लिखना न सीखेंगे तब तक उनकी अधिक उन्नति न हो सकेगी ।” हर एक हिन्दी-प्रेमी जानता है कि नेहरू जी के इस कथन में कितनी सत्यता थी । यदि किसी भाषा को अनादि काल तक जीवित रहना है तथा उसके साहित्य को अमर होना है, तो उसे जनता की बातों को, जनता की भाषा में अपने साहित्य में स्थान देना होगा । तभी उस साहित्य में सत्य, शिव, सुन्दरम् का वास्तविक दिग्दर्शन होगा, और वह जनता का तथा राष्ट्रीय साहित्य कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर पावेगा ।

इसके अतिरिक्त नेहरू जी ने मालवीय जी के आग्रह पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भी अपना जोरदार भाषण दिया, तथा उसमें सम्प्रदायवादियों एवं साम्प्रदायिकता को खूब लथेड़ा । इसके अतिरिक्त उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों की भयंकर अनुदार साम्प्रदायिक नीति पर पत्रों में तर्क और विद्वतापूर्ण लेख भी लिखे, जिसे तत्कालीन पढ़ी-लिखी जनता ने काफी पसन्द किया और उनकी काफी दिनों तक चर्चा होती रही ।

इन सब कार्यों के अतिरिक्त भी नेहरू जी अपना जनसम्पर्क बराबर बनाये रखते थे । वे सार्वजनिक समारोहों में भाषण देते, जनता के समक्ष उसकी राष्ट्रीय समस्या रखते तथा उसे प्रोत्साहन देते थे । वे अपने

सहयोगी नेताओं से बराबर मिलते रहते तथा तत्कालीन परिस्थिति पर विचार करते रहते थे ।

अक्टूबर १९३३ में, प्रयाग में मौजूदा परिस्थिति पर विचार करने और आगे का कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए युक्त-प्रात के कांग्रेस-कार्यकर्ताओं की बैठक हुई । इस कांग्रेस ने एक समाजवादी प्रस्ताव पास किया, जिसमें भारतवासियों के लक्ष्य का बयान किया गया था और सविनय आंदोलन भंग किये जाने का विरोध किया गया था । कार्यकर्ताओं से यह कहा गया था कि वे देहातों से अपना संबन्ध फिर से स्थापित करें, और यह जानने की कोशिश करें कि लगान में छूट और सरकारी दमन-नीति, इन दोनों के परिणाम स्वरूप किसानों की क्या अवस्था है ?

यद्यपि यह कार्यक्रम नरम और निर्दोष था, परन्तु फिर भी सरकार ने करमन्दी-आन्दोलन के प्रचार का झूठा दोषारोपण कर देहातों में जाने-वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया । युक्त-प्रातीय कांग्रेस कमेटी के प्रभावशाली मंत्री श्री रफी अहमद क़िदवई भी गिरफ्तार कर लिये गये । २६ जनवरी—स्वतंत्रता-दिवस—नजदीक आ रहा था, अतः नेहरू जो ने स्वतंत्रता-दिवस को उचित रूप से मनाने के लिये जनता के समक्ष एक छोटी सी अपील निकाली ।

नेहरू जी की प्रिय पत्नी का स्वास्थ्य इन दिनों काफी गिर गया था । वे किसी योग्य डाक्टर से उनकी बीमारी के संबंध में सलाह लेकर उनका इलाज कराना चाहते थे, अतः १५ जनवरी को उन्होंने कलकत्ता जाने का निश्चय किया, जिससे २६ जनवरी को स्वतंत्रता-दिवस के अवसर पर वे लौट कर प्रयाग में राष्ट्रीय समारोह में उपस्थित रह सकें ।

बिहार-भूकम्प में नेहरू जी के कार्य

१५ जनवरी १९३४ को तीसरा पहर था। उन दिनों प्रयाग में माघ-मेला आरंभ हो गया था। नेहरू जी अपने भवन के बरामदे में खड़े आगत किसानों से बात कर रहे थे कि इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि सारी धरती जोरो से कोंप रही है। भूकम्प का इतना तीव्र अनुभव उन्हें अपने जीवन में इसके पूर्व कभी न हुआ था। कुछ क्षणों के लिए तो वे स्तम्भित से रह गये, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रचंड दानव गेब की सूखी डाल की तरह सम्पूर्ण पृथ्वी को क्रोधित हो हिला रहा है। उस समय उन्हें यह न मालूम हो सका कि कुछ ही मिनटों की जमीन के दिला की वह अजीब प्राकृतिक धडकन बिहार और अन्य स्थानों के लाखों असहाय आदमियों के लिये कितनी घातक साबित हुई।

उसी दिन शाम को नेहरू जी अपनी पत्नी को लेकर उनके इलाज के लिये कलकत्ता चल दिये। विनाशकारी भूकम्प के दुष्परिणाम से अनभिज्ञ अपनी गाड़ी में बैठे हुए वे उसी रात को भूकम्प-पीडित प्रदेश के दक्षिण हिस्से से हो कर गुजरे। दूसरे दिन भी कलकत्ते में भूकम्प द्वारा हुए घोर अनर्थ के बारे में उन्हें विशेष जानकारी न प्राप्त हुई; यद्यपि तीसरे दिन कुछ-कुछ उबती खबरों द्वारा उस वज्रपात का उन्हें आभास लगा; परन्तु फिर भी उन्होंने उसे उतना भयानक नहीं समझा था जितना भयानक वास्तव में उसका प्रभाव हुआ। अतः वे उसकी विशेष चिन्ता न करके कलकत्ते जिस उद्देश्य से आये थे उसे पूर्ण करने में लग गये। अपनी पत्नी के विषय में वह कई डाक्टरों से मिले और अन्त

मे यही निश्चय हुआ कि एक दो महीने बाद कमला देवी फिर कलकत्ते आकर अपना इलाज कराये । इसके अतिरिक्त वहाँ नेहरू जी अपने बहुत से पुराने मित्रों और सहयोगियों से भी मिले, जिनसे लम्बे अर्से से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी । बंगाल में चारों तरफ दमन के कारण लोगों के दिलों में जो डर बैठ गया था उसका भी उन्होंने अनुभव किया ।

कलकत्ता में नेहरू जी तीन दिन ठहरे तथा तीन सार्वजनिक सभाओं में उन्होंने व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने आतंकवादी क्रान्तिकारियों के कार्यों को देश के लिये अहितकर बतलाया । उन्होंने शासकों के उन तरीकों पर भी बहुत ही जोर प्रकट किया जिसके जरिये बंगाल की सारी जनता का अंधाधुंध दमन कर मानव-समाज पर बलात्कार किया जा रहा था । इस मानवता के प्रश्न के आगे राजनीतिक प्रश्न ने अत्यन्त आवश्यक होते हुये भी, गौण स्थान प्राप्त कर लिया था । बाद में कलकत्ता में उन-पर जो मुकदमा चला उसमें ये ही तीन भाषण उनके विरुद्ध तीन आरोप बनाये गये थे ।

कलकत्ता से पं० नेहरू सपत्नीक विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर से मेंट करने शान्ति-निकेतन गये । कवि से मिलना हमेशा ही आनन्ददायक होता है । इसके पूर्व जवाहरलाल जी दो बार और शान्ति-निकेतन आ चुके थे, तथा बंगाल की आत्मा, कवि रवीन्द्र से मेंट कर चुके थे । परन्तु उनकी पत्नी कमला देवी का शान्ति-निकेतन के वातावरण से परिचित होने का यहाँ पहला अवसर था ।

कलकत्ता से प्रयाग लौटते हुये नेहरू जी भूकम्प द्वारा हुई हानि का वास्तविक ज्ञान करने के लिये पटना उतर गये । मिहार-केसरी बाबू राजेन्द्र प्रसाद हाल ही में जेल से छूटे थे, और वे भूकम्प-पीड़ितों को सहायता के लिये काफी तत्परता से कार्य कर रहे थे । नेहरू जी को उस दिन पहली बार ज्ञात हुआ कि उत्तर भारत में आये उस भीषण भूकम्प ने मिहार-प्रात को प्रायः खस्त ही कर दिया था । जवाहरलाल अपनी पत्नी के भाई के मकान में ठहरने वाले थे, परन्तु भूकम्प से वह खण्डहर

हो गया था । पहले वह भवन ईंटों की एक बड़ी, दो-मंजिली इमारत थी । अतः जवाहर लाल जी को अन्य लोगों की तरह खुले मैदान में ही डेरा डालना पड़ा ।

दूसरे दिन जवाहरलाल जी मुजफ्फरपुर गये । भूकम्प आये पूरे सात दिन गुजर चुके थे । पर अभी तक सिवा कुछ खास रास्तों के साफ करने के अलावा कहीं भी मलबा उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था । इन रास्तों को साफ करते समय बहुत सी लाशें निकली थीं । इनमें से कुछ तो विचित्र भावमयी अवस्था में थीं, जैसे किसी गिरती हुई छत या दीवार से बचने का प्रयत्न कर रही हों । बस्तु घरों और बड़ी-बड़ी इमारतों के खंडहरों का दृश्य बहुत ही मार्मिक और रोमांचकारी था । जो लोग बच गये थे, वे अपने दिल दहलाने वाले अनुभवों की याद कर बहुत भयभीत हो जाते थे । जवाहरलाल जी ने कितने ही बस्तु स्थानों में घूम-घूमकर वहाँ की दुर्दशा देखी और पीड़ित जनता को सन्तुष्ट करना दाँ ।

प्रयाग लौट आने के पश्चात् कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ वे पीड़ित क्षेत्र की मदद के लिए धन और जन जुटाने में व्यस्त हो गये । नेहरू जी ने धन के लिये एक अपील प्रकाशित की और उसी अपील में उन्होंने बिहार-सरकार की अकर्मण्यता की आलोचना भी की थी । जिसका मतलब यह था कि यदि बिहार-सरकार के अधिकारियों ने मलबा आदि हटाने में कुछ भी तत्परता दिखाई होती तो बहुतों की जान बच जाती । केवल एक मुँगेर नगर में ही भूकम्प से हजारों व्यक्ति मरे थे, और तीन सप्ताह बाद भी नेहरू जी ने वहाँ जाकर देखा कि गिरे हुए बस्तु मकानों के मलबे का पहाड़ ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था ।

प्रयाग की भूकम्प-सहायक-समिति ने नेहरू जी को बिहार के भूकम्प पीड़ित इलाकों में जाने के लिये, और वहाँ की जानेवाली सहायता के कार्यों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त किया । वे तुरन्त

अकेले ही खाना हो गये तथा भूकम्प-ग्रस्त क्षेत्रों का कई दिनों तक निरीक्षण करते रहे। नेहरू जी को इस दौरान में बड़ा परिश्रम करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें सोने तक की फुर्सत न मिल पाती थी। प्रातः ५ बजे से लगभग अर्धरात्रि तक वे कार्यकर्ताओं के साथ बराबर निरीक्षण ही करते रहते तथा रिपोर्ट ही बनाते रहते थे।

नेहरू जी के ही शब्दों में, “हम कभी दरारोंवाली टूटी-फूटी सड़कों पर मोटर में जा रहे होते, तो कभी छोटी-छांटी डोंगियों के द्वारा ऐसे स्थानों में उतर रहे होते जहाँ पुल गिरे पड़े थे, या जहाँ जमीन का सतह में फर्क आ जाने से सड़के पानी में डूब गयी थीं। मानों किसी दैत्य के हाथों द्वारा मरोड़ी हुई, शहरों में ढेर के ढेर खंडहरों और टूटी हुई इमारतों, तथा दोनों ओर के मकानों की कुर्सी से ऊपर उठी हुई सड़कों का दृश्य बड़ा हृदयस्पर्शी था। इन सड़कों की बड़ों-बड़ी दरारों में से पानी और रेत जोर से निकल रहे थे, जिसमें असंख्य मनुष्य और जानवर बह रहे थे। उन शहरों से भी ज्यादा उत्तर बिहार के मैदानों पर—जिन्हें बिहार का बाग कहा जाता था—उजड़ेपन और विनाश की छाप लगी हुई थी। मीलों तक फैली हुई बालू की रेत, पानी के बड़े-बड़े तालाब और विशालकाय दरारे छोटे-छोटे असंख्य ज्वालामुखी के मुँह से बन गये थे, जिनमें से बालू, रेत, पानी निकलता था। इस इलाके में हवाईजहाज पर उड़ने वाले अंग्रेजों ने कहा था कि ये दृश्य लंबाई के जमाने में और उसके कुछ बाद के उत्तरी फ्रांस के युद्ध-क्षेत्रों से बहुत कुछ मिलते जुलते थे। ऐसे अनेक भयानक दृश्यों को देखते हुए नेहरू जी कार्य-कर्ताओं के साथ सहायता-कार्य में संलग्न रहे।

नेहरू जी ने मुँगेर में स्वयं अपने हाथों से कठिन कार्य करने का उदाहरण उपस्थित किया। उस समय वहाँ अनेक सेवा-समितियों के कार्यकर्ता—जिसमें पुरुष और स्त्रियों दोनों ही थे—कार्य कर रहे थे। जवाहरलाल जी स्वयं टोकरी और फावड़ा लेकर इन कार्यकर्ताओं के साथ

आगे बढ़े और ध्वस्त इमारतों के मलवे को खोदने लगे। दिन भर परिश्रम के साथ वे खुदाई करते रहे, जिससे अन्य कार्यकर्ताओं का भी उत्साह काफी बढ़ गया और वे अधिक तत्परता से कार्य करने लग गये।

नेहरू जी ने व्यापक रूप से घटनाका प्रदेशों का दौरा किया। यहाँ तक कि वे नेपाल की सीमा तक पहुँच गये। उन्होंने अनक हृदय-विदारक दृश्य देखे। नेहरू जी पटना आये तथा वहाँ सहयोगी कार्यकर्ताओं से, पीड़ितों को सहायता पहुँचाने के विषय पर देर तक बात करते रहे, इसके पश्चात् वे ११ फरवरी को प्रयाग लौट आये। भूकम्प-ग्रस्त क्षेत्रों में काम करने तथा सहायता पहुँचाने वाली संस्थाओं में सेन्ट्रल रिलीफ कमिटी ने जिसके अव्यक्त ब्रावू राजेन्द्र प्रसाद जी थे तथा जिसका कांग्रेस से कोई विशेष सम्बन्ध न था, काफी काम किया।

लम्बे दौरे के कारण नेहरू जी बहुत थक गये थे, और प्रतिकूल मौसम के प्रभाव से उनके चेहरे का रंग भी बदल गया था। अत्यधिक परिश्रम और पूरी नींद न होने के कारण वे बिल्कुल शिथिल हो गये थे। उन्होंने आने के पश्चात् प्रयाग-सहायता-समिति के लिए रिपोर्ट लिखने का प्रयत्न किया, परन्तु, वे असफल रहे तथा नींद ने उन्हें दबोच लिया। उस दिन वह १२ घण्टे तक खराब भरते रहे।

दूसरे दिन सायंकाल ५० नेहरू अपनी पत्नी के साथ चाय-पान कर रहे थे कि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन उनसे मिलने पहुँचे। वे लोग वरामदे में खड़े ही हुए थे कि इतने में पुलिस की एक मोटर आयी और उस पर से एक पुलिस अफसर ने उतर कर उन्हें सलाम किया। नेहरू जी तत्काल ही सड़ कुछ समझ गये अतः उन्होंने हास्य करते हुए कहा, “आइये! आप का इन्तज़ार तो बहुत दिनों से था।” पुलिस इन्स्पेक्टर ने क्षमा-याचना करते हुए कहा, “कसूर हम लोगों का नहीं है। वारण्ट कलकत्ते से आया है।”

नेहरू जी ५ महीने १३ दिन की स्वतंत्रता के पश्चात् फिर अपने

चिरपरिचित स्थान जेल में भेज दिये गये। कलकत्ते में उन्होंने जो तीन भाषण दिये थे वह उसी की सजा थी। पहले नेहरू जी को कलकत्ता प्रेसिडेन्सी जेल में रखा गया परन्तु बाद में उनका तगदला अर्लीपुर सेंट्रल जेल में हो गया। वहाँ उन्हें एक १० फुट लम्बी और ६ फुट चौड़ी कोठरी रहने के लिये दी गयी। इस कोठरी के सामने एक बरानदा और छोटा सा सदन था। कोठरी की ओर जेल के वायचौलाने की चिमनियाँ थी जो लगातार अपने मुँह से काला धुआँ उगलती रहती थीं। कभी-कभी यह धुआँ हवा के रुख पर उड़ता हुआ आकर नेहरू जी का दम घोटने लगता था। उन्हें अधिकतर अपनी कोठरी में बन्द रहना पड़ता, कसरत और टहलने की कोई सुविधा न दी गयी थी, अतः उस गन्दे वातावरण में उनका स्वास्थ्य तेजी के साथ गिरने लगा। अंततः उन्हें अधिकारियों ने कुछ समय के लिए कोठरी के बाहर टहलने तथा कसरत करने की इजाजत दे दी।

परन्तु नेहरू जी का स्वास्थ्य न सुधरा और बजन दिन पर दिन गिरता गया, फलस्वरूप उन्हें वहाँ से अपने चिर-परिचित स्थान देहरादून के जेल में भेज दिया गया। नेहरू जी पर्वतीय जलवायु का स्वन तथा हृदयग्राही दृश्यों के अवलोकन की कल्पना कर इस तबादले से काफी प्रसन्न हुए। किन्तु उसकी यह मनोकामना पूर्ण न हो सकी, कारण वे १४ फुट ऊँची चहारदीवारी से घिरे एक बंद स्थान में रखे गये थे। जहाँ से प्रकृति की सहृदय लीला तथा हर देखने की कल्पना स्वप्नमात्र ही थी। नेहरू जी के ही शब्दों में, 'मैं जानता था कि इन दीवारों के दूसरी ओर कुछ फुट की दूरी पर, वायुमंडल में ताज़गी और सुगन्ध भरी हुई है, पृथ्वी और आकाश में घर्ती की ठंडी-ठंडी न्हल फैल रही है और दूर-दूर तक के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं : लेकिन ये सब मेरी पहुँच के बाहर थे। बार-बार उन्हीं घेरदार दीवारों को देखते-देखते मेरी आँखें पथरा जाती थीं। जेल के गार्डर के जाने जाने के लिए जब कभी मेरे सदन का लोह का दरवाजा खुलता था

तो एक क्षण के लिए बाहरी दुनिया की झलक, लहराते हुए हरे-भरे खेत और रंग-विरंगे वृक्ष, जिन पर मेह की वृद्धों मोती की तरह चमकती थीं, बिजली की कौंध की भाँति अकस्मात् दृष्टिगोचर होकर तत्काल विलीन हो जाते थे " हरियाली और ताजगी को ये अल्प भौक्तियाँ अब मुझे अच्छी नहीं लगती थीं। उन्हें देख कर मुझे घर की याद आ जाती और दिल में एक टीस सी उठती थी; इसलिए जब कभी दरवाजा खुलता मैं बाहर की ओर नहीं देखता था।"

अलीपुर-कारागार में नेहरू जी को समाचार-पत्र पढ़ने को नहीं दिये जाते थे पर देहरादून में वे फिर से मिलने लगे, अतः उन्हें बाहर के दूसरे समाचारों का भी कुछ-कुछ ज्ञान होने लगा। उन्हें शायद हुआ कि अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन करों ३ वर्ष के बाद फिर से पटना में हुआ है। अधिवेशन की ठंढी कार्यवाहियों से नेहरू जी को विशेष निराशा हुई। वे झुंझला उठे तथा अपने उग्र विचारों के कारण वे अपने देश में अपने साथियों के बीच भी, अपने को बौद्धिक रूप में अकेला और असहाय पाने लगे।

जुलाई के अन्तिम दिनों में कमला नेहरू का स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिरने लगा था तथा स्थिति चिंताजनक हो गयी। अतः ११ अगस्त को नेहरू जी को अस्थायी तौर पर मुक्त कर दिया गया। नेहरू जी जब घर पहुँचे तब उन्होंने देखा, उनकी प्रिय पत्नी के शरीर में केवल अस्ति-यस्त्र मात्र ही शेष रह गया है। वह अत्यन्त कमजोर हो गयी थी। रोग से टकर लेते-लेते उनका शरीर छायामान रह गया था।

श्रीमती कमला नेहरू

जवाहरलाल सरीखे उत्कट देशभक्त, क्रान्तिकारी नेता की पत्नी कमला नेहरू भी कोई सामान्य स्त्री नहीं थीं। एक अत्यन्त तेजस्वी और तपस्वी पति के साथी, श्रीमती कमला नेहरू भी संयमी तपस्विनी की तरह सच्ची देश-सेविका हो गयी थीं। वह अपने कर्मठ पति के राजनीतिक आन्दोलन और कार्यों में जीवन के अन्त समय तक शामिल रही, और किसी भी प्रकार के कट सहन करने अथवा आत्मत्याग करने से वह कभी पीछे न हटीं। निश्चय ही नेहरूजी के साथ उनकी आदर्श पत्नी का नाम भी भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरो में अंकित और अमर रहेगा।

नेहरू जी जब २६ साल के थे तब उनके परिणय-सम्बन्ध में आवद्ध नव बधू कमला ने, सासारिक बातों से सर्वथा अनभिज्ञ अबोध बालिका की भाँति, उनके सम्पन्न गृह में प्रवेश किया था। नेहरू जी ने असीम आनन्द के साथ अनुभव किया था कि वय और मानसिक दृष्टि-विन्दुओं में काफी अन्तर होते हुए भी इस सुकुमार और भावुक वाला का मस्तिष्क फूल की तरह धीरे-धीरे विकसित हो उनके अनुत्पन्न हो रहा है। कभी-कभी घर और बधू विपरीत दृष्टिकोण होने के कारण बच्चों की तरह झगड़ पड़ते और थोड़ी देर बाद ही दूध और पानी की तरह एक हो अपने हठ पर खिलखिला कर हँस भी पड़ते। दोनों का स्वभाव तेज था, दोनों ही तुनकमिजाज थे और दोनों में ही अपनी शान रखने की बच्चों की सी जिद थी।

कुछ दिनों पश्चात् देश की राजनीति ने नेहरू जी को पूर्णतः अपनी

और खींच लिया। पंजाब में ब्रिटिश शासकों के द्वारा भीषण हत्याकाण्ड होने के पश्चात्, रोते हुए पंजाब के आतस आँसुओं को पोखने के लिए जनता के खून ने जोर मारा, एक अभूतपूर्व राजनीतिक आन्दोलन की लहर उठी, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में दावागिरी की तेजी के साथ सर्वव्यापी क्रान्ति के रूप में, हिन्दुस्तान के कोने-कोने तक फैल गयी। स्वतंत्रता-संग्राम में पं० जवाहरलाल, गांधी जी के एक प्रमुख सहयोगी तथा नायक रहे, और वीराङ्गना कमलादेवी पतिदेव की भक्त अनुयायिनी तथा सहकारिणी रही। इतना ही नहीं, वह पति को चिन्तित अथवा निराश देखकर, अपनी वेदना को गरल की तरह पीती हुई प्रसन्न मुख से उन्हें उत्साहित करतीं, और यह कहना अत्युक्ति न होगा कि जवाहरलाल जी को उनकी सम्मति और मीठी बातों से काफी सान्त्वना तथा उत्साह मिलता था।

अस्वस्थ रहने पर भी श्रीमती कमला नेहरू पति की भोंति राजनीतिक आन्दोलन में सदा उनके साथ रहीं और उन्हीं की भोंति वह भी कई बार कारागार गई थीं। सत्याग्रह-आन्दोलन ने उन्हें राष्ट्र की स्वतंत्रता के प्रेमी सैनिकों की प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया था। वह यद्यपि एक सुकोमल राजकुमारी की तरह थी, पर देश के लिए कष्ट सहन करने और आन्दोलन की गतिविधि संचालन करने में रण की एक ऐसी निभंक वीराङ्गना भी थीं, जो किसी भी सुख-चैन की परवाह नहीं करतीं। स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार होते ही उन्होंने अपने विदेशी कपड़ों की होली जलाई तथा खादी धारण की। वे राष्ट्रीय जुलूसों के साथ भंडा लिए आगे-आगे चलतीं, विदेशी वस्त्र-विक्रेताओं से ऐसा न करने के लिए आरजू-मिन्नत करतीं, तथा दुकानों पर धरना देतीं, और पुलिस के निर्दय प्रहारों की अवहेलना करती हुई लोगों में जोश का संचार करती थीं। वह अपने पति की तरह त्रिभुज निडर और साहसी थीं। पं० नेहरू की दोनों बहनो तथा अन्य महिलाओं के साथ वह हर मुहल्ले में स्वदेशी और स्वराज्य का स्वर पहुँचातीं। उनके प्रयत्न से नगर की बहुतेरी लड़कियाँ तथा

महिलाओं ने स्वयंसेविकाओं में अपने नाम लिखा लिये थे। नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात् भी ये स्वयंसेविकाएँ सत्याग्रह-आन्दोलन को जीवित रखती थीं।

महात्मा गांधी ने जब नमक-कानून तोड़ने का आन्दोलन आरम्भ किया तो जवाहरलाल जी भी प्रयाग में अपने साथियों के साथ नमक बनाने में जुट गये थे। गांधी जी डाढ़ी में गिरफ्तार हुए, तथा जवाहरलाल जी भी दो दिन बाद प्रयाग में गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये थे। श्रीमती कमला नेहरू ने पति की गिरफ्तारी के पश्चात् भी उनका कार्य जारी रखा, तथा अपनी स्वयंसेविका-सेना के साथ प्रयाग में अधिकारियों की नाक के नीचे ही नमक बना कर कानून भंग किया था, पर सरकार ने असन्तोष की वृद्धि के डर से उस समय उन्हें गिरफ्तार न करना ही उपयुक्त समझा।

नमक-कानून-भंग करने के अपराध में पं० जवाहरलाल की गिरफ्तारी के पश्चात् वीराङ्गना कमला देवी के उस रुग्ण दुबले-पतले शरीर में न जाने कहीं से असीम विद्युत् शक्ति आ गयी। वे बहिष्कार-आन्दोलन में और भी तीव्रता के साथ जुट गयीं। ग्रीष्म की तपता हुई लू और दुपहरिया में, वे स्वयंसेविकाओं के साथ निकलती और लोगों से विदेशी वस्त्र न खरीदने के लिए प्रार्थना करतीं। उन्होंने सुदूर गाँवों का दौरा किया और उन्हें स्वराज्य तथा स्वदेशी का सन्देश सुनाया। उन्होंने कर-वन्दी आन्दोलन में भी प्रमुख भाग लिया था।

एक बार प्रयाग के बाहर एक गाँव में विद्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में वे वन्दी कर ली गयीं। उन पर 'कानून द्वारा स्थापित सरकार' के विरुद्ध लोगों को भड़काने का अपराध लगा कर उन्हें कुछ महीनों की सजा दी गई, और वे लखनऊ जेल में भेज दी गयीं। इसके पश्चात् सरकार और कांग्रेस में सुलह की बातें प्रारम्भ हुईं, और देश में कुछ समय के लिए शान्ति का वातावरण स्थापित हो गया।

अस्थायी सधि के पश्चात् गांधी जी गोलमेज-परिषद् में कांग्रेस के

एक मात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गये, और देश में अस्थाई रूप में आन्दोलन रोक लिया गया। पति के अनुसार ही श्रीमती कमला नेहरू भी संधि का महत्त्व, और शान्ति के नियमों के पालन का संदेश जनता को मुनाती थी। आन्दोलन में परिश्रम के साथ निरन्तर भाग लेने से उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था अतः पं० जवाहरलाल जी जल-वायु परिवर्तन कराने के उद्देश्य में उन्हें लंका ले गये। कुछ समय तक वहाँ रहने के पश्चात् वे जब फिर सपत्नीक भारत लौटे उस समय तक लंडन में गोलमेज-परिषद् का स्वर्ग समाप्त हो चुका था। ब्रिटिश सरकार की कूटनीति और धूर्तता से देश में फिर असन्तोष फैल गया था। गांधी जी लंडन से चल चुके थे और मार्ग में ही थे कि शासकों की ओर से छेड़-छाड़ के फलस्वरूप भारत में फिर आन्दोलन छिड़ गया। नेहरू जी ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का फिर संचालन किया तथा बन्दी हुए। कांग्रेस का आन्दोलन तथा सरकारी दमन-चक्र दोनों ही तीव्रता से चल रहे थे। कुछ दिनों के भीतर ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता फिर से जेल में ठूस दिये गये। प्रयाग में सिर्फ श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित तथा कमला जी ही बच गई थीं। नगर में घारा १४४ का कड़ा प्रतिबंध था, परन्तु वे दोनों ही महिलायें पुलिस की लाठी और अन्य निर्दयता के बीच भी कानून-भंग कर स्वयंसेविकाओं का संगठन करतीं।

कमला जी इसी समय कांग्रेस-कार्यकारिणी की सदस्या चुनी गयीं और उसकी बैठक के सम्बन्ध में उन्हें बन्दी जाना पड़ा। वहाँ भी उन्होंने आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तत्पश्चात् प्रयाग लौट आयीं। यहाँ लौटने पर वह अत्यधिक अस्वस्थ हो गयीं। उनकी सास, माता-स्वरूप रानी भी बीमार थीं। आनन्द-भवन में सास और बहू अलग-अलग रोग-शय्या पर पड़ी थीं। कमला देवी को तपेठिक का पुराना रोग था, जो इलाज होने पर कुछ अच्छा हो जाता था पर परिश्रम करने से फिर उभर आता था। कलकत्ते से डाक्टर विधानचन्द्र राय उनके इलाज के लिए बुलाये गये। पं० नेहरू उस समय जेल में थे। माता तथा पत्नी की बीमारी जब

अधिक बढ़ी तब सरकार ने उन्हें अस्थाई तौर पर कुछ दिन के लिए मुक्त कर दिया ।

नेहरू जी अपनी प्रिय पत्नी से मिलने शीघ्र आनंद-भवन में पहुँचे । माता की रूग्णावस्था का समाचार प्राप्त कर उनकी पुत्री इन्दिरा शान्तिनिकेतन से आ चुकी थी । पत्नी के शरीर और स्वास्थ्य की यह दशा देखकर नेहरू जी का हृदय रो पड़ा । दाना चुगने के लिए आते पक्षियों की भोंति, कमला के सहवास में व्यतीत किये हुए पिछले सुखद दिनों की याद, एक एक कर उनके स्मृति-पटल पर उतरने लगी । वैवाहिक जीवन के ये अठारह वर्ष, परन्तु वे कितने दिनों तक आनंदपूर्वक एक साथ रह सके ? जीवन के इन अठारह वर्षों में से कितने ही साल उन्होंने जेल की दुर्गन्धयुक्त सीलन भरी कोठरी में बिता दिये, और उनकी प्रिय पत्नी ने एकाकी ढंग से पति के सान्निध्य और प्रेम-पूर्ण व्यवहार से दूर, मन मारे अस्पताल और सेनिटोरियम में बिता दिये । वह बीमार पड़ी हुई जीवन के लिये संघर्ष कर रही थीं, क्योंकि राष्ट्रीय संग्राम में पूर्ण हिस्सा लेने में अशक्त होने के कारण उनकी तेजस्वी आत्मा पिंजरे में बन्द पक्षी की भोंति छूटपटा रही थी । शरीर के समर्थ न होने के कारण न तो वह ठीक तरह से कार्य ही कर सकती थी न ठीक तौर पर अपना इलाज ही करा पाती थी, नतीजा यह हुआ कि अन्दर ही अन्दर सुलगती रहनेवाली आग ने उनके शरीर को खा डाला ।

क्रूर काल के निष्ठुर प्रहार होने पर भी उनके सौन्दर्य तथा तेज में कमी न हुई थी । नेहरू जी के ही शब्दों में, “वैवाहिक जीवन के अठारह वर्ष पश्चात् भी उसके मुख पर मुग्धा कुमारी का भाव अभी तक वैसा ही बना था, प्रौढ़ता तथा जरावस्था का कोई चिह्न न था । प्रथम दिन नव वधू बन कर वह जैसी हमारे घर आई थी, अब भी विल्कुल वैसी ही मालूम होती थी ।”

अपने छुटकारे के ११ वें दिन, २३ अगस्त को नेहरू जी फिर गिरफ्तार कर लिए गये । जैसे ही वे मोटर पर बैठे उनकी रूग्ण माँ

वाहे फैलाये दौड़ी हुई आई' । परन्तु वेब्स नेहरू को माता को उसी दशा में छोड़ तत्काल ही नैनी-जेल की ओर रवाना होना पड़ा । पति के पुनः जेल जाने से कमला देवी की सुधरती हालत फिर बिगड़ गयी । नेहरू जी को यह सूचना दी गई कि यदि वे सरकार को यह आश्वासन दें कि अस्थायी समय तक के लिए छोड़ दिए जाने पर वे उन दिनों राजनीति में भाग न लेंगे—चाहे वह अलिखित ही क्यों न हो—तो उन्हें प्रिय पत्नी की सेवा शुश्रूषा के लिए छोड़ा जा सकता है । परन्तु उन्होंने कमला के तथा अपने आत्मसम्मान का ध्यान कर उसे स्वीकृत न किया ।

अक्टूबर के आरम्भ में उन्हें एक दिन पत्नी से भेट कराने के लिये ले जाया गया । वे ज्वर में अचेत पड़ी हुई थीं, पति को देखते ही उनके अधरों पर मन्द मुस्कराहट नाच उठी और उन्होंने उन्हें कुछ नीचे झुकने का इशारा किया । उनके नीचे झुकने पर उन्होंने धीरे से उनके कान में कहा—“सरकार को आश्वासन देने की यह कैसी बात हो रही है ? ऐसा हरगिज न करना ।” पति के सहवास में रहने की तीव्र इच्छा होते हुए भी उस वीरगना ने अपने कर्तव्य को प्रथम स्थान दिया तथा अपनी मनोभावना के मधुर भावों को भी कुचल डाला ।

कमला देवी का स्वास्थ्य तेजी से गिरता देख कर उन्हें डाक्टरों ने भुवाली ले जाने की सलाह दी । जाने के एक दिन पूर्व नेहरू जी को उनके पास पहुँचाया गया । नेहरू जी के दुखित मन में उस समय अनेक अनिष्टकारी भावनाएँ उठ रही थी । पर चेहरे से वे अपना भाव व्यक्त नहीं कर रहे थे । उन्होंने देखा कि उस दिन उनकी प्रिय पत्नी कुछ स्वस्थ तथा प्रसन्न थी । उनके जाने के करीब ३ सप्ताह पश्चात् नेहरू जी भी अल्मोड़ा जेल पहुँचाये गये, ताकि वे कमला के निकट रहे तथा उनसे मिल सकें । पत्नी की हालत में उतार चढ़ाव होते रहने से उन्हें हमेशा चिन्ता रहती थी और वे उदास से रहते थे, परन्तु पर्वत की शीतल वायु कुछ समय के लिये उन्हें स्वस्थ तथा शान्त कर देती थी ।

कमला देवी से नेहरू जी की मुलाकात महीने दो महीने में एक दो बार ही हो पाती थी। यह बात समाचार-पत्रों में छपने पर तथा विरोधी पार्टी द्वारा प्रश्न किये जाने पर उसका खंडन करते हुए तत्कालीन भारत-मंत्री ने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में कहा था, “पं० नेहरू को सप्ताह में एक या दो बार अपनी पत्नी से मिलने की आज्ञा है।” भारत-मंत्री की यह बात कैसी मिथ्या थी। पत्नी के पास ले जाये जाने पर पं० नेहरू भरे हुये हृदय से अपनी रूग्ण प्रियतमा से मिलते, और कभी कभी तो बड़े वेदना भरे हृदय से सोचने भी लगते थे कि निकट भविष्य में एक ऐसा दिन भी आ सकता है, जब जेल वापस लौटते समय पत्नी से यह विदा शायद चिर विदा हो। इन्हीं दिनों पं० नेहरू पर नियति का दूसरा क्रूर प्रहार हुआ, उन्हें यह सूचना मिली कि उनकी रूग्ण माता को बम्बई में लकवा मार गया है।

इन्हीं दिनों बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। नेहरू जी को इसकी सूचना प्राप्य अखबारों द्वारा हुई। परन्तु अधिवेशन की तत्कालीन कार्यवाहियों ने उनके मन में स्फूर्ति का संचार नहीं किया। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होते हुये भी उन्हें सम्पूर्ण अधिवेशन की कार्यवाही नीरस सी ज्ञात हुई। इस कान्फ्रेंस में गांधी जी का कांग्रेस से अलग होना कुछ महत्वपूर्ण घटना थी, यद्यपि इसका महत्व कोई विशेष नहीं था क्योंकि यदि वे चाहते तो भी अपने व्यापक नेतृत्व-पद से अपना पीछा नहीं छुड़ाते सकते थे। वे उस समय शायद कांग्रेस से इसलिये अलग हो गये थे कि कहाँ उनके कारण कांग्रेस किसी कठिनाई में न पड़ जाये। वे अपने व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात सोच रहे थे, जिसमें यदि कांग्रेस को भी घसीटा जाता तो सरकार से फिर युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना थी और वे इसे कांग्रेस का प्रश्न बनाना नहीं चाहते थे। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत का भावी विधान बनाने के उद्देश्य से विधान-समिति-निर्माण का विचार स्वीकार कर लिया। नेहरू जी को भी इस विचार से विशेष प्रसन्नता हुई।

बम्बई-कांग्रेस के पश्चात् फौरन ही असेम्बली का चुनाव आया । कांग्रेस ने उसमें भाग लिया तथा काफी स्थानों पर जीती भी । नेहरू जी को चुनाव में विशेष दिलचस्पी न होने पर भी कांग्रेस की जांत से विशेष प्रसन्नता हुई, क्योंकि चुनाव में सम्प्रदायवादी तथा अवसरवादी दलों को विशेष हार हुई थी । वे यह पूर्णतः जानते थे कि असेम्बलियों में पहुँच कर भी कांग्रेसी नेता देश का कोई विशेष हित न कर सकेंगे ।

इधर भारतीय राजनीति का क्रम अपनी अवाध गति से बढ़ता हुआ एक-एक पग आगे जा रहा था, और साथ ही उधर नेहरू जी की प्रिय पत्नी के जीवन के दीप का तेल भी धीरे-धीरे चुक रहा था । उनकी स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गयी, अतः डाक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें विदेश भेजा जाना निश्चित किया गया । पहले कुछ दिन तक उनका इलाज जर्मनी में होता रहा पश्चात् उन्हें लॉजान (स्विट्जरलैंड) भेजा गया । इसके पश्चात् ४ सितम्बर १९३५ को पं० जवाहरलाल जी भी अल्मोड़ा जेल से छोड़ दिये गये । वे तुरन्त वायुयान से अपनी प्रिय पत्नी से मिलने के लिये योरोप खाना हो गये । उन्होंने देखा कि वहाँ उनकी पत्नी जीवन और मृत्यु के बीच पड़ी संघर्ष कर रही हैं । पति को आया देखकर कमला देवी को काफी सान्त्वना प्राप्त हुई ।

२८ फरवरी १९३६ को जब श्रीमती कमला नेहरू का देहावसान हुआ, पं० जवाहरलाल नेहरू उनके निकट ही थे, और अपनी निष्प्राण प्रिया को देखकर आँसू बहा रहे थे । उसके कुछ दिन पूर्व ही उन्हें यह समाचार मिला था कि ये दूसरी बार कांग्रेस के सभापति चुने गये हैं । अभी चिर वियोग के गीले आँसू सूख भी न पाये थे कि कर्त्तव्य ने, देश ने, भारत माता की ३५ कोटि सन्तान ने, अपने युद्ध के नेतृत्व के लिए फिर से उस महान् जननायक का आह्वान किया ।

डा० पट्टाभि सीतारमैया के शब्दानुसार, “श्रीमती कमला देवी की मृत्यु केवल जवाहरलाल जी पर ही एक व्यक्तिगत चोट न थी वरन् वह राष्ट्र के लिए एक असाधारण क्षति थी । जवाहरलाल जी के

जीवन-कार्य में उनकी पत्नी का जो सहयोग था, उसके प्रति राष्ट्रीय कृतज्ञता, और जवाहरलाल जी के दुख से राष्ट्रीय सदानुभूति की यह तो एक तुच्छ अभिव्यक्ति थी कि उनको कांग्रेस का दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया ।” परंतु क्या यह ‘तुच्छ अभिव्यक्ति’ बिराट् व्यक्तित्व और उस महान् व्यक्ति को इस पद पर एक बार फिर अधिष्ठित कर उसके महत्व को कुछ विशेष बढ़ा सकती थी ? और उसकी मरुत आशाओं पर चक्र से पड़े उस तुषारपात द्वारा हुई हानि अथवा क्षति को अंश मात्र भी पूर्ण कर सकती थी ? नहीं, कदापि नहीं !

पत्नी का अस्थि-फूल लेकर नेहरू जी प्रयाग आये । बमरौली हवाई अड्डे पर अन्य भारतीय नेतागण उनसे मिले । उसी दिन आनंदभवन में एक बहुत बड़ा जुलूस उठा. जो कटरे से होता हुआ चौक गया, और वहाँ जवाहरलाल पार्क में एक वृहत् सभा हुई जिसमें श्रीमती कमला नेहरू की सेवाओं का स्मरण कर उन्हें श्रद्धाजलि अर्पित की गयी । इसके पश्चात् जुलूस वहाँ से त्रिवेणी-तट पर पहुँचा । नेहरू जी ने वहाँ अपनी सहवर्त्मिणी के अस्थि-फूलों का विसर्जन किया । उस समय हजारों मनुष्यों के कंठ शोक से आवद्ध थे । अपने प्रिय नेता की प्रिय पत्नी के शोक में उनके नेत्रों में अश्रुवर्षा हो रही थी ।

लखनऊ तथा फैजपुर कांग्रेस एवं चुनाव

लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस का ४६ वॉ अधिवेशन १२ अप्रैल १९३६ को आरम्भ हुआ। इसके पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन अक्टूबर १९३४ में श्री राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में बम्बई में हो चुका था। कांग्रेस में समाजवादी तथा वामपंथी विचारधारा का उदय हो जाने के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष-पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता सभी को अनुभव हो रही थी, जो कांग्रेस के भीतर दिन पर दिन जोर पकड़ने वाले समाजवादी दल का विश्वास प्राप्त करने के साथ-साथ महात्मा गान्धी के सिद्धान्तों का सच्चा अनुयायी भी हो, तथा उनके आदर्शों के अनुसार कांग्रेस की बागडोर सम्हाल सके। डा० पट्टाभि सीतारमैया के शब्दों में, “गान्धी जी के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली सदस्य वे ही (नेहरू जी) थे, जो कांग्रेस को अन्दर से आगे बढ़ने की शक्ति भी देते और बाहर से उस पर रोक लगाते।” इसके अतिरिक्त “वे पुराने और नये को जोड़ने वाली एक कड़ी भी थे और इसीलिए लखनऊ में अध्यक्ष-पद ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति भी थे”। अतः उन्हें ही २८ फरवरी १९३६ को कांग्रेस के दक्षिण एवं वाम पंथी नेताओं ने सर्वसम्मति से उस साल के लिए अपना अध्यक्ष चुना।

नेहरू जी के निर्वाचन पर उनके विपक्षियों ने उन पर व्यंग्य-बाणों के कटु प्रहार भी किये। श्री सुभाष बोस ने चुटकी लेते हुए कहा था, “पं० नेहरू की स्थिति बड़ी मनो रंजक है। उनके विचार तो आमूल परिवर्तनकारी हैं, और वे अपने को समाजवादी कहते भी हैं, किन्तु कार्य रूप में

चे महात्मा गान्धी के पूर्ण अनुयायी हैं। उन्होंने एक स्थान पर और भी कहा था, “महात्मा गांधी ने जवाहरलाल का अव्यक्त-पद के लिये समर्थन कर समझदारी का काम किया, क्योंकि यहाँ से गांधी जी और पं० नेहरू का सैद्धान्तिक मेल आरम्भ होता है, और परिणाम स्वरूप नेहरू जी और कामपक्षी दल के बीच पार्थक्य आरम्भ होता है।”

विश्व की बदलती परिस्थितियों के साथ भारतीय नेताओं के भी दृष्टि-कोण में परिवर्तन हो रहा था। उन आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों की, जो योरोप को क्रान्ति के भँवर में फँके रहीं थीं, प्रतिक्रिया इस महादेश में भी होना स्वाभाविक ही था। क्या यह सम्भव था कि असीम एटलान्टिक, गम्भीर प्रशान्त महासागर और दुर्गम हिमालय की पर्वत शिखारें, पश्चिम में उथल-पुथल मचाने वाली विचार-धाराओं को यहाँ आने से रोक सकतीं? अलग-२ जमाने में दुनिया की प्रगति के बुनियादी मकसद नई-२ शक्त ले कर हर जगह उपस्थित होते हैं। अपनी आन्तरिक समस्याओं और विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रचंड राष्ट्रीय संघर्ष के फलस्वरूप भारत में समाजवादी विचार धारा का जोरो से प्रचार होने लगा। यहाँ तक कि लखनऊ-कांग्रेस के कई माह पूर्व ही ‘कांग्रेस समाजवादी दल’ की स्थापना हो चुकी थी, जिसका युक्तप्रान्त में विशेष प्रभाव था। इनका एक व्यवस्थित आर्थिक सिद्धान्त था तथा ये जमींदारी प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन करना चाहते थे। कांग्रेस की नरम नीति में इसके सदस्य अपने को विशेष ‘फिट’ नहीं पा रहे थे। आपसी विरोध और वैमनस्यता की यह चिनगारी कभी कभी फूट पड़ती थी। नेहरू जी इधर काफी असें से जेल में बन्दी जीवन ही व्यतीत कर रहे थे, तथा मुक्ति के पश्चात् सीधे रुग्ण पत्नी को देखने विदेश चले गये थे, अतः कांग्रेस के अन्दर होने वाली इस भयंकर प्रतिक्रिया तथा विषम स्थिति का पूर्ण ज्ञान उन्हें न था। जब वे स्वदेश वापस लौटे तथा कार्य-भार ग्रहण किया तब उन्हें कांग्रेस का परिवर्तित स्थिति का वास्तविक ज्ञान हुआ। उसके भीतर संघर्ष, कटुता और संदेह का बीजारोपण हो चुका था। नेहरू जी ने इस

पर विशेष ध्यान न दिया; कारण उन्हें अपने ऊपर विश्वास था और वे सोचते थे कि कुछ दिनों के परिश्रम से ही वे स्थिति को अपने मनोदुःख बना लेंगे।

अतः नेहरू जी ने कांग्रेस उत्साह के साथ लखनऊ-कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कार्य आरम्भ कर दिया। उन्होंने अधिवेशन में १५ प्रस्ताव पेश कराये; जिसमें देश-निर्वाचन के सम्वे समय के पश्चात् श्री सुनार चन्द्र बोस की फिर से निरुत्तारों पर रोष प्रकट किया गया। नागरिक अधिकारों के अपहरण की निन्दा का भी प्रस्ताव पेश किया गया; और प्रचारित भारतीयों तथा अन्य देशों की राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाओं और नजदूर-दूर ने सम्पर्क बढ़ाने के लिए एक वैदेशिक विभाग खोलने का निश्चय किया गया। एक प्रस्ताव द्वारा आगामी सम्राज्यवादी न्यायद्वय ने भारत के भाग न लेने की घोषणा की गई, और एक अन्य प्रस्ताव ने इटली की फासिस्ट नाति से अन्त अर्वात्तानिया के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए लीग आफ नेशन्स के नपुंसकत्व की निन्दा की गई। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव द्वारा रियासतों प्रजा के लिए जनतन्त्रात्मक स्वतन्त्रता के अधिकारों की घोषणा की गई। नावो शासन-विधान को ग्रहण न करने का प्रस्ताव सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। कुछ लोगों ने वर्किंग कमेटी के इन प्रस्तावों की तीव्र निन्दा की, परन्तु अंत में मूल प्रस्ताव बहुमत से पार हो गये। प्रस्तावानुसार नया शासन-विधान अस्वीकृत कर दिया गया तथा विधान निर्माणार्थ एक परिषद् की गैंग की गई। पार्लियामेन्टरी बोर्ड तोड़कर 'सर्व अधिकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी को दे दिया गया। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया। असेम्बलियों ने जाकर प्रतिनिधियों का कार्य वहाँ जन-स्वार्थ की रक्षा के लिए युद्ध करना, तथा ऐसा करते हुए अपनी अंदरूनी वाकत बढ़ाना था। वही पर पद-ग्रहण करने का विवाद-असत प्रश्न अ० ना० कांग्रेस कमेटी के निर्णय के लिए स्थगित कर दिया गया। एक प्रस्ताव द्वारा जनता से सम्पर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार करने के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री जयरामदास दौलतराम

और श्री जयप्रकाश नारायण को एक उप-समिति बनाई गई। कांग्रेस में किसान मजदूर-सभाओं के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव तो न पास हो सका पर एक प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस ने किसानों की बहुत सी माँगें स्वीकार अवश्य कर ली।

अधिवेशन के समाप्त होते ही नेहरू जी उसके द्वारा निश्चित कार्य-क्रमों को पूर्ण करने के लिए जुट गये। उन्होंने नागरिक-स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में 'सिविल लिबरटि यूनियन' की स्थापना की। इसमें उन्हें विभिन्न दलों और विचारों के डेढ़ सौ से अधिक नेताओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। डा० राममनोहर लोहिया की देख-रेख में कांग्रेस का एक वैदेशिक विभाग भी खोला गया, जो विभिन्न देशों के स्वतंत्रता-आन्दोलन और जन-आन्दोलनों से पूरा सम्पर्क रखता और विदेशों की विभिन्न संस्थाओं और समाचार पत्रों को भारतीय अवस्था का प्रामाणिक परिचय देने का महत्वपूर्ण कार्य करता था।

अपने इन रचनात्मक कार्यों को करने के पश्चात् नेहरू जी को यह पूर्ण विश्वास था कि वे कांग्रेस के अंदर उपस्थित इन दोनों दलों—दक्षिण पंथी तथा वाम पंथी—का विश्वास तथा सहयोग प्राप्त कर लेंगे, परन्तु उनका यह समझना भ्रमपूर्ण साबित हुआ। कारण उनके कार्यों को उनके सभी सहयोगी—वाम पंथी तथा दक्षिण पंथी—संदेह की दृष्टि से देखते थे। समाजवादी वामपंथी दल उन्हें गांधीजी के सिद्धांतों से विशेष प्रभावित समझ कर वृजुआ करार करता था, जब कि कांग्रेस का नरमदल उन्हें आवश्यकता से अधिक क्रांतिकारी विचारों का कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। ऐसी स्थिति में नेहरू जी के लिए कांग्रेस का अन्यत्त-पद-ग्रहण करते हुए, तथा अपने सिद्धान्तों की रक्षा करते हुए कार्य करना असम्भव हो गया। उन्होंने पद-त्याग कर देना ही उचित समझा, और इसे ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने गांधीजी को तत्काल एक पत्र में लिखा भी था, “यूरोप से लौट आने के पश्चात् मैंने देखा कि मैं कार्य-समिति की इन बैठकों से बहुत ऊब गया हूँ।

इसका असर यह हो रहा है कि मेरी ताकत कम होती जा रही है और हर एक नई घटना के पश्चात् मुझे यह अनुभव होने लगा है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ ।”

किन्तु तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने, जो अपने साथ प्रबल संभावना की तरह युद्ध के काले बादल खींचती जा रही थीं, ऐसे संकट काल में उन्हें भारतीय कांग्रेस से अलग होकर उस पर इस प्रकार का अप्रत्याशित आघात करने से रोका। जहाँ गांधी जी दुनिया के पथ-प्रदर्शन में ही नहीं, बल्कि विश्व-सन्धता के पुनर्निर्माण में भारत के लिए ऊँचे स्थान की बात सोच रहे थे, वहाँ जवाहरलाल की तीव्र इच्छा यह थी कि संसार में अंतर्राष्ट्रीयता की प्रगति को ध्यान में रखते हुए भारत को राष्ट्र-समुदाय में एक उचित स्थान मिले। अतः वे भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम को विश्व की घटनाओं से अपरचित रह कर तथा बिना उसके सम्पर्क रखे हुए ही संचालित होने देना नहीं चाहते थे। अतः वाक्य हो पद-त्याग का विचार उन्हें छोड़ना पड़ा।

जेनरल फ्रैंकों का स्पेन में विद्रोह तथा अपने स्वार्थों के लिए विश्व की प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ द्वारा उसे सहायता, अंतर्राष्ट्रीय-शस्त्र-नियंत्रण-परिषदों का दुःखद अंत, चीन, अवीसीनिया, जेकोस्लोवाकिया आदि का बलि के बकरे की तरह मूक क्रन्दन, मावी दुःख का दिग्दर्शन करा रहा था। विश्व शक्तिशाली राष्ट्रों के स्वार्थों की रंग-भूमि बना हुआ था, जहाँ बिना हिचकिचाहट शान्ति के नाम पर छोटे और असहाय राष्ट्रों को खुलकर ढाव पर लगाया जा रहा था। सभी ‘शान्ति प्रेमी’ महान राष्ट्र भूल चुके थे कि यदि विश्व में शांति और स्वतंत्रता की स्थापना करना है तो न केवल फासिज्म और नाजीवाद का ही अंत करना होगा, अपितु साम्राज्यवाद की भी चिता जलानी होगी। नेहरू जी ने शक्तिशाली राष्ट्रों की अविकार-लिप्सा में विलीन होते हुए शोषित-शापित छोटे-छोटे-राष्ट्रों के प्रति, अपनी समवेदना प्रकट की। उन्होंने

६ मई को अवीसीनिया-दिवस तथा २७ सितम्बर को फिलस्तीन-दिवस मनाकर उन प्रताडित राष्ट्रों के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट की।

भारत की आन्तरिक अवस्था तो और भी सोचनीय थी। किसानों और मजदूरों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वे भयंकर गरीबी तथा अन्य कई प्रकार के बोझ से कुचले जा रहे थे। इसके अतिरिक्त विरोधों के पश्चात् भी जबरदस्ती लादे गये नये विधान में यद्यपि संघ शासन मंजूर कर लिया गया था, फिर भी देश का राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन न हो पाया था; कारण, यद्यपि सत्ता केन्द्रीय शासन के हाथ से निकल कर प्रांतीय नौकरशाही के हाथ में चली गई थी, किन्तु वहाँ भी विशेषाधिकार के नाम पर हुकूमत गवर्नर तथा अन्य ब्रिटिश पदस्थ कर्मचारियों के ही हाथ में जनता के प्रतिनिधियों से छीन कर रख दी गई थी। आश्वासन की मृग-मरीचिका के पश्चात् भी उत्तरदायी शासन अब भी स्थापित न हो पाया था।

यह भारत का दुर्भाग्य रहा है कि जब कभी प्रगतिशील शक्तियों ने किसी मोंग को पेश किया तो सबसे पहले उसका विरोध किसी मृतप्राय-सत्ता के हिन्दुस्तानी नेता द्वारा हुआ। जब कि एक स्वर से जनता के सच्चे प्रतिनिधि नेता इस नये विधान को राष्ट्र के लिये अहितकर बतलाकर उसका विरोध करने के लिए तत्पर थे, कुछ प्रतिक्रियावादी नेता तथा ब्रिटिश नौकरशाही के सदस्य इसे राष्ट्रीय आत्मा तथा जनता के विचारा का सच्चा प्रतिनिधित्व करनेवाला विधान मानकर, अपने अंग्रेज प्रभुओं को उनकी कृपा और राष्ट्र को ऐसे उपहार के लिए धन्यवाद और बढ़ाई देने से न थकते थे। परन्तु इंग्लैंड में भी कुछ ऐसे निष्पक्ष अंग्रेज थे, जो हर एक वस्तु को राष्ट्र विशेष की परिधि में न बाँधकर मानव मात्र की उपयोगिता का तराजू पर तौलते थे। राजनीति शास्त्र के दिग्गज अंग्रेज विद्वान प्रो० कांथ पर अफसरों का असर नहीं था और वे अल्प मतवाले मंत्री-मंडल के निन्दक थे। प्रस्तुत विधान का भारतीय

नेताओं द्वारा विरोध देख कर उन्होंने गांधी जी और उनके साथियों को इस बात पर बधाई देते हुए प्रसन्नता प्रकट की थी कि उन्होंने उत्तरदायी सरकार के सिद्धान्तों का वास्तविक रूप में अध्ययन किया है। उनके अनुसार “विचाराधीन विधान दोष पूर्ण था, क्योंकि गवर्नर को विशेषाधिकार देकर सारे उत्तरदायित्व को समाप्त कर दिया गया था।”

कांग्रेस वैधानिक ढंग से लड़कर ही इस इस विधान को परिवर्तित कराना चाहती थी, अतः उसने यह निश्चित किया कि अगले चुनाव में वह भाग लेगी। अगस्त में बंबई में एक विशेष अधिवेशन भी हुआ, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने चुनाव का घोषणा-पत्र पास किया।

लखनऊ-अधिवेशन के पश्चात् दिसम्बर १९३६ में कांग्रेस का अगला अधिवेशन फैजपुर में हुआ। अभी तक प्रायः कांग्रेस का अधिवेशन देश के प्रमुख शहरों में ही हुआ करता था। परन्तु सन् १९३०-३२ के सत्याग्रह के पश्चात् गांधी जी ने ऐसा अनुभव किया कि असली हिन्दुस्तान तीन हजार शहरों और कस्बों में नहीं बल्कि साढ़े सात लाख गाँवों में बसता है। अतः गाँवों और शहरों का सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने अपना अधिवेशन गाँवों में करने के लिए कांग्रेस को प्रोत्साहित किया।

नेहरू जी की अनिच्छा होते हुए भी बहुमत से फैजपुर कांग्रेस के भी अध्यक्षा वे ही बनाये गये। वास्तव में देश विदेशों-की ऐसी संकट पूर्ण एवं उलझी हुई परिस्थिति में पं० नेहरू से अधिक उपयुक्त, ‘समय का व्यक्ति’ दूसरा कोई नहीं था। गांधी जी ने स्वयं फैजपुर-कांग्रेस में मंजूर किया था, “जवाहरलाल जी ही इस समय के उपयुक्त व्यक्ति हैं।” देश को उस समय अत्यन्त तेजस्वी, शक्तिशाली और साहस से भरे हुए नेतृत्व की आवश्यकता थी और उसने जवाहरलाल जी के रूप में ये सभी चीजें मूर्तिमान पायीं।

समापति-पद के लिये अपना निर्वाचन होने के पूर्व नेहरू जी ने अपनी विचारधारा को देश के समक्ष स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा । अतः उन्होंने एक वक्तव्य द्वारा अपने सहयोगियों तथा राष्ट्र के समक्ष यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया कि वह समाजवादी कार्य क्रम और सिद्धांत को विशेष महत्व देते हैं । इस स्पष्टीकरण के पश्चात् भी गांधी जी ने नेहरू जी का नाम उक्त पद के लिए उपस्थित किया, तथा गांधी जी की इच्छानुसार सरदार पटेल ने अव्यक्त-पद का उम्मेदवारी से अपना नाम वापस लेकर नेहरू जी के नाम का समर्थन किया । एक वक्तव्य में उन्होंने स्पष्टतः कहा कि यद्यपि मैं नेहरू जी की विचारधारा से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, फिर भी हम लोगों के मूल उद्देश्य—स्वतंत्रता-प्राप्ति—में कोई अंतर नहीं है । इसके अतिरिक्त “देश में जो विभिन्न शक्तियाँ काम कर रही हैं, उनका ठीक दिशा में नियंत्रण और निदेशन करने, तथा साथ ही साथ राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जवाहरलाल सर्वोत्तम व्यक्ति हैं ।”

फजपुर का अधिवेशन हर ढंग से अपने आप में सफल कहा जा सकता है । कांग्रेस के कार्यक्रमों एवं निश्चय के पीछे गांधी जी का गहन अव्यवसाय एवं संरक्षण छिपा होता था । वास्तव में कांग्रेस के पीछे गांधी जी की शक्ति थी, और वे चाहे आगे रहे या पीछे उनकी भारतीय राजनीति के क्षेत्र में और अपने देश की जनता के बीच बहुत बड़ी हस्ती थी ।

फजपुर अधिवेशन में अपने राष्ट्रपति-पद से दिये गये भाषण में श्री जवाहरलाल जी ने खान अब्दुल गफ्फार खॉं और श्री एम० एन० राय का, जो बड़ी लग्नी और सख्त कैद से हाल में ही छूटे थे, स्वागत करते हुए योरोप में फासिस्टवाद के विजय की चर्चा की तथा उस पर प्रकाश डाला । साथ ही इस ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि अगर रोक-थाम न की गई तो महायुद्ध अनिवार्य हो जायेगा । अविरोधनीति पर बलात्कार एवं स्पेन की दुर्दशा इसके प्रमाण थे ।

ब्रिटेन की नीति भी निर्दोष नहीं थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि “कांग्रेस का ध्येय अब भी लोकतंत्र तथा उसकी प्राप्ति के लिये संघर्ष करना है। वह साम्राज्यवाद विरोधी है तथा मौजूदा सामाजिक एवं राजनीतिक ढाँचे के परिवर्तन की कांशिश में है। मेरी ऐसी आशा है कि इन घटनाओं के प्रवाह में समाजवाद स्वयं आ जायेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश की आर्थिक बीमारी का यहाँ एक मात्र इलाज है।” इसके अतिरिक्त उन्होंने आनेवाले चुनाव तथा प्रस्तुत विधान की बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए जनता के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त एक प्रस्ताव द्वारा उन्होंने जनता से यह अनुरोध किया कि युद्धारम्भ होने पर वे ब्रिटिश शासकों की धन-जन, किसी प्रकार से भी सहायता न करें। कैदियों के प्रति सरकार की नीति, तथा सीमा-प्रान्त में किये गये कार्यों की निन्दा भी की गई थी। नये विधान के विरोध में कांग्रेस ने जनता से १ अप्रैल १९३७ को ग्राम हड़ताल करने की अपील की। नेहरू जी तथा कांग्रेस के अनुसार यह विधान भारत की स्वतंत्रता के युद्ध के साथ विश्वासघात था, क्योंकि उसके लादे जाने से भारतीय जनता के शोषण के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती। हिन्दुस्तान की जनता अपने लिए स्वयं ही विधान निर्मित करना चाहती थी।

चुनाव के उम्मेदवार न होते हुए भी पं० नेहरू ने अपने सहयोगी उम्मेदवारों के प्रचार के लिए सम्पूर्ण देश का दौरा किया। वे दिन-दिन भर लाखों व्यक्तियों की भीड़ में अपनी ओर से कांग्रेस का संदेश पहुँचाते, तथा बोटों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही मत देने के लिए आग्रह करते। प्रचार महीने के इस कठिन परिश्रम में वे देश की करोड़ों जनता के सम्पर्क में आये। इस यात्रा से उन्हें भारत के वास्तविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हुआ। उन्हीं के शब्दों में, “मैंने अपने देश के हजारों रूप देखे, लेकिन सब में भारतीयता की छाप थी। मैं उन लाखों स्तंभ-भरी ओखलों को देखता जो मुझे निहारा करती थीं, और यह जानने की

कोशिश करता था कि उनके पीछे क्या छिपा है ? जितना ही ज्यादा मैं हिन्दुस्तान को अंदर से देखता, उतना ही ज्यादा मुझको लगता कि उसके असीम आकर्षण और विविध रूपों का मुझे कितना कम ज्ञान है। मुझे लगता कि मुझे देखकर भारत माता कभी नुस्करा देती हैं, कभी मेरा उपहास करती हैं, और कभी मेरे लिए अवोध हो जाती हैं।”

इस चुनाव में कांग्रेस को आशातीत सफलता प्राप्त हुई तथा उसके अवसरवादी विरोधियों ने मुँह को खाई। धारासभाओं के भीतर जमकर काम करने, और असेम्बली के मंचों पर राष्ट्रीय युद्ध के इस पक्ष को ले जाने का शीर्गशेष पहली अप्रैल की शान्तिपूर्ण हड़ताल से आरम्भ हुआ। मंत्री पदग्रहण करने से पहले दिल्ली में एक अधिवेशन होना निश्चित हुआ—दिल्ली, जहाँ सात नए साम्राज्यों की दफनाई स्मृति कब्र से कराह रही थी, और जहाँ नये सिरे से उठने की क्रान्तिकारी परिवर्तनों की फिर से आशा थी जितने कि विगत इतिहास ने सो चुका थे। मंत्री-पद-ग्रहण के सवाल पर महासमिति ने इस बात का अधिकार व अनुमति दी थी कि जिन प्रांतों में कांग्रेस-बहुमत है, वहाँ यदि उस प्रांत की धारा-सभा-की कांग्रेस-पार्टी को इस बात का विश्वास हो, और यदि वह इस बात को खुले आम घोषित कर सके कि गवर्नर हस्तक्षेप के अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, या वैधानिक कार्यवाहियों में मंत्रियों के निर्णय को अमान्य नहीं करेगा, तो वहाँ कांग्रेस पद-ग्रहण कर सकती है। उस सम्मेलन में कांग्रेस के सभी सदस्यों ने देश-सेवा, और धारासभा के भीतर व बाहर भारत की आजादी के लिए वैधानिक युद्ध करने की शपथ ग्रहण की।

मंत्री-पद ग्रहण करने के पूर्व गवर्नर से यह आश्वासन मोंगा गया कि वह विशेषाधिकारों के बल पर सदस्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और मंत्रियों के वैधानिक कार्य को अमान्य नहीं करेंगे। देश के कुछ नेताओं, विशेषतः लिबरल नेता श्री सप्रू ने कांग्रेस की इस मोंग को

सरासर अवैधानिक बतलाया । उनके अनुसार जब विधान द्वारा ही गवर्नर को 'विशेषाधिकार' दे दिये गये हैं तब गवर्नर उनका खंडन कर कांग्रेस के इस प्रस्ताव को मान ही कैसे सकता था । किंतु इंगलैंड के विधान-विशारद प्रो० वेरिडल कीथ ने, तथा भारत के दो धुरंधर कानून पंडित भूतपूर्व एडवोकेट जेनरल श्री तारापोरा वाला तथा डा० बहादुर जी ने, उनकी बातों का खंडन करते हुए कांग्रेस की मोंग का समर्थन किया । कांग्रेस की मोंग का मतलब था कि गवर्नर, आस्ट्रेलियन गवर्नर की तरह काम करे । उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह जब चाहे अपनी इच्छा से मंत्रियों को पदच्युत कर दे । उनके कथनानुसार मंत्रियों का वेतन कांग्रेस द्वारा तै होना चाहिए । गवर्नर मंत्रियों की काउन्सिल में सभापति न बन सके । वह सुरक्षा के नाम पर आर्डिनेन्स न लागू कर सके तथा एडवोकेट जेनरल की नियुक्ति में उसका हाथ न हो । वह पुलिस के नियम भी न बनाये । अंत में काफी वाद-विवाद के पश्चात् वायसराय का आश्वासन प्राप्त कर लेने के पश्चात् कांग्रेस ने मंन्त्रिमंडल में पद-ग्रहण किया । इस प्रकार कांग्रेस ने देश में राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में ही सात प्रांतों में अपना मंन्त्रिमंडल स्थापित किया ।

उस वर्ष पं० नेहरू ने राष्ट्रपति-पद से अत्यन्त उत्साह तथा परिश्रम से कार्य किया । जंजीवार-दिवस २१ जून, चीन-दिवस २६ सितम्बर, नव विधान-विरोधी दिवस १ अप्रैल, अंडमंड-दिवस, स्वाधीनता-दिवस २६ जनवरी १९३७, तथा सीमाप्राप्त दिवस २२ मई १९३७ को मनाये गये । इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न समस्याओं पर राष्ट्रपति के वक्तव्य भी प्रकाशित होते रहे । कांग्रेस के वैदेशिक और आर्थिक विभाग भी सुचारु रूप से संगठित हो जाने के कारण उनकी अव्यक्तता में उत्साह और लगन के साथ कार्य करते रहे ।

युद्ध-संकट और भारत

१९३८ के पतझड़ में युद्ध के बादल घिरने लगे थे। पहले वे मनुष्य के हाथ से अधिक बड़े न थे, किन्तु शीघ्र ही आसमान में अचिरा छा गया और दुर्दिन की काली मेघमालायें समस्त संसार को डसने के लिए नागिन सी झुक पड़ीं। ब्रिटेन और जर्मनी में उन दिनों जो कुछ हो रहा था उसकी सूचना कांग्रेस कार्य समिति को प्रति सप्ताह नेहरू जी से मिलती रहती थी, जो २ जून को यूरोपीय परिस्थिति के अध्ययन के लिए भारत से रवाना हो चुके थे और मलाया में भारतीय व्यापारियों तथा सिकन्दरिया में नहासपाशा व दूसरे वफद नेताओं से मिलने के बाद सीधे ब्रिसेलोन चले गये थे। वहाँ उन्होंने निर्दयतापूर्वक होती हुई बम-वर्षा तथा उससे होने वाले विनाश को आँखों से देखा। इसके उपरान्त वे पेरिस गये—जन क्रांति का स्थल पेरिस, सारी दुनिया की आजादी का प्रतीक—वहाँ उन्होंने रेडियो पर भाषण करते हुए भारतीय स्वाधीनता के आन्दोलन के आदर्शों पर प्रकाश डाला तथा फ्रांसीसियों से सहानुभूति की माँग की। स्टेन के युद्ध की दूसरी सालगिरह के दिन पण्डित जी ने ट्राफल्गर स्क्वेयर में नेलसन की मूर्ति के नीचे, खहर की पोशाक में, फासिज्म के विरोध में संघर्ष करते हुए स्टेन के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा था, “हम आपका समर्थन करते हैं तथा आपसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से किसी भी प्रकार का सम्झौता करने को तैयार नहीं हैं, जो हमारे ऊपर विशुद्ध प्रभुत्व का प्रतीक है और भारत में अपने साम्राज्यवाद का अन्त करने के लिए तैयार नहीं है।”

युद्ध आरम्भ होने के पश्चात् अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक सितम्बर १९३८ को दिल्ली में हुई। गांधी जी ने इस समय कार्यसमिति के समक्ष स्पष्ट शब्दों में कहा था, यदि भारत की राजनीतिक प्रगति के लिए कांग्रेस इस संकट पूर्ण परिस्थिति से लाभ उठाना चाहती है तो वे उसका साथ न देंगे, और उसे आंदोलन के नेतृत्व के लिए दूसरा नेता चुन लेना आवश्यक होगा। उनका यह सिद्धान्त था कि दुश्मन पर ऐसे समय में कदापि चोट न करनी चाहिए जब कि वह स्वयं सकटापन्न अवस्था में हो। वे इसे अहिंसात्मक नीति के विरुद्ध समझते थे।

कार्यसमिति की बैठक के एक साल पश्चात् विश्वव्यापी द्वितीय महायुद्ध आरम्भ हो गया। जिस समय महायुद्ध आरम्भ हुआ, पं० नेहरू चीन में थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने युद्धारम्भ होते ही तत्काल लौट आने के लिए उन्हें तार द्वारा सूचित किया। जिस समय नेहरू जी भारत वापस लौटे इस समय युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों, तथा कांग्रेस के अगले कदम पर विचार करने के लिए कांग्रेस-कार्यसमिति की बैठकें जारी थी। देश के लिए एक सम्मिलित कार्यक्रम निश्चित करने के लिए इस बैठक में श्री जिन्ना को भी निर्मन्त्रित किया गया, परन्तु उन्होंने आने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इधर वायसराय ने भारत को बिना उसके नेताओं से सलाह लिए जबरदस्ती युद्ध में शामिल कर लिया था, तथा सुव्यवस्था के नाम पर मंत्री-मंडल की राय लिए बिना कई आर्डिनेन्स जारी कर दिये थे। ब्रिटिश-पार्लियामेन्ट ने भी भारत में अपनी स्थिति विशेष सुरक्षित रखने के लिए सन् १९३५ के विधान में मनमाना संशोधन कर दिया था। इसने प्रान्तों की सरकारों के अधिकार और कार्यक्षेत्रों को सीमित कर दिया था। देश के किसी भी दल के नेताओं से इस विषय में परामर्श लेना उचित न समझा गया था, तथा कांग्रेस की हमेशा से दुहराई जाने वाली इच्छाओं और प्रस्तुत की गयी सूचनाओं की पूर्ण अवहेलना की गई थी। अन्त में वाध्य हो कांग्रेस-कार्यसमिति ने १४ दिसम्बर १९३६ को लम्बी

वहस के पश्चात् महायुद्ध के सिलसिले में एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित कराया, जिसमें वायसराय तथा ब्रिटिश-पार्लियामेंट द्वारा भारत के प्रति अविश्वास कर उठाये गये कदमों की निन्दा की गई थी, और यह शिफारिस की गई थी कि “कांग्रेस कार्यसमिति को इन घटनाओं को बड़े गम्भीर रूप में लेना चाहिए, तथा अपने मत और कार्यक्रम को तत्काल निश्चित करना चाहिये।”

कार्यसमिति के फैसले का स्वीकरण करते हुए जवाहरलाल जी ने बतलाया कि यद्यपि भारत इस संकट-काल में ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने के लिए तैयार था परन्तु अब जबरदस्ती मढ़े हुए इस फैसले को मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। यदि किसी ऊँचे आदर्श को लेकर कोई सहयोग की माँग करता है तो वह जबरदस्ती या दबाव से कदापि नहीं मिल सकता, और न कांग्रेस-कार्यसमिति ही इस बात को, कि हिन्दुस्तानी उन हुकमों को पावन्दी करने को बाध्य हैं जो विदेशी शक्ति द्वारा दिये गये हैं, मानने के लिए तैयार है। नेहरू जी के अनुसार भारत किसी ऐसी लड़ाई में कदापि शामिल होना न चाहेगा, जिसके लिए कहा तो यह जाये कि यह लोकतंत्र की आजादी के लिए है लेकिन वह आजादी उसे खुद हासिल न हो, बल्कि जो कुछ थोड़ी सी आजादी उसे मिली भी हो वह भी सुरक्षा के नाम पर इस प्रकार छीन ली जाये।

नेहरू जी की राय में कांग्रेस-कार्यसमिति ने राष्ट्रीय होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया था। जिस संकट से यूरोप घिरा था वह सिर्फ यूरोप का ही नहीं, सारी दुनिया का संकट था। इस संकट से दुनिया का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढाँचा बदल जाना था। इस संकट के आविर्भाव की बुनियाद इस पर थी कि एक देश का दूसरे देश के ऊपर से आधिपत्य और शोषण समाप्त हो जाये, तथा आर्थिक सम्बन्धों को एक नये सिरे से ऐसे ढर्रे पर लाया जाये जिसमें सबके फायदे और सबके साथ इन्साफ का ध्यान हो। उन्होंने वृटेन को चेता-

बर्ना देते हुए कहा था कि आजादी का बंटवारा नहीं हो सकता । दुनिया के किसी भी हिस्से में साम्राज्यवादी कब्जा बनाने का कांशिश का अवश्यम्भावी फल ऐसा ही भयंकर विध्वंसक युद्ध होता है ।

अस्तु, कार्य समिति ने ब्रिटिश सरकार को आमंत्रित किया कि वह "विलुप्त चाफ शब्दों में यह स्पष्ट करे कि लोकतंत्र और साम्राज्यवाद, तथा विचारार्थी दुनिया के नये नकशे के बारे में उसकी इस लड़ाई के नक़्साद क्या हैं; और ये दुखोद्देश्य भारत में किस प्रकार कार्यरूप में परिणत किये जायेंगे ? क्या उनमें साम्राज्यवाद को मिटाने और भारत के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह व्यवहार करने की बात सम्मिलित है—उस आजाद भारत के साथ जिसकी नीति जनता की इच्छाओं से तय होगी ?"

नेहरू जी तथा कांग्रेस-कार्यकारिणी ने ब्रिटिश सरकार से भारत को आजादी देने के लिए अपील की, तथा इस बात का आश्वासन दिया कि पूर्ण स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् भारत बन-जन से इस युद्ध में मित्र-राष्ट्रों की पूर्ण सहायता करेगा । नेहरू जी को उम्मीद थी कि बटनाओं की मार ने क़त्त ब्रिटिश नेता अपने संकुचित विचारों के गड्ढों से बाहर आकर, दूर तक की चीजों को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे ।

पं० नेहरू तथा कांग्रेस के प्रयत्न के पश्चात् भी हुआ वही जिसके होने का भय था । क्योंकि सरकार तो अपनी इच्छानुसार ही कार्य करना चाहती थी, "तथा ब्रिटिश-राजनुष्ठ के सबसे बहुमूल्य हारे भारत को खो देने का उसका इरादा कदापि न था ।" 'विश्व के लोकतंत्रों की रक्षा' आदि का नारा तो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक 'शब्द-जात मात्र' था । वे भारत के साथ मित्रवत् व्यवहार पसन्द न कर जोर और जुल्म से अपनी इच्छा उसके द्वारा मनवाना चाहते थे । 'भारत उनके साथ युद्ध में सहयोग करे' ने उनका तात्पर्य यह था कि भारत उनकी इच्छानुसार संचालित हो, तथा अपने छुटकारे के लिए जवान तक न हिलाये । देश के राष्ट्रीय नेता अपने चरम लक्ष्य, स्वतंत्रता ने मुँह मोड़ कर इसे कैने

वरदास्त कर सकते थे ? फलस्वरूप कांग्रेस ने विभिन्न प्रान्तों में नन्दोन्द से स्वीकृति दे दिया । वायसमार्थ तथा संसद सन्नत हो गयीं एवं कांग्रेस ने नये चुनाव का नौग की । परन्तु सरकार यह पूर्णतः जानती थी कि नये चुनाव में भी ये ही व्यक्ति फिर आवेंगे तथा संसदों में सर्वत्र अनिवार्य होगा; अतः उसने नन्दोन्दसिद्ध को अपने विशेषाधिकारों से स्थगित करने दिया तथा नये चुनाव की आज्ञा न दी । प्रान्तीय गवर्नरों ने पूर्ण अधिकार अपने हाथों में ले लिए और अब वे अपने प्रान्तों के पूर्ण रूप से निरंकुश शासक हो गये । कांग्रेस इस गतिरोध का कैसे वरदास्त कर सकती थी । नेहरू जी के शब्दों में, “कांग्रेस जैसी शक्तिशाली अर्थक्रान्तिकारी संस्था चुन होकर एक व्यक्ति (वायसमार्थ) के निरंकुश राज्य को वरदास्त नहीं कर सकती थी । जो चुन हो रहा था उसके लिए वह एक दर्शन भी नहीं हो सकती थी, बल्कि उस समय तो और भी नहीं जब वह सब उसी के खिलाफ था ।” ब्रिटिश सरकार ने अब तक कांग्रेस के उक्त आग्रह पर भी धनना इरादा जाहिर न किया था ।

परिस्थिति विशेष गम्भीर हो जाने के पश्चात्, तथा सरकार की ओर से उसके इरादों का कुछ भी प्रकटकरण न होने के कारण, कांग्रेस कार्यसमिति ने इसके लिए एक युद्ध समिति का निर्माण किया जिसके अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू बनाये गये । इसका कार्य यह था कि परिस्थितियों को देखकर वह देश की तमाम कांग्रेस कमेटीयों को आदेश जारी करे कि उन्हें मौजूदा स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्य करना है । इससे पश्चात् ही कार्यसमिति ने एक घोषणापत्र भी प्रकाशित कराया, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा नवियन ने कार्य में लाई जाने वाला नीति का पूर्ण खंडोकरण न करने से स्पष्ट प्रकट किया गया था । तथा भारत की स्वतंत्रता के युद्ध के विषय में अपने इरादे और अन्तिम फैसले घोषित कर देने का नौग की गई थी । सरकार ने ८ अगस्त १९४० को इस विषय पर अपनी घोषणा प्रकाशित की जिसमें एक बार फिर कांग्रेस को चुनवाने का प्रस्ताव किया गया था ।

ब्रिटिश सरकार ने स्थिति तथा अपना विचार साफ तौर पर व्यक्त नहीं किया था, फलतः विवश हो कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार से इस विषय पर स्थिति में भी अपना सम्बन्ध तोड़ना पड़ा, और उनके सहयोग का पहला कदम था प्रान्तों के मंत्री-मंडल तथा धारासभाओं से कांग्रेस का पद-त्याग। रामगढ़-कांग्रेस (१९४०) में मौलाना आजाद के सभापतित्व में कांग्रेस को मजबूरन तै करना पड़ा कि अब सिर्फ सविनय-अवज्ञा के अतिरिक्त कोई रास्ता कांग्रेस के पास शेष नहीं रह गया है। इसके अतिरिक्त आंतरिक संकट इस तरह धनीभूत हो उठा था कि उसका टालना अब असम्भव हो गया था, क्योंकि युद्ध के निमित्त शासकों ने भारत-रक्षा-कानून जनता पर लाद दिया था जो उनकी सामान्य स्वतंत्रता तथा अधिकार को भी कुचलता हुआ देशव्यापी हो लोगों को अपनी लपेट में जकड़ रहा था। इंग्लैंड को संकट में देख कांग्रेस में गांधी जी की नीति के अनुसार इंग्लैंड से सघर्ष नहीं करना चाहती थी अतः उसने सरकार से समझौते की अंत तक पूर्ण कोशिश की थी। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन से हिन्दुस्तान को स्वतंत्रता देने की माँग की, तथा केन्द्र में वायसराय को अध्यक्षता में तत्काल एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार बना देने के लिये कहा जो मौजूदा केन्द्रीय धारासभा के प्रति उत्तरदायी हो उसमें यह आश्वासन दिया गया था कि यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूर कर ले तो भारत विश्व युद्ध में योग देने के लिए तैयार है। इस लाभप्रद योजना से कांग्रेस यह चाहती थी कि शासन में एक नई भावना का जन्म हो, एक नई शक्ति का उदय हो और लड़ाई की तैयारियों में तथा राष्ट्र के सामने जो गम्भीर समस्याएँ हैं उन्हें हल करने में जनता का सहयोग हो। यद्यपि इस सीमित सरकार से देश को और कोई विशेष लाभ होने की उम्मीद न थी। कांग्रेस में बहुत विरोध के पश्चात् इस प्रस्ताव ने कार्य-समिति की मान्यता प्राप्त की, कारण गांधी जी किसी भी हालत में इस संकट-पूर्ण नाजुक परिस्थिति के अवसर पर अपने शत्रु ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को तंग न करना चाहते थे। यदि कांग्रेस ऐसा करती तो वे उससे अलग

हो जाने के लिए तैयार थे । परिस्थितियों के प्रवाह में वहती कांग्रेस को उस समय उनसे भी अलग होना मजूर था । परन्तु घटना-चक्र ने ऐसा न होने दिया और इस विपम परिस्थिति में गांधी जी कांग्रेस को छोड़ कर अलग न हो सके ।

सरकार ने कांग्रेस की इन मँगो और सुझावों को बंदर-बुडकी समझ कुठु भाँ न्यान न दिशा अतः समझौता करने का प्रयत्न निष्फल हुआ । तत्कालीन अदूरदर्शी वायसराय लिनलिथगो ने विपम परिस्थिति पर विल्कुल ध्यान न देते हुए उसे अमान्य कर दिया । नेहत जी के शब्दों में, “लार्ड लिनलिथगो का शरीर बड़ा था परन्तु दिमाग शून्य था । उनका मस्तिष्क चट्टान की तरह ठोस था और उसी की तरह जड़ भी था । उनमें पुराने ढंग के ब्रिटिश रईसों की तरह ही गुण और अवगुण थे ।”

भारत की परतंत्रता के जयदस्त समर्थक अप्रगतिवादी प्रधानमंत्री मि० चर्चिल हिन्दुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य से निकलता नहीं देख सकते थे । उनका शब्दों में “ब्रिटिश राष्ट्र का भारत की आजादी और तरक्की पर से अपना नियंत्रण उठा लेने का विचार कदापि नहीं है, बादशाह के ताज के समसे ज्यादा कीमती और समसे ज्यादा चमकीले उस हीरे को खो देने का हमारा इरादा कतई नहीं है । वह अकेला ही और सग उपनिवेशों और अधिकृत प्रदेशों के मुकाबले ब्रिटिश शासन की ताकत और शान कायम रखता है ।” उन्होंने दिसम्बर सन् १९३१ में कहा था कि “भारत में अपने साम्राज्य को छोड़ देने के पश्चात्, इंग्लैण्ड को अगर शक्ति क्षीण हो जायेगी ।” इससे ज्ञात होता है कि चर्चिल की दृष्टि में भारत ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे बड़ा क्षेत्र था तथा हिन्दुस्तान पर अधिकार और शोषण ने ही इंग्लैण्ड को अतुलनीय ऐश्वर्य और शक्ति दे रखा था । वे उस इंग्लैण्ड की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जिसमें वह भारत की शासन सत्ता से वंचित हो गया हो ।

नेहरू जी के अनुसार मि० चर्चिल में “हिम्मत और नेतागिरी की अनेक खूबियाँ होने के पश्चात् भी वे उन्नीसवीं शती के अनुदार साम्राज्यवादी तथा प्रगति विरोधी, इंगलैंड के एक नागरिक थे। ऐसा मालूम होता था कि नई दुनिया, उसकी जटिल समस्याएँ और उसकी ताकत को समझ सकने में वे असमर्थ थे, तथा उससे भी कम उस भविष्य को समझ सकते थे जो अब बनने की स्थिति में था।”

नेहरू जी ने सरकार की स्पष्ट नीति परख लेने के पश्चात् “अलग अलग रास्ते” शीर्षक एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने बतलाया कि जब तक भारत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता, उसकी स्वांगीण उन्नति कोरी कल्पना ही होगी। उसे साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार से अपने लक्ष्य की विशेष आशा न रखनी चाहिए।

अंत में कांग्रेस के सभी प्रयत्न विफल हो चुके थे, अतः वह सत्याग्रह के लिए कटिबद्ध हो गई। १७ अगस्त को सत्याग्रह की रणभेरी बज उठी। उसके पहले सेनानी विनोबा जी थे। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात् सर्वसम्मति से नेहरू जी को दूसरा सत्याग्रही सेनानी बनाया गया। वे भी विद्रोहात्मक भाषण देने के अपराध में गिरफ्तार कर लिए गये तथा सरकार ने उन्हें ४ साल के कठिन कारावास का टुकड़ा दिया। यह उनकी नवीं बार की परन्तु अंतिम और सबसे लम्बी कैद थी। यहाँ कैदी-जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक ‘डिस्कवरी आफ इंडिया’ लिखी थी। नेहरू जी की गिरफ्तारी के पश्चात् सत्याग्रह आन्दोलन बड़ी तीव्रता से बढ़ने लगा। सरकार ५० नेहरू को अधिक दिनों तक जेल में न रख सकी। अतः अन्य नेताओं की भोंति ४ दिसम्बर १९४१ को उन्हें भी रिहा कर दिया गया।

सन् ब्यालीस

भारत में विषम विरोधी परिस्थिति तथा सामयिक अन्तर्राष्ट्रीय संकट से चिन्तित हो, अगस्त १९४० की घोषणा के लगभग दो वर्ष पश्चात् ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को उचित और अन्तिम हल के प्रस्तावों को लेकर भारत भेजा। सर क्रिप्स ने भारत में आकर २६ मार्च सन् १९४२ को अपनी योजना सम्बन्धी वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसे नेहरू आदि नेताओं ने विल्कुल पसन्द नहीं किया। गांधी जी ने भी उस योजना को “भविष्य में भुनाने की तारीख वाला चेक” कहकर अस्वीकार कर दिया। कारण क्रिप्स की योजना के अनुसार युद्ध के पश्चात् भी भारत को सिर्फ एक डोमीनियन बनाने का आश्वासन दिया गया था न कि पूर्ण स्वतन्त्रता का। उनके कथनानुसार वास्तविक अधिकार और अन्तिम नियन्त्रण-शक्ति ब्रिटिश सरकार के ही हाथ में रह जानेवाली थी। क्रिप्स महोदय भारत के सभी दलों के प्रमुख नेताओं से मिले। रुस में सफलता प्राप्त करने के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उनकी काफी ख्याति हो चुकी थी और भारत के सम्बन्ध में भी ब्रिटिश सरकार को उनसे बहुत आशा थी। किन्तु उसकी आशा पर तुषारपात हुआ जब कि भारत की सभी प्रमुख राजनीतिक सस्थाओं ने उनकी योजना को एक स्वर से अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप मि० क्रिप्स को असफल हो लौट जाना पड़ा। सरकार ने क्रिप्स-मिशन की असफलता का सारा दोष कांग्रेस पर डाल दिया जिसका तत्कालीन पत्रों ने तर्क पूर्ण विरोध किया।

क्रिप्स के चले जाने के पश्चात् महात्मा गांधी भारतीय राजनीति से वन्धित लेखमाला ‘हरिजन’ में प्रकाशित करते रहे, जिनमें उन्होंने

कांग्रेस का मत संसार के समक्ष रखा और उसके पक्ष का समर्थन किया । इन्हीं लेखों का सारांश आगे चल कर अगस्त में 'भारत छोड़ो' विचार तथा प्रस्ताव के रूप में प्रकट हुआ । अंग्रेजों की नीति से गाँधी जी को क्रमशः यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीय समस्याओं के जटिल होने का मुख्य कारण देश में अंग्रेजों का अस्तित्व है, अतः उन्होंने कहा था, "भारत तथा वृटेन का हित इसी में है कि समय रहते अंग्रेज अनुशासित ढंग से यहाँ से हट जायें ।" मौलाना आजाद ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये थे । उनके अनुसार "सरकार की ओर देखना और उससे समझौते की आशा करना केवल समय को नष्ट करना है ।" गांधी जी का 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव जुलाई में कांग्रेस के वर्षा-अधिवेशन द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया, कारण देश की जापानी आक्रमण से रक्षा के लिए यह आवश्यक था । कांग्रेस ने यह भी घोषणा कर दी थी कि यदि इस अपील को अमान्य किया गया तो कांग्रेस देश-रक्षा के लिए देशव्यापी अहिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ कर देगी, और इस प्रकार के व्यापक संघर्ष का नेतृत्व गांधी जी ही करेंगे । ८ अगस्त सन् १९४२ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी बम्बई के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया । गांधी जी ने अपने वक्तव्य को इस प्रकार समाप्त किया "प्रत्येक व्यक्ति को अहिंसात्मक होकर, हड़ताल, कामबन्दी, तथा अन्य अहिंसात्मक साधनों द्वारा अधिक से अधिक दूरी तक जाने की स्वतन्त्रता है । सत्याग्रहियों को मरने के लिए, जीवित रहने के लिए नहीं, आगे बढ़ना है । जब व्यक्ति इस प्रकार मृत्यु की खोज तथा उसका सामना करने के लिए तैयार हो जायेंगे तभी वे राष्ट्र को सजीव बना सकेंगे ।" समस्त भारतीयों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, "आज से प्रत्येक भारतीय अपने को स्वतन्त्र समझे । ... हम कोई निकम्मा वार नहीं करेंगे । मैंने कांग्रेस को बाजी पर लगा दिया है; वह करेगी या मरेगी अब की जो लड़ाई होगी वह सामूहिक लड़ाई होगी ।" हम एक सत्तन्त्रता का मुकाबला करने जा रहे हैं और हमारी

लड़ाई बिल्कुल सीधी होगी ।” महात्मा गांधी के इस वक्तव्य का असर भारत की कोटि-कोटि जनता पर जादू सा हुआ था, इससे भारतीयों में एक नूतन आत्मविश्वास और आत्मबल का संचार हुआ । उनमें यह ज्वरदस्त इच्छा पैदा हुई कि अपनी वर्तमान अवस्था के फटे-पुराने, विच्छिन्न चीथड़ों को चीर-फाड़ कर राजनीतिक, आर्थिक और मानसिक बन्धनों को छिन्न-भिन्न कर, तथा मार्ग की सब विघ्न-बाधाओं को ठुकरा कर हम आगे बढ़ ऊपर उठें और संसार में अपना योग्य स्थान बनाने का आमरण प्रयत्न करें । उनके मन, मा. १. १ और दृष्टि-क्षेत्र में एक कान्ति उपस्थित हुई जिसने झकझोर कर उन्हें उठाया और बतलाया कि वे दूसरे देश की गुलामी की वेड़ी में आवद्ध रह कर, दुसह दारिद्र्य, दुःख, शोषण और निराशा का जीवन बिताने के लिए नहीं पैदा हुए हैं । उन्हें भी विश्व में शीश उठा कर चलने का अधिकार है, उन्हें भी दुनिया के स्वतन्त्र वायु-मण्डल में सोंस लेने का अधिकार है, उनके भी कुछ मनुष्योचित अधिकार हैं जिनसे संसार की कोई भी नारकीय भौतिक ताकत उन्हें अधिक दिन तक अलग नहीं रख सकती । आज उन्हें अपनी महान शक्ति और स्वरूप का अनुभव हुआ था जिसे भुल्ला कर वे अब तक अपने मनुष्यत्व और पौरुष को नष्ट कर रहे थे । अब उन्होंने समझा कि वे एक विशाल देश के निवासी हैं जो दुनिया में अपूर्व है, यह विश्व में महान तथा अजेय कहे जानेवाले राष्ट्र ग्रेट ब्रिटेन से १५ गुना बड़ा और फ्रांस तथा जर्मनी से आठ-आठ गुना बड़ा है । इस देश की जन-संख्या सम्पूर्ण मनुष्य जाति का ५ वाँ हिस्सा है । चीन को छोड़कर अन्य किसी भी देश से इसकी जन-संख्या अधिक है । रूस की जनसंख्या से दुगुनी, अमेरिका से ढाई गुनी, जर्मनी से पाँच गुनी, फ्रांस से आठ गुनी तथा सम्पूर्ण ब्रिटेन की जनसंख्या से दस गुनी बड़ी है । यह देश दुनिया के हर हिस्से की जलवायु, गरमी, सर्दी और वनस्पति का प्रतिनिधि है । इतने महान देश के अधिवासी होकर, तथा असीम शक्ति के स्वामी होकर भी परतन्त्रता की वेड़ी में जकड़े रहना उनकी निम्न प्रवृत्ति तथा अकर्मण्यता का द्योतक

है। अन्तर्विक्रता श्री रंगमेरी वज्र चुकी थी और वीरवरो ने उसकी मंजूरत ताक ने आन्दोलित हो केसरिया जाना पहनना आरम्भ कर दिया था। एक विनगारी श्री आवश्यक्ता थी जो विशाल अग्नि का रूप धर कर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नाना को अपनी जिह्वा से चाट लेती।

सरकार पर इस प्रभाव, तथा इस नवीन जनजाग्रिति का तत्कालिक अन्तः पड़ा। उसने दमन के साधनों का प्रयोग पुनः आरम्भ किया। तैयारियाँ पढ़ते ने ही थीं अतः कांग्रेस के सभी सदस्य सुबह होते-होते गिरफ्तार कर लिए गये तथा अज्ञात स्थानों को भेज दिये गये। सरकार ने इतनी व्यग्रता और गतिता शायद इसलिए दिखलाई कि वह अबकी आन्दोलन आरम्भ होने के पहले ही दबा देना चाहती थी। कांग्रेस गैरकानूनी करार कर दी गई। लगभग ६ बंदे में भारी परिस्थिति बढ़ गई थी। मौलाना आजाद के शब्दों में, “एक रात में दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। शाम को सड़कों के दिलों में उनगों की रंगीनियाँ थीं, हसरतों की हलचल थी, बहकहों के फूल थे और अब कफ़न था, बेड़ियाँ थीं, गुलामी थी।”

जनता इस विद्युत्-परिवर्तन से स्तब्ध नहीं रह गयी। समस्त देश में यह समचार पाते ही इधरतात दुई तथा जुलूस निकाले गये। इसके विरोध में पुलिस ने निहन्धी जनता पर लाठियों और गोलियों के प्रहार किये और सरकार ने अध्यादेशों का शासन स्थापित किया। कांग्रेसी दंगरों के अन्दर दन्द थे। जनता नेता-विहीन हो गयी और दूसरे और अधिकारियों के द्वारा ने उसे और भी उत्तेजित किया। वह बपों से पढ़ाये गये गांधी जी के अहिंसात्मक युद्ध का पाठ भूल गई। विप्लव हिंसात्मक हो गया। तार बंटे गये, रेल की पटरियाँ उखाड़ी गयीं, थानों में आग लगाई गयी, सरकारी अम्बारों पर आक्रमण किये गये, और सरकारी खजाने तथा डाकघर लूटे गये: गुप्त रेडियो-स्टेशन खाले गये तथा समानान्तर सरकारी संस्थाओं का निर्माण हुआ। विद्यार्थियों, किसानों तथा नजदूरों ने इस आन्दोलन में पूर्ण हाथ बटिया। सरकार ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अन्धाधुंध दमन-क़द चलवाया गया तथा जनता पर भयंकर अत्या-

चार हुए। जनता के साथ जो वर्चस्व का व्यवहार किया गया उसके समक्ष सन् '५७ के विद्रोह के पश्चात् का वर्ताव दया का मूर्तिमान स्वरूप प्रतीत होता है। अवसर पा कर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की कामन्स सभा में भारत की स्वतन्त्रता के कट्टर शत्रु मि० एमरी ने कांग्रेस-नेता तथा उनके सिद्धान्तों के प्रति विष उगलते हुए कहा था कि कांग्रेस एक ऐसा आन्दोलन करने जा रही है जिसमें हिंसा और अहिंसा में कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है। इस प्रकार उन्होंने भारत में होनेवाले दमन का समर्थन किया था। किन्तु दमन का स्थायी प्रभाव भारत की अंग्रेजी सरकार और ब्रिटिश राष्ट्र के पक्ष में न होकर भारतीय राष्ट्र के पक्ष में हुआ। ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता की दृढ़ता का ज्ञान हो गया और कालान्तर में उसे वही करना पड़ा जो गांधी जी, प० नेहरू तथा कांग्रेस कार्य-समिति एवं अ० भा० कांग्रेस कमेटी चाहती थी।

नेहरू आदि सभी नेताओं ने सरकार की इस निर्दयता पूर्ण दमन-नीति को अत्यन्त घृणित बतलाया। यद्यपि जनता के हिंसात्मक कार्यों से नेहरू जी को क्लेश अवश्य हुआ फिर भी उन्होंने गर्व का अनुभव करते हुए कहा था कि यदि जनता उस राष्ट्रीय अपमान को चुपचाप सह लेती तो मुझे विशेष निराशा तथा अफसोस होता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि “मेरी यह निश्चित धारणा है कि अगस्त सन् १९४२ के आन्दोलन से राष्ट्र को वह अदम्य शक्ति और बहुमूल्य अवसर प्राप्त हुआ जिसकी हमें बहुत आवश्यकता थी। इससे हमें अपनी वलिदान-शक्ति और ब्रूटेन के दमन करने की वर्चस्व शक्ति का भी काफी ज्ञान हुआ।”

विद्रोह के अन्त के पश्चात् ब्रूटेन की कामन्स सभा में भाषण देते हुए मि० चर्चिल ने ‘गर्वपूर्वक’ कहा था, “सरकार की पूरी ताकत से यह उपद्रव कुचल दिया गया।” इतिहास के पन्नों पर पड़े हुए खून के छींटे, असहाय सत्य और मानवता की छाती में मोकी हुई कटार और वेवस

उदनाथ चोन्न, युग युग तक आने वाली मन्त्रानों को मात्राज्यवादी वृद्धों के दृष्टिगत तथा वृद्धों के मन्त्रानों की याद दिलाने गहेंगे :

१८४२ का मातृ मारनाथ इतिहास में सिर्फ अगल की क्रांति के लिए ही नहीं प्रसिद्ध रहेगा बल्कि एक और हृदय विदारक घटना के लिए भी वह याद किया जायेगा । वह घटना है बंगाल का भयंकर अकाल ।

जागती वह गेये । अंग्रेज वना छाड़कर भाग रहे थे सरकार ने बंगाल को भय का क्षेत्र घोषित कर दिया तथा वहाँ ने अनाज आदि इतना आरंभ कर दिया । साथ ही साथ बातायात के साथ आदि भी अत्यन्त स्थिति हो गये । वना में चावल आना बंद हो गया । उसके बदले सरगारियों के दल के दल पहुँचने लगे । उन्हीं दिनों बंगाल में एक बड़ा नृपान आया । इन सब संकटों के साथ-साथ बंगाल की तत्कालीन सरकार की अयोग्यता, सरकार कर्मचारियों की स्वार्थता और पूँजीपतियों की कमी न नृत्त होने वाला नृनाफा कमाने की इच्छा ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि बंगाल एक भयंकर विपत्ति के भूनावातों से ग्रसित हो गया । देश की विभिन्न संस्थाओं ने तथा विद्वानों ने इस अकाल ने अर्थात् ३५,००,००० व्यक्तियों की मृत्यु-संख्या का अनुमान लगाया । इस ननुप्य-कृत अकाल ने बंगाल की जन-हानि ही नहीं की बल्कि उनसे भी बढ़कर उनकी नैतिक गंद तोड़ डाली । पैट की ज्वाला ने नृखे नाँगम की अगती नावलन वच्चियों को वेश्याओं के हाथ बेचने के लिए लाचार किया । उन्ड जाँती के दुकड़ों पर ननुप्य की आत्मा तथा सत्ता काया करंद लेने का दम्भ रखनेवाले वनिक कुत्तों ने उन सूत्री हड्डियों ने अगती अनानि शान्त करने का प्रयत्न किया । नागरता गे पड़ी, और 'न्यायी' ईश्वर ने भय से अगती आँवे बन्द कर लीं ।

आजाद हिन्द फौज के मुकदमे

कांग्रेस से सैद्धान्तिक मतभेद होने के पश्चात् नेता श्री सुभाषचन्द्र

बोस भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति का दूसरा उपाय सोचने लगे । अंग्रेजों की शक्ति और कांग्रेस की सफलताओं से उनका विश्वास अहिंसात्मक आन्दोलनों से उठने लगा था, और उनके विचार से इन सब आन्दोलनों से यदि स्वराज्य पाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था । अतः वे बलपूर्वक, अंग्रेजों के शत्रुओं की सहायता से तथा विजय की अशान्तिपूर्ण राजनीतिक स्थिति से फायदा उठाकर, लंदन की सरकार के चंगुल से अपने देश को स्वतन्त्र करा लेने का स्वप्न देखने लगे । उन्होंने धूम-धूम कर देश के जोशीले नवयुवकों तथा सेना के देशभक्त अफसरों को संगठित कर आजाद हिन्द फौज की स्थापना की । वे और उनके सैनिक साथी ब्रिटिश सरकार की ओर ख बचाकर भारत की सीमा पार करते हुए मित्र राष्ट्रों के शत्रुओं से 'स्वतन्त्रता प्राप्ति में सहायता' की शर्तों पर ना मिले ।

अपनी आजाद हिन्द फौज के साथ नेता सुभाष ने 'दिल्ली चलो' के नारे के साथ भारत में प्रवेश भी किया था, परन्तु अभाग्यवश तभी उनकी सहायक (कम से कम सहायता के लिए उनका जिसपर भरोसा था) जापानी सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया । फलतः युद्ध सामग्री की कमी के कारण उन्हें निराश हो वापस लौटना पड़ा था । युद्ध-समाप्ति के पश्चात् निराश आजाद हिन्द फौज के सेनानी एक-एक कर भारत लौटने लगे । सरकार ने ब्रिटिश स्वार्थों के विरोधी उन बहादुर नवयुवकों को गिरफ्तार कर लिया तथा न्याय और अनुशासन का ढोंग करती हुई उनपर मुकदमा चलाने की तैयारी करने लगी । विरोधी जनता ब्रिटिश

सरकार के इस कार्य से उन्मत्त हो उठी। इन वीर बंदियों को बचाने के लिए तीव्र आन्दोलन आरम्भ हुआ। सम्पूर्ण भारत में प्रदर्शनकारियों को हतोत्साह करने के लिए गोलियों चलीं। कलकत्ते में ४० व्यक्ति मरे तथा ३०० घायल हुए। बम्बई आदि स्थानों पर मृत्यु तथा घायलों की संख्या करीब-करीब उतनी ही रही। इसी प्रसंग में १८ फरवरी को भारतीय नौ-मैनिकों ने प्रसिद्ध नाविक-विद्रोह शान्तिमय ढंग से आरम्भ किया। उन्होंने जंगी जहाजों पर से अंग्रेजी झंडे उतार कर कांग्रेस और मुस्लिम-लीग के झंडे फहरा दिये, और आजाद हिन्द के सैनिकों को छोड़ देने तथा इण्डोनेशिया से भारतीय सैनिकों को हटा लेने की माँग की। यह नाविक-विद्रोह कलकत्ता, विशाखापट्टम, मद्रास और कराँची में फैल गया। वायु-सेना का भी कुछ अंश इसमें सम्मिलित हुआ। बम्बई में तीन लाख मजदूरों ने सहानुभूति में हड़ताल की। इस असन्तोषात्मक विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने अपनी दानवीय शक्ति से काम लिया, परन्तु उससे विद्रोह की भावना दबी नहीं। आजाद हिन्द फौज की छूत फैलने लगी। अगले महीनों में सेना और पुलिस के कर्मचारियों ने भी अनेक स्थानों पर हड़ताल की।

विपत्ति में पड़े इन साहसी व्यक्तियों की रक्षा और सहायता के लिए पं० नेहरू ने भी जेल से छूटते ही सर्वप्रथम इसके विरुद्ध आवाज उठायी, तथा बाद में उस फौज के कैप्टन साहनबाज, कैप्टन सहगल और लेफ्टिनेन्ट दिल्लीन आदि के मुकदमों की पैरवी के लिए उन्होंने कांग्रेस को तैयार कर अपनी सारी शक्ति और ध्यान उस ओर लगा दिया। जो पं० नेहरू २५ वर्ष पूर्व अपने वकालत पेजे का त्याग कर स्वराज्य-प्राप्ति के सग्राम में जुट गये थे, वे अपने असहाय पर देशभक्त भाइयों के मुकदमों की मिलिटरी कोर्ट के सामने पैरवी करने के लिए श्री भूलाभाई देसाई, ब्रिस्टर आसफअली आदि के साथ वकालत की पोशाक में एकबार फिर फौजी न्यायालय के स्थान, लाल किले में उपस्थित हुए थे।

नेहरू जी तथा श्री सुभाष बोस में सिद्धान्ततः इतना मतभेद था कि श्री

(१७१)

बोस ने कांग्रेस-सिद्धान्त के विरोध में फार्वर्ड ब्लॉक संस्थापना की थी, और नेहरू जी आदि व्यक्तियों के विरोध के पश्चात् भी हिंसात्मक ढंग से देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आजाद हिन्द फौज की स्थापना की थी। इतना विरोध होते हुए भी नेता श्री सुभाष बोस ने गाँधी जी, उनके सिद्धान्त अहिंसा तथा उनके साथियों के प्रति अंत तक सम्मान तथा आस्था ही प्रकट की थी। उन्होंने आजाद हिन्द फौज के सेनानायक की हैसियत से सिंगापुर-रेडियो से बोलते हुए भारत की आत्मा के प्रतीक से आशीर्वाद मोंगा था, “हमारे राष्ट्रपिता महात्मा जी ! भारत को स्वतंत्र करने के इस पवित्र युद्ध तथा अपने प्रयत्न में हम आपके आशीर्वाद और शुभकामना की याचना करते हैं।” स्वयं महात्मा गाँधी ने ऐसे अवसर पर कहा था, “सुभाष बाबू के साथ मेरा सम्बंध सदा पवित्रतम तथा सर्वोत्तम रहा है। बलिदान की उनकी योग्यता मैं सदैव से जानता रहा हूँ। लेकिन उनकी संगठन की योग्यता, सैनिक का चातुर्य एवं साहस और साधन जुटाने की क्षमता का पूरा ज्ञान तो मुझे तब हुआ, जब वे भारत से भाग निकले।” नेताजी की फौज के एक परम प्रतिष्ठित मेजर जेनरल शाहनवाज खाँ ने अपने मुकदमे से छुटकारा पाने के पश्चात् अपने एक विचारपूर्ण लेख में नेताजी की निस्वार्थता का बयान करते हुए लिखा था कि, बृहत्तर पूर्वी एशिया की एक कान्फ्रेंस में जब जापान के प्रधान मंत्री जेनरल तोजो ने अपने भाषण में यह कहा कि नेताजी स्वतंत्र भारत के सर्वे-सर्वा होंगे, तब नेताजी ने उठकर दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। कारण भारत में कौन क्या होगा, यह निश्चय करने का पूर्ण अधिकार भारतीय जनता को होगा। मैं तो भारत का एक तुच्छ सेवक हूँ, और वस्तुतः भारत के सर्वे-सर्वा बनने के जो लोग अधिकारी हैं, वे हैं महात्मा गाँधी, मौलाना अबुलकलाम आजाद और पं० जवाहरलाल नेहरू।”

पं० नेहरू का सुभाष बाबू के प्रति क्या विचार था यह शिमले में, १ जुलाई १९४५ को एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने व्यक्त किया था,

“मेरे विचार आज भी वही हैं, जो १९४२ के आरम्भ में मैंने व्यक्त किया था। तब मैंने कहा था यदि सुभाष बोस जापान की सरकार के तत्वावधान में भारत आयेगे, तो मैं उनके विरुद्ध लड़ूँगा, क्योंकि ऐसी हालत में उनका भारत आना भारत के भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध होगा, किन्तु जापान की लड़ाई के बाद यदि वे भारत आये तो उनका विरोध करना ठीक न होगा।.....कोई भारतीय नेता किसी दूसरे भारतीय नेता के प्रधान उद्देश्य की उपेक्षा नहीं कर सकता, और श्री बोस के सम्बन्ध में मुझे कोई शक नहीं कि उनका प्रधान उद्देश्य ‘भारत की स्वतन्त्रता’ है।

स्वयं महात्मा गान्धी ने भी कहा था कि मैं इस बात से अत्यन्त प्रसन्न हूँ कि भारत ने आजाद हिन्द के छूटे हुए फौजी जवानों का शानदार स्वागत किया। “मैं आजाद हिन्द फौज और नेताजी सुभाष बोस की कुर्बानी और देश-प्रेम की सराहना करता हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके को अपनाया था उससे मैं सहमत नहीं हूँ।” उन्होंने आगे कहा था, “नेताजी मेरे लिए पुत्र के समान थे। स्व० श्री देशबन्धु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कार्य करने वाले एक होनहार कार्यकर्ता के रूप में मैंने पहले-पहल उन्हें जाना था। आजाद हिन्द फौज के लिये उनका आखिरी सदेश यह था कि विदेश में वे हथियारों से लड़ रहे हैं, लेकिन भारत लौटने पर उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में अहिंसा का सिपाही बनना है और इस नाते देश की सेवा करनी है। हिन्दुस्तान के लिए आजाद हिन्द फौज और नेताजी का सदेश यह नहीं है कि आपसी झगड़ों को मिटाने के लिए हम हथियार चलाने के तरीकों को अपनाये—क्योंकि उसकी आजमाइश हो चुकी है, और वह कच्चा साबित हो चुका है—बल्कि उनका संदेश तो यह है कि अपने बीच हम अहिंसा, एकता, मेलजोल और सगठन बढ़ायें।.....हिन्दुस्तान के सभी धर्मों और सभी कौमों के लोग एक ही झण्डे के नीचे, एक ही उद्देश्य से एकत्रित हुए यही उनका सबसे बड़ा तथा अनुकरणीय कार्य था।.....तलवार की ताकत से सत्याग्रह की ताकत कहीं ज्यादा मजबूत है। आजाद हिन्द फौज के लोगों से

मैंने यह बात कही और उन्होंने खुशी के साथ मुझसे कहा कि वे इस चीज को समझ चुके हैं और अब वे कांग्रेस के झण्डे के नीचे, अहिंसा के सच्चे सिपाही बनकर, भारत की सेवा करने का प्रयत्न करेंगे ?” कहने की आवश्यकता नहीं कि नेहरू जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी नेताओं का भी आजाद हिंद फौज के सम्बन्ध में यही भाव था ।

आजाद हिन्द फौज से सम्बन्धित दो प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पास किया । एक प्रस्ताव इस आग्रह का था, “चूँकि आजाद हिन्द फौज के लोगों की कानूनी पैरवी के लिए नियुक्त की गई कमेटी के बाद भी उनके सम्बन्ध की अनेक समस्याएँ और हैं, इसलिए एक और कमेटी नियुक्त की जाती है, जो ‘आजाद हिन्द फौज-जाँच और सहायता कमेटी’ कही जायेगी । इस कमेटी का कार्य उन लोगों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर उन्हें सहायता पहुँचाना होगा । यह कमेटी आजाद हिन्द फौज की सेवा में मरे हुए लोगों के आश्रितों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके उनको सहायता प्रदान करेगी । कमेटी के अध्यक्ष श्री पटेल बनाये गये तथा सदस्यों में सर्वप्रथम नाम नेहरू जी का ही था । कांग्रेस कमेटी ने एक अन्य प्रस्ताव द्वारा घोषित किया कि, “यद्यपि कांग्रेस आजाद हिन्द फौज द्वारा प्रदर्शित बलिदान, अनुशासन, देशभक्ति और वीरता तथा एकता की भावना के लिए गर्व अवश्य अनुभव करती है, जो श्री सुभाषचन्द्र बोस द्वारा विदेशों में अभूतपूर्व अवस्थाओं में संगठित की गई थी, और यद्यपि कांग्रेस यह ठीक आर उचित समझती है कि वह उस संगठन के उन लोगों की पैरवी करे जिन पर मुकदमें चल रहे हैं, और उसमें उन लोगों की सहायता करे जो कष्ट में हैं, पर कांग्रेस-जनों को यह भूलना नहीं चाहिए कि उनकी सहायता और सहानुभूति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि कांग्रेस अपनी उस नीति से हट गई है, जो उसने शान्तिपूर्ण और उचित साधनों से स्वराज्य प्राप्त करने के लिए बना रखी है ।” स्वयं नेहरू जी ने भी यह कहा था कि कांग्रेस द्वारा निर्धारित ‘आजाद हिन्द फौज-रक्षा-कमेटी’ का विशेष कार्य उन लोगों की रक्षा करना है जिन

पर मुकदमा चलेगा । हम लोगों को स्वभावतः आजाद हिन्द फौज के सनी सदस्यों के भाग्य की चिन्ता है । इस फौज के जो सदस्य मर गये हैं, अथवा जो काम करने के योग्य नहीं हैं, उनकी हम लोगों पर विशेष जिम्मेदारी है ।

बन्दी होने के पश्चात् आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को सरकार के हाथ से अनेक यातनाये मिलीं, परन्तु कांग्रेस तथा देश के एकमत से पञ्च में हो जाने के पश्चात् दिन-प्रतिदिन उनके दुःख कम होने लगे । जिन सैनिकों पर कोर्ट मार्शल के अन्तर्गत मुकदमें चलाये गये थे उनके मुकदमों की पैरवी नित्यार्थ भाव से देश के नामी वकीलों—श्री सप्रू, श्री फैलाशनाथ काटजू, श्री नेहरू आदि—ने की ।

कांग्रेस को आजाद हिन्द फौज के लोगों की पैरवी करते देखकर सरकार को भी अपनी नीति अन्त में यह बनानी पड़ी थी कि जिन आदमियों के विरुद्ध युद्ध-कैदियों के प्रति निर्दयता एवं पाशविकता के अपराध करने का आरोप है, सिर्फ उनके विरुद्ध ही मुकदमें चलाये जायें, तथा किसी पर केवल इसलिए कानूनी कार्यवाही न की जाये कि वह उस फौज में था । पहला और सबसे महत्वपूर्ण आरोप वह था जो आजाद हिन्द फौज के मेजर जेनरल शाहनवाज, कैप्टन सहगल और दिल्लीन पर लगाया गया था । इन्हें छोड़ देने के लिए देश भर में जुलूस आदि निकाल कर विराट प्रदर्शन हुआ और त्वर्य नेहरू जी ने भारत के प्रधान सेनापति सर आचिन लेक से मिलकर आजाद हिन्द फौज वालों के सम्बन्ध में नरम नीति काम में लाने का अनुरोध किया था । नामला नियमपूर्वक चला और अंत में कोर्ट मार्शल के न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को अपराधी ठहराते हुए आजीवन कालेपानी की सजा दे दी थी । पर वह सजा सुनाई नहीं गई, न किसी पर प्रकट ही की गई थी, क्योंकि कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा जब तक प्रधान कमांडर से स्वीकृत न कर ली जाये वह सुनाई नहीं जाती । जेनरल सर आचिन लेक ने कोर्ट मार्शल के फैसले पर विचार कर कालेपानी की सजा तो

रद्द कर दी, किन्तु सेना से उनके बर्खास्त किये जाने और बकाया वेतन तथा एलाउन्स की जव्ती की आज्ञा जारी रखी । इस प्रकार ये तीनों सेनानी ३ जनवरी १९४६ को छोड़ दिये गये । उनके मुक्त होने के पश्चात् देश ने असाधारण प्रसन्नता व्यक्त की थी । उस अवसर पर नेताजी सुभाष बोस के कलकत्ते के निवासस्थान से ६ जनवरी की रात को तीन तार भेजे गये थे; उनमें से एक तो उन छूटे हुए तीनों व्यक्तियों के नाम और दूसरा पैरवी-कमेटी के नाम बधाई सूचक था । तीसरा तार पैरवी के लिए सबसे उद्योगी प० नेहरू के नाम इस आग्रह का था, “देश को जागृत करने के आपके प्रारम्भिक प्रयास से ही इन लोगों की जीवन-रक्षा हुई है । जयहिन्द ।” इसमें सन्देह नहीं कि नेहरू जी ने आजाद हिन्द फौज के अभियुक्तों को छुड़ाने में इस प्रश्न को लेकर जैसा जागृत लौकमत तैयार कराया, उससे नेहरू जी की महानता सम्पूर्ण भारत में फैल गयी ।



कि इन जातियों की सामूहिक प्रतिद्वंद्विता अंग्रेजी राज्य के समय से आरम्भ हुई है ।” प्रधान मंत्री रैमजे मैकडानल्ड भी यह कहने पर बाध्य हुए थे कि, “हिन्दू और मुसलमान-समाज में फूट डालने के लिए सरकार की ओर से दुष्ट शक्तियाँ कार्य कर रही हैं ।... भारतीय विषयों से जानकारी रखने वाला कोई भी इसे इनकार नहीं कर सकता कि हिन्दू-राष्ट्रीयता के विरुद्ध.....और मुसलमानों के पक्ष में ब्रिटिश शासक-वर्ग में एक जबरदस्त पक्षपात का भाव है ।” ऊपर व्यक्त किये गये इन कुछ विचारों तथा वक्तव्यों से अंग्रेजों की साम्प्रदायिक कूटनीति का स्पष्ट भंडाफोड़ हो जाता है ।

अस्तु, साम्प्रदायिक विचारों से संचालित तथा सरकार के दूध से पली मुसलिम लीग आरम्भ से ही कांग्रेस के विरुद्ध विष उगलती रही, तथा अपने सम्प्रदाय के स्वार्थ के लिए कार्य करती रही । यह दूसरी बात है कि कभी-कभी अपने ही स्वार्थ से प्रेरित हो वह कुछ दिनों तक के लिए कांग्रेस से मिल गई हो । इस छोटी पर उच्चवर्गीय संस्था का न तो जनता से विशेष सम्पर्क ही था और न उसपर विशेष प्रभाव ही । प्रथम महायुद्ध तथा तुर्कों में खिलाफत और मुस्लिम तीर्थ-स्थानों के प्रश्नों को लेकर भारत के मुसलमानों में काफी उत्तेजना तथा जागृति का प्रसार हुआ, और वे भीतर ही भीतर भीषण रूप से ब्रिटिश नीति के विरोधी हो गए । लीग के नेताओं ने इस स्थिति से लाभ उठाया और उन्होंने कांग्रेस से मिलकर तथा खिलाफत का प्रश्न उठाकर उत्तेजित जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया । १९२०-२३ के असहयोग आन्दोलन के पश्चात् धीरे-धीरे खिलाफत कमेटी का भी अंत होने लगा, क्योंकि अब उसका आधार—तुर्कों-खिलाफत का मामला—दब चुका था । खिलाफत कमेटी के काफी मुसलिम नेता कांग्रेस में आ गये । अतः १९३० के अवज्ञा-आन्दोलन में मुसलमानों का काफी साथ कांग्रेस को मिला । पीछे मि० जिन्ना जब लीग में जा शामिल हुए, तब लीग का आन्दोलन और उसके साथ ही सरकारी नौकरियों और काउंसिलों में

मुसलमानों के लिए काफी प्रतिनिधित्व की उनकी मांग ही लोग के आन्दोलन का प्रमुख कार्य रह गया। उनकी विचार-धारा, उनके द्वारा उपस्थित की जाने वाली मांग, एक संकुचित क्षेत्र, एक सम्प्रदाय के स्वार्थों तक ही सीमित रह गई। गाँधी जी तथा नेहरू जो आदि नेताओं ने, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आन्दोलन में सभी वर्गों, सभी सम्प्रदायों का—सम्पूर्ण भारत के नेताओं का—सहयोग चाहते थे, कांग्रेस और लीग में समझौता कराने का अथक परिश्रम किया, परन्तु सभी प्रयत्न निष्फल रहे।

अब प्रश्न उठता है कि भारत को खंडित कर पाकिस्तान बनाने के विचार की उत्पत्ति ही कैसे हो पायी। पाकिस्तान की 'सूझ' का काफी श्रेय सर मुहम्मद इकबाल को है। 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' राष्ट्रीय गीत के रचयिता कवि ने अपना चोला बदल कर उसे साम्प्रदायिकता के रंग में रंग लिया था। ब्रिटिश-सरकार अपना कूटनीतिक खेल बड़ी योग्यता और चालाकी से खेल रही थी। कांग्रेस-मंच से गरम राष्ट्रीय मुस्लिम नेता के तौर पर दहाड़ने वाले उन अली-बंधुओं के भी पाव लड़खड़ाने लगे थे, जिनके छोटे भाई मौलाना मुहम्मद अली ने १९२३ में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। मि० स्मिथ के अनुसार, "आदर्शवादी होने के कारण वे मानवीय व्यवहार को समझने में असमर्थ थे।" सन् १९३० के मुस्लिम लीग के प्रयाग के अधिवेशन में उन्होंने परोक्ष रीति से पाकिस्तान के विचार की नींव डाली। वह चाहते थे कि प्रान्तों के पुनर्संगठन के समय मुस्लिम प्रान्तों को भारतीय संघ के अंतर्गत स्वायत्त शासन का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। इसके तीन वर्ष पश्चात् कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के चार मुस्लिम छात्रों ने, "अब या कभी नहीं" नामक चार पृष्ठों की एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें मुसलमानों की सांस्कृतिक पृथक्ता पर जोर देते हुए उन्होंने यह सुझाव पेश किया था कि भारत का बँटवारा करके मुस्लिम राष्ट्र का एक पृथक् राज्य स्थापित किया जावे। उस समय मुस्लिम लीग के नेताओं ने इसे 'काल्पनिक' तथा 'अव्यवहारिक' लड़को

की योजना बतलाई थी । परन्तु पाँच वर्ष पश्चात् ही यह 'अव्यवहारिक कल्पना' समझी जाने वाली विचार-धारा से सभी प्रतिक्रियावादी साम्प्रदायिक मुसलमान अनुप्राणित हो उठे । मि० जिन्ना ने कांग्रेस के 'सहयोग तथा सम्मिलित कार्य' के नियन्त्रण पर कहा था कि ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब कि हम खुले शब्दों में मंजूर कर ले कि हिन्दु-स्तान के मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था मुस्लिम लीग है, तथा कांग्रेस अपने को विशुद्ध हिन्दू संगठन समझे । ऐसा घोषित करना कांग्रेस के लिए कभी सम्भव नहीं था, अतः उनसे कभी मेल न हो सका । मि० जिन्ना को ब्रिटिश शासकों के परोक्ष 'अमय बरदान' पर मरोसा था, और वे सोचते थे कि यदि कांग्रेस के उद्योग से देश को कुछ भी प्राप्त हो सका तो उसमें वे बड़ा हिस्सा बिना मेहनत ही पाने से वंचित न रहेंगे ।

सन् १९३८ में सिंध के प्रान्तीय मुस्लिम-सम्मेलन में अध्यक्ष-पद से मि० जिन्ना ने यह माँग पेश की कि एशिया, विशेषतः भारतीय महाद्वीप में स्थायी शान्ति बनाये रखने, उसके हिन्दू और मुसलमान सम्प्रदायों को सांस्कृतिक विकास का अवसर देने, तथा उन्हें आर्थिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से भारत दो सघ राज्यों में बाँट दिया जाना चाहिए, जिसमें एक मुस्लिम प्रान्तों का सघ हो और दूसरा हिन्दू प्रान्तों का । कुछ दिनों पश्चात् सन् १९४० में इस प्रस्ताव को भारतीय मुस्लिम लीग की कार्य-समिति ने अपने लाहौर-अभिवेगन में भी अपना लिया । नेहरू जी ने इसपर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा था कि यदि राष्ट्रीयता का आधार मजहब है तो दो ही क्यों, भारत के बहुत से टुकड़े हो सकते हैं ।

पाकिस्तान की इस माँग का कांग्रेस की ओर से जोरदार विरोध हुआ, परन्तु मि० जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की यह माँग जोर पकड़ती गयी । देश जब कि महान् सकट के गर्त पर खड़ा था, और विपरीत वायु का एक झोंका ही उसे अनन्त काल के लिए चिर निद्रा में सुला देतो, नेता कहे जाने वाले ये रंगे मियार अबोध मुस्लिम जनता को

धर्म के नाम पर मीठा जहर पिला रहे थे । जनता नीलकंठ तो है नहीं, आखिर वह इसे कब तक पचा पाती ?

मुसलमानों के एक अलग मजहबी राज्य पाकिस्तान के बारे में नेहरू जी के विचार हमेशा ही विरोधी रहे हैं । ७ जनवरी १९४६ को सिन्ध की एक विराट सभा में भाषण देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा था, “विश्व की वर्तमान सकटपूर्ण स्थिति में पाकिस्तान की माँग बिल्कुल अवाञ्छित और अवास्तविक है । पाकिस्तान स्वतन्त्र नहीं रह सकता, उसका अर्थ गुलाम देश होगा ।.....कांग्रेस देश का विभाजन हर्गिज न होने देगी । कांग्रेस का लक्ष्य संयुक्त एवं सगठित भारत है ।” उन्होंने अपने एक और भाषण में भी कहा था, “हम प्रगतिशील आधुनिक विचारों के कारण अखंड भारत के समर्थक हैं । विभाजित भारत एक कमजोर राष्ट्र होगा ।..... पाकिस्तान साम्प्रदायिक समस्या का हल नहीं है ।.....यदि मुसलमान विभाजन पर अड़ ही जायेंगे तो वे रोके नहीं जा सकते, लेकिन विभाजन से किसी का भी हित न होगा, मुसलमानों का भी नहीं ।”

भारतीय साम्प्रदायिक स्थिति तथा लोकमत का ज्ञान करने के लिए तथा उसके आधार पर उन्हें शासन-व्यवस्था सौपने के उद्देश्य से (यद्यपि यह सब ब्रिटिश शासन की ऊपरी दिखलावे की चाल थी और वह स्वयं हृदय से भारत को दो भागों में विभाजित हो दो निर्बल राष्ट्र बनते देखना चाहती थी ।) यहाँ इंग्लैंड द्वारा एक गिष्ट-मंडल मेजा गया । जिसके एक सदस्य मि० सोरेन सेन ने, आते ही पूर्व निश्चित योजना के अनुसार अपना रटा-रटाया विचार व्यक्त किया, “मेरा विचार है कि यदि मुस्लिम बहुसंख्यक प्रान्तों को डोमीनियन स्टेट्स के आधार पर पृथक् अस्तित्व का आश्वासन दे दिया जाये तो अखिल भारतीय विषयों में शेष भारत के साथ उनके सहयोग की समस्या कुछ अंश तक हल की जा सकती है ।” ब्रिटिश सरकार ने अपनी जीत का अंतिम पासा फेका था ।

सरदार पटेल ने उक्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा था,

“कांग्रेस न्यायोचित तरीके से अल्प-संख्यकों की रक्षा तथा संरक्षण के पक्ष में है, किन्तु वह देश का बँटवारा करके मि० जिन्ना की असंभव माँग को स्वीकार नहीं कर सकती।” अपने प्रस्ताव में कांग्रेस भारत की स्वतन्त्रता और एकता के प्रस्ताव को अपना चुकी है।” किन्तु इन सबका कोई परिणाम न हुआ। मुस्लिम लीग अपनी पाकिस्तान सम्बन्धी माँग पर अड़ी रही।

९ अप्रैल १९४६ को मि० जिन्ना के सभापतित्व में केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-मंडलों में मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ, जिसमें मि० जिन्ना ने भारत निवासी मुसलमानों की रक्षा और उद्धार के लिए पाकिस्तान बनाना आवश्यक बतलाया। सर फिरोज खॉं नून ने एक भाषण में मुसलमानों से कहा, “हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा सकट आने वाला है। हमारी अतर्भावना की गहराई को न तो हिन्दू समझते हैं न अंग्रेज। यदि हिन्दू हमें पाकिस्तान और स्वतन्त्रता देंगे तो वे हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं; और यदि अंग्रेज देंगे तो अंग्रेज। लेकिन यदि इनमें से कोई न देगा तो रूस हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र होगा।” “चाहे हमें लड़ते हुए ही क्यों न मरना पड़े, हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे वंशज अखंड हिन्दुस्तान के गुलाम न रहे।” “यदि ग्रेट ब्रिटेन हमें हिन्दू राज्य के अधीन रखेगा, तो हम उसे यह बतला देना चाहते हैं कि मुसलमान इस देश में इतनी ज्यादा सत्यानाशी और तबाही करेंगे कि उनके कारण चंगेज खॉं के तत्सम्बन्धी कार्य भी फीके पड़ जायेंगे।” मुसलमान नेता की यह धमकी और चुनौती कितनी निम्नकोटि की तथा नृशंसतापूर्ण थी कि हमें एकबार फिर इस देश में आकर बस जाने, और इसकी सौधी मिट्टी को अपनी न समझने वाले सदियों पूर्व के लुटेरे काफिरों की याद आ जाती है, जिनकी रूढ़ काबुल, फारस, मिश्र और इरान आदि देशों की गलियों में चक्कर लगाती थी, और जिनका नापाक जिस भारत की कुंवारी धरती के साथ बलात्कार करने के लिए यहाँ ढोलता था।

अंग्रेजों की कूटनीति का साम्प्रदायिक पासा उनके मन के सुताविक

पड़ा। उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष आक्षेपों से बच कर, मुस्लिम लीग की पीठ के पीछे से, भारतीय आत्मा पर अपना अन्तिम प्रहार किया। भजहरी मुसलमानों की मूर्खतापूर्ण नीति के फलस्वरूप हिन्दुस्तान के दिल के दो टुकड़े होना निश्चित हो गया। लार्ड लिटोवेल ने भी घाव पर निमक छिड़कते हुए कहा, “विभाजन से लाभ उस समय भलीभाँति समझ में आ जायेगा जब विभाजन कर दिया जायेगा।” सारे राष्ट्रीय नेता स्तब्ध थे। स्थिति से निराश गाँधी जी ने अन्त में कहा था, “जनता को यह बिसरण न कर देना चाहिए कि कांग्रेस को इस स्थिति में (विभाजन की) आने के लिए बाध्य किया गया है। मैं आप लोगों के हृदय की कसक को यह कह कर कम कर देना चाहता हूँ कि हिन्दुओं, मुसलमानों और सिक्खों का अब तक कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। जो कुछ वायसराय ने किया है उसे वे परस्पर समझौते द्वारा रद्द कर सकते हैं।” हिन्दू महासभा के समापति श्री एल० बी० मोपटकर के विचारानुकूल नयी योजना से यह स्पष्ट था कि “ब्रिटिश सरकार सच्चा हस्तान्तरण के लिए उत्सुक थी, और मुस्लिम लीग का परिपक्व नेतृत्व (Virile Leadership) कांग्रेस हाई कमाण्ड के कच्चे नेतृत्व (Puerile Leadership) के सम्मुख विजय प्राप्त कर रहा है।” कुछ विदेशी लोगों के विचार भी विभाजन के अनुकूल न थे। बर्मा के नेता आंगसेन के शब्दों में, “विभाजित भारत केवल भारतीयों के ही लिए नहीं, बल्कि समस्त एशिया और समस्त संसार की शान्ति के लिए अपशकुनसूचक था।” अमेरिका के भी कुछ लोग विभाजन के प्रतिकूल थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के न्यूयार्क के प्रतिनिधि मि० इमेन्युएल सेलर के अनुसार, “ब्रिटिश सरकार ने मि० जिन्ना को प्रसन्न करने की कोशिश की है। मेरी समझ ने यह नहीं आता कि किस प्रकार से देश का पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में विभाजन किया जायेगा, अथवा अंग-विच्छिन्न पाकिस्तान अपना कान चला सकेगा।”

प्रधान मंत्री नेहरू

आज विश्व का प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि जागते हुए विश्व में, जागते हुए एशिया, और जागते हुए एशिया में जागते हुए भारत की कल्पना को साकार करने वाले पं० जवाहरलाल इस महान गणतंत्रात्मक राष्ट्र के पहले प्रधान मंत्री हैं। वे ही जवाहरलाल जिन्हें महात्मा गांधी 'भारत के जवाहर' और उनके सहयोगी तथा मित्र 'मनुष्यों में जवाहर' कह कर सम्मान से सम्बोधित करते थे; और जिन्हे आज से बहुत दिन पूर्व ही महात्मा गांधी ने अपना 'राजनीतिक उत्तराधिकारी' घोषित कर दिया था। महात्मा गांधी की तरह जनता को भी अपने इस प्रिय नेता पर पूर्ण विश्वास है। भारत के भावी भविष्य और उसके भाग्य से सम्बद्ध जवाहर की विश्वस्त कल्पना करते हुए कवीन्द्र रवीन्द्र ने कहा था, 'निस्संदेह नव भारत के सिंहासन पर जवाहरलाल का स्वत्वाधिकार है।.....यौवन के नव संचार एवं विजयोत्थास, अन्याय के प्रति दुर्जय संग्राम एवं स्वतंत्रता के प्रति अक्षुण्ण आस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले जवाहरलाल भारत के ऋतुराज हैं।' आखिर किन कारणों से बाध्य होकर अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कट्टर शत्रु पं० नेहरू के हाथों में इस महादेश का शासन-सत्त संचालित करने के लिए सर्वोच्च सत्ता सौंपी? भारतीय राजनीति और उसमें नेहरू का स्थान ज्ञात करने के लिए विहंगम दृष्टि से तात्कालिक घटनाओं की ओर दृष्टिपात करना अत्यन्त आवश्यक है, जिसने उन्हें इस महान उत्तरदायित्व के पद पर आरुढ़ कर दिया।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि अंग्रेजों की अस्पष्ट नीति के फलस्वरूप, गांधी जी के प्रयत्न से १९४२ में कांग्रेस ने 'भारत को छोड़ा'

प्रस्ताव पास किया था, तथा अपने इस उद्देश्य-पूर्ति के लिए उसने गांधी जी को सत्याग्रह-आन्दोलन आरम्भ करने तथा उसका संचालन करने का पूर्ण अधिकार दे दिया था। अपने रचनात्मक कार्यों के फलस्वरूप इधर कई वर्षों से नेहरू जी, महात्मा गांधी के बाद इन् आन्दोलनों के प्राण तथा इसके प्रधान नेता हो गये थे। वे कार्यकारिणी के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, गांधी जी की इच्छानुसार भावी आन्दोलन की रूपरेखा तैयार करने में जी-जान से जुट गये थे।

ब्रिटिश सत्ता ने यह पहले ही निश्चित कर लिया था कि अबकी कांग्रेस की शान को मिट्टी में मिलाकर इस आन्दोलन को पूर्णतः कुचल देगे, जिससे इसे फिर कभी सिर उठाने का साहस ही न हो। अतः आन्दोलन आरम्भ होने के पूर्व ही कांग्रेस के सभी नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर, उसे गैरकानूनी संस्था करार कर दिया गया था। परन्तु जनता को अपने नेताओं के निश्चय का ज्ञान हो गया था; अतः उसने नेता विहीन होने पर भी भीषण रूप से विद्रोह आरम्भ कर दिया। सरकार ने आन्दोलन कुचलने के लिए उन सभी बर्बरतापूर्ण नृशंस साधनों का प्रयोग किया जो उसके पास थे। अपने घृणित पक्ष का समर्थन करते हुए, इस अवसर पर ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की कामन्स सभा में, भारत की स्वतंत्रता के कट्टर शत्रु मि० एमरी ने कांग्रेस और उसके सिद्धान्तों पर आक्षेप करते हुए तथा महात्मा गांधी और उनकी नीति को झूठा बतलाते हुए कहा था, “कांग्रेस एक ऐसा आन्दोलन करने जा रही है जिसमें हिंसा और अहिंसा में कोई भेद नहीं रखा गया है।”

जिस लोकतंत्र के नाम पर अंग्रेज और उनके ‘प्रजातंत्र-रक्षक’ साथी, जर्मनी और जापान की फासिस्ट शक्तियों से जीवन और मरण का सग्राम कर रहे थे, उसीके सारे सिद्धान्तों की हत्या उन्हीं अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने भारत की सबसे बड़ी, जनप्रिय लोकतंत्री सत्ता कांग्रेस को कुचल डालने के उद्देश्य से कर डाला। जिससे कि वह अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए, और उसमें जनतंत्रात्मक—“जनता का, जनता

के लिए, जनता के द्वारा"—शासन की स्थापना का सफल प्रयास न कर सके। उनके दानवीय कार्यों द्वारा आतंक और भय की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप, यद्यपि थोड़े समय के लिए अंग्रेज शासकों को अल्प सफलता मिल तो अवश्य गई, किन्तु नेता विहीन होते हुए भी भारत की जनता ने जिस साहस तथा देश-प्रेम की भावना से पूर्ण, साम्राज्यवादी शासन के प्रति अपनी घृणा प्रकट की, उससे अंग्रेजों की आत्मा भी कांप उठी, और उन्हें यह निश्चय हो गया कि अब और अधिक समय तक भारत पर विदेशी शासन बनाये रखना असम्भव है।

इसके अतिरिक्त बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में ही वे अपनी मलाई समझने लगे थे। विन्व, द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ से ही दो गुटों में विभक्त हो गया था। एक तो अमेरिका, इङ्गलैण्ड आदि का पूँजीवादी गुट, दूसरा सोवियत रूस का साम्यवादी गुट, जो सर्वहारा के अधिनायकत्व के अन्तर्गत मजदूरों के विश्व-स्वातंत्र्य और संगठन, तथा उनके राज्य का स्वप्न देख रहा था। भारत एक अतिविशाल देश है। गणना के अनुसार विन्व का हर पँचवा व्यक्ति भारतीय है। इतने बड़े राष्ट्र और उसकी इतनी बड़ी जनसंख्या को उसके जन्म सिद्ध अधिकारों से दीर्घकाल तक वंचित रख उनके रोष और घृणा का पात्र बनना, इंगलैण्ड और अमेरिका आदि पूँजीवादी राष्ट्रों के स्वार्थतापूर्ण अस्तित्व के लिए हानिकर हो सकता था। अंग्रेजों के वर्चस्वपूर्ण व्यवहार तथा घोषण से त्रस्त भारतीय जनता तथा नेताओं का ध्यान पहले ही उन्नतिशील रूस की ओर जा चुका था और वे उससे प्रभावित भी हो चुके थे। इस बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, भविष्य की आशंकाओं से त्रस्त पूँजीवादी राष्ट्रों, विशेषतः अमेरिका के दबाव तथा अपने भावी स्वायत्तों की रक्षा के निमित्त, पहले ही से भीषण काग्रेसी आन्दोलन से त्रस्त, विवग इङ्गलैण्ड को मित्रता का दोग कर भारत के क्षत-विक्षत घावों पर मलहम लगाने का उपक्रम करते हुए उसे वेमन से स्वतंत्रता देने का निश्चय करना पड़ा। लेकिन फिर भी

भारत की असीम और अजेय आन्तरिक शक्ति को ग्रियिल और नष्ट कर देने के उद्देश्य से, जिससे वह आने वाले युग में अपने प्रभाव से विश्व की स्वार्थपूर्ण गलित तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों का नियंत्रण न कर सके, उन्होंने भारत को दो ऐसे भागों में विभाजित करने का कुचक्र किया जो हमेशा आपसी वैमनस्य में उलझे रहकर एक दूसरे की ही शक्ति क्षीण करते रहने का प्रयत्न करें। इंग्लैण्ड का यह अमानवीय प्रयत्न बहुत अंशों तक सफल भी हुआ। इतिहास और राजनीति के विद्यार्थी जिन्होंने विशेषतः इंग्लैण्ड के शक्ति-संतुलन (Balance of power) के लिए विश्व की राजनीति में किये गये घृणित कार्यों का अध्ययन किया होगा, वे उसके भारत के साथ किये गये इस अन्तिम कार्य तथा उसमें छिपे कूटनीतिक तात्पर्य के स्वार्थमय अंग को अवश्य ही अवलोकित कर लेंगे।

लार्ड वेवेल के शासन-काल में सन् १९४५ से ही भारत को थोड़ी-थोड़ी करके सच्चा हस्तांतरित करने का निश्चय कर लिया गया था। इसी उद्देश्य से जून में लार्ड वेवेल ने गिमला में 'सर्वदल-सम्मेलन' बुलाने का निश्चय किया, जिसका उद्देश्य केन्द्र में सर्वदली सरकार की स्थापना करना था। इस योजना के कारण भारत का निस्तब्ध वातावरण फिर से स्फूर्तिमय हो गया। यद्यपि प्रारम्भ में तो वह कान्फ्रेंस सफल होती माखूम पड़ी, किन्तु अंत में मुस्लिम लीग के नेता मि० जिन्ना की जिद और साम्प्रदायिक भावना ने उसे सफल नहीं होने दिया। उन्होंने कांग्रेस और गोंधी जी के प्रति क्रमशः, 'सजातीय हिन्दू सस्था' और 'सजातीय हिन्दू' कह कर असंतोष तथा अविश्वास प्रकट किया था। उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता था कि कांग्रेस मुसलमानों के स्वार्थों का भी ध्यान रख कर कार्य करेगी।

२३ मार्च १९४६ को ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्री-मंडल के तीन सदस्यों का एक कमीशन भारत को इस उद्देश्य से भेजा कि वह वायसराय की सहायता से वहाँ के प्रमुख दलों के नेताओं से मिल कर समझौते

की बातचीत करे तथा भारतीय संविधान के निर्माण के विषय में विचार-विनिमय करे। कमीशन ने भारत पहुँच कर सरकारी पदाधिकारियों से तथा विभिन्न दलों के नेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उनका मनोभाव ज्ञात किया। कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय नेताओं का मतभेद अत्यन्त दृढ़ है तथा उसे आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। लीगी नेता स्पष्ट तथा खुले शब्दों में पाकिस्तान की माग कर रहे थे। फिर भी कतिपय प्रदेशों को समूहबद्ध करने की जो योजना कमीशन ने प्रस्तुत की थी उससे भारत के उत्तर-पश्चिमी, और उसी प्रकार उत्तरपूर्वीय क्षेत्रों पर मुसलमानों के नियंत्रण होने की माग की पूर्ति होती थी। दोनों दलों—कांग्रेस तथा लीग ने—इस योजना को मान लिया था। मि० जिन्ना ने तो प्रान्तों के समूहबद्ध किये जाने की योजना यह कह कर लीग वालों को मान लेने के लिए सलाह दी थी कि इससे पाकिस्तान की नींव पड़ जाती है, और दो वर्ष के भीतर ही पूर्ण पाकिस्तान प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। परन्तु नेहरू तथा अन्य नेताओं ने इस योजना के कार्यान्वित किये जाने में किसी प्रान्त या उसके किसी भाग को, उसके निवासियों की इच्छा के विरुद्ध जबर्दस्ती किसी समूह में न रखने, यानी स्वभाग्य निर्णय के सिद्धान्त पर जोर दिया था। केन्द्र में संयुक्त दली सरकार बनने में इसलिए रुकावट खड़ी हुई कि मि० जिन्ना ने, राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य मुसलमानों पर अविश्वास प्रकट करते हुए माँग की थी कि, लीग के लिए निर्धारित सीट के अतिरिक्त भी जो सीटें साम्प्रदायिक आधार पर मुसलमानों को दी जायें उनपर मुस्लिम लीग के ही सदस्यों को निर्वाचित होने का अधिकार हो, न कि राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम सदस्यों को; क्योंकि वे मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करते। तत्कालीन स्थिति तथा मि० जिन्ना के हठ से ऐसा लग रहा था कि भारत में कोई भी ऐसी सरकार स्थापित नहीं हो सकती जिसको सम्पूर्ण जनता का सहयोग और विश्वास प्राप्त हो, तथा जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो; क्योंकि

कांग्रेसी नेताओं ने मि० जिन्ना को समझाने का अथक प्रयत्न किया पर वे किसी भी प्रकार राजी होने के लिए तैयार न थे। मि० जिन्ना के शब्दों में, “यदि वायसराय ने पं० जवाहरलाल नेहरू को गवर्नर जनरल की इक्वेक्यूटिव कौंसिल के निर्माण का अधिकार, तथा उनके परामर्श को कार्यान्वित करने का वचन दिया है तो मेरे लिए इस आधारजनित स्थिति का मानना असम्भव है।”

फलस्वरूप लीग के सहयोग के बिना ही अन्तःकालीन सरकार बनी। नयी सरकार ने २ सितम्बर से अपना कार्य आरम्भ कर दिया। वह मुस्लिम लीग के सक्रिय आन्दोलन का सामना करने के लिए तैयार थी। मुस्लिम लीग ने भी अपने निर्धारित कार्यक्रम—सीधी चोट (Direct Action)—को घणित ढंग से आरम्भ कर दिया। पंजाब में लीग-आन्दोलन के फलस्वरूप भारी अशान्ति पैदा हो गई, और जब उसे संयुक्त दली मंत्री मण्डल का अन्त करने में सफलता न मिली, तब सीमाप्रान्त की कांग्रेसी मिनिस्ट्री को गिराने का हिंसात्मक आन्दोलन आरम्भ किया गया। कलकत्ते में १६ अगस्त से ही भीषण हत्याएँ और अग्निकांड हो रहे थे, तत्पश्चात् नोआखाली की बारी आयी। ऐसा लगता था कि मजहब के नशे से प्रमत्त मनुष्य ने मनुष्यता खो दी है। लगी बहुमत प्रान्तों में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अमानुषिक अत्याचार होते रहे, जिन्हें रोकने में उनकी सरकारें असमर्थ थीं, और जिनके सम्बन्ध में प्रान्तीय स्वराज्य के कारण न तो केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी और न गवर्नर जनरल अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग ही कर सकते थे। ऐसी भीषण परिस्थिति के बीच नेहरू-सरकार का २ सितम्बर १९४६ को जन्म हुआ था। महामना मालवीय जी के शब्दों में इस पुण्य तिथि को “अपने देश में अपना राज्य स्थापित हुआ।”

अन्तःकालीन सरकार बन तो गई, किन्तु उससे लीग के अलग होने के कारण न तो कांग्रेस को सन्तोष था न तो वायसराय को ही। अतः सितम्बर के अन्त में भूपाल के नवाब ने मध्यस्थ का कार्य किया। मि०

जिन्ना, पं० नेहरू तथा लार्ड वेवेल में डेढ़ महीने तक इसी आशय का पत्र व्यवहार होता रहा। अन्त में अपने साम्प्रदायिक स्वार्थों की रक्षा के लिए मि० जिन्ना ने अन्तःकालीन सरकार में शामिल हो जाना ही उचित समझा। मुस्लिम लीग ने अपने ५ मनोनीत नेताओं के नाम भी भेज दिये।

अन्तःकालीन सरकार में आते ही लीगी नेताओं ने अड़झा की नीति अख्तियार की। वे पं० जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता मानने के लिए तैयार न थे। फलस्वरूप संयुक्त उत्तरदायित्व की सब आशाएँ विफल होने लगीं। एक ही देश के नेताओं द्वारा बने हुए मंत्री मंडल के सदस्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक दूसरे के प्रतिकूल अपने विचार प्रकट करने लगे। अब लीगी नेताओं को निकालने से देश की अशान्तिपूर्ण परिस्थिति और भी अधिक विगड़ जाती, अतः भीतर ही भीतर कांग्रेस और लीग में समझौता कराने का प्रयत्न जारी रहा। किन्तु मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में सम्मिलित न होने की घोषणा कर दी तथा पाकिस्तान की माँग करती रही।

१९४७ के मार्च में लार्ड वेवेल चले गये तथा लार्ड माउन्टबेटन गवर्नर जनरल होकर भारत आये। इसके पूर्व फरवरी में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि “सम्राट की सरकार स्पष्ट रूप से अपने इस निश्चय की घोषणा करती है कि वह जून १९४८ तक, उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में अधिकार सौंपने के कार्य को सम्पन्न कर देगी।” देश की साम्प्रदायिक स्थिति, तथा अमानुषिक रक्तपात होते हुए देखकर अन्त में कांग्रेस को देश-विभाजन के प्रस्ताव को मानना पड़ा; और १५ अगस्त १९४७ को भारत और पाकिस्तान नाम के दो उपनिवेश बनाकर हमेशा के लिए भारत की अविभाज्य आत्मा को खण्डित कर दिया गया। इसके पूर्व नेहरू जी को ब्रिटिश मंत्रीमण्डल के निर्मंत्रण पर इंग्लैण्ड जाना पड़ा था, परन्तु वहाँ भी लीगी नेताओं से समझौता करने में वे असमर्थ रहे। अतः ९ दिसम्बर से आरम्भ होने वाली विधान-परिषद् के लिये उन्हें लौट आना पड़ा था। ३ जून १९४७ को पं० नेहरू

ने एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें अपने और कांग्रेस के द्वारा भारत के विभाजन की स्वीकृति की असहायतापूर्ण अवस्था पर शोक प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था, “जिस संयुक्त भारत के लिए हम लड़ते और काम करते आये हैं उसका आधार जबरदस्ती नहीं, जनता की स्वेच्छा होना चाहिए। हो सकता है कि इस प्रकार हम संयुक्त भारत के ध्येय को जल्दी प्राप्त कर सकें।” ४ जून को गांधी जी ने विभाजन के प्रति अपने विचार प्रकट किये थे, “जनता को यह विस्मरण न कर देना चाहिए कि कांग्रेस को इस स्थिति को मानने के लिए बाध्य किया गया है।”

४ जुलाई सन्, १९४७ को ही, जबकि भारतीय स्वतन्त्रता ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था तभी से मोटे तौर पर देश का विभाजन हो गया था। १९ जुलाई को मुस्लिम लीग और उसके नेताओं द्वारा पाकिस्तान की निरन्तर माँग, ब्रिटिश सरकार की भेद और शासन की नीति के फलस्वरूप भारत दो स्वतन्त्र डोमीनियनों में विभक्त हो गया। भारत अखण्ड न रह कर खण्डित हो गया, और उसकी उस मौलिक एकता की इतिश्री हो गयी जो वैदिक काल से उस समय तक अकाट्य तथा सर्वमान्य थी, और जो देश की भौगोलिक रचना के अतिरिक्त उसके सांस्कृतिक जीवन तथा उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं का मूर्तिमान स्वरूप थी। ब्रिटिश सरकार ने देश को छोड़ते-छोड़ते परिस्थिति को जटिलतर बनाने वाली एक और बात कर डाली थी। भारतीय रियासते, जो समस्त ब्रिटिश शासनकाल में व्यवहारिक दृष्टि से भारत-सरकार के आधीन थीं, उन सब वन्धनों से मुक्त कर दी गईं जो संधियों, सनदों, सम्झौतों तथा चलनों पर निर्भर थे। प्रभुसत्ता हटा ली गयी। इस प्रकार भारतीय नवाबों तथा नरेशों को यह समझने का अवसर मिला कि वह नवनिर्मित भारत-सरकार से सर्वथा स्वतन्त्र हैं और स्वतन्त्र शासकों की भाँति उनसे व्यवहार कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त भारत की आन्तरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी बहुत भयानक एवं निराशाजनक थी। यूरोपीय महासमर के प्रभाव

के कारण भारत में अन्न-वस्त्र का अत्यन्त अभाव था। मुद्रा-बाहुल्य के कारण वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक बढ़ गया था। चोर बाजार गर्म था और मुनाफाखोरी की बन आयी थी। श्रमजीवियों की कमी थी और जो थे वे ऐसे लोगों के प्रभाव में थे, जो उत्पादन वृद्धि द्वारा देश का हित-साधन न करके, उन्हें वर्ग-संघर्ष की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। साम्प्रदायिक वैमनस्य के कारण हिन्दू और मुसलमानों में फूट का अस्तित्व था तथा उनके कुत्सित कार्यों पर मानवता धिक्कार रही थी। दो सौ वर्ष के विदेशी शासन के कारण, भारतीयों का नैतिक अधःपतन इतना अधिक हो गया था कि बहुत से मनुष्य, मानव जीवन के उच्च आदर्शों को भूल कर, अपने सब कार्यों को स्वार्थपरायणता दश करते थे। सरकारी नौकर तक इस प्रकार के अधःपतन से मुक्त न थे। उनमें से कुछ साम्प्रदायिक पक्षपात की ओर झुके थे और कुछ आर्थिक लोभ की ओर। मानसिक दासत्व, राजनीतिक दासत्व की अपेक्षा कई गुना अधिक था, और उसका अस्तित्व उस शिक्षित समुदाय पर भी था जिसके अधिकांश व्यक्ति राजनीतिक स्वतन्त्रता का राग अलापते तथा अन्य सब बातों में राष्ट्रीय उन्नति के लिए प्रयत्नशील थे। यह थी देश की आन्तरिक स्थिति, जब कुटिल ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन भारतीयों के हाथ में देने का निश्चय किया।

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इससे भी अधिक चिन्ताजनक थी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् विजयी राष्ट्र अपनी शक्ति-वृद्धि करने तथा स्वार्थ-साधन में लिस थे। वे दो प्रधान गुटों में विभक्त थे, जिनमें से एक लाल रूस को अपना नेता मानता था, और दूसरा 'सफेद पोश' इंग्लैंड और अमेरिका को अपना नायक। ससार के विभिन्न देशों में भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहे थे, और किसी देश में भारत का कोई ऐसा राजदूत अथवा प्रतिनिधि नहीं था जो प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करते हुए वहाँ अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को समझाता तथा उसके अनुकूल कार्य करता। पाकिस्तान की नव-निर्मित डोमोनियन के कारण अंतर्राष्ट्रीय

परिस्थिति और भी जटिल हो गयी थी। इधर विभाजित भारत में भी धर्म के नाम पर पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में अनेक हिन्दू और मुसलमान हताहत हो रहे थे। इसके कारण शरणार्थियों की एक नयी विकट समस्या नवजात दुधमुँहे भारतीय राष्ट्र के समक्ष उपस्थित थी।

ऐसे सकट-काल में देश के शासन-भार को सम्हाल कर उसे उन्नति के पथ की ओर ले जाना सरल कार्य न था। सम्पूर्ण देश अत्राध रूप से ऐसे व्यक्ति को ढूँढ़ रहा था जो भगवान शिव की भाँति इन विषम परिस्थितियों का कालकूट विष धारण कर, नीलकंठ की तरह उन्हें भावी की चिन्ता और भय से मुक्त करता। ३५ कोटि व्यक्तियों की दृष्टि सहसा नेहरू पर केन्द्रित हो गयी और अचानक उनके हृदय गाँधीजी के पूर्व-कथित शब्दों से झंकृत हो उठे, “राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है।” अतः १५ अगस्त १९४७ को पं० जवाहरलाल नेहरू एक स्वर से स्वतंत्र भारतीय गणतन्त्र के प्रथम प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुए और उन्होंने अपना मन्त्रिमण्डल बनाया। इसके पूर्व २२ जुलाई को अशोक-चक्र के साथ, कांग्रेस के तिरगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने भारत का राष्ट्रीय झंडा स्वीकार कर लिया था। १५ अगस्त को आधी रात में २०० वर्ष का हमारा दासत्व धुल गया और स्वतन्त्र भारत में नया प्रभात हुआ।

ब्रिटिश शासकों द्वारा सत्ता हस्तान्तरित होते समय नेहरू जी ने स्वतन्त्र भारत की भावी शासन-नीति तथा कार्यक्रम पर कुछ प्रकाश डाला था। गृह-शासन में अल्पसंख्यकों को धर्म, संस्कृति और भाषा की स्वतन्त्रता का आश्वासन देने के पश्चात् उन्होंने कहा था, “हमारा ध्येय है भारत के जनसाधारण, किसान और मजदूर को स्वाधीनता और सुयोग देना; अज्ञान, बीमारी और गरीबी के विरुद्ध लड़ना और उनको मिटाना; समृद्ध, प्रगतिशील और सम्पन्न जनतन्त्र का निर्माण करना, ऐसी राज-नीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाना जिससे देश के प्रत्येक नर-नारी को समुचित अधिकार और जीवन के पूर्ण विकास का अवसर मिल सके।”

विधान-परिषद् और नेहरू

६ दिसम्बर १९४६ को वयोवृद्ध डा० सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में विधानसभा का अधिवेशन बड़े समारोह के साथ आरम्भ हुआ। ११ दिसम्बर को डा० राजेन्द्र प्रसाद उसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डा० राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार विधानसभा के अधिवेशन के आरम्भ में २९६ सदस्यों में से २१० उपस्थित थे। उनमें से १५५ हिन्दू, ३० परिगणित जातियों, ५ सिक्खों, ६ भारतीय ईसाइयों, ५ पिछड़ी हुई जातियों, ३ अंग्रेज भारतीयों, ३ पारसीयों और ४ मुसलमानों के प्रतिनिधि थे। सम्प्रदाय की दृष्टि से मुसलमानों के अतिरिक्त भारतीय संविधानसभा सब दलों की प्रतिनिधि स्वरूप थी। भारतीय विधानसभा में मुसलमानों की संख्या की यह अल्प स्थिति मुस्लिम लीग के उस साम्प्रदायिक निर्णय (पाकिस्तान) के कारण थी। अन्यथा पहले मुसलमानों के प्रतिनिधियों की संख्या ८० निर्धारित हुई थी।

१३ दिसम्बर को पं० जवाहरलाल नेहरू ने परिषद् के उद्देश्य और लक्ष्य (objectives) के सम्बंध में प्रस्ताव उपस्थित किया; जिसमें भारत का लक्ष्य “सम्पूर्ण सत्ताधिकारी प्रजातन्त्रात्मक गणराज्य” बतलाया गया था। उसे उपस्थित करते हुए नेहरू जी ने इस आशय का वक्तव्य दिया; “हम जो शासनविधान बनाने जा रहे हैं, यह प्रस्ताव उसका भाग नहीं है, इसलिए इसे उसका भाग समझ कर विचार करना ठीक न होगा। इस परिषद् को चाहे जैसा विधान बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है, और जो लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं उन्हें भी, जब वे परिषद् में

शामिल होंगे, पूरा हक होगा कि वे विधान को चाहे जैसा रूप दे। यह प्रस्ताव महत्व पूर्ण मौलिक अधिकार को उपस्थित करता है, जिसके विषय में किसी दल या व्यक्ति को शायद कोई आपत्ति न होगी। यह परिषद् के आगे के कार्यों में किसी प्रकार का दखल नहीं देता, और न यह दो दलों के किसी वार्तालाप में ही वाधा उपस्थित करता है। एक तरह से यह हमारा काम सीमित करता है यदि आप इसे सीमित करना कह सकें।.....जो नई दिक्कतें सामने आ गयी हैं, वे इसलिए उठ खड़ी हुई हैं कि ब्रिटिश मंत्री-मंडल तथा अन्य व्यक्तियों ने हाल में ही कुछ खास तरह के वक्तव्य दिये हैं: लेकिन मैं आशा करता हूँ कि ये दिक्कतें हमारा रास्ता बंद न कर सकेंगी।.....हम में से अधिकांश पिछले वर्षों में एक पीढ़ी से अधिक समय तक मृत्युछाया की दुर्गम घाटी से गुजर चुके हैं और जल्द ही तो फिर उसी रास्ते से गुजरने के लिए तैयार हैं।”

“उस विकट समय में भी हम यह सोचते थे कि युद्ध करने और विध्वंस होने के पश्चात् रचना और विकास का भी अवसर आयेगा। अब ऐसा लगता है कि स्वतन्त्र भारत के निर्माण-कार्य का शुभ अवसर आ उपस्थित हुआ है। हम इस शुभ नुहूर्त का उत्साह से स्वागत करते हैं। हमारे सामने पिछले महीनों में जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुई, उनके होते हुए भी हमने परस्पर सहयोग का वातावरण उत्पन्न करने की ईमानदारी से कार्पाचेष्टा की।.....हम एक महान कार्य की सिद्धि के लिए सकल-बद्ध हैं। अतः अपना प्रयत्न जारी रखेंगे और नुझे आशा है कि ब्रानर प्रयत्नशील रहने से अन्त में सफल भी रहेंगे।.....हमारे कुछ भाइयों ने गलत रास्ता पकड़ा है।.....हमें इस देश में एक साथ रहना है और एक साथ ही काम करना है, आज नहीं तो कल या परसों सही। इसलिए उन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, जो उस मविष्य के निर्माण में कठिनाइयाँ उत्पन्न करें, जिसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। हमें अपने देगभाइयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए पूरी-पूरी कोशिश

करना चाहिए, परन्तु सहयोग के माने यह नहीं हैं और न होंगे कि हम जिन आधारभूत सिद्धान्तों पर खड़े हैं, जिन पर राष्ट्र को खड़ा रहना चाहिए, हम उन्हीं को त्याग दे ।.....”

“गत महायुद्ध से छुट्टी पाने के पश्चात् हम एक ऐसे युग में खड़े हैं, जिसमें लोग भावी युद्ध के विषय में अस्पष्ट पर जोरदार चर्चा कर रहे हैं । ऐसे ही समय में नव भारत का जन्म हो रहा है । विश्व की अशान्ति के बीच में ही शायद नव भारत का अभ्युदय श्रेयस्कर हो, लेकिन इस अवसर पर हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिए । हमारे समक्ष आज विधान बनाने का महान कार्य है । हमें वर्तमान के महान दायित्व को भी सम्हालना है और भविष्य के कठिन दायित्व को भी निभाना है । ऐसे अवसर पर हमें इस या उस दल के छोटे-मोटे लाभ में अपने आप को नहीं भुल बैठना चाहिए ।”

“कुछ लोगो ने मेरा ध्यान इस बात की ओर खींचा कि प्रस्ताव में ‘रिपब्लिक’ शब्द का होना भारत की देशी रियासतों के शासकों को शायद कुछ नाराज न कर दे । हो सकता है कि इस शब्द से वे नाराज हो, लेकिन मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर से कहीं भी राजतन्त्र पसन्द नहीं करता और आज के संसार में राजतन्त्र तेजी से मिटता जा रहा है, किन्तु इस विषय में व्यक्तिगत विचार का प्रश्न नहीं उठता । रियासतों के विषय में वर्षों से हमारी सर्वोपरि राय यह रही है कि आनेवाली स्वतंत्रता में रियासतों की जनता को पूर्ण अधिकार होना चाहिए । यह कैसे हो सकता है कि विभिन्न रियासतों की प्रजाओं में स्वाधीनता की मात्रा और रूप भारत की जनता से भिन्न हो ? रियासते भी हमारे सघ का अङ्ग होंगी । हम चाहे विधान में लिख दे या आपस में सहमत हो जायें कि स्वाधीनता का रूप देशी रियासतों और भारत में समान होना चाहिए । व्यक्तिगत रूप से मैं यह पसन्द करता हूँ कि भावी रियासती सरकारों की रचना और रूप भी एक समान हो । यह ऐसा प्रश्न है कि जिसपर देशी रियासतों से बात की जायगी और उनके सह-

योग से यह प्रश्न हल किया जायेगा ।.....अगर किसी खास रियासत की प्रजा किसी खास तरह का शासन चाहती है, तो फिर वह शासन चाहे राजतन्त्र ही क्यों न हो, वहाँ की प्रजा अपनी मर्जी के अनुसार उसे अपना सकती है ।”

“परिपद जानती है कि बहुत से सदस्य अनुपस्थित हैं । हमें इसका दुःख है, क्योंकि हम भारत के अधिक से अधिक भागों और अधिक से अधिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलना चाहते हैं । हमने एक महान कार्य का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है जिसमें हम सब का सहयोग चाहते हैं, क्योंकि भारत के जिस भविष्य की कल्पना हमने की है वह किसी धार्मिक, प्रान्तीय या अन्य प्रकार के दल विशेष की नहीं है ।..... हमें हर काम भारत के ४० करोड़ निवासियों को दृष्टि में रखकर करना है ।.....ताकि दुनिया यह मान ले कि इस महान अवसर पर हमने वैसा ही कार्य किया है जैसा हमें करना चाहिए था ।”

महात्मा गांधी की अनुपस्थिति की चर्चा करते हुए पं० नेहरू ने कहा, “एक और महापुरुष अनुपस्थित है ।.....वह पुरुष हमारी जनता और हमारा महान नेता, हमारे राष्ट्र का पिता, इस परिषद् का जनक, और जो वीर चुका तथा जो आने वाला है उसका निर्माता है । वह आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि अपने आदर्श की प्राप्ति में वह भारत के एक सुदूर कोने में कार्यरत है । लेकिन मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि उसकी महान आत्मा हमारे साथ है और हमारे कार्य को आशीर्वाद दे रही है ।”

“हम भारत के लिए एक नवीन शासन-विधान बनाने जा रहे हैं । यह प्रत्यक्ष है कि हम भारत में जो कुछ करने जा रहे हैं, शेष संसार पर उसका काफी असर पड़ेगा । आज भी जब की हम स्वतंत्रता के सिंहद्वार पर खड़े हैं, भारत संसार की समस्याओं में महत्वपूर्ण भाग लेने लगा गया है । निरंतर उसमें वृद्धि होगी; अतः भारत के विधान-विधायक विस्तृत दृष्टिकोण रखें, यह आवश्यक है । हमारा समस्त संसार से विश्व-बंधुत्व

का नाता है। हम सब देशों के साथ मित्रता चाहते हैं, अतीत में संघर्ष का लम्बा इतिहास रहते हुए भी हम इंग्लैण्ड के साथ भी मित्रता चाहते हैं।”

२० जनवरी के द्वितीय अधिवेशन में नेहरू जी का यह प्रस्ताव विधान परिषद द्वारा स्वीकार कर लिया गया। नेहरू जी अपने बहुमूल्य सलाह से विधान निर्मात्री समिति को पूर्ण सहयोग देते रहे। भारतीय विधान की पाण्डुलिपि तैयार हो जाने के पश्चात् विधान-परिषद ने मई १९४८ में उसे मान्यता प्रदान कर दी।



एशियाई सम्मेलन और नेहरू

“एशिया में एक नया जीवन लहरे मार रहा है और एक पुराना युग समाप्त हो चुका है। अब सदियों बाद फिर भारत अपने पड़ोसी देशों और मित्रों के लिए अपने द्वार खोल रहा है, जिससे वह अपनी इस प्राचीन भूमि पर उन सब देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनके साथ फिर से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर सके। शान्ति, स्वतन्त्रता और प्रगति के हेतु को सामने रखकर इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए भारत-वर्ष अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है। इस सामान्य हेतु से प्रेरित होकर एशिया के विविध भागों से बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे देश में आ रहे हैं। पिछले कटु अनुभव ने उन्हें सिखला दिया है कि कोई भी एक देश अन्य देशों से सहयोग किये बिना न तो अपनी रक्षा ही कर सकता है, और न अपनी स्वतन्त्रता को ही कायम रख सकता है।”

भारतीय स्वतन्त्रता के अभ्युदय के पश्चात् किये गये अपने प्रथम महान् कार्य एशियाई-सम्मेलन के अवसर पर पं० जवाहरलाल नेहरू का उपर्युक्त संदेश भारत की राजधानी दिल्ली के प्राचीन किले से—दिल्ली, जहाँ भारतीय इतिहास की रूप-रेखा निर्मित हुई थी और जो अपने गर्भ में ७ साम्राज्यों के न जाने कितने मीठे और कड़वे तथ्यों को छिपाये हुए है—प्रसारित हुआ। सम्मेलन २३ मार्च १९४७ को आरम्भ हुआ। यह सम्मेलन भारत तो क्या समस्त एशिया में अपने दंग का अकेला था। दिल्ली अपने सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। सम्मेलन जिस वातावरण में हुआ वह अत्यन्त प्रभावोत्पादक था। सम्मेलन के प्राण पं० जवाहरलाल नेहरू के निर्मंत्रण का एशियाई देशों से आशातीत

उत्तर मिला । सम्मेलन की अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मर्मस्पर्शी शब्दों में अपने हृदय के भाव व्यक्त किये थे, “एशियाई देशों को एक दूसरे के निकट लाने की कल्पना कई वर्षों से विचार-जगत में भ्रमण कर रही थी, किन्तु उसके व्यावहारिक रूप धारण करने के लिए अनुकूल समय और परिस्थिति की आवश्यकता थी । वह अनुकूल समय भी आया और इस दिशा में पहला कदम उठाने का सौभाग्य भारत को ही प्राप्त हुआ । देशभक्त स्व० श्री चित्तरंजन दास की यह प्रथम प्रिय कल्पना थी । इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए काश वे जीवित रहते । एशिया का भूतकाल महान था; किन्तु पिछली कुछ शताब्दियों से वह पश्चिम के लोलुप राष्ट्रों की अर्थलिसा का शिकार हुआ और राजनीतिक बन्धनों में जकड़ा जाकर शोषण का क्रियास्थल बन गया ।”

“अब एशिया की काल-रात्रि का अन्त हो गया है । उसके राजनीतिक बन्धन या तो टूट चुके हैं या टूट रहे हैं । वह अपनी जड़ता और स्थिरता को छोड़ कर आगे कूँच करने के लिए कटिबद्ध हो रहा है ।” नेहरू जी के शब्दों में, “अब वह जमाना गुजर गया है जब एशियाई देश पश्चिमी राष्ट्रों की चासलरी में आवेदनकर्ता के रूप में हाथ बाँधे खड़े नजर आते थे । अब उन्हें शतरंज के मुहरे नहीं बनाया जा सकता । उनका अपना अस्तित्व और व्यक्तित्व होगा और वे नये विश्व की रचना और निर्माण में, अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसार भाग लेंगे ।”

वह कौन सा आदर्श है जो नव-जाएत एशिया को उस समय भी प्रेरित और अनुप्राणित कर रहा था; और जिसकी अमिव्यक्ति नेहरू और श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा अन्य एशियाई प्रतिनिधियों ने अपने वक्तव्य में की थी ? वह है एक मात्र एशिया के भ्रातृ-प्रेम द्वारा विश्व-ऐक्य की स्थापना । साम्राज्यवाद के कष्टों से अवगत एशिया ने संकुचित राष्ट्रवाद को तज कर, संयुक्त एशिया, विश्व-एकता और विश्व-सहयोग के लिए पहला प्रयत्न किया था ।

एशियाई सम्मेलन के सम्बन्ध में नेहरू जी ने कहा था, “इस सम्मेलन में न तो कोई नेता है और न कोई अनुयायी। समस्त एशियाई देशों को समान रूप से, समान कार्य के लिए एक साथ कार्य करना है। भारत भी एशिया के विकास में महत्वपूर्ण भाग लेना चाहता है।” उनका यह पूर्ण विश्वास था कि “संसार में स्थाई शान्ति तभी हो सकती है, जब संसार के समस्त राष्ट्र स्वतंत्र हो जायें और सभी प्राणियों को स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत सुरक्षा प्राप्त हो।”

करवट बटल कर जागते एशिया की ओर इंगित करते हुए नेहरू जी ने सभी एशियाई राष्ट्रों को सदेश दिया था कि पुनर्निर्माण के लिए हमें “जनसाधारण की ओर ध्यान देना होगा, और उनके चतुर्मुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करना होगा, जिनकी अब तक बहुत ही उपेक्षा की गई है।” उन्होंने एक स्थान पर कहा था, “एशिया के देश बहुत पिछड़े हुए हैं और उनके जीवन का मान अन्य देशों की तरह नहीं है। इस असमानता के प्रश्न को हमें तत्काल हल करना होगा। हमें सभी मनुष्यों के लिए समान आदर्श रख कर अपने राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक ढाँचे को खड़ा करना होगा, ताकि वे उन समस्त भागों से मुक्त हो जायें, जिनसे उनका व्यक्तित्व दबा हुआ है।”

श्रीमती सरोजिनी नायडू के शब्दों में, एशिया के स्वर्णयुग की कल्पना को पूर्ण करने के पहले हमें “जनसाधारण को शोक, दुःख, शोषण, कष्ट, दरिद्रता, अज्ञान, विनाश और मृत्यु के मुख से बचाना होगा तभी वे नये विश्व की रचना करने में अपना योग दे सकेंगे।” ‘जनसाधारण का उत्थान ही प्रगति की कसौटी होगी’ का महत्वपूर्ण लक्ष्य इस सम्मेलन में निश्चित हुआ।

२३ मार्च १९४७ को श्री जवाहरलाल नेहरू के कर-क्रमलो द्वारा, नये उत्साह और नई आशा से इस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक सम्मेलन में एशिया के प्रायः समस्त राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था। यह पहला अवसर था जब कि संसार की

आधी से अधिक जनता के लगभग २५० प्रतिनिधि अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के साधनों पर विचार करने के लिए भारत की पवित्र भूमि पर एकत्रित हुए थे। एक विशाल रंग-मंच पर एशिया के विराट मानचित्र के दोनों पक्षों में एशिया के विभिन्न राष्ट्रों की पताकायें एक पास लगी अपनी मित्रता की सूचना दे रही थीं। सम्मेलन २३ मार्च की शाम को आरम्भ हुआ। ज्योंही विशाल तोरण के नीचे से विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने पंढाल में प्रवेश किया कि सारा मंडप गगनभेदी करतल ध्वनि से गूँज उठा।

सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष ने एक छोटे वक्तव्य में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए बतलाया कि “यह सम्मेलन एक महान भावी कल्याण का सूचक है और ऐसे ही अनेक भावी सम्मेलनों का अग्रदूत है। सम्मेलन किसी राष्ट्र के तत्वावधान में नहीं हो रहा है, बल्कि सभी देशों ने अपनी-अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए स्वेच्छा से अपने प्रतिनिधि भेजे हैं।”

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हमारे राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना वक्तव्य दिया, “किसकी पुकार सुनकर आप लोग यहाँ दूर-दूर से आये हैं ?.....यह वस्तु का तकाजा था।.....एक जमाना खत्म हो रहा है और दूसरा आरम्भ हो रहा है। बीच में हम खड़े हैं और यह कान्फ्रेंस उस नये जमाने की ओर अगला कदम है। एशिया आज पहली बार अपने कदम पर खड़ा हो रहा है, लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी पुरानी शान से दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए.....बड़े-बड़े इन्कलाब हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है, एशिया बदल रहा है, सैकड़ों वर्षों से यह पड़ा रहा, इसके हाथ पैर अब धीरे-धीरे खुल रहे हैं।”

“आज हम अपने अतीत की ओर दृष्टिपात करते हैं और फिर उस भविष्य की ओर देखते हैं जिसका हमारी आँखों के सामने नवनिर्माण हो रहा है। बहुत दिनों तक अंधकार में रहने के पश्चात् एशिया ने फिर

विश्व की आँखों में अपना सम्मानपूर्ण स्थान बना लिया है। इतिहास पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि एशिया के इस महाद्वीप ने, जिसमें मिश्र का सांस्कृतिक सम्बन्ध भी शामिल है, मानव-जाति के विकास में अपना प्रमुख योग दिया है। वह एशिया ही है जहाँ मानव-संस्कृति का जन्म हुआ और जहाँ के निवासियों ने मानव-जीवन के अत्यन्त साहस पूर्ण कार्य किये। यही मनुष्य ने सर्वप्रथम सत्य का पूर्ण रूप से अनुसन्धान किया, और मानवता की आत्मा प्रकाश-दीप बनकर इतने वेग से प्रज्वलित हुई कि उसने सम्पूर्ण संसार को प्रकाशमय बना दिया। परन्तु कालान्तर पश्चात् वही एशिया, जहाँ से सभ्यता और संस्कृति की प्रचंड धाराये समस्त दिशाओं में प्रवाहित हुई थी, क्रमशः इकलान्न से हट गया और उसका विकास रुक गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य महादेशों, और विशेषतः योरोप के लोग शक्ति-सम्पन्न हो क्रमशः रंगमंच पर आ धमके और उन्होंने विश्व के समस्त देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यही नहीं धीरे-धीरे योरोपीय देशों ने एशियाई देशों का मनमाना शोषण किया और एशिया योरोप का क्रीडा-स्थल बन गया। परन्तु समय ने पलटा खाया है, अब एशिया एकवार फिर अपने गौरव को प्राप्त कर रहा है। आज हम फिर इस महान अवसर पर एक साथ मिल रहे हैं, और निसन्देह यह भारतवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि उन्हें अपने दूर देश से आये सहयोगी एशियावासियों का स्वागत करने और उनसे वर्तमान एवं भविष्य के सम्बन्ध में परामर्श करने का अवसर मिला।” इसके पश्चात् नेहरू जी ने भारत और उसके समवर्ती अन्य एशियाई राष्ट्रों की नष्ट प्राय प्राचीन संस्कृति तथा उससे भारत के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला।

नेहरू जी ने भावी एशिया के रचनात्मक कार्यक्रम तथा उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा, “हमारा ध्येय आक्रमणकारी नहीं है। हमारी एक मात्र महान योजना सारे संसार में शान्ति-स्थापना करना और उसे समृद्धिशाली बना देना है। हम विदेशों का काफी मुख देख चुके हैं !

अब हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, और उन लोगों के साथ सहयोग करना चाहते हैं जो हम से सहयोग करने को तैयार हैं' प्राचीन काल की भाँति आज भी त्रिना एशिया के सहयोग और मत्प्रयत्नों के शान्ति असम्भव है।”

“एशिया के महान निर्माताओं—श्री सनयात सेन, जगतुल पाशा और कमाल पाशा—के परिश्रम और सद्प्रयासों का ही लाभ आज एशिया उठा रहा है। एक महान आत्मा की प्रेरणा और प्रयत्न से भारत भी आज स्वतंत्रता के द्वार पर पहुँच चुका है। यह महामानव—महात्मा गांधी—आज जनता की सेवा में लीन हैं।”

श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए कहा, “मैं अपने देश में आपके आगमन का स्वागत करती हूँ” हम एशियावासी विरोधों तथा कठिनाइयों से न घबड़ाकर अपने सम्मुख उपस्थित होने वाली समस्त आपत्तियों का सामना करते हुए साथ-साथ आगे बढ़ेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए जब तक हमें अनंत लक्ष्य तक पहुँचने का पथ न मिल जाये। हमें नक्षत्रों की ओर उठना चाहिए, हम आकाश-स्थित चन्द्र का स्वप्न ही नहीं देखते बल्कि उसे आकाश से तोड़कर एशियाई स्वातंत्र्य के मंगलसूत्र में पिरो कर पहनने की सामर्थ्य भी रखते हैं। . . . महात्मा गाँधी ने हमें सिखलाया है कि विश्व को मुक्ति, युद्ध, घृणा या क्रोध से नहीं, बल्कि शान्ति से होगी; क्षमा से होगी, दया और अहिंसा से होगी। यह हमारे महादेश एशिया का प्राचीनतम सन्देश है। आज भारत ने एशिया के अन्य देशों को विश्व के लिए आशा के नये संदेश पर विचार करने के लिए याद किया है।”

इसके पश्चात् आगत सभी राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन के प्रति आस्था तथा शुभकामनायें प्रकट कीं, सभी ने एक स्वर से इसके इस निर्णय को माना कि आज एशिया की मुक्ति एवं विश्व-शान्ति हमारी एकता पर ही निहित है।

एशियाई सम्मेलन के अधिवेशन का दूसरा दिन चीन के एक सन्देश से आरम्भ हुआ, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि संसार की मुक्ति एवं शान्ति का एक मात्र मार्ग महात्मा गान्धी की अहिंसा ही है। इसके पश्चात् विभिन्न प्रतिनिधियों ने भारत की मित्रता के सूत्र में बँधे रहने का आश्वासन दिया; तथा एक स्वर से कहा कि महान भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह एशियाई संगठन के कार्य का नेतृत्व करे।



भारतीय स्वतंत्रता-दिवस

१९४७ के अगस्त की समाप्ति के साथ भारत से अंग्रेजी प्रभुसत्ता का हमेशा के लिए अन्त हो गया। १५ अगस्त को सारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपलक्ष्य में आनन्दोत्सव मनाया गया। खंडित देश की स्वतंत्रता का आनन्द हमने उसी प्रकार मनाया जिस प्रकार एक घायल सिपाही युद्ध की विजय का आनन्द मनाता है। उसी दिन पं० नेहरू के प्रधान मंत्रित्व में स्वतंत्र-भारत का प्रथम मंत्री-मण्डल बना, जिसमें पं० जवाहर लाल सहित चौदह मंत्री थे। भारत की विधान परिषद की बैठक १५ अगस्त को सवा घण्टे तक होती रही जिसमें सभी सदस्यों ने निम्न-लिखित शपथ ली, “इस गम्भीर अवसर पर जब की भारत की जनता ने कष्ट सहन और बलिदान द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की है, मैं.....भारत की विधान परिषद का एक सदस्य होने के नाते, विनम्र भाव से भारत और उसकी जनता की सेवा में अपने को इस उद्देश्य से अर्पित करता हूँ कि यह प्राचीन देश विश्व में अपने यथोचित स्थान को प्राप्त करे, और विश्व-शान्ति तथा मानव जाति के कल्याण की वृद्धि में पूर्ण रूप से और स्वेच्छापूर्वक योगदान करे।”

स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर भारत के प्रधान मंत्री नेहरू ने राष्ट्र को संदेश दिया, “निर्धारित दिवस आ गया है—वह दिवस जो नियति द्वारा निर्धारित हुआ था। लम्बी निद्रा एवं संघर्ष के पश्चात् भारत आज जागृत, जीवित, स्वतंत्र एवं स्वाधीन होकर फिर खड़ा हुआ है। भूतकाल की कुछ बातें अब तक हम से चिपकी हुई हैं और हम जो प्रतिज्ञायें कर चुके

हैं उनको पूरा करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है, तथापि अवस्था बदल चुकी है। हमारे लिए इतिहास फिर नये सिरे से शुरू हो रहा है—वह इतिहास जिसमें हम रहेगे और कार्य करेंगे और जिसके लिप्य में भावी इतिहासकार लिखेंगे।”

“यह अवसर भारत में हम लोगों के लिए, समस्त एशिया के लिए और विश्व के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक नये नक्षत्र का उदय हो रहा है। यह पूर्व में स्वतंत्रता का नक्षत्र है। एक नई आशा साकार हो रही है और बहुत दिनों का स्वप्न चरितार्थ हो रहा है। आज हमारी यही कामना है कि यह नक्षत्र कभी अस्त न हो और हमारी आशा कभी मंग न हो।”

“हम इस स्वतंत्रता में आनन्द अनुभव कर रहे हैं, यद्यपि हमारे सभी ओर वादल घिरे हुए हैं और हमारे बहुत से देशमाई गोकाकुल हैं, तथा कठिन समस्याएँ हमें सभी ओर से घेरे हुए हैं। किन्तु स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं और हमें स्वतंत्र अनुशासनशील राष्ट्र की भाँति उन्हें वहन करना है।”

“आज के दिन हमारा ध्यान सर्वप्रथम इस स्वतन्त्रता के निर्माता की ओर जाता है, जो हमारे राष्ट्र-पिता हैं, जिन्होंने भारत को प्राचीन आत्मा की साकार प्रतिमा के रूप में स्वतन्त्रता की मशाल सदा ऊँची रखी, और हम जिस अन्धकार से घिरे हुए थे, उसके बीच प्रकाश फैलाया। हम बहुधा उनके अयोग्य अनुयायी रहे हैं और उनके सन्देश से भटक जाते रहे हैं, किन्तु केवल हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ियाँ भी इस सन्देश को स्मरण रखेंगी और उनके हृदयों पर भारत के इस महान् पुत्र के सन्देश की सदा छाप रहेगी, जो अपने विश्वास, शक्ति, साहस और नम्रता में इतना विभूतिमान है। हवा चाहे कितने ही वेग से क्यों न चले या ओधी चाहे जितनी ही प्रचण्ड क्यों न हो, हम स्वतन्त्रता की मशाल को कभी बुझने न देंगे।”

“हमारा ध्यान स्वतन्त्रता के उन अज्ञात सैनिकों एवं स्वयंसेवकों की

भी ओर जाता है, जिन्होंने बिना किसी प्रशंसा या पुरस्कार की आशा के भारत की सेवा की और अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दिये। हमें उन भाइयों और बहनों का भी ध्यान आता है जो राजनीतिक सीमाओं द्वारा हमसे अलग हो गये हैं और जो दुर्भाग्य से इस समय आयी हुई स्वतन्त्रता में भाग नहीं ले सकते। चाहे जो हो वे हमारे हैं और हमारे बने रहेंगे, तथा हम उनके सौभाग्य और दुर्भाग्य के एक समान भागी होंगे।”

“भविष्य हमारी ओर देख रहा है। हम किस ओर जायेंगे और हमारा प्रयत्न क्या होगा ? हमें सर्वसाधारण के लिए तथा भारत के किसानों और श्रमजीवियों के लिए सुराज एवं सुखवसर लाना है। गरीबी, अज्ञान और रोगों से लड़ना और इनका अन्त करना है। एक समृद्धिशाली प्रजातन्त्र और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना है, और ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक संस्था बनाना है जो प्रत्येक नर-नारी के लिए न्याय और जीवन की पूर्णता को निश्चित बनायेगी।”

“हमारे आगे कठिन कार्य करने को है। जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा पूर्णरूप से पूरी न कर ले, और जब तक भारत के सभी निवासियों को वैसा ही न बना ले जैसा नियति उसे बनाना चाहती है, तब तक हममें से किसी को विश्राम नहीं करना है। हम एक महान देश के नागरिक हैं, जिसे साहस के साथ आगे बढ़ना है। हमें उस उच्च आदर्श के अनुसार ही जीवन-यापन करना है। हम चाहे जिस धर्म के अनुयायी हो, हम सभी भारत की सन्तान हैं और हम सभी के समान अधिकार तथा उत्तरदायित्व हैं। हम साम्प्रदायिकता या संकीर्णता को प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि जिस राष्ट्र के लोग विचार या कार्य में संकीर्ण हों, वह कदापि महान् नहीं हो सकता।”

“हम ससार के सभी राष्ट्रों और उनके निवासियों का अभिवादन करते और शान्ति, स्वतन्त्रता एवं प्रजातन्त्रवाद को आगे बढ़ाने में उनसे सहयोग की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को, अपनी प्यारी मातृ-

भूमि को, जो प्राचीन, अनन्त एवं चिर नवीन है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ओर उसकी सेवा में अपने जीवन को लगा देने की फिर से प्रतिज्ञा करते हैं। जय हिन्द ।”

भारत की स्वतन्त्रता के अवसर पर नेहरू जी के पास अनेक राष्ट्रों के प्रधान मन्त्रियों के अभिनन्दन एवं शुभकामना के पत्र आये थे। नेहरू जी ने उन्हें उनका उत्तर देते हुए लिखा था, “भारत-सरकार के अपने सहयोगियों तथा अपनी ओर से मैं आपके अभिनन्दन तथा शुभकामनाओं के उन संदेशों के लिए आपको कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ, जो आपने इस ऐतिहासिक दिवस पर भेजा है जब भारत स्वतंत्र हो रहा है। इस स्वतंत्रता का अर्थ हमारे लिए बहुत है, किन्तु यह एशिया और विश्व के लिए भी महान अर्थ रखती है। हम इस स्वतंत्रता का उपयोग जैसे अपने देशवासियों की उन्नति के लिए, उसी प्रकार विश्व की शान्ति एवं समृद्धि को उन्नत बनाने के लिए करने की आशा करते हैं। इस कठिन कार्य में हम आपकी गवर्नमेन्ट से धनित सहयोग की आशा करते हैं।”

स्वतंत्रता के द्वितीय जन्मोत्सव, १५ अगस्त १९४८ को पं० नेहरू—भारत के प्रधान मंत्री—ने राष्ट्र को यह संदेश सुनाया था, “१५ अगस्त की तारीख आयी और देश के विभाजन की पीड़ा होने पर भी अपनी नवजात स्वतंत्रता की प्राप्ति पर हमने आनंद मनाया। हम स्वतंत्रता के सूर्योदय और स्वतंत्रता द्वारा लाये जाने वाले अवसर की ओर दृष्टि लगाये हुए हैं। यद्यपि सूर्य का उदय हुआ किन्तु वह काले बादलों से आच्छादित होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं हुआ और हमारे लिए ऊषाकाल ही बना रहा। इस ऊषाकाल को काफी समय बीत चुका है और अब दिवस का प्रकाश छाने वाला ही है। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक निर्णय या नये शासन विधान का ही विषय नहीं है और न वह और भी अधिक महत्व वाली आर्थिक नीति का ही विषय है, वह तो मस्तिष्क और हृदय का विषय है। और यदि मस्तिष्क अपने को सकीर्ण और धुंधला बना लेता है और हृदय कटुता एवं घृणा से पूर्ण है तो स्वतंत्रता कहाँ ?”

“आज एकबार फिर १५ अगस्त की तारीख आयी है। अतीत की सारी घटनाओं के होते हुए भी हमारे लिए यह दिवस गम्भीर और पवित्र है। इस वर्ष के भीतर बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई है और हमें जो लम्बा मार्ग पूरा करना है उस पर बहुत दूर तक हम आगे बढ़े हैं। किन्तु यह वर्ष दुःख और अमर्यादा; एवं उस भावना के परित्याग से भी परिपूर्ण है जो भारत के लिए मुक्तिदायक विशेषता रही है। इस वर्ष ने राष्ट्रपिता की हत्या में पाप की विजय देखी है, और इससे अधिक लज्जा और दुःख हममें से किसी के लिए और क्या हो सकता था।”

“हम यह पवित्र दिवस उसी प्रकार मना रहे हैं, जैसे हमें मनाना चाहिए। किन्तु इस अवसर पर हमें न तो व्यर्थ की डींग होंकनी चाहिए और न कोरी निरर्थक बकवाद ही करनी चाहिए। आज हमें अपने दिल को टटोलना चाहिए, और फिर से अपने महान् कार्य के लिए अपने को अर्पित करना चाहिए। हमें उसका इतना विचार नहीं होना चाहिए, जो हम कर चुके हैं। विचार तो होना चाहिए उसका जो हम नहीं कर पाये हैं; और उसका, जिसे हमने ठीक से नहीं किया है। हमें उन लक्ष-लक्ष शरणार्थियों के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए जो अपने सर्वस्व से वंचित हो जाने से बेघर-द्वार के होकर अभी तक भटक रहे हैं। हमें भारत के जनसाधारण के सम्बन्ध में सोचना चाहिए जो आज भी कष्ट झेल रहे हैं। जिन्होंने हमारी आर आशा भरी दृष्टि से देखा है और अपने असुखी भाग्य के सुधरने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें भारत के उन साधनों का भी ध्यान करना चाहिए जिन्हें ठीक से तैयार कर यदि जन-कल्याण के लिए उनका उपयोग किया जाये तो वे भारत को कुछ का कुछ बना दे सकते हैं। उसे महान तथा समृद्धि-शाली बना दे सकते हैं। आइये, हम सब अपनी सारी शक्ति के साथ इस महान् कार्य में जुट जायें, लेकिन सबसे अधिक हमें महात्मा गाँधी के सिखाये हुए पाठों का ध्यान होना चाहिए और उन आदर्शों का स्मरण होना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए उन्नत किया था। यदि हम उन

पाठो और आदर्शों को भुला देंगे, तो अपने महान कार्य और देश के प्रति विश्वासघात करेंगे ।”

“अतः अपनी स्वतंत्रता के इस द्वितीय वर्ष के अवसर पर हम स्वतंत्र भारत और उसकी जनता के महान कार्य के लिए फिर से अपने को अर्पित करते हैं। हमारी कामना है कि हम योग्य सिद्ध हों। जय-हिन्द ।”

इसी प्रकार प्रति वर्ष स्वतंत्रता-दिवस आता है और अतीत के संघर्षों और हमारे उद्देश्यों की ओर इंगित कर चुपचाप समय की गिला पर एक अंक खींच जाता है। उससे हम अपने आदर्शों को पूर्ण करने के लिए साहस मिलता है, धैर्य मिलता, और मिलती है असीम आत्मबुद्धि और शान्ति की चिर संचित निधि।



साम्प्रदायिक दंगे

यह भारत का दुर्भाग्य है कि भारतीय राजनीति में हम राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता की भावनाओं को एक साथ बढ़ते तथा पल्लवित होते देखते हैं। एक दूसरे के समक्ष बहने वाली इन धाराओं में हम कभी एक को अधिक वेगवान पाते हैं तथा कभी दूसरी को अधिक द्रुतगामी। कायदे आजम जिन्ना और लीग के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग एक राजनीतिक सौदे के आधार से कहीं अधिक व्यापक रूप ले चुकी थी। हिन्दुस्तान की जमीन में मुस्लिम साम्प्रदायिक भावना कितनी गहरी चली गई थी, इसका ठीक अदाज और उसके भयंकर दुष्परिणाम का पता शायद साम्प्रदायिक अग्नि सुलाने वाले लीगी नेताओं को भी ठीक से नहीं था। पाकिस्तान की बुलंद माँग ने दानव का रूप धारण कर लिया था। लीग के जिम्मेवार समझे जाने वाले नेताओं ने अपने जलसे में जिस मजहबी पागलपन से भरे भाव व्यक्त किये थे उसे सुनकर आश्चर्य होता है। कहा गया कि मुसलमान एक बार फिर चंगेज खाँ और हलाकू खाँ के समान हिन्दुस्तान की जमीन खून से रंग देंगे। हिन्दुओं की हस्ती को बिल्कुल मिटा देंगे और देश भर में तलवार के जोर से अपना शासन स्थापित कर लेंगे। आगे आने वाली घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया कि यह कोरी धमकी ही नहीं थी। यद्यपि पं० नेहरू ने आने वाले दुर्दिन का कुछ अनुमान बहुत पहले ही कर लिया था, किन्तु फिर भी उन्होंने देश की हिन्दू और मुसमान जनता के प्रति अहमदनगर के किले से, १९४४ में, विश्वास प्रकट करते हुए कहा था, “मजहब के

आधार पर हिन्दू और मुसलमानों के बीच हिन्दुस्तान का बंटवारा, जैसा कि मुसलिम लीग सोचती है, इन खास दो घमों को मानने वालों को अलगा-अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वह सारे देश में फैले हुए हैं ।”

इसके अतिरिक्त उन्होंने विभाजन के दुष्परिणामों की ओर इंगित करते हुए चेतावनी भी दी थी, “यदि भारत को दो या इससे अधिक भागों में तोड़ दिया जायेगा, और यदि वह एक आर्थिक और राजनीतिक एकाई की तरह काम न करेगा, तो उसकी उन्नति पर भारी प्रभाव पड़ेगा । एक तो स्वयं निर्वलता आयेगी, लेकिन इससे भी बुरी चीज वह मनो-वैज्ञानिक लड़ाई होगी, जो भारत को अखंड बनाये रखने के पक्षपातियों और उसके विरोधियों में होगी ।” कालान्तर पश्चात् हम जानते हैं कि नेहरूजी की यह आशंका सच हुई ।

धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता के इस जिहाद का आरम्भ १६ अगस्त १९४६ की उस ‘सीधी कार्यवाही’ (*Direct action*) से हुआ जिसने कलकत्ते की सड़कों की खुली छाती को खून से रंग दिया । रक्तपात और वर्चस्व का नग्न ताण्डव आरम्भ हुआ जिसने देश भर में साम्प्रदायिक विद्वेष की एक ऐसी ज्वाला को, और हिंसा-प्रतिहिंसा की एक ऐसी विषैली धूमशिखा को जन्म दिया, जिसने अपने खूनी दामन में मानवता का गला घोट दिया । कलकत्ते के बाद नोआखाली और पूर्वी बंगाल; पूर्वी बंगाल के बाद बिहार, गढ़मुक्तेश्वर और पंजाब के पश्चिमी जिले, एक के बाद एक इस आग की लपट में जलने लगे, जिसे १५ अगस्त की महान सच्चा परिवर्तन की घड़ी भी, जिसने हमें २०० वर्षों की अंग्रेजी गुलामी से मुक्त किया था और जो हमारे इतिहास की एक स्वर्णिम घड़ी थी, अपने समस्त महत्त्व के साथ भी बुझा नहीं सकी ।

नोआखाली और बंगाल का हत्याकांड देख कर गैतान की भी रूढ़ काप उठी होगी, सारे देश का हृदय क्षुब्ध था, पीड़ित मानवता रोती थी, और उसकी हँसी उड़ाते ये अट्टहास करते हुए शृगाल और स्वान ।

गाँव-गाँव में कत्ले आम मचा था तथा अनन्त धन-राशि स्वाहा हो रही थी। नगर और गाँव उजड़ गये थे। डगर-डगर पर मनुष्य को सस्ती काया बिक्री हुई थी, हिंसा के प्रचंड ताण्डव के आगे खूखार पशु भी पराजित था। हिन्दुस्तान की कुलदेवी अपनी छाती पर हो रही उस अमानुषिकता को देख कर फूट-फूट कर रो रही थी।

नोआखाली के अवर्णनीय अत्याचारों को सुनकर बिहार के हिन्दू भी क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने वहाँ के उन दृष्यों की पुनरावृत्ति अपने यहाँ करनी आरम्भ की। बिहार के भयंकर उपद्रव का ज्ञान होते ही नेहरू जी तत्काल वहाँ पहुँचे और उपद्रवियों को करारी फटकार सुनायी। बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने से रोकते हुए उन्होंने कहा कलकत्ता या नोआखाली में किये गये हिन्दुओं पर अत्याचार का बदला यहाँ बिहार के निरपराध मुसलमानों से लेना अनुचित है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उपद्रवकारी अपनी प्रतिहिंसा की इस भावना को नहीं छोड़ेंगे तो वे राष्ट्र की सम्पूर्ण शक्ति से उसे कुचल डालने तथा उसमें लगे साम्प्रदायिक व्यक्तियों को कठोर से कठोर दंड देने की व्यवस्था करेंगे। नेहरू जी के प्रयत्न से कुछ दिनों के अन्दर ही बिहार का साम्प्रदायिक हिंसात्मक आन्दोलन रुक गया, इसके विपरीत मुसलिम क्षेत्रों में यह घृणित और दुर्दमनीय कार्य उसी वेग से जारी रहा, तथा उसे बंद करने का किसी भी नेता ने विशेष प्रयत्न नहीं किया।

१५ अगस्त के विभाजन के पश्चात् पंजाब में साम्प्रदायिक दंगों ने तीव्र अग्नि का रूप धारण कर लिया। देश के बँटवारे तथा साम्प्रदायिक उत्पात के कारण सीमाप्रान्त, पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब, सिन्ध आदि प्रांतों में रक्तपात, नरसंहार, लूट-मार और आगजनी के जो भयंकर काण्ड हुए उनका स्मरण कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पैशाचिकता का नम्र ताण्डव हुआ। गाँव के गाँव जला दिये गये। हजारों वेवस नर-नारी और मासूम बच्चों की निर्मम हत्याएँ हुईं। निस्सहाय स्त्रियों के साथ, जिनके पति, भाई और पुत्र कत्ल कर दिये गये थे, खुलेआम बलात्कार किया गया। हजारों

व्यक्ति जिन्दा जला दिये गये । इन्हे देख और सुनकर चङ्गेज खों और हलाकू खों की नृशंसताओं की स्मृति सजीव होने लगी थी । इस साम्प्रदायिक भावना का भारत में बढ़ने का दो विशेष कारण था । एक तो जगह-जगह पर उन असह्य अत्याचारों से पीड़ित शरणार्थियों का फैल जाना, जो अपने साथ पाकिस्तान में आपत्ती लोमहर्षक घटनाओं की तीखी स्मृति लाये थे और सजल नेत्रों से उन्हें सुनाते फिरते थे, जिससे लोगों के हृदय में बदला लेने की भावना का उदय होता था । दूसरे हिन्दुओं में पाकिस्तान के बन जाने पर मुसलमानों के प्रति पहले से ही अस्वभाविक घृणा और कटुता बढ़ गयी थी । शरणार्थियों की सुनाई हुई कथाओं ने उसे और भी प्रज्वलित कर दिया । उनका रक्त उबल पड़ा और उन्होंने आपे से बाहर होकर प्रतिशोध लेना आरम्भ कर दिया । फलस्वरूप भारत की राजधानी दिल्ली और सारा पंजाब जल उठा, लाहौर और अमृतसर की सौंदर्य श्री जलकर राख हो गयी; और लोग ऐसे-ऐसे अमानुषिक अत्याचारों के शिकार बनाये गये कि पं० नेहरू का सगत्त हृदय भी कांप उठा । उन्हें ऐसा लगने लगा कि यदि ये लोमहर्षक कांड समाप्त नहीं किये जा सकते तो हम लोगों का अपने पद पर बने रहने का कोई अर्थ नहीं है । इसमें शक नहीं कि पंजाब और दिल्ली के उस महाभयंकर नर-संहार और विध्वंस के बीच नेहरू और महात्मा गांधी आदि नेताओं ने साम्प्रदायिक भावना से अपने को पूर्ण अलग रखकर अपनी सारी शक्ति लगी हुई आग बुझाने और शान्ति की स्थापना के उद्योग में लगा दी ।

नेहरूजी ने साम्प्रदायिक उपद्रव तथा पागलपन को बराबर निंदा की । कई बार तो वे आक्रमणकारियों के बीच निहत्थे ही मोटर से कूट पड़े तथा अपने थप्पड़ों से गल्ल-सज्जित साम्प्रदायिक गुंडों की पूजा की । वे विपत्तिग्रस्त शरणार्थियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे ।

इन्हीं दिनों कुछ ऐसे पडयन्त्रकारियों का भी पता चला जो इस नवजात स्वतन्त्र राष्ट्र की सत्ता को उलटने तथा नष्ट करने का जी-जान

से प्रयत्न कर रहे थे । मुस्लिम-एंग्लोइंडियन पडयन्त्र उसमें प्रधान था । नेहरू-सरकार ने अपूर्व दृढ़ता तथा शान्तिपूर्वक इन परिस्थितियों का सामना किया तथा स्वतन्त्रता-पथ के रोड़ों को चुन-चुन कर दूर करनी रही ।

इस अमानुषिकता को बन्द करने के लिए तथा शान्ति-स्थापना के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकार ने मिल कर कई अपीलें निकालीं । भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की तत्संबन्धी एक काफ़ेस भी अम्बाला में हुई । १९ अगस्त को दिल्ली-रेडियो से ब्राडकास्ट करते हुए नेहरूजी ने इस रक्तपात को बंद करने की देश की जनता से अविलम्ब मांग की, तथा दोनों सरकारों से इसके लिए कठोर दमनात्मक कदम उठाने की अपील की । २८ अगस्त को प्रेस-कान्फ़ेंस में नेहरूजी ने कहा, “प्रतिहिंसा और प्रतिद्वन्दिता अवाञ्छनीय है । इस तरह की प्रतिहिंसा की भावना से ऐसे आदमियों की रक्षा नहीं की जा सकती जिनकी हम वास्तव में रक्षा करना चाहते हैं ।” “.....व्यक्तिगत हिंसा और प्रतिशोध का अर्थ स्वयं अपनी सरकार को उचित कार्यवाही कर सकने के अयोग्य प्रमाणित करना है । यदि समस्याओं का उचित रूप में समाधान करना मुख्य लक्ष्य है तो दोनों सरकार के बीच पूर्ण सहयोग आवश्यक है ।”

भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों ने अल्पसंख्यक पीड़ितों के आवागमन के लिए सुविधाजनक तथा शान्तिमय व्यवस्थाएँ की । करीब ५० लाख हिन्दू सिक्ख पाकिस्तान से भारत लाये गये तथा भारत से सुरक्षा-पूर्वक उन मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा गया जो वहाँ जाना चाहते थे ।

नोआखाली तथा कलकत्ते की दानवीय लीला से व्यथित महामानव गांधी ने तो अनशन ही आरम्भ कर दिया था । नेहरूजी भी स्वयं दौड़-दौड़ कर घटनास्थलों का निरीक्षण कर रहे थे तथा पीड़ितों को सान्त्वना दे रहे थे । पंजाब में एक दर्जन हिन्दू महिलाओं ने उन्हें राखी बाँध कर

अपनी रक्षा की कृष्ण प्रार्थना की थी। नेहरू ने प्राणपण से उनकी रक्षा का आग्रह किया था। स्वयं गाँधीजी ने इस भीषण स्थिति से खिन्न होकर शान्ति अथवा उसकी प्राप्ति में आत्मोत्सर्ग का संकल्प किया था।

९ सितम्बर को पं० नेहरू तथा लियाकत अली ने फिर से मिलकर एक संयुक्त वक्तव्य निकाला जिसमें शान्ति की अपील करते हुए उन्होंने पंजाब के उपद्रवों को निर्दयतापूर्वक कुचल देने की घोषणा तथा निश्चय प्रकट किया था। नेहरू जी ने दंगे को दबाने के लिए उपद्रवी क्षेत्रों के लिए अनेक कानून पास कराये और हत्या के साथ ही कई अन्य निर्मम अपराधों के लिए प्राण-दंड की व्यवस्था की। साम्प्रदायिक अफसरो के ऊपर कड़ी दृष्टि रखी गई तथा उन्हें चेतावनी भी दी गई।

९ सितम्बर को जब महात्मा गाँधी दिल्ली की चिन्ताजनक स्थिति देखकर वहाँ पहुँचे, तब नेहरूजी ने बड़े कृष्ण भरे मार्मिक शब्दों में अपने हृदय की व्यथा प्रकट की थी, “आज हमारे नेता महात्मा जी, कलकत्ते से यहाँ आये हैं। जब मैं उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठा तो आसानी से चार आँखें न हो पायीं। मुझे शर्म मालूम होती थी कि मैं प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं अदा कर पाया। देश में जहाँ भी जो कुछ हो रहा है उसे मैं अपना कसूर मानता हूँ। हिन्दु-स्तान का महान व्यक्ति आज यहाँ क्या देख रहा है? कलकत्ते में तो उनकी आश्चर्यजनक विजय हुई। वे यहाँ आये हैं और हम चाहते हैं कि उनके जादू का प्रभाव यहाँ भी हो।..... हमें देश की उन्नति के लिए सब कुछ सोचना होगा। हमने अपने हाथ यदि जल्द नहीं रोके तो देश तबाह हो जायेगा।.....हम भारत को कदापि लुटेरों का देश नहीं बनने देंगे। यह तमाशा देखने का समय नहीं है।.....हमें यदि स्वतन्त्रता बनाये रखनी है तो शान्ति स्थापित रखना ज़रूरी है।”

नेहरू जी ने अपने देशवासियों के कार्यों पर गोक प्रकट करते हुए कहा, “मेरे देशभाइयों ने जो कुछ किया है, उसके लिए मैं शर्मिन्दा हूँ, और मुझे भय होता है कि इन पाप-कर्मों के परिणाम बहुत

समय तक बने रहेंगे, और वैसे ही उसके लिए हुई बदनामी भी । पाप द्वारा पाप का अन्त नहीं होता और आप हत्या द्वारा हत्या को नहीं रोक सकते ।”

महात्मा गान्धी के प्रयत्न तथा नेहरू जी के आश्वासन का मुसलमानों तथा हिन्दुओं दोनों पर ही काफी प्रभाव पड़ा । मुसलमान नेहरू-शासन के अन्तर्गत रह कर अपने को पूर्ण सुरक्षित समझने लगे । स्वयं भारत-स्थित पाकिस्तान के हाईकमिश्नर ने प्रेस-कान्फ्रेंस में कहा था कि मैं भारत में स्थित जितने मुसलमानों से मिला हूँ वे दिल्ली छोड़ना नहीं पसन्द करते । मुसलमान ऐसा विश्वास करते हैं कि महात्मा गान्धी, पं० नेहरू, श्री वियोगी तथा भारत-सरकार के सभी सदस्य वर्तमान आतङ्क को दूर करने की हार्दिक इच्छा रखते हैं, तथा अल्पसंख्यकों की रक्षा में प्रयत्नशील हैं ।

२९ सितम्बर को दिल्ली में हिन्दुओं और मुसलमानों की विराट सभा में भाषण देते हुए नेहरू जी ने कहा था, “हर आदमी को जो भारत का भक्त है इस देश में रहने का अधिकार है, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान । उसकी और उसके हितों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और वह उसके लिए कोई कसर बाकी न रखेगी । ऐसे मुसलमान भारत में प्रसन्नतापूर्वक रहें जो इसे सन्तुष्ट अपना देश समझते हैं । हों, जो आदमी देश के प्रति वफादार नहीं है उनके लिए भारत में कोई स्थान नहीं है, और उन्हें उनकी पसन्द के देश तक पहुँचाने के लिए सरकार पूरी सुविधा प्रदान करेगी ।.....भारत को हिन्दू-राज्य बनाने का मतलब है, मुस्लिम लीग थी वास्तविक विजय—ऐसी विजय जिसकी तुलना में पाकिस्तान की स्थापना भी कम महत्वपूर्ण है ।”

भारत के भाग्याकाश पर जब स्वतंत्रता की प्रथम किरण ही फूटी थी, तभी से नव-विधान का संदेश देने वाली नेहरू-सरकार को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा जिस धैर्य और शान्ति के साथ उसने उन पर विजय प्राप्त की, वह वास्तव में सराहनीय है । नेहरूजी

के ही शब्दों में, “भावी इतिहासकार यह लिखेंगे कि इस विचार और भयंकर समस्या से किसी भी सरकार की नींव हिल जाती और सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाती... किन्तु भारत की जनता ने इन समस्याओं का धीरता से सामना किया, इसे सुलझाने की चेष्टा की और राष्ट्र के कल्याण के लिए अन्ततः इस समस्या को सुलझा भी लिया।” पं० नेहरू के अदम्य उत्साह, योग्यता तथा कार्य-शक्ति को देखकर ही लौह-पुरुष सरदार पटेल ने विश्वास और स्नेह से मिश्रित शब्दों में कहा था, “पं० नेहरू ने संकट काल में देश का उचित नेतृत्व किया और अपने महान नेतृत्व द्वारा भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई।”



महामानव गाँधी का महाप्रयाण

स्वतंत्र भारत के गृह-शासन, विधेयतः साम्प्रदायिकता विरोधी नीति से कुछ भारतीय जनता असंतुष्ट थी। उसका विचार था कि नेहरू-सरकार, कांग्रेस और महात्मा गाँधी की पूर्वकालीन नीति की भाँति मुसलमानों का तोपण और हिन्दू हितों का बलिदान कर रही है। पाकिस्तान की साम्प्रदायिक नीति और वहाँ होने वाले हिन्दुओं पर जत्रन्य अत्याचार उनकी क्रोधाग्नि में घी का कार्य कर उसे उत्तेजित कर रहे थे। पाकिस्तान में एक मुस्लिम राज्य की स्थापना की जा चुकी थी जो 'शरीयत' पर अवलम्बित था तथा जिसमें 'काफ़ीर' हिन्दुओं को कोई स्थान न था। इसके विपरीत भारतीय नेताओं ने एक लौकिक राज्य (Secular State) की स्थापना की थी, जिसमें सभी धर्मावलम्बियों को समान अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त थी। फलस्वरूप, इस व्यवस्था के विरुद्ध उनका रोप साम्प्रदायिक दंगे के रूप में प्रकट हुआ। अपनी नीति के विरुद्ध, घृणा और प्रतिशोध के इस दूषित रूप को नेहरू सरकार कैसे सह सकती थी? अतः उसने इसे पूर्णतः कुचले में कोई कसर न की। परन्तु दंगे और साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को कुचलने का इससे भी महान उद्योग गाँधी जी के त्यागबल का था। कलकत्ते में साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए आमरण उपवास आरम्भ करके उन्होंने वहाँ की परिस्थिति को विद्युत गति से बदल दिया था। दिल्ली में भी उनके उपवास का यही परिणाम हुआ। भारत की पवित्र धरती निर्दोषों के रक्त में रंजित होने में बचा ली गयी और नर-पैशाचिकता का नग्न तांडव

यहो न होने पाया । कौन जानता था कि इस महान आत्मा के तपनक जीवन का यही अन्तिम व्रत होगा ।

मिस्टर जिन्ना जिन्हें 'इसलामी मजहब का सबसे बड़ा दुश्मन' मानते थे, उन्हीं के साथी ब्रुहगवर्दों के मुँह से गांधी जी के कलकत्ते में किये गये कार्यों के फलस्वरूप अचानक निकल पड़ा था, "महात्मा गांधी वास्तव में महात्मा हैं ।" और उन्हीं के कार्यों से आवृत्त मुसलमानों ने एक त्वर से दिल्ली में कहा था, "महात्मा गांधी और नेहरू के हाथ में हम अपने को पूर्ण सुरक्षित समझते हैं ।"

हिन्दू साम्प्रदायवादियों की दृष्टि में महात्मा गांधी द्वारा मुसलमानों के रक्षार्थ किये गये वे कार्य हिन्दू हितों के विरुद्ध थे । ऐसी परिस्थिति में हिन्दू राष्ट्रवादी, नेहरू-सरकार तथा गांधी जी की ओर से खिन्ने लगे । वे वापू की इस नीति से अत्यधिक नाराज थे । उनकी यह क्षुब्धता तथा नाराजगी यदा-कदा प्रकट भी होती रहती थी । उनके पास कोई ऐसी शक्ति तो थी नहीं जिसके आधार पर वे प्रत्यक्ष रूप से उनका विरोध करते, अतः उन्होंने एक निर्मम और अमानुषिक मार्ग अपनाया । उनके द्वारा गाँधी जी की प्रार्थना सभा में बम फेंका गया, परन्तु वार खाली रहा । राष्ट्र के कर्णधारों ने राष्ट्रपिता की रक्षा के लिए पूर्ण व्यवस्था करने का निश्चय किया, किन्तु जनता के नेता वापू ने इसे पसन्द न किया ।

इस घटना के दस दिन पश्चात् नाथूराम विनायक गोडसे नामक एक व्यक्ति ने ३० जनवरी १९४८ को लगभग दो गज के फासले से गाँधी जी पर तीन बार गोली चलायी । उस तपोधन की मुट्ठी भर ठठरियों को छोड़ कर प्राण-पखेरू उड़ गये । भारत का वह जगमगाता नक्षत्र हमेशा के लिए बुझ गया । सत्य और अहिंसा का पुजारी, २० वीं शती का बुद्ध, भारत का ईसा, भारत का पैगम्बर अपने ही धर्मावलम्बियों द्वारा हृदय विदारक हिंसा-पूर्ण ढंग से उठा लिया गया । ईसा पर, देश के विधान के अनुसार एक नये धर्म के प्रचार का दोषारोपण कर उन्हें सूखी का दंड दिया गया था । गाँधी की हत्या भी एक मानवीय विचार के प्रतिपादन तथा प्रतिष्ठा-

पन—हिन्दू मुसलिम एकता तथा साम्प्रदायिकता के विरोध के फल-स्वरूप हुई। उस गाँधी की-बापू की-हत्या, जिसने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर एक शक्तिशाली विदेशी साम्राज्य के साथ जीवन भर संघर्ष कर परतंत्रता की वेडी से गढ़ को मुक्त किया था। जिन्हें देशवासियों ने 'महात्मा और बापू' कह कर अपने हृदय की गहरी श्रद्धा और भक्ति का पुष्प अर्पित किया था। जिन्हें समस्त विश्व ने (लाल रूस को छोड़कर, जो मार्क्स, ऐन्जिल्स, लेनिन तथा स्टालिन के अतिरिक्त सभी देश के सभी महान व्यक्तियों को पाखंडी, नर-पिशाच और पूँजीपतियों का समर्थन करने वाला वृर्द्धा मानता है।) आधुनिक युग का एक महान शिक्षक, मानवता का पुजारी तथा विश्व-बन्धु कह कर पूजित किया था, एक भारतीय, एक हिन्दू—अपने को हिन्दू धर्म और संस्कृति का अभिमानार्थ कहने वाले नवयुवक—से हुई, जब कि वे देश के शोक-ग्रस्त विक्षुब्ध वातावरण में शान्ति और सहिष्णुता की स्थापना के लिए प्राणपण से सल्लग्न थे। आजादी मिली, लेकिन भारत के हिन्दुओं के सिर पर अपने सबसे बड़े उद्धारक की हत्या के कलंक का अमिट टीका उसी प्रकार लगा गया जिस प्रकार ईसा के पवित्र लाल खून के छींटे यहूदियों के नत मस्तक पर स्थित उनका आज भी उपहास कर रहे हैं।

बापू संसार से उठ गये, और चन्द घंटों बाद उनकी नश्वर काया ज्ञातल चंदन की लकड़ियों से जल कर हमेशा के लिए भस्म कर दी जाने वाली थी। अहिंसा का पुजारी हिंसा का शिकार हुआ और समस्त संसार उसके वियोग से शोकाकुल हो, प्रकाश के लिए हतप्रभ हो मटकने लगा। भारत माता का वह लाल उससे छिन गया जिसने अपने को अनेक बार श्रृंखलाबद्ध कर उसे श्रृंखलामुक्त होने का मार्ग दिखलाया था।

इस अप्रत्याशित घटना की सूचना पाते ही नेहरू आदि नेता घटना-स्थल पर तत्काल पहुँचे। उपस्थित शोकाकुल जनसमूह को समझाते समय, अपने को आज अनाथ समझने वाले नेहरू के हृदय का बोध बरसस टूट पड़ा। रँवे गले से समझाते समय उनके आँखों से स्वयं अश्रुधारा प्रवाहित

होने लगी और वे सिसकने लगे । पलमर में, जागते भारत को जागते
 बापू की अनंत निद्रा का आकस्मिक ज्ञान हुआ । सब स्तब्ध रह गये ।
 राष्ट्रपिता के आकस्मिक निधन के कारण भारतवासियों पर हुए वज्रपात के
 उस शोकपूर्ण अवसर पर, भावनाओं की तीव्रता से कोपते हुए पं० नेहरू ने
 रेडियो में चिरस्मरणीय भाषण दिया था, “बंधुआ, हमारे जीवन का आलोक
 बुझ गया है और चारों ओर अंधेरा छा रहा है । मैं यह नहीं जानता कि
 इस समय आप से क्या कहूँ और कैसे कहूँ । हमारे प्रिय नेता, हमारे
 राष्ट्रपिता, हमारे बापू अब नहीं रहे । लेकिन यह कहना कदाचित् अनु-
 चित् है ।... मैंने कहा कि आलोक बुझ गया है; लेकिन यह मेरी
 भूल है । इस देश में जो आलोक दीप्त हुआ था वह कोई साधारण आलोक
 नहीं था । पिछले कई वर्षों से जो आलोक इस देश को आलोकित कर
 रहा था वह अभी बहुत वर्षों तक प्रकाश देता रहेगा । आज से हजारों
 वर्ष बाद भी वह आलोक इस देश में वैसा ही दीखेगा; सारे विश्व में
 दीखेगा और अक्षय्य हृदयों को सान्त्वना देगा । क्योंकि वह आलोक
 केवल वर्तमान का नहीं था, वह चिरन्तन, जीवित शाश्वत सत्य का
 आलोक था, तथा वह आलोक इस प्राचीन देश को स्वतंत्रता के पथ पर
 ले जाते हुए ठीक रास्ता दिखलाता था और पथ-भ्रष्ट होने से हमारी
 रक्षा करता था ।”

“... ऐसे विकट समय में जब कि हमारे समक्ष इतनी कठिन
 समस्याएँ उपस्थित हैं, उनका हमारे बीच में न रहना अत्यधिक असहनीय
 है ।..... हमारे राष्ट्रपिता ने जो आदेश हमें दिया है, उन्हें अमल में
 लाने का हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए । हमें सदा यह स्मरण रखना
 चाहिए कि उनकी आत्मा हमें अब भी देख रही है । अतः हमें कोई ऐसा
 कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उनकी आत्मा को कष्ट हो । यदि हमने
 कोई ओछा व्यवहार किया या साम्प्रदायिक हिंसात्मक कार्य किया, तो
 उनकी आत्मा को उससे अधिक अरुचिकर कोई दूसरी बात न होगी ।”

“..... हमें आपस में एकता रखनी चाहिये, और पूज्य बापू के

इस निधन से जो क्षति हुई है उसका ध्यान रखते हुए अपने सभी छोटे-मोटे झगड़े और बाधाओं तथा कठिनाइयों का अंत कर देना चाहिये।... उन्होंने अपनी मृत्यु से हमें जीवन की बड़ी बातों के लिए, सत्य के लिए, प्रेरणा दी है और यदि हमने उस पर ध्यान दिया तो उससे भास्त का हित होगा।”

पं० नेहरू ने भारतीय संसद में महात्मा गाँधी के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए अत्यन्त मार्मिक शब्दों में कहा था, “एक विमूर्ति हमारे बीच से उठ गयी है। जो सूर्य हमारे देश को आलोक तथा उष्णता प्रदान करता था वह अस्त हो गया है, और हम अन्धकार में ठिठुर रहे हैं। फिर भी हमें अपने हृदय के भीतर यह भाव नहीं लाना चाहिए। जब हम अपने हृदय को देखते हैं, तो अब भी उसमें वह अग्नि प्रज्वलित पाते हैं जिसे वे सुलगा गये थे, और यदि वह अग्नि बनी रही तो हमारे देश में अन्धकार नहीं होगा। उनका स्मरण कर, उनके मार्ग का अनुसरण कर, हम अपने प्रयत्नों से इस देश को पुनः प्रकाश युक्त करेंगे।.....”

“.....इस समा की यह प्रथा रही है कि यहाँ दिवंगत प्रमुख आत्माओं के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता रहा है।.....उन लोगों की प्रशंसा हम कुछ चुने हुए शब्दों में करते हैं, और वही उनकी महत्ता की हमारे पास माप होती है, किन्तु गाँधी जी की प्रशंसा हम कैसे करेंगे? और उनकी महत्ता की माप हम कैसे करेंगे? क्योंकि वे उस साधारण मिट्टी के बने नहीं थे, जिसके हमलोग बने हैं। वे आये और काफी समय तक जीवित रहे तथा चले गये। उनके लिए हमारी किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में ही उससे अधिक प्रशंसा प्राप्त कर ली थी जितनी इतिहास में किसी जीवित मनुष्य को मिली है, या जितनी उसकी मृत्यु के समय से अब तक मिली होगी। समस्त संसार ने उनके प्रति सम्मान प्रकट किया है और अब हम सब उसमें और क्या जोड़ सकते हैं? हम लोग जो उनके वच्चे हैं, और शायद

उनके गरीर से उत्पन्न वज्रो से भी अधिक निकट रहे हैं, उनकी कैसे प्रशंसा कर सकते हैं ?.....”

.....इतने वर्षों तक हमने जिस विभूति को देखा, हमारे बीच जो दिव्य-ज्योति-सम्पन्न व्यक्ति रहा, उसने हमें भी बदल दिया। आज हम जैसे भी हो उन्हीं के वर्षों के परिश्रम से बनाये हुए हैं। उनकी उस दिव्य हुताग्नि में से हममें से कइयों ने एक-एक चिनगारी ग्रहण की, जिसने हमें शक्ति दी और उन्हीं के बनाए हुए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसलिए आज उनकी प्रशंसा में कहे गये शब्द क्षुद्र हो जाते हैं, और हमारी प्रशंसा आत्मप्रशंसा का रूप ले लेती है। महापुरुषों के स्मारक पत्थर और धातु से निर्मित किये जाते हैं, लेकिन इस हुतात्मा ने अपने जीवनकाल में ही कोटि-कोटि हृदयों में अपनी प्रतिमा बना ली है। यहाँ तक कि हममें से प्रत्येक उनका अंश धारण किये हुए है। इस प्रकार वे सारे भारत पर छा गये हैं। केवल प्रासादों में ही नहीं, केवल विशिष्ट स्थानों में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक गाँव और झोपड़े में, और दीनों और दुखियों में उसका रूप विद्यमान है। आज वह कोटि-कोटि जनता के हृदय में जीवित है, और युगों तक जीवित रहेगा।”

“महात्मा गाँधी प्राचीन भारत के, और यदि मैं कहूँ तो भारी भारत के भी सबसे बड़े प्रतीक थे।..... वह इश्वरीय दूत अपने जीवन-काल में जैसा महान रहा है, अपनी मृत्यु के पश्चात् उससे भी अधिक महान हो गया है। हम सदैव उसके लिए शोकाकुल रहेंगे, क्योंकि हम मनुष्य ही हैं और अपने प्रिय स्वामी को भूल नहीं सकते। मैं जानता हूँ कि वे यह नहीं चाहते थे कि हम उनके लिए शोक मनायें। उनके नेत्रों में आँसू कभी उनके अत्यन्त प्रिय और निकटवर्ती के चले जाने पर भी नहीं आया, केवल उसके महान कार्य को पूर्ण करने की दृढ़ता की चमक अवश्य आयी। अतः यदि हम उनके लिए शोक मनायेंगे तो वे अप्रसन्न होंगे। उनके प्रति हमारा ठीक सम्मान यही होगा कि जिस कार्य को इतनी दूर लाकर वे पूरा किये बिना छोड़ गये हैं, उसे पूरा करने की हम

जिजा करें और उसे पूरा करने में हम अपना जीवन समर्पित कर दें ।.....आगामी युगों में इतिहास हमारे युग पर अपना निर्गुण देगा । हमारी सफलता और असफलता का फैसला करेगा ।.....।”

बापू के विद्वान के आग नार का वातावरण पूर्णतया बदल गया । जो जान थे अपने जीवन काल में करना चाहते थे परन्तु पूर्ण करने के गृहे ही जीवन-यात्रा का अन्त कर चुके थे, उनके महाप्रमाण के पश्चात् वे सब लनः उड़ी शक्ति के साथ पूर्ण होते लगे । साम्प्रदायिकता का नाश अंत सा हो गया, जो बापू का हार्दिक इच्छा थी । इसी के लिए वे जीवन व्यस्त भारत माता की सेवा में संलग्न रहे । जब भी हम और हमारा देश कोई गलत कदम उठाने के लिए तत्पर होगा, राष्ट्र की उन्नति तथा मानवता के एक विशेष कार्य की पूर्ति के लिए शहीद हुई बापू की आत्मा, हमें अपने कदम गंकर कर उसे सही करने के लिए मजबूर करेगी । विद्वान और इतिहास का सबक बेकार और झूठा नहीं होता । वह ऐसे ही समय किसी देश को अपनी भूल सुधारने में सहायता देता है । हम भी उन्हें शिक्षा ग्रहण करेंगे ।



देशी रियासतों की समस्या

अंग्रेजी शासनकाल में हिन्दुस्तान दो अप्राकृतिक, पर शासन की दृष्टि से एक दूसरे से सम्बद्ध भागों में बँटा हुआ था। इसमें से एक अंग्रेजी हिन्दुस्तान कहलाता था जो ११ प्रान्तों में बँटा हुआ था। इनमें शासन की समानता एक बड़ी सीमा तक प्राप्त की जा चुकी थी, तथा सभी प्रान्तों में तथाकथित जनतंत्र की भावना एवं जनतंत्रीय शासन प्रणाली का निश्चित रूप से विकास हो रहा था। दूसरा भाग देशी राज्यों के रूप में था, जिसमें से अधिकांश में शासन के कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं थे और सामन्तशाही तथा स्वेच्छाचारी सत्ता दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए थी। ये देशी रियासतें लगभग ६०० छोटे बड़े टुकड़ों में बँटी हुई थीं, जिनमें किसी भी प्रकार का साम्य पाना असम्भव था। इसमें से कुछ तो हैदराबाद, काश्मीर जैसी, क्षेत्रफल और महत्व दोनों की दृष्टि से अंग्रेजी प्रान्तों की समकक्ष थीं और कुछ काटियावाड़ की जागीर के समान इतनी छोटी कि उनका विस्तार कुछ एकड़ तक ही सीमित था।

हिन्दुस्तान के नकशे पर यदि हम दृष्टि डालें तो हमें मालूम होगा कि किसी प्रकार का भौगोलिक अन्तर अंग्रेजी हिन्दुस्तान और इन देशी रियासतों को बँटता हुआ नहीं दिखलाई देता, केवल शासन का भेद उन्हें एक दूसरे से अलग किये हुए था। बाहर के आक्रमण और बाद में अंग्रेजी शासन के स्थापन के पश्चात्, वे उनके आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक आधिपत्य के शिकार भी समान रूप से हुए थे। अंग्रेजी हिन्दुस्तान से देशी रियासतों का काटने वाले तत्व न तो भौगोलिक थे, न

- . आर्थिक और सांस्कृतिक ही; केवल ऐतिहासिक और राजनैतिक शक्तियों ने उन्हें दो भागों में बाँट रखा था ।

इन देशी रियासतों का विकास विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में हुआ था । इनमें से अधिकांश की स्थापना, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् साहसी विद्रोहियों द्वारा की गयी थी, और कुछ राज्य ऐसे भी थे, जिनकी स्थापना अथवा जीर्णोद्धार अंग्रेजों द्वारा अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ-पूर्ति के लिए वाद में हुआ । मि० वार्नर के शब्दों में इन्हें संगठित कर अंग्रेजी शासक “अपने चारों ओर एक फौलादी घेरा बनाकर रहने” की व्यवस्था कर रहे थे । सर जान माल्कन ने बहुत दिन पहले ही अपनी राय जाहिर की थी, “यदि हम कुछ देशी राज्यों को, उनके हाथ से राजनीतिक सत्ता छीनकर, साम्राज्य के औजारों के रूप में बना रहने दें तो हम हिन्दुस्तान में, जब तक हमारी समुद्री-शक्ति बढ़ी-चढ़ी है अपना अस्तित्व बनाये रख सकते हैं ।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस मंतव्य के पीछे ठोस सच्चाई थी और इसको कार्यान्वित करने के पश्चात् सचमुच अंग्रेजी सत्ता अपने पाँव बहुत दिनों तक भारत में जमाये रख सकी । स्वयं रशद्रुक विलियम्स ने भी इसे मानते हुए कहा है, “देशी राज्यों के शासक अंग्रेजी सम्बन्ध के प्रति बहुत अधिक राजभक्त सिद्ध हुए हैं ।” इनमें से बहुतों का अस्तित्व अंग्रेजी न्याय और सेनाओं पर निर्भर था । लार्ड चर्जन के शब्दों में, “हमारी नीति के परिणाम स्वरूप देशी नरेश हिन्दुस्तान के साम्राज्यवादी संगठन के एक आवश्यक अंग बन गये हैं ।”

देशी रियासतों का वर्णन करते हुए पं० जवाहरलाल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, उनकी स्थिति देखकर “दम घुटने लगता है और साँस लेने में कठिनाई प्रतीत होती है । ऊपर से शान्त अथवा बहुत धीमे बहनेवाली धार के नीचे सर्वत्र रुकावट और सड़ास है । हमें चारों ओर से अवरुद्ध, सीमित, मस्तिष्क और शरीर को जकड़े हुए होने की भावना का अनुभव होता है । उसके साथ ही यहाँ एक ओर तो हम जनता ,

को पिछड़ा हुआ और कष्टमय जीवन बिताते हुए पाते हैं और दूसरी ओर राजा के भव्य प्रासाद का चमकीला वैभव देखते हैं ।” भारत के इन देशी राज्यों में वेगार और गुलामी की प्रथाएँ भी जारी थीं । नागरिक अधिकारों का तो प्रश्न ही नहीं उठता था । राजा को बिना जनता के प्रतिनिधियों से पूछे सभी प्रकार के कर लगाने का अधिकार था । इन देशी राज्यों के सब अन्तर्राष्ट्रीय तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य अंग्रेजी सरकार के माध्यम से होते थे । जैसा कि प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विधान वेत्ता प्रो० वेस्टलेक ने लिखा है, देशी राज्यों और भारत सरकार के बीच जितने वैधानिक सम्बन्ध थे उनका आधार अन्तर्राष्ट्रीय तथा सुरक्षा सम्बन्धी न रहते हुए सम्राज्यवादी था ।

भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम, एशिया की नवीन जागृति तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति से बाध्य हो अंग्रेजों ने भारत को स्वराज्य देने का निश्चय किया । ३ जून १९४७ को घोषित की जाने वाली लार्ड माउण्टबेटन की योजना के प्रकाशन, और देश के प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा उसे स्वीकृत कर लिये जाने के पश्चात् बनने वाले ‘भारतीय स्वाधीनता एक्ट’ ने सारी परिस्थिति को एक बार फिर तेजी से बदल दिया । इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने देशी राज्यों पर से अपनी सार्वभौम सत्ता हटा ली थी, तथा स्वतन्त्र कर केन्द्रीय सरकार से उन्हें संयुक्त करने वाली सारी कड़ियों और सम्बन्ध को एक साथ तोड़ डाला था । इस घोषणा का अर्थ विभिन्न रियासतों ने भिन्न-भिन्न लगाया तथा यह त्रिक्कुल सम्भव था कि इसके परिणाम स्वरूप देश में अराजकता फैल जाती । एव लोक-तन्त्रात्मक भावना का उद्देग दूषित हो जाता । फिर तो भारत की दशा योरोप के बलकान प्रदेशों से भी अधिक गड़ गुजरी हो जाती । अतः प्रधानमंत्री नेहरू का यह कथन त्रिक्कुल यथार्थ था कि अगणित खण्डों में विभक्त स्वतन्त्र भारत तो पराधीन भारत से भी बुरी अवस्था को प्राप्त हो जायगा ।

पं० नेहरू ने बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तत्परता से इस विपम स्थिति को

महाला । यहाँ तक कि उनके विपक्षियों को भी उनकी दूरदर्शिता देख कर दोतों तले उँगली दबानी पड़ी । लार्ड माउण्टबेटन ने तो ६ अक्तूबर को रायल एम्पायर सोसायटी के समक्ष यहाँ तक स्वीकार किया कि “पण्डित नेहरू से बड़े किसी राजनीतिज्ञ से मेरी मेंट आज तक नहीं हुई ।”

ब्रिटिश सरकार की देशी रियासत की स्वतंत्रता सम्बन्धी घोषणा के पश्चात्, स्थिति सुधारने के उद्देश्य से सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक देशी रियासती विभाग खोला गया, जिसका उद्देश्य दुर्दिन सी इस नयी घिरती हुई विकट समस्या को हल करना था । ५ जुलाई सन् १९४७ को अध्यक्ष-पद से सरदार पटेल ने एक राजनीतिज्ञता पूर्ण वक्तव्य प्रकाशित कराया, जिसमें उन्होंने देशी राज्यों को नये संघनामन में सम्मिलित हो, उस एकता को बनाये रखने की ओर आकृष्ट किया, जिसके अभाव में देश ने अनेकों कष्ट उठाये थे, और जिसके बिना भविष्य में भी वह किसी महान कार्य की आशा नहीं कर सकता था । २५ जुलाई १९४७ को लार्ड माउण्टबेटन ने भी सरदार पटेल के कथन पर जोर देते हुए नरेगो को सचेत किया और कहा कि “उपनिवेश सरकार से आप उसी प्रकार नाता नहीं तोड़ सकते जिस प्रकार की आप जनता से नाता नहीं तोड़ सकते, जिसके कल्याण के प्रति आप उत्तरदायी हैं ।” फलस्वरूप १५ अगस्त १९४७ को जब कि देश को केवल दो भागों में ही विभाजित करने का सवाल नहीं था, बल्कि उसके शत-शत खंड हो जाने का भय था, नेहरू-सरकार की राजनीतिक दूरदर्शिता के फलस्वरूप, हैदराबाद, जनागढ़ और काश्मीर की रियासतों को छोड़कर जेप सभी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित होने का वचन दे चुकी थी । हिन्द की एकता बनाये रखने की दिशा में यह एक बहुत ही मुद्दह तथा महान पहला कदम था जिसने भारतीय प्रगति, संगठन और जनतंत्रीकरण की दिशा में एक रक्तहीन क्रान्ति का सूत्रपात किया ।

१५ अगस्त की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सभी देशी राज्यों में राज-

नीतिक आन्दोलन तीव्रता के साथ फैलने लगा तथा जनता द्वारा जन-तंत्रीय संस्थाओं की माँग होने लगी। फलस्वरूप सरदार पटेल ने १६ दिसम्बर को अपने एक वक्तव्य में कहा कि जब तक छोटी रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व को मिटा नहीं दिया जाता तब तक उनमें जनतंत्रीय शासन की स्थापना असम्भव होगी। यह एक प्रकार से भारत के गणतंत्रीय शासन का छोटे नरेशों के प्रति आदेश था, जिसके सामने अपने अस्तित्व को विवश हो खो देने और जनतंत्रीय संस्थाओं का निर्माण करने के अलावा उनके समक्ष कोई रास्ता ही न रह गया था। छोटे राज्यों के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति की इतनी स्पष्ट व्याख्या इसके पहले कभी न हुई थी। १९४८ के ग्रीष्मार्द्ध तक देश की लगभग सभी छोटी रियासतें या तो अपने समीपवर्ती प्रान्तों में विलय हो चुकी थी या उनका शासन केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आ गया था, और एक ऐसी समस्या जो पिछले कई वर्षों से समस्त प्रयत्नों को उपहासास्पद बना रही थी चुटकियों में सुलझ गई।

ऊपर ही कहा जा चुका है कि इन रियासतों के अतिरिक्त तीन अन्य बड़ी देशी रियासतें—जूनागढ़, हैदराबाद और काश्मीर—ऐसी भी थी जो भारतीय संघ में सम्मिलित न होना चाहती थी तथा अपना स्वतंत्र अस्तित्व एवं शासन बनाये रखना चाहती थीं। जूनागढ़ के नवाब विचित्र पुरुष थे। वे कुत्तों के शौकीन थे तथा उनके खास राजमहल में ही ६०० विभिन्न जाति के कुत्ते थे। ये अपने स्वतन्त्र शासन का अलग ही डफली पर राग बजा रहे थे। विलय के लिए भारतीय गणतन्त्र के दबाव पर जूनागढ़ के नवाब ने भौगोलिक अनिवार्यताओं की अवहेलना करके, पाकिस्तान से गठबंधन करना चाहा। किन्तु भारतीय गणतन्त्र ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार न किया। इस सम्बन्ध में उसका सिद्धान्त जनानुमति के अनुसार अन्तिम निर्णय के पक्ष में था। कालांतर में जनमत ग्रहण किया गया और निर्णय भारतीय

यूनियन से मिलने के पक्ष में हुआ। अतः अन्त में बाध हो उसे भारतीय संघ में मिलना पड़ा।

समग्रीकरण और लोकतन्त्रीकरण की इन बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के बावजूद भी एक बड़े राज्य ने न केवल भारतीय संघ में सम्मिलित होने से ही इन्कार किया, अपितु स्वतन्त्रता के अपने छूछे अधिकार को भी अनवरत घोषित करने में न चूका, और भारतीय संघ से एक बड़े संघर्ष की भी तैयारी में व्यस्त रहा। वह हैदराबाद का राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से वह केवल काश्मीर का ममकश और आव.दी तथा आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था। हैदराबाद भारतीय संघ की सीमाओं से घिरा हुआ एक प्रदेश है। यातायात और आर्थिक सम्बन्धों की दृष्टि से वह भारतीय संघ का एक अविच्छिन्न अंग सा है। भाषा, संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि से भी उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं जान पड़ता। आवादी का ८६३ प्रतिशत हिन्दू धर्म को मानता है। पं० नेहरू के लिए “यह एक अकल्पनीय बात थी कि आधुनिक युग में और हिन्दुस्तान के बिल्कुल मध्य में, जहाँ उसका हृदय एक नई स्वतन्त्रता की धड़कन का अनुभव कर रहा हो, एक ऐसा प्रदेश भी हो सकता था जहाँ इस स्वतन्त्रता की पहुँच न हो और जो एक अनिश्चित काल के लिए स्वेच्छाचारी शासन के अन्तर्गत रहना पसन्द करता हो।” अतः हैदराबाद की स्वतन्त्रता का समर्थन पं० नेहरू आत्मनिर्णय के किसी भी अधिकार के आधार पर करने के लिए तत्पर नहीं थे। उन्होंने रेडियो से ब्राडकास्ट करते हुए कहा था, “हैदराबाद राज्य की भौगोलिक स्थिति और देश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने से यह स्पष्ट बात होता है कि हैदराबाद स्वाधीन राज्य नहीं रह सकता। जब तक भारत स्वतन्त्र है हैदराबाद स्वतन्त्र नहीं रह सकता। आज प्रश्न यह है कि या तो भारत स्वाधीन रहेगा या हैदराबाद।.... अतः मेरे मत से हैदराबाद के लिए भारत में शामिल होने के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भारत में शामिल होने का यह अर्थ नहीं है कि हैदराबाद गुलाम हो जायेगा। देश के प्रत्येक भाग

मे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्रता देना हमारा उद्देश्य है । भारत में शामिल होने का अर्थ है संघ में समान रूप से साझीदार होना ।.....या तो हैदराबाद को भारत में सम्मिलित होकर रहना होगा या उसे भारत के नक्शे से सदा के लिए मिट जाना होगा ।”

भारतीय गणतन्त्र और हैदराबाद के आपसी तनाव को देखकर तत्कालीन गवर्नर जेनरल लार्ड माउंटबेटन ने स्थिति सुधारने के लिए निजाम के पास एक संदेश तार द्वारा भेजा था, “यदि निजाम सरकार अपने लिए अब भी वह रास्ता निश्चय करने में असमर्थ है, जो एक मात्र है, तो निजाम को यह प्रश्न जनता की इच्छा पर छोड़ देने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका जो भी निर्णय हो उसके अनुसार कार्य करे ।” परन्तु निजाम ने यह प्रस्ताव न माना ।

नवम्बर १९४७ में भारत सरकार और निजाम के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार निजाम ने हैदराबाद के वैदेशिक मामले, रक्षा और यातायात की व्यवस्था का भार, एक वर्ष के लिए भारत सरकार को सौंप दिया । परन्तु सच पूछा जाये तो इस समझौते में निजाम का उद्देश्य भारत-सरकार की आँख में धूल झाँक कर अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा लेना था । समझौता करने के पश्चात् निजाम ने अपने एक पत्र में स्पष्ट किया था कि “स्थिति बनाये रखने के लिए, मैंने यह समझौता करके अच्छी तरह समझ लिया है कि जब तक यह बना रहेगा तब तक के लिए मैं इन अधिकारों को, (एक स्वतन्त्र और मार्क्सवादी सत्ता सम्पन्न नृपति के) कुछ महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में स्थगित कर रहा हूँ ।” अतः इस समझौते के पश्चात् भी भारत से स्वतन्त्र रहने के दावे पर निजाम और उसकी सरकार बराबर जोर देती रही । दूसरी ओर भारत सरकार इस समझौते के लिए इसलिए तैयार हुई थी कि अलांतर पश्चात् शान्तिपूर्ण ढंग से निजाम को समझाकर भारत में सम्मिलित होने के लिए तैयार कर लिया जा सकता है । परन्तु हैदराबाद के अर्ध-नैतिक ढंग पर संगठित राजाकारों के प्रभाव के कारण वह पूर्ण न हो सका था ।

हैदराबाद में रजाकारों की संस्था 'इत्तिहादुल-मुसलमीन' का संगठन सांप्रदायिक धर्मान्धता के आधार पर हुआ था। इस संस्था को आर्थिक सहायता के अतिरिक्त निजाम का समर्थन भी प्राप्त था। दुबले-पतले, धर्मान्ध, पर कुटिल आकृति के आवरण को घीर कर बीच-बीच में चमक उठने और आग उगलने वाली पैनी आखों वाले कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों का यह संगठन अपना प्रभाव हैदराबाद पर तेजी से बढ़ाता जा रहा था। इसी संगठन का एक व्यक्ति लायकअली, छतरी के नवाब को अपदस्त कर प्रधान मंत्री के उत्तरदायित्व पूर्ण आसन पर आसीन हुआ था। वह रिजवी के इस संगठन को सब तरह की सहायता देता था। वह भारतीय गणतन्त्र को 'हिन्दुओं का राष्ट्र' समझ कर उससे घृणा करता था तथा किसी भी शर्त पर उसमें विलीन होने को तैयार नहीं था और अपनी स्वतन्त्रता का राग अलापता था।

नेहरू-सरकार के इस पूर्ण प्रकटीकरण पर कि वे हैदराबाद की स्वतंत्र सत्ता कभी भी बरदास्त नहीं कर सकते तथा उसे भारतीय संघ के अन्तर्गत अनिच्छा या इच्छा पूर्वक आना ही होगा, निजाम की सरकार अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिकतम युद्ध के हथियार और लड़ाई के अन्य साधन प्राप्त करने और उस फौजी सामान को, जो हैदराबाद की सरकार ने देश के विभिन्न स्थानों पर बहुत बड़े परिमाण में खरीद कर जुटा रखा था, तेजी से हैदराबाद पहुँचाने में व्यस्त थी। सैनिक शक्ति एवं रजाकारों की शक्ति में बेहद वृद्धि की जा रही थी। निजाम तो अपने प्रधान मंत्री लायक अली तथा रजाकारों के बौद्धिक रूप से कैदी थे।

रिजवी ने रजाकारों की एक सैनिक टुकड़ी के समक्ष ३१ मार्च १९४८ को कहा था, "हैदराबाद किसी भी अवस्था का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से हथियारों से लैस है। यह एक इस्लामी राज्य है। भारत संघ दक्षिण से इस मुसलमानी शासन को उठा देने के लिए प्रयत्नशील है। हैदराबाद के मुसलमान याद रखो ! कि भारत उपनिवेश में अब भी साढ़े चार करोड़ मुसलमान हैं, जो हमारी ओर देख रहे हैं कि हम इस इस्लामी

राज्य का झण्डा ऊँचा करें। भारत संघ जत्र हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, तो भारत के साढ़े चार करोड़ मुसलमान वगावत का झंडा खड़ा कर देंगे। मेरे मुसलिम भाइयों! दक्षिण में इस्लाम का भविष्य आपके ही हाथों में है, आपकी ही ओर संघ के भीतर रहने वाले हमारे भाई देख रहे हैं। जो अत्याचारों से पीड़ित हैं, क्या आप उनको धोखा देंगे? इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों!... आइये हम अपने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर कूँच करे और दुश्मन के टुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा इस्लाम का प्रभुत्व स्थापित करे।

३१ जुलाई को हैदराबाद की लायकअली सरकार के स्थाई 'लायक मंत्री' यामिन जुवेरी ने भी इसी आग्रह का वक्तव्य दिया, तथा वहाँ के हिन्दुओं को यह चेतावनी दी कि यदि उन्होंने किसी प्रकार भी भारतीय संघ का साथ दिया तो उसे राजभक्ति के खिलाफ समझ कर उन्हें गोली मार दी जायेगी।

हैदराबाद के सम्बन्ध में भारत-सरकार बड़े धैर्य से कार्य कर रही थी। वह उसे भारत का एक अविभाज्य अंग मानती थी तथा उसकी स्वतंत्रता को कभी भी मान्यता देना पसन्द नहीं करती थी। हैदराबाद में होने वाली अव्यवस्था को देखकर नेहरू जी ने मद्रास में दिये गये एक व्याख्यान में यह साफ प्रकट कर दिया था कि हैदराबाद किसी प्रकार भी रास्ते पर आने को तैयार नहीं है, अतः उसके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करनी ही होगी। परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी व्यक्त कर दिया था कि भारतीय संघ हैदराबाद की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं समझती, अतः इस सैनिक कार्यवाही को किसी प्रकार भी उसके विरुद्ध 'युद्ध' नहीं कहा जा सकता। तत्कालीन परिस्थिति की जटिलता समझ कर लायक अली की सरकार ने हैदराबाद के इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिषद के सामने रखा।

समस्या को सुलझते न देखकर जून १९४८ में नई दिल्ली में हैदराबाद के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच, दोनों के भावी सम्बन्धों का

निश्चय करने के लिए जो बातचीत चार दिनों तक चलती रही थी, उसके भङ्ग हो जाने के बाद नेहरूजी ने १७ जून की प्रेस-कान्फ्रेंस में साफ शब्दों में कहा था कि अब झगड़े के शान्तिपूर्वक निपटारे जाने की कुछ भी आशा नहीं है। “भारत उन प्रस्तावों से और आगे जाने को कतई तैयार नहीं है तथा वह समझौते के उन प्रस्तावों में कतई परिवर्तन करने को तैयार न होगा। .. अगर समझौता नहीं होता और हैदराबाद भारत मंथ में सम्मिलित नहीं होता, तथा अवस्था ऐसी हो जाती है कि लड़ाई हो तो ऐसी लड़ाई का जो परिणाम होगा वह स्पष्ट है। एक ही परिणाम हो सकता है, और मुझे निश्चय है कि वह हैदराबाद के अधिकारियों को पसन्द न होगा। अगर शान्तिपूर्ण सुलझाव होना अब भी सम्भव है, तो हम उसे मंजूर करते हैं।”

१० अगस्त १९४८ को नेहरू-सरकार की ओर से भारतीय विधान परिषद् के मामले ध्वेत पत्र रखा गया, जिसमें हैदराबाद की सारी बातों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया था। उसमें साफ शब्दों में यह कह दिया गया था कि भारत-सरकार हैदराबाद के कुशासन के प्रवाह को चुपचाप असह्य होकर देखती नहीं रह सकती। यदि वहाँ की न्याय और व्यवस्था की स्थिति, जिनके अस्तव्यस्त होने के लक्षण प्रकट होने लगे हैं, और भी बिगड़ती है और उससे भारत की शान्ति और सुव्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है तो भारत सरकार को बाध्य होकर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। भारत सरकार निजाम के स्वतन्त्रता के दावे को किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं कर सकती, विशेषकर जब इस दावे को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है।

७ सितम्बर १९४८ को प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय पार्लियामेण्ट में इस आशय का वक्तव्य दिया, “एक वर्ष से अधिक समय से हम हैदराबाद की सरकार के साथ संतोषजनक और शान्तिपूर्ण समझौता करने के लिए हृदय से प्रयत्न करते रहे।.....दुर्भाग्यवश समझौते के लिए हमारे बार-बार किये गये प्रयत्न जो एक-दो बार

सफल हो गये थे, अन्त में विफल ही रहे। कारण हैदराबाद में कुछ ऐसी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, जिन्होंने भारत के साथ कोई समझौता न होने देने का निश्चय कर लिया है। उन शक्तियों का नेतृत्व गैर जिम्मेदार व्यक्तियों के हाथ में है। ये बराबर अधिक शक्ति-सम्पन्न होती गयी और अब वहाँ की सरकार पर पूर्ण नियंत्रण रखती हैं।” इसके पश्चात् नेहरू जी ने वहाँ की जनता पर किये जाने वाले रजाकारों के नृशंस अत्याचारों का विगद वर्णन किया जिसमें उन्होंने बतलाया कि उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर आयोजित सैनिक-प्रदर्शनों का स्पष्ट उद्देश्य अल्प संख्याओं पर आतंक फैलाना है। भारतीय सीमान्त प्रदेशों में लूट-मार करने, भारतीय सैनिकों पर हमला कर उनके अस्त्र-शस्त्र नष्ट करने, स्त्रियों को वेष्टित करने तथा आग लगाने की घटनाएँ प्रायः नित्य ही होती हैं। मुसलमान और गैर मुसलमान, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक, जिन किसी ने भी रजाकारों के विरोध का साहस किया वह उनके पाशविक क्रोध का भाजक बना। ७ सितम्बर १९४८ तक, नेहरू जी के कथनानुसार, रजाकारों ने ७० गावों पर आक्रमण किया, लगभग १५० बार भारतीय संघ की सीमा के भीतर प्रवेश किया, सैकड़ों व्यक्तियों को मार डाला, तथा अनेक स्त्रियों के साथ बलात्कार किया अथवा उन्हें अपहरण कर के ले गये, १८ ट्रेनों पर आक्रमण किया और एक करोड़ से अधिक की जायदाद लूटी। नेहरू जी ने आगे कहा था कि “कोई सम्यक् सरकार अपनी सीमा के भीतर ऐसे अत्याचार होते नहीं देख सकती।...अतः इस समय सबसे प्रमुख समस्या हैदराबाद-रियासत के जीवन एवं सम्मान की रक्षा तथा पाशविक आतंक की समाप्ति करना है।”

हैदराबाद की सरकार ने उस आतंकवाद को दवाने में अपनी अनिच्छा एवं असमर्थता प्रकट की। वहाँ के शान्तिप्रिय नागरिकों का जीवन इतना अश्वस्त देखकर भारत-सरकार ने फिर से अपनी सेना, व्यवस्था-स्थापन के लिए सिकंदराबाद में भेजना चाहा परन्तु निजाम ने तत्कालीन अवस्था को सामान्य बतलाकर उस प्रस्ताव को अनावश्यक बतलाया।

इसके पश्चात् गवर्नर जेनरल ने रजाकारों को विगठित कर देने की माँग की परन्तु निजाम ने इस माँग पर भी विशेष ध्यान न दिया । तत्कालीन परिस्थिति को लेकर भारत-सरकार तथा निजाम-सरकार में काफी पत्र-व्यवहार हुए परन्तु उसका कोई विशेष फल न निकल । उधर पूर्ण अराजकता तथा नृशंस अत्याचारों के कारण साधारण नागरिकों की अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक हो गयी थी । फलस्वरूप शान्ति और सुव्यवस्था के नाम पर भारतीय सेना ने हैदराबाद की सीमा में प्रवेश किया । निजाम-सरकार को भी भविष्य की काली घटाओं का हलका-सा आभास लग गया था । अतः अपने अस्तित्व को संकट में देखकर हैदराबाद की सरकार ने मुईननवाज जग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल हैदराबाद के मामले की पैरवी करने के लिए राष्ट्र संघ में भेजा । उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से वर्तमान परिस्थिति पर तत्काल विचार कर कार्य करने की अपील की, पर हैदराबाद में भारतीय सेना के प्रवेश के पश्चात् तक उस पर विचार न हो सका । यह पहला और अंतिम अवसर था जब भारतीय संघ द्वारा निर्धारित समग्रीकरण और जनतंत्रीकरण की प्रवृत्ति को किसी देशी राज्य ने शस्त्र-प्रतिरोध के द्वारा रोकने का प्रयत्न किया था । परन्तु भारतीय सेना के चतुर सेना-नायकों ने एक सौ नौ घंटे के अन्दर निजाम की सेना को शस्त्र-समर्पण के लिए बाध्य किया । १८ सितम्बर को सबेरे विजयी भारतीय सेना पुनः, सात मास पश्चात् सिकन्दराबाद में प्रविष्ट हुई ।

१८ सितम्बर की रात को साढ़े आठ बजे नेहरूजी ने भाषण दिया, “मैं हैदराबाद के मुस्लिम और गैरमुस्लिम दोनों को बधाई देता हूँ । इस देश के लोग आपस में हथियारों से लड़े यह हमारे लिए दुःख की बात है । लेकिन यह प्रसन्नता की बात है कि झगड़ा अब समाप्त हो गया है । हैदराबाद के शासकवर्ग ने एक गलत रास्ता पकड़ा था और उसी से यह झगड़ा पैदा हुआ था ।” इसके पश्चात् उन्होंने, हैदराबाद के हिन्दू और मुसलमानों ने युद्ध और अशान्ति के समय जो धीरता, संयम, अनुशासन और एकता का परिचय दिया था, उसके प्रति प्रसन्नता जाहिर

की तथा कहा कि “हमें संयुक्त भारत का दृढ़ता से निर्माण करना चाहिए, जिसमें किसी भेद-भाव के बिना सबको समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो ।”

सुरक्षा-परिपद् में भारत की ओर से हैदराबाद के सम्बन्ध में पैरवी करने के लिए नेहरूजी ने सर रामास्वामी मुदालियर को नियुक्त किया था । पहले-पहल इस प्रश्न पर परिपद् में विचार १६ सितम्बर, १९४८ को आरम्भ हुआ । सर रामास्वामी ने हैदराबाद के आरोपों का उत्तर देते हुए कहा था, कि मेरी सरकार के विचार से हैदराबाद को इस काउन्सिल के सामने इस प्रश्न को लाने का कोई भी अधिकार नहीं है । वह एक स्वतंत्र राज्य नहीं है । न तो अति प्राचीन काल में न १९४७ के अगस्त के पहले अंग्रेजों के शासन काल में ही वह पूर्ण स्वतंत्र था । पीछे निजाम ने अपनी ओर से इस मामले को सुरक्षा परिपद् से उठा लिया, यद्यपि उसके पूर्व प्रतिनिधि वाद में भी काफी दिनों तक वह प्रश्न पुनः परिपद् के समक्ष लाने का असफल प्रयत्न करते रहे ।

स्वाधीनता के प्रथम वर्ष का अन्त होते-होते इस प्रकार समस्त देश में राजनीतिक एकता की स्थापना की गई । देशी राज्यों और अन्य प्रान्तों के बीच जो अप्राकृतिक व्यवधान, अपनी साम्राज्यवादी भित्ति को स्थिर रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था वह टूट गया । विचारों और प्रवृत्तियों की धाराये अब आसानी से इस विशाल देश के तिरंगे झंडे के नीचे से एक भाग के जीवन के सन्दन का अनुभव दूसरे भाग में पूर्णतः करा सकती थी ।

इस प्रकार, यद्यपि विदेशी सत्ता से मुक्ति पाने के पञ्चात्, अनिवार्य कठिनाइयों के रोड़ों को चुन-चुन कर अपने स्वातन्त्र पथ से हटाकर, हम अपने लक्ष्य की एक मंजिल को तय कर चुके थे; परन्तु स्वतन्त्रता की कल्पना के साथ हमारी आँखों में भावी समाज के जो उज्ज्वल स्वप्न झूल रहे थे उन्हें प्राप्त करना अभी ल्यों का ल्यो बाकी था । हम अपने ध्येय की ओर आगे बढ़े अवश्य किन्तु उनकी शीतल छाया अभी दूर थी ।

जिस सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति की बात हम सोचते हैं, उसकी कीमत हमें अपने राजनीतिक संघर्ष से कई गुना अधिक चुकानी होगी । आज कोई भी देश सिर्फ अपनी ही समस्याओं की दीवारों में बँधा नहीं रह सकता । बाहर की विशाल दुनिया की हलचल, उसकी सीमा को लोंघ कर भी उस पर सदा प्रभाव डालती है । इस स्थिति में हमें निष्पक्ष रूप से अपने देश की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर तौलना होगा । उस अहिंसा, सत्य, जनतन्त्र और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की तुल्य पर जिस पर हमारा महान राष्ट्र चलना चाहता है ।



काश्मीर-समस्या

यों तो काश्मीर की शोषित-शापित जनता और स्वेच्छाचारी ढोंगरा शासको मे बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा था, किन्तु पाकिस्तान के निर्माण और भारत मे प्रस्फुटित स्वतन्त्रता के स्वर्णिम नव-विहान के फलस्वरूप वहाँ की शस्य-श्यामला भूमि में भी जनतन्त्र का बीजारोपण हुआ । जनता का शासन, काश्मीर की हिन्दू-मुसलमान जनता के हाथों मे पहली बार आया, और सही माने मे पहली बार स्वतन्त्र राष्ट्र के स्वतंत्र वायु से पुलकित प्राङ्गण मे उन्होंने खुल कर साँस लीं । परन्तु काश्मीरी जनता के भाग्य मे इतने लम्बे अर्से के कठिन संघर्ष के पश्चात् पायी हुई स्वतन्त्रता का सुख और चैन से उपभोग करना शायद न लिखा था । भारत के विभाजन और अंग्रेजों की सत्ता हटने के साथ ही कूटनीतिक गतरंजी दाव पर उसका भाग्य जबरदस्ती लुगाया गया । असहाय काश्मीरी जनता के पास किस्मत की इस वाजी के हार-जीत को दूर खड़े होकर देखने के अलावा और कोई चारा न था ।

१५ अगस्त १९४७ को भारत और पाकिस्तान का शासन क्रमशः कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सौंप दिया गया था, तथा सत्ता-हस्तांतरण की शर्तों के अनुसार देगी राज्यों पर से भी ब्रिटिश प्रभुशक्ति का नियंत्रण उठ गया था । फलस्वरूप नव-निर्मित राष्ट्रों—भारत एवं पाकिस्तान—में से किसी एक से अपनी इच्छानुसार स्थायी संबंध स्थापित करने के लिए वे स्वतन्त्र हो गये थे । काश्मीर-सरकार ने दोनों ही राष्ट्रों से व्यावहारिक 'संधि स्थापित की । परन्तु पाकिस्तान काश्मीर की इस तुच्छ संधि से ही

संयुक्त न था; वह तो भारत-स्थित अन्य प्रदेशों की सीमाएँ रखकर काश्मीर को भी पूर्णतः आत्मसात् करवाने का कुत्सक रज रहा था।

वद्यपि महात्मा गाँधी ने कहा था कि "काश्मीर में हिन्दू-मुसलमान का कोई तगल नहीं है। भाषा और संस्कृति से वे सब एक से लगते हैं और हैं भी। काश्मीर का शासन उनके ही हाथों से और उन्हीं की इच्छादुसार होना चाहिए।" किन्तु फिर भी महात्माकांक्षी 'कायदे आज़म' विभा की 'न्यायप्रियता' वहाँ की जनता को आत्मनिष्ठ के इस हक से वंचित कर, काश्मीर को अखण्डता 'पाकिस्तान' में मिलाकर चहती थी। और अपने इस 'धुन जनताधिक' उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'कायदे आज़म' ने सीमाप्रान्त के कगड़ली छुट्टे को तैयार किया था। उन्होंने उनसे मयकर सामुदायिक बोध करने के लिए प्रसिद्ध किया कि मुसलिम राज्य पाकिस्तान ने काश्मीर में 'जेहाद' (धर्म-युद्ध) छेड़ दिया है। अर्द्ध-सत्य कगड़लियों द्वारा काश्मीर में किये गये निर्दोष अत्याचारों के विरोध और आलोचकों का स्वागत देते हुए सीमाप्रान्त के मुख्य लीगी नर्त्री नियाँ अम्बुल न्यून लों ने बड़े शर्मानाक शब्दों में उन छुट्टे कायों का समर्थन किया था, और उन अक्रान्तों को उचित बतलाया था।

वद्यपि काश्मीर की सरकार पाकिस्तान अथवा भारत संघ से अपना स्थायी सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न को कुछ दिनों तक समर्थित रखना चाहती थी, तथा उस पर शान्ति के समर्थ, जनता के महादुःखार विचार करना चाहती थी; किन्तु पाकिस्तान से सहायता प्राप्त इस आक्रामिक अक्रान्त ने उसे दुस्त निराश करने के लिए बाध्य किया। २३ अक्टूबर को रक्षा के आकाश में काश्मीर सरकार ने अपने को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया। अपने एक नवीन बंधु काश्मीर और उसके जनता की उर्वर अक्रान्तकारियों से रक्षा के लिए भारतीय संघ ने अविलम्ब सेवा देने की व्यवस्था की। भारतीय सेवा देने ठीक समय पर पहुँच कर श्रीनगर की रक्षा की तथा कगड़ली और पाकिस्तानी सेवा को गंड़े हटना मंडा। काश्मीर जमेगले सारे स्थलभूगर्भ पाकिस्तान-स्थित

प्रदेशों से होकर जाते थे, अतः भारत-सरकार को सेना तथा सैन्य-सामग्री भेजने की व्यवस्था वायुयानों द्वारा करनी पड़ी। भारतीय हवाई-सेना के विमानों ने लड़ाई में अपनी सेना को सहायता पहुँचाने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त स्थानों से वहाँ के निवासियों को हटाकर सुरक्षित स्थानों में पहुँचाने का भी कार्य किया।

इन्हीं दिनों पं० नेहरू ने भारतीय पार्लियामेन्ट के समक्ष काश्मीर सम्बन्धी एक श्वेत पत्र उपस्थित किया, जिसमें उन्होंने काश्मीर सम्बन्धी अपनी नीति तथा उद्देश्य का पूर्ण स्पष्टीकरण किया था। उसमें यह पूर्ण स्पष्ट कर दिया गया था कि अन्त्य स्थानों की भाँति काश्मीर के विषय में भी भारत-सरकार की यह इच्छा है कि उसके भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित होने का अन्तिम निर्णय वहाँ की जनता करे। अतः भारत अस्थायी रूप से काश्मीर को उसके संकटकाल में अपने संघ में सम्मिलित करता है। शान्ति-स्थापन के पश्चात् इस विषय पर जनमत-ग्रहण करने का आश्वासन दिया गया। शान्ति-स्थापन के लिए प्रयत्नशील नेहरू-सरकार ने कई बार पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को इस विषय पर वार्तालाप करने के लिए निमंत्रित भी किया, परन्तु इन सब का कोई भी फल न हुआ; तथा पाकिस्तानियों की प्राप्य सहायता से काश्मीर और जम्मू में आक्रमणकारियों की गतिविधि बढ़ती ही रही। अतः भारत-सरकार को अन्तिम उपाय के रूप में संयुक्तराष्ट्रसंघ की सुरक्षा-परिपद् से प्रार्थना करनी पड़ी कि “वह पाकिस्तान-सरकार से आग्रह करे कि वह दोनों देशों में अशान्ति पैदा करने की इस नीति को त्याग दे।” भारत-सरकार ने सुरक्षा-परिपद् को १ जनवरी १९४८ को एक पत्र लिखकर चार्टर की धारा ३५ के अंतर्गत उससे यह अनुरोध किया था। सुरक्षा-परिपद् ने जाँच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की, इसने १३ अगस्त १९४८ को अपना निम्नलिखित निर्णय दिया। (१) काश्मीर की लड़ाई बंद कर दी जावे। (२) दोनों देशों में एक विराम-सन्धि की जाय जिनके अनुसार पाकिस्तानी सेनाये काश्मीर से हटा ली जाये, और तत्पश्चात् भारतीय सेनाये

भी रियासत की रक्षा के अतिरिक्त वहाँ से हटा ली जाये । (३) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाये कि स्वतन्त्रतापूर्वक जनमत-संग्रह द्वारा रियासत के भविष्य का निपटारा किया जा सके । एडमिरल चेस्टर निमिट्ज़ जना-नुमति के अधिकारी नियुक्त हुए । किन्तु कमीशन के इस निर्णय का पूर्ण सदुपयोग न हो पाया । अंत में कमीशन ने अपने निर्णय को वापस ले लिया तथा असफल हो वापस लौट गयी । काश्मीर का प्रश्न पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ के विचाराधीन पड़ा रहा । सचमुच, यह कैसी घृणित और स्वार्थपूर्ण कूटनीतिक चाल है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा-परिषद् ने अधिनायकों की तरह स्थित जिन शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों ने, कोरिया में चीन के एक सूक्ष्म हस्तक्षेप के फलस्वरूप उसे आक्रमणकारी राष्ट्र करार कर दिया, उन्होंने इतनी भी तटस्थता और न्यायप्रियता दिखलाने का कष्ट न किया कि काश्मीर में पाकिस्तानियों की वास्तविक और प्रत्यक्ष चढ़ाई को एक स्वार्थपूर्ण आक्रमण घोषित कर उसके विरुद्ध भी यदि वैसी ही सैनिक कार्रवाई न भी करते तो कम से कम भारत के रक्षात्मक कार्यों का सम-वेदनात्मक समर्थन करते तथा उसे सहयोग देते ।

भारत और पाकिस्तान दोनों ही संघों की सेनायें काश्मीर की रण-स्थली पर जमी रही । एक का उद्देश्य था काश्मीर की रक्षा और दूसरे की इच्छा थी काश्मीर के स्वतन्त्र अस्तित्व का अन्त कर देना । पाकिस्तान की ओर से भारत के विरुद्ध सर्वथा निर्मूल और अनर्गल प्रचार होते रहे । पं० नेहरू ने इन असत्य आरोपों का उत्तर देते हुए श्रीनगर में कहा था, “पाकिस्तानी पत्रों का यह प्रचार निराधार है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है । संघर्ष से हमें कोई लाभ नहीं । जब पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया, तो अपने पड़ोसी राष्ट्र की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य हो गया । पाकिस्तानी पत्रों के विचार में काश्मीर में भारतीय सेना के इकट्ठा होने का मतलब पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी करना है । पांडुरोगी की आँखों को हर एक

चीज पीली ही दिखाई देती है। हम तो पाकिस्तान द्वारा प्रेरित आक्रमण-कारियों से काश्मीर की रक्षा कर रहे हैं।”

एक अन्य अवसर पर पं० नेहरू ने रेडियो पर भाषण देते हुए कहा था, “हमारे पड़ोसी देश की सरकार ने ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए, जो सरकारों और यहाँ तक कि जिम्मेदार लोगों की भाषा नहीं है, भारतीय संघ में काश्मीर के प्रवेश के सम्बन्ध में भारत-सरकार पर धोखाधड़ी और हिंसा का अभियोग लगाया है। मैं वैसी भाषा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार लोगों की ओर से बोल रहा हूँ। बाहरी आक्रमणकारियों के आक्रमण के कारण जम्मू और काश्मीर रियासत के बहुत से भाग पहले ही रौंदे जा चुके हैं। आक्रमणकारी पूर्णतः शस्त्रास्त्रों से लैस थे और उन्होंने गाँवों और शहरों को खूब लूटा एवं नष्ट-भ्रष्ट किया। उन्होंने बहुत से लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। जब श्रीनगर के ऊपर भी विनाश की विभीषिका मँडराने लगी तब हमने सहाय-तार्थ सेना भेजी। हम लोगों ने काश्मीर के सम्बन्ध में जो पग उठाया है, उसके परिणामों को खूब सोच-समझ कर ही। मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो कुछ किया है ठीक किया है। हम ऐसा न करते तो विश्वास-घात और कायरता के दोषी ठहराये जाते, और यह समझा जाता कि हमने तलवार के आगे, और उसके फलस्वरूप होने वाले अभिकाण्डों, बलात्कारों और जनसंहार के समक्ष घुटने टेक दिए।”.. .

“हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि काश्मीर का यह संघर्ष आक्रमण-कारियों के विरुद्ध वहाँ की जनता का है। हमारी सेना इस संघर्ष में वहाँ की जनता की सहायता के लिए गयी है, और जैसे ही आक्रमणकारी काश्मीर से निकाल दिये जायेंगे, वह वहाँ न रहेगी, तथा काश्मीर का भाग्य स्वयं वहाँ के लोगों पर छोड़ दिया जायेगा। हमें कितने ही सफ़टों से गुजरना पड़ा है, और अब भी उनका अंत नहीं हो पाया है। काश्मीर पर आक्रमण करने वाले शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हैं और उनका नेतृत्व योग्य व्यक्तियों के हाथों में है। हमें पाकिस्तान की सरकार से यह पृच्छने

का हक है कि ये लोग किस तरह और कैसे उत्तर-पश्चिम के सीमाप्रान्त, अथवा पश्चिमी पंजाब से होकर आये हैं, और कैसे इतनी अच्छी तरह शस्त्र-सज्जित हैं ? क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय विधान की अवहेलना और एक पड़ोसी राष्ट्र के प्रति शत्रुता की कार्यवाही नहीं है ? क्या पाकिस्तान की सरकार इतनी कमजोर है कि वह एक अन्य देश पर आक्रमण करने के लिए, अपने प्रदेश से होकर गुजरनेवाली सेना को नहीं रोक सकती, अथवा वह यह चाहती है कि ऐसा ही हो ? हमने पाकिस्तान की सरकार से बारम्बार आक्रमणकारियों को आने से रोकने, और जो आ गये हैं उन्हें लौटा ले जाने को कहा है । हमने काश्मीर की जनता को आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा करने का वचन दिया है और हम अपने इस वचन पर दृढ़ रहेंगे ।”

यद्यपि १ जनवरी १९४९ को दोनों देशों के बीच होने वाला यह युद्ध बंद हो गया था, किन्तु फिर भी काश्मीर में पूर्ण शांति और व्यवस्था-स्थापन का सभी प्रयत्न असफल रहा । फलतः कुछ दिनों पश्चात् सुरक्ष-परिषद् ने काश्मीर के प्रश्न को पुनः उठाया । १७ दिसम्बर, सन् १९४९ को उसने अपने सेनापति, जेनरल मेकनाटक को दोनों देशों के प्रतिनिधियों के परामर्श से इस प्रश्न के हल का अधिकार दिया । मेकनाटक महोदय ने दोनों देशों के प्रतिनिधियों से वार्तालाप किया, और तत्पश्चात् समस्या हल के लिए एक योजना बनायी, जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित थीं । (१) काश्मीर का प्रश्न निष्पक्ष जनानुमति के लोकतन्त्रात्मक ढंग से, शीघ्र से शीघ्र हल किया जाये । (२) दोनों राज्य एक मत हो ‘लड़ाई बंद करें’ रेखा के दोनों ओर से अपनी सेना इस प्रकार हटा लें कि किसी भी पक्ष को किसी भी प्रकार की आशंका न रह जाये । (३) ‘लड़ाई बंद करें’ रेखा के दोनों ओर की काश्मीरी सेनायें इतनी कम कर दी जायें जितनी शांति और व्यवस्था के लिए आवश्यक हो । (४) दोनों राज्य एकमत होकर यह स्वीकार करें कि उनकी अनुमति से संयुक्त राष्ट्र संघ का मंत्री

जिस व्यक्ति को संयुक्तराष्ट्र संघ का प्रतिनिधि नियुक्त करे वह लोकतन्त्रात्मक ढंग से इस समस्या के हल का निरीक्षण करे ।

यह योजना भारत को स्वीकार न थी । जिस बात की जाँच के लिए भारत ने काश्मीर के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ के विचाराधीन किया था उसकी ओर लेशमात्र भी ध्यान न देकर वह काश्मीर की समस्या को जटिलतर बना रहा था । प्रश्न तो यह था कि कौन राज्य आक्रमण का दोषी था, किन्तु संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात पर विचार कर रहा था कि अन्त में काश्मीर की समस्या किस प्रकार हल की जाये ।

१४ मार्च सन् १९५० को सुरक्षा परिषद् ने काश्मीर की समस्या के हल के लिए एक निर्णायक की नियुक्ति का प्रस्ताव पास किया । पाँच महीने के भीतर भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाओं को हटाने को थे, और तत्पश्चात् निर्णायक महोदय जनानुमति के लोकतन्त्रात्मक ढंग से काश्मीर के प्रश्न को हल करने को थे । सर ओवेन डिक्सन, जो आस्ट्रेलिया के न्यायाधीश थे इस प्रश्न के लिए निर्णायक नियुक्त हुए । उन्होंने काश्मीर के प्रश्न की जाँच करके अपनी रिपोर्ट तैयार की और यह स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया है । किन्तु उन्हें इस बात की जाँच करने का न तो अधिकार था और न घोषणा करने का ही । सुरक्षा-परिषद् का प्रस्ताव इस सम्बन्ध में मान था । इसीसे सुरक्षा-परिषद् तथा उसके कर्णधार कितने निष्पक्ष थे इसका अन्दाज लगाया जा सकता है । डिक्सन महोदय ने अन्त में सुरक्षा-परिषद् से यह सिफारिश की कि काश्मीर की समस्या का हल परस्पर बात-लाप द्वारा भारत और पाकिस्तान पर छोड़ दिया जाये । और जब तक समझौता न हो जाये, 'लड़ाई बन्द करो' (Cease fire Line) की रेखा के अनुसार काश्मीर का प्रदेश पाकिस्तान और भारत के आधीन रहे । भारत को यह निर्णय भी अमान्य था । इसके सम्बन्ध में सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह थी कि पाकिस्तान को आक्रमणकारी मानते हुए भी संयुक्त राष्ट्रसंघ उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में हिचकिचाता

था, जो साधारणतः इस प्रकार के राज्यों के साथ की जाती, तथा उसके चार्टर के अनुसार की जानी चाहिए थी। अपने स्वार्थों से संचालित शक्ति-शाली राष्ट्रों ने सुरक्षा-परिषद् में काश्मीर की समस्या को कभी भी तटस्थ तथा न्यायपूर्ण दृष्टि से देखने का प्रयत्न नहीं किया। इसके पश्चात् सुरक्षा-परिषद् ने इस समस्या के हल के लिए कई प्रयत्न किये, जिनमें निर्णायकों का कार्य घटनास्थल का निरीक्षण कर समस्या-हल के लिए अपनी रिपोर्ट देना था। पर भारत को यह पक्षपातपूर्ण निर्णय भी मान्य न था। ऐसा विदित होता है कि सुरक्षा-परिषद् काश्मीर को विभाजित देखने को विशेष उत्सुक है। किन्तु भारत समस्त काश्मीर को अपना अंग समझता है। वह जनानुमति द्वारा इस प्रश्न को हल करने के लिए तैयार है, किसी विदेशी निर्णायक के सर्वोच्च निर्णय द्वारा नहीं; और यह भी उसी अवस्था में जब आक्रमणकारी सेनाये काश्मीरी प्रदेश से हट जाये; कारण आक्रमणकारियों की उपस्थिति में, जनानुमति का पता लगाना एक भयंकर पाखंड के समान होता।

नवीन प्रतिनिधि मण्डल के प्रधान डा० ग्राहम की, काश्मीर सम्बन्धी रिपोर्ट, २३ दिसम्बर १९५१ को सुरक्षा-परिषद् के समक्ष विचारार्थ उपस्थित हुई। भारत के प्रधान प्रतिनिधि श्री वेंगल नरसिंह राव, तथा पाकिस्तान के श्री जफरुल्ला खॉ अपनी सरकार के विचार व्यक्त करने को वहाँ उपस्थित थे। डा० ग्राहम की रिपोर्ट में यह व्यक्त किया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही, इसके पहले कि संयुक्तराष्ट्र द्वारा निश्चित जनानुमति ली जा सकती, सुरक्षा-परिषद् की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए घटनास्थल से अपनी सेना हटाने में असफल रहे।

मि० ग्राहम ने दोनों राष्ट्रों को एक निश्चित सैन्य-संख्या ही उनके द्वारा अधिकृत 'लडाई बन्द करो' रेखा की सीमा में रखने का प्रस्ताव किया। इसके अतिरिक्त तत्सम्बन्धी निम्नलिखित पुराने सुझावों को उन्होंने अपने प्रस्ताव में फिर से दुहराया था।

(१) १५ जुलाई १९५२ तक काश्मीर के निश्चित स्थल से, स्वसम्मति से दोनों राष्ट्रों को अपनी सेना हटा लेनी चाहिए।

(२) दोनों देशों को, कम से कम संख्या में 'युद्ध बन्द करो' रेखा तक अपने सैनिक रखने चाहिए।

(३) जनानुमति-निरीक्षक अधिक से अधिक १५ जुलाई १९५२ तक इस कार्य के लिए नियुक्त हो जाना चाहिए।

प्रतिनिधि मण्डल के उपर्युक्त प्रथम दो प्रस्तावों को पहले की ही भाँति भारत-सरकार की ओर से फिर यह कह कर अमान्य कर दिया गया कि भारत काश्मीर की रक्षा के लिए उत्तरदायी है, अतः वह छूछे आवासन पर ही उस स्थल से अपनी सेना हटा लेने अथवा संख्या में कम करने में असमर्थ है। अतः मैं सुरक्षा-परिषद् ने यह प्रश्न जेनेवा-सम्मेलन तक के लिए स्थगित कर देने का निश्चय किया। न्याय और निष्पक्षता का ढोंग करती हुई, शक्तिशाली राष्ट्रों की कठपुतली सुरक्षा-परिषद् ने अनेक प्रस्तावों द्वारा भारत-सरकार को वहलाने का प्रयत्न किया, परन्तु संघर्ष और दुर्दिन में पले भारतीय नेताओं ने कच्ची गोली नहीं खेली थी।

इसी समय जब कि काश्मीर की समस्या, संयुक्तराष्ट्र संघ में जटिल होती जा रही थी, काश्मीर के प्रधान मन्त्री शेख अब्दुल्ला गिरगिट की तरह रंग बदल रहे थे। उनके कार्ड, उनके वक्तव्य अब भारत के मस्तिष्क में उनके प्रति सन्देह उत्पन्न करने लगे थे। आचार्य कृपलानी के शब्दों में, "वे अपने विचार व्यक्त करने में ऐसी भाषा का उपयोग करने लगे थे जो काश्मीर के मित्र भारत की स्थिति बड़ी हास्यास्पद बनाती हुई उनके शत्रुओं को विनोदपूर्ण कटाक्ष करने का अवसर दे रही थी।" वे अब काश्मीर के लिए एक अलग राष्ट्र-पताका बनाने का निश्चय कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अब वे डोगरा शासक को, उसे नाम मात्र के शासनाधिकार से भी वंचित करना चाहते थे। यह विधान के लिए संकट की एक पूर्व सूचना थी, तथा जो जनता के बीच साम्प्रदायिकता की भावना

उत्पन्न कर रही थी। शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर का सदरे-रियासत अब जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति को ही बनाने का निश्चय किया था।

इन आशंकाओं तथा अनिश्चितता के वातावरण में २६ अगस्त को जेनेवा-काफ़्रेस आरम्भ हुई, जिसमें दोनों देशों—भारत और पाकिस्तान—ने डा० ग्राहम के निःसैनिकरण तथा जनानुमति लेने के कार्य में योग देने का वचन दिया। दोनों देशों ने जेनरल निमिट्ज़ को जनानुमति-निरीक्षक मानना स्वीकार किया।

संयुक्तराष्ट्र के स्वार्था अधिनायकवादी देश, प्रजातन्त्र की रक्षा, न्याय और शान्ति के नाम पर अपना कूटनीतिपूर्ण पासा फेंक ही रहे थे कि अगस्त १९५३ में काश्मीर की आन्तरिक राजनीतिक स्थिति भयंकर हो गयी। गत मास से ही, प्रधान मन्त्री शेख अब्दुल्ला और उनके सहयोगी मन्त्रियों में, काश्मीर और भारत के सम्बन्ध पर गहरा मतभेद चल रहा था। यह संकट उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया जब वहाँ के प्रधान मन्त्री ने अपने एक सहयोगी मन्त्री, श्री शामलाल सराफ को अपने पद से स्तीफा देने के लिए कहा, और उन्होंने ऐसा करने से साफ इकार कर दिया। फलस्वरूप शेख साहब ने उन्हें अपदस्थ कर बंदी करने की आज्ञा प्रचारित कर दी। शेख अब्दुल्ला के तानाशाही कार्यों से क्षुब्ध मन्त्री-परिषद् के तीन मन्त्रियों, बक्शी गुलाममुहम्मद, श्री गिरधारीलाल डोगरा तथा ज्यामलाल सराफ ने एक सामूहिक प्रस्ताव द्वारा उनके कार्यों की निन्दा की तथा उन्हें अवैधानिक एवं जनतन्त्र के सामान्य अधिकारों का विरोधी बतलाया।

८ अगस्त को काश्मीर, और काश्मीर की जनता के स्वार्थ को खतरे में देख कर वहाँ के सदरे रियासत ने तत्कालीन मन्त्री-परिषद् को मंग कर दिया; तथा शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजलबेग तथा उनके अन्य ३० सहयोगियों को 'जन-रक्षा-कानून' के अन्तर्गत बंदी बना लिया। इसके पश्चात् उन्होंने, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, बक्शी गुलाममुहम्मद से अपनी

मंत्री-परिषद् निर्मित करने के लिए कहा । नवीन प्रधान मंत्री काश्मीर का भारत से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे । वे पाकिस्तान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के शक्तिशाली संचालक राष्ट्रों के स्वार्थ तथा उनकी काश्मीर के प्रति कृतनीति के पूर्णतः विरोधी थे । उनके इस विचार के फल-स्वरूप काश्मीर के संकट से लाभान्वित हो, अपनी महत्वाकांक्षा का अस्थिर प्रासाद खड़ा करने वाले राष्ट्रों के सभी पूर्व निश्चित कुचक्रों पर पानी फिर गया ।

काश्मीर के झगड़े और विभाजन में पूँजीवादी राष्ट्रों का क्या लाभ था, इसका भंडाफोड़ करते हुए, राजनीति के एक अमेरिकी विशारद, मि० लारेन्स० के० रोजिनगर, ने लिखा था, “काश्मीर में अमेरिका का स्वार्थ विशेषतः उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण है, सोवियत रूस के नजदीक होने से, तथा चीन, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटा होने के फलस्वरूप उसका सैनिक महत्व अत्यधिक है ।” यह सर्व-विदित है कि पाकिस्तान ने काश्मीर पर अधिकार होने के पश्चात्, वहाँ अमेरिका को अपना वायुयान-स्थल बनाने की आज्ञा देने का आश्वासन दिया था । यही कारण है कि अमेरिका और बृटेन, जो तृतीय महायुद्ध के लिए अपना सैनिक-आधार शक्तिशाली करना चाहते हैं, उस प्रदेश को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं । वे जानते हैं कि भारत तटस्थता की नीति तथा सभी देशों से मित्रता के व्यवहार का पक्षपाती होने के फलस्वरूप काश्मीर प्राप्त कर लेने के पश्चात् उन्हें कभी भी वहाँ सैनिक-स्थल बनाने की आज्ञा नहीं देगा । अतः इसीलिए वे अपनी, तथा अपने द्वारा पाली जाने वाली पूँजीवादी व्यवस्था की इसी में भलाई समझते हैं कि किसी प्रकार भी उस महत्वपूर्ण प्रदेश को भारत के हाथ से अलग रख कर उसे अपने सैनिक-साधन के लिए कार्य में ला सकें, और यही कारण है कि उन्होंने काश्मीर के प्रश्न पर सुरक्षा-परिषद् में बराबर पाकिस्तान का पक्ष ग्रहण किया ।

इतने वादविवाद तथा मनोमालिन्य के पश्चात् भी काश्मीर का प्रश्न अभी तक नहीं सुलझ पाया है। दोनों राष्ट्र एक दूसरे को सदेह की दृष्टि से देखते रहते हैं। पाकिस्तान-सरकार उक्त प्रश्न को लेकर बराबर भारत-सरकार पर असभ्यतापूर्ण कटु वाक्प्रहार किया करती है, तथा भारत-सरकार को विद्वत् के राजनीतिक क्षेत्र में बदनाम करने का कोई अवसर नहीं चूकती। देखे, भाग्यनियंता परमात्मा इस प्रश्न को कब सुलझाते हैं।



अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता और आलोचक नेहरू

भारत के समस्त राजनीतिज्ञों में पं० नेहरू अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। संसार के विभिन्न देशों के प्रति आपकी अनुभूति और सहानुभूति गहरी और व्यापक रही है। आप हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा उसकी निष्पक्ष आलोचना में अग्रगण्य रहे हैं। भारतीय राजनीति की अनेक कठिन समस्याओं में व्यस्त रहने पर भी वे अपने मन और मस्तिष्क को दूर-दूर का पर्यटन कराने और उसे स्वस्थ ज्ञानोपार्जन कराने में व्यस्त रखते हैं।

वे अनेक वर्षों से भारतीय जनता को यह स्मरण कराते रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप विश्व की घटनाओं का सम्पर्क बहुत घनिष्ठ हो गया है। कोई भी राष्ट्र विश्व के किसी भी कोने में होने वाली क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं के प्रभाव से अछूता नहीं बच सकता। भारत का स्वतंत्रता-संग्राम भी विश्वव्यापी संघर्ष का एक अंग था, जिसमें समस्त गोषित-शापित, परतंत्र मानवता की बुलंद आवाज छिपी हुई थी। जिस प्रकार भारत की प्रगति के प्रभाव से अन्य राष्ट्र प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते उसी प्रकार भारत संसार के घटना-चक्रों तथा राजनीतिक प्रभावों से अछूता बचकर अलग नहीं रह सकता।

पं० नेहरू-समाजवादी विचार के पोषक तो पहले से ही थे पर बाद में सोवियत रूस में जाकर उन्होंने समाजवाद का जो रूप देखा उससे उनके सिद्धान्त को और दृढ़ता मिली और वे पक्के समाजवादी हो गये। वे स्पेन में उस समय गये थे जब वहाँ घोर गृह-युद्ध हो रहा था उन्होंने

रूप में शान्ति हो पायेगी। नेहरू जी को यह पूर्ण विश्वास था कि विश्व की इस विषम परिस्थिति में, प्राचीनकाल की मूर्ति भविष्य में भी, अपनी सर्वोद्गीर्ण उन्नति के पश्चात्, भारत ही विश्व-शान्ति और आत्म-विकास का प्रकाश दिखलायेगा तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पाठ पढ़ायेगा।

नेहरू जी ने राष्ट्रपति-पद से १९२९ में विश्व की समस्याओं का दिग्दर्शन कराते हुए कहा भी था, "यूरोप का एशिया पर आधिपत्य करीब करीब समाप्त हो चला है।.....भविष्य एशिया के हाथ में है।"

पं० नेहरू पूर्णजीवाद और साम्राज्यवाद के घोर विरोधी हैं और इसी को विश्व में उपस्थित संकटों का मूल कारण समझते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास है कि संसार में जब तक यह दोनों रहेंगे तब तक शान्ति कदापि स्थापित नहीं हो सकती। सन् १९३९ की जुलाई में लन्दन में 'इंडिया लीग' तथा 'लन्दन फेडरेशन आफ पीस काउन्सिल' के अध्यक्ष-पद से नेहरू ने साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का दिग्दर्शन कराते हुए कहा था, "शान्ति और साम्राज्य! मूल में ही एक दूसरे के विरोधी शब्दों का अनोखा मेल है।.....मैं समझता हूँ कि जब तक साम्राज्य-वादो विचार दूर न होगा, तब तक हम संसार में शान्ति न पा सकेंगे। जब तक साम्राज्य फूलते-फूलते और शक्तिशाली रहते हैं, तब तक सम्भव है उनमें खुली लड़ाई न हो, पर तब भी शान्ति नहीं रहती, क्योंकि तब संघर्ष और युद्ध की तैयारी भीतर ही भीतर चलती रहती है। साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रों में, शासकों और शासितों के बीच संघर्ष तो रहता ही है—क्योंकि साम्राज्यवादी राष्ट्र का आधार निर्बल जनता का दमन और शोषण करना है—अतः उसका विरोध भी होगा, और उस शासन का अन्त करने के लिए प्रयत्न भी होंगे। अतः इस संघर्ष के आधार पर शांति कभी भी कायम नहीं की जा सकती।" उन्होंने जर्मनी के नाजीवाद और इटली के फासिस्टवाद की तीव्र आलोचना करते हुए कहा था, "फासिज्म, नाजीवाद अथवा साम्राज्यवाद की भावनाओं में भेद नहीं है, फासिज्म वास्तव में साम्राज्यवाद का ही एक उग्र रूप है।"

पं० नेहरू ने साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा निर्मित 'कामनवेल्थ आफ नेशन्स' की भी टीका-टिप्पणी करते हुए एक बार कहा था, प्रस्तुत कामन-वेल्थ का आधार दोषपूर्ण है और किसी दिन भी इसके शक्तिशाली राष्ट्र इसमें शामिल निर्बल राष्ट्रों पर हावी हो सकते हैं। यह एक धोखे की टट्टी, है क्योंकि ये साम्राज्यवादी राष्ट्र कभी की अपने से कम शक्ति-शाली राष्ट्र को अपने बीच समानता का अधिकार नहीं दे सकते।

नेहरू जी 'राष्ट्र संघ की संरक्षण-प्रथा (Mandate System) के भी सख्त विरोधी थे, जिसकी स्थापना प्रथम महायुद्ध के पश्चात् राष्ट्र-संघ की स्थापना के साथ ही हुई थी, तथा जिसके अनुसार एक शक्ति-शाली राष्ट्र को पराजित राष्ट्र के कुछ भागों पर शासन करने का अधिकार मिल जाता था, अथवा अविकसित क्षेत्रों (Under developed Areas) के निवासियों पर, "उनमें सभ्यता तथा सस्कृति के विकास के लिए संरक्षण" के नाम पर, दूसरे राष्ट्रों का शासन तथा हस्तक्षेप आरम्भ हो जाता था।

नेहरू जी का विचार था कि पेलेस्टाइन में अरब-यहूदी समस्या ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उपस्थित की गई है। उन्होंने यहूदियों के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की थी, क्योंकि वे बेचारे विश्व के हर एक भाग से निकाले जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि पेलेस्टाइन की समस्या को स्वयं अरबों और यहूदियों को आपसी समझौते से सुलझाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा ब्रिटिश साम्राज्यवाद उसे कदापि हल नहीं कर सकता।

नेहरू जी समस्त देशों की घरेलू तथा आंतरिक समस्याओं को विश्व-व्यापी आर्थिक संघर्ष का ही अंग समझते हैं तथा समाजवादी विचार-धारा के होने के कारण उन समस्याओं के हल के सम्बन्ध में उनका दृष्टि-कोण बड़ा व्यापक रहता है। संकुचित राष्ट्रीयता के आधार पर वे कभी एक देश को हानि पहुँचा कर दूसरे देश को लाभ पहुँचाने का समर्थन न करेंगे। उन्होंने रूस, अमेरिका, चीन आदि देशों में जाकर वहाँ की

जनता की आवश्यकताओं तथा सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किया और उनकी महत्वाकांक्षाये समझी, तथा उनका सम्बन्ध भारत के लिए कहाँ तक लाभजनक, हानिकर, मूल्यवान अथवा उपयोगी हो सकता है इसे भी उन्होंने सदा ध्यान में रखा। वे कभी-कभी संसार को कठिनाइयों पर विचार करते-करते अपने व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय झगड़ों को भी भूल जाते हैं, और उनमें न जाने कैसी विचित्र व्यापक सहानुभूति है कि वे मानवता को समस्त कठिनाइयों से मुक्त करने का स्वप्न देखने लगते हैं।

१९३९ में जब स्पेन में गृहयुद्ध हो रहा था और जर्मनी तथा इटली की फासिस्ट सेनाओं ने वहाँ जेनरल फ्रेन्को के पक्ष से प्रजातंत्रवादियों को दबाया तो नेहरू जी उस समय फासिस्ट शक्तियों की उन्नता, तथा ब्रटेन की शिथिल नीति पर बहुत नाराज हुए थे। वे स्वयं स्पेन गये थे और उन्होंने वहाँ कहा भी था, “हम, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहे हैं, स्पेन के इस ऐतिहासिक युद्ध पर बहुत चिन्तित हैं, क्योंकि संसार की स्वतंत्रता यहाँ पर कुण्ठित हो रही है। हमारे संघर्ष की सीमायें हमारे देश तक ही नहीं बरन् वे स्पेन और चीन तक फैली हुई हैं।” विश्व के प्रत्येक दलित-देश, इन्डोचाइना, इन्डोनेशिया, ईरान, मिश्र, वीटनाम, व्यूनीशिया आदि के प्रश्नों पर भी, जिन पर पश्चिम के साम्राज्यवादी राष्ट्र अपनी स्वार्थपूर्ण लोछुट दृष्टि लगाये हैं, उनका यही विचार है।

नेहरू जी ने काफी निकट से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं कूटनीतिपूर्ण स्वार्थों का अध्ययन किया है। १९३८ में जब योरोप कमजोर राष्ट्रों के स्वार्थों का बलिदान कर, चेम्बरलेन की ‘सबको खुश करने की नीति’ के साथ पैर मिलाता हुआ म्यूनिख-संधि के नाटक का अन्तिम दृश्य देख रहा था, और जब कि लंदन में इस बात पर खुशियाँ मनायी जा रही थी कि संकट टल गया—इस बात को प्रायः भूल कर कि उसके लिए कितनी बड़ी कीमत असहाय राष्ट्रों को, जबरदस्ती अपनी चीख दबा कर चुकानी पड़ी है—तब नेहरू ने चेम्बरलेन की इस नीति पर कहा था, “मैं ब्रिटिश-सरकार की नीति से घृणा करता हूँ, और धोषणा करता

हूँ कि मैं उसे सहन नहीं कर सकता तथा भारत उस नीति का साथ मविष्य में कभी न देगा ।.....राष्ट्रों का संघ शान्ति की कब्र है और इतिहास उस विश्वासघात को कभी न भूलेगा जो ब्रिटिश और फ्रेंच सरकारों ने एक छोटे से लोकतन्त्रवादी देश चेकोस्लोवाकिया के साथ किया है ।” म्यूनिख संकट के दिनों नेहरू जी ने जेनेवा का भी निरीक्षण किया था । तटस्थता का ढोंग करने वाली उस जेनेवा का, जहाँ शान्ति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के शव आज भी बिखरे पड़े मिलेंगे, और जिस पर साम्राज्यवादी गिद्ध आज भी चोंचें लड़ा कर अपने हिस्से के लिए झगड़ रहे हैं ।

आज भी उन्हीं सब साम्राज्यवादी चालों की पुनरावृत्ति हो रही है । प्रबल राष्ट्रों के स्वार्थ का इतिहास अपने को दोहरा रहा है । परिस्थितियों से उत्पन्न आशा-निराशा में आज भी झूलते हुए पं० नेहरू अपने उसी पुराने निष्कर्ष पर पहुँचे कि जब तक साम्राज्यवादी राष्ट्रों के स्वार्थ संबंधी परस्पर द्वन्द्व और संघर्ष जारी रहेंगे, तब तक कभी भी विश्व में चिर शान्ति नहीं हो सकती । बन्धुत्व और मित्रता का ढोंग करते हुए आज भी सबल राष्ट्र आपस में शक्ति, विजय और सम्मान (Power, glory & fame) के लिए कटु प्रतियोगिता और गहरा घड़्यन्त्र कर रहे हैं, जिससे संसार की निर्बल जनता भयत्रस्त तथा कुण्ठित है । मावी विश्व-युद्ध की घटा पश्चिमी भित्ति पर घिरती चली आ रही है । विश्व की परिस्थिति, विशेषतः अशक्त एशिया की शान्ति और रक्षा से चिन्तित पं० नेहरू, अडिग भ्रातृत्व-वर्धन तथा मित्रता के एक नवीन चित्र की रेखाओं में रंग भरने का प्रयत्न कर रहे हैं । पंचशील की नीति इसी महान उद्देश्य का एक अङ्ग है, जिसमें विश्व के शान्तिप्रिय राष्ट्रों के, विशेषतः एशिया के, संयुक्त आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग, मानवीय अधिकारों तथा आंतरिक प्रश्नों के स्वनिश्चय तथा स्वसञ्चालन का सहअस्तित्व के आधार पर प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार, उपनिवेशवादिता का विरोध तथा विश्व शांति रक्षा के प्रश्न पर जोर दिया गया है, तथा सभी जातिप्रेमी

राष्ट्रों से, अपने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यक्रमों में इसे स्थान देने की अपील की गयी है ।

नेहरू जी सभी औपनिवेशिक देशों की राष्ट्रीय जागृति और स्वतंत्रता को शान्ति और लोकतंत्रवादी विश्व-व्यवस्था के लिए अधिक उपयोगी और आवश्यक समझते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि यह राष्ट्रीय जागृति जितनी ही बढ़ेगी उतनी ही साम्राज्यवादी भावना क्षीण और अशक्त होती जायेगी । लोकतंत्रवादी सिद्धान्तों के लिए उन्हें पूरी श्रद्धा तथा आस्था है, पर संसार के बड़े-बड़े लोभी तथाकथित 'लोकतंत्रवादियों' को वे घृणा की दृष्टि से देखते हैं । यही कारण है कि आज भी उन्होंने अपनी स्वतन्त्र तथा तटस्थ वैदेशिक नीति रखकर, दो में से किसी भी शक्ति-गुट्टे—रूस अथवा अमेरिका—से अपना गंदाकूटनीति पूर्ण सम्बन्ध नहीं रखना चाहते जिसे विश्वशान्ति खतरे में पड़े । आज नेहरू जी एक स्वतंत्र देश के राष्ट्राधी, पर संसार के नागरिक की हैसियत से अन्तर्राष्ट्रीय तथा समाजवादी विचारक होकर संसार की राजनीति को देखते और समझते हैं तथा निष्पक्ष हो उसकी आलोचना करते हैं । इस अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मानवकल्याण के निमित्त उनकी सृज-समझ और सहानुभूति विश्व के किसी भी महान मानवता-प्रेमी से कम व्यापक नहीं है । जवाहरलाल केवल भारत के ही नहीं, बल्कि सुपुष्ट जगलामुखी पर बैठे हुए अस्त-एशिया के नेतृत्व की बागडोर अपने हाथ में सम्हाले हुए हैं । इस अजेय पुरुष की ओर, जो आज पीड़ित जन-समूह का पक्ष लेकर विश्व की खूनी प्रवृत्तियों से संघर्ष करता हुआ समता और भ्रातृत्व का गावत संगीत विश्व-वाणी के टूटे तारों से स्पंदित कर रहा है, विश्व के समस्त गोपित और पददलित राष्ट्र आशा भरी निगाह से निहार रहे हैं । आज उन्हें किसी देश, जाति अथवा समय के बन्धन से बांधना कोरी विडम्बना होगी ।



नेहरू और ब्रिटिश कामनवेल्थ

ब्रिटिश कामनवेल्थ के अधिवेशन का निर्माण मिलने पर स्वतन्त्र भारत के प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने, देश में संकटपूर्ण स्थिति होते हुए भी, इस महत्वपूर्ण अवसर पर वहाँ जाना निश्चित किया; कारण इसमें उन्हें विभिन्न देशों के प्रधान मन्त्रियों से सम्पर्क बढ़ाने का तथा भारत के सम्बन्ध में विदेश में, पाकिस्तान द्वारा प्रचारित भ्रमपूर्ण, मिथ्या और घृणित प्रचारों का तर्कपूर्ण खंडन कर निवारण करने का अवसर मिलता, तथा भारत का संदेश सुनाने में समर्थ हो वे दूसरे राष्ट्रों के हृदय में उसके प्रति सम्मान तथा आस्था का बीज बो सकते। इसके अतिरिक्त संयोगवश उन्हीं दिनों पेरिस में संयुक्तराष्ट्र-संघ की जनरल असेम्बली तथा सुरक्षा-परिषद् का भी अधिवेशन होने वाला था, जिसमें उपस्थित हो पं० नेहरू काश्मीर तथा हैदराबाद की समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहते थे, जिससे पाकिस्तान द्वारा उड़ाये असत्य तथा अविश्वास के बादल को छिन्न-भिन्न करने में वे सफल हो सकें। अतः उस समय नेहरू का विदेश जाना, सर्वथा अनुकूल तथा आवश्यक था। उन्होंने ६ अक्टूबर १९४८ को भारत से प्रस्थान करने का निश्चय किया।

भारत से यारोप-यात्रा के पूर्व १ अक्टूबर १९४८ को नेहरू जी ने श्रीनगर में पाकिस्तान के निर्मूल प्रचारों का उत्तर देते हुए कहा कि भारत का न तो कभी पाकिस्तान पर आक्रमण करने का ही विचार रहा है और न भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों का प्रवाह ही रोकने का, परन्तु इसमें शक नहीं कि भारत पाकिस्तान की

वृणित कूटनीति की शतरंजी चाल में उसे मात देने के लिए पूर्ण सचेत है। काश्मीर सम्बन्धी आक्रमणकारी पाकिस्तानी नीति को भारत सहन नहीं कर सकता और आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए तलवार का जवाब तलवार से देने में भारत हिचकेंगा भी नहीं।

बृटिश राष्ट्र मंडल के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए पं० नेहरू ५ अक्टूबर १९४८ को वायुयान से बम्बई पहुँचने के लिए रवाना हुए। हवाई अड्डे पर उनके सहयोगी तथा मित्र, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचार्य, उप-प्रधान मंत्री सरदार पटेल, अन्य मन्त्रागण तथा कुछ प्रमुख व्यक्ति उन्हें विदा करने के लिए एकत्र हुए थे। पं० नेहरू के साथ परराष्ट्र विभाग के सचिव सर गिरजा शंकर वाजपेयी, तथा उनके निजी सेक्रेटरी श्री मथाई भी थे।

वायुयान के बम्बई पहुँचने पर वहाँ के मुख्यमन्त्री, सरकारी अफसरों तथा प्रमुख नागरिकों ने नेहरू जी का स्वागत किया। उसी दिन साढ़े चारह बजे फिर वे विमान पर सवार हुए। संयोगवश लंका के प्रधान मंत्री श्री सेनानायक भी उसी विमान से लन्दन की कान्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। उन्होंने नेहरू जी के साथ यात्रा करने के इस संयोग को अपने लिए सौभाग्य की बात कही थी तथा उन्हें विश्वास दिलाया था कि वे कान्फ्रेंस में उनसे मिलकर कार्य करेंगे।

लन्दन पहुँचने के पूर्व नेहरू जी का वायुयान कई स्थान पर कुछ देर के लिए रुका। नेहरू जी ने उन चन्द घण्टों को व्यर्थ न जाने दिया तथा उसे उस स्थान के प्रमुख व्यक्तियों से बात करने तथा उनके साथ भारत की ओर से सम्पर्क बढ़ाने में लगाया। ६ अक्टूबर को उनका वायुयान काहिरा के फारुक हवाई अड्डे पर उतरा। वहाँ पं० नेहरू ने आधे घण्टे तक अरब संघ के सेक्रेटरी—जेनरल आजम पाशा से वार्तालाप किया। वहाँ पत्र-प्रतिनिधियों के समक्ष उन्होंने कहा, “पैलेस्टाइन के सम्बन्ध में भारत का मता यह मत रहा है कि स्वायत्त शासन प्राप्त

क्षेत्रों का एक संघ बने। तभी आपसी बैमनस्य का यह प्रश्न हल हो सकता है ।”

७ अक्टूबर की रात को ‘राजपूत प्रिन्सेज’ विमान से पं० नेहरू लन्दन पहुँचे । उस समय वह अपने प्रिय भारतीय वस्त्र पहने हुए थे । हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राष्ट्रमण्डल सम्पर्क विभाग के ब्रिटिश मंत्री मि० नोएल बेकर, लन्दन स्थित भारतीय हाई कमिश्नर श्री मेनन तथा अन्य प्रमुख भारतीय तथा विदेशी व्यक्तियों ने किया । श्रीमती विजया-लक्ष्मी पण्डित भी अपने सुयोग्य भ्राता से आवश्यक विषयों पर परामर्श करने के लिए उसी दिन लन्दन पहुँची । वहाँ के पत्रकारों से बात करते हुए पं० नेहरू ने कहा कि “भारत इंग्लैण्ड के साथ रहते हुए भी सार्वभौम सत्ता (Sovereignty) सम्पन्न और स्वतंत्र रहना चाहता है ।”

दूसरे दिन सुबह पं० नेहरू तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री मि० एटली से उनके लन्दन वाले सरकारी घर, १० डाइनिंग स्ट्रीट में, मिलने गये और वहाँ जलपान किया । वहाँ पर ब्रिटिश परराष्ट्र मंत्री मि० बेविन, मि० नोएल बेकर लार्ड लिस्टोवेल प्रभृति कई अन्य ब्रिटिश मंत्री भी उपस्थित थे । दोनों प्रधान मंत्रियों में ३ घण्टे तक वार्तालाप होता रहा । वहाँ से पं० नेहरू इंडिया हाउस पहुँचे, वहाँ महात्मा गांधी के चित्रों, लेखों, फोटो आदि की एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया तत्पश्चात् हाईकमिश्नर मि० मेनन के साथ चाय पी ।

११ अक्टूबर को १०॥ बजे दिन से, लन्दन में राष्ट्रमण्डल के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन प्रारम्भ हुआ । इसमें ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मि० क्लिमेंट एटली, भारत के प्रधान मन्त्री पं० नेहरू, पाकिस्तान के मि० लियाकतअली खॉं, न्यूजीलैण्ड के मि० पीटर फ्रेजर, लंका के मि० सेना-नायक, आस्ट्रेलिया के परराष्ट्र मन्त्री मि० एब्राहम और दक्षिण अफ्रिका के मि० लो उपस्थित थे । कनाडा के प्रधान मन्त्री मि० मेकेजी किंग बीमार होने के कारण उपस्थित न हो सके थे । मि० एटली ने आगत

मन्त्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह एक पारिवारिक सम्मेलन है, जिसके भीतर तीन नये उपनिवेशो—भारत, पाकिस्तान और सिलोन—के प्रधान मन्त्रियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। इस कान्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य उन विषयों पर बात करना है जो राष्ट्रमण्डल के सभी देशों से सम्बन्धित हैं। हम यहाँ एक दूसरे की समस्या समझने तथा उन्हें उचित प्रकार से सहायता देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोगो का एक ही उद्देश्य है और वह है गान्ति-स्थापना तथा अपने देश को समृद्धिशाली बनाना। पं० नेहरू ने वहाँ अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा कि “यह प्रथम अवसर है कि स्वतन्त्र भारत के प्रतिनिधि को सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। एक राष्ट्र की समस्या दूसरे से अलग नहीं की जा सकती। भारत राष्ट्रमण्डल के अन्य राष्ट्रों से सहयोग करने के लिए उत्सुक है। मैं यहाँ की मित्रता और सहयोग के वातावरण से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इसे मैं तार्किक वाद-विवाद से अधिक महत्व का समझता हूँ।” इस प्रकार प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन में पं० नेहरू के भाषणों का प्रभाव पड़ा तथा उन्हीं के प्रस्ताव पर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से, बहुमत द्वारा, ‘ब्रिटिश’ शब्द हटा देना स्वीकृत हुआ।

आस्ट्रेलिया के लन्दन स्थित सम्वाददाता ने लिखा था, “सम्मेलन में उपनिवेशों के तमाम प्रतिनिधि पं० नेहरू द्वारा प्रत्येक प्रश्न के समाधान की पहुँच से अत्यन्त प्रभावित हुए हैं। पं० नेहरू को भारत की युद्ध सम्बन्धी शीघ्र आ पड़ने वाली महत्ता के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है।”

न्यूयार्क टाइम्स के लन्दन स्थित सम्वाददाता ने लिखा था, “सम्मेलन में प्रधान मन्त्री पं० नेहरू महत्वशाली और सर्वप्रिय व्यक्ति सिद्ध हुए हैं। अपनी ओर से उन्होंने मित्रता और सहयोगपूर्ण ही व्यवहार किया।”

न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून के सम्वाददाता ने लिखा था, “यदि भारत ने ‘राष्ट्र-परिवार’ से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया तो ब्रिटिश राष्ट्र का पूरा खाका ही बदल जायेगा।”

१२ अक्टूबर को भूतपूर्व भारत मन्त्री, और भारत में १९४६ में आये हुए ब्रिटिश मन्त्री-मण्डल के प्रधान, लार्ड पैथिक लारेन्स की अध्यक्षता में, इंडिया लीग के तत्वावधान में लन्दन के किंग्स वे हाल में पं० नेहरू का अपूर्व स्वागत हुआ, तथा उन्हें मानपत्र प्रदान किया गया। इसमें राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक प्रो० हेरल्ड जे० लास्की, लेडी माउन्टबैटन, सर स्टेनली रीड आदि प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। लार्ड पैथिक लारेन्स ने नेहरू जी की प्रशंसा करते हुए कहा, “इनके पास ऐसा विशाल हृदय है, जो मनुष्य द्वारा पृथक् किए हुए सम्बन्धों के बीच की खाई के लिए पुल का कार्य करता है। मैं यह जानता हूँ कि नेहरू जी अन्य किसी भी आदमी से अधिक पूर्व और पश्चिम को मिलाते हैं, यह इस आदमी की प्रधान विशेषता है, जो सर्वप्रथम अपने देश के भाग्य-निर्माण का पथ-प्रदर्शक हुआ है।” इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा था कि “ईर्ष्या तो वे जानते ही नहीं, कटुता से तो उनका सम्बन्ध ही नहीं रहा है, असफलता और पराजय ने उन्हें कभी निराश नहीं किया और सफलता तथा विजय से वे कभी अनावश्यक रूप से उत्फुल्ल नहीं हुए।”

पं० नेहरू ने अपने वक्तव्य में सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा-गान्धी की महानता और राष्ट्र के प्रति अमूल्य निस्वार्थ सेवाओं के प्रति, महान भारत राष्ट्र की ओर से, आभार प्रकट करते हुए श्रद्धाजलि अर्पित की; पश्चात् कहा कि ब्रिटिश सरकार ने लार्ड माउन्टबैटन को भारत का अंतिम वायसराय चुनकर बुद्धिमानी की, क्योंकि वे भारत सम्बन्धी तत्कालीन ब्रिटिश नीति को कार्यान्वित करने के लिए सर्वोचित व्यक्ति थे। इसके पश्चात् लार्ड माउन्टबैटन तथा लेडी माउन्टबैटन की संक्रमण कालीन संकटों में की गई सेवाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भारतवासियों और ब्रिटेन के निवासियों के बीच घनिष्ठतम सम्पर्क और सहयोग चाहता हूँ।

पं० नेहरू के व्यक्तित्व से प्रभावित प्रो० लास्की ने उस समय कहा था, “दीन-हीन जनता की दशा में सुधार करने के लिए जो

जागरूकता मैंने पं० नेहरू में देखी वह अपने जीवनभर में मैं केवल दो तीन व्यक्तियों में ही पा सका हूँ।”

इंगलैंड के सम्राट ने, १३ अक्टूबर की रात में अपने त्रकिंघम रानप्रासाद में प्रधान मंत्रियों की कान्फ्रेंस में समवेत प्रधान मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों के सम्मान में एक भोज दिया। नेहरू जी भी उसमें सम्मिलित हुए थे। सम्राट ने आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए राष्ट्रमण्डल को ‘राष्ट्रों का कुटुम्ब’ कहा। उन्होंने यह भी कहा कि “मैं भारत, पाकिस्तान और सिलोन के प्रधान मंत्रियों का स्वागत विशेष रूप से करता हूँ जो हमारे ‘राष्ट्रों के कौटुम्बिक वार्तालाप’ में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं।”

१३ अक्टूबर की रात को पं० नेहरू ने डोरचेस्टर होटल में कनाडा के प्रधान मंत्री मि० मेकेंजी किंग से १ घंटे तक राष्ट्रमण्डल विषयक मामलों में बातचीत की, पश्चात् दक्षिणी अफ्रिका के भारतीय नेता मि० पाटू से बातचीत की। दूसरे दिन सुबह नेहरू जी ने दो आस्ट्रेलियन अतिथियों को भोजन कराया। प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजवादी नेता मि० वेल्सफोर्ड ने अपने एक लेख में लिखा है कि नेहरू जी को पूर्व और पश्चिम में मध्यस्थ का आसन ग्रहण कर मानवजाति के लिए शान्ति की स्थापना का प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने लिखा है, “पं० नेहरू दो संसार के बीच स्थित हैं। पूर्व तथा पश्चिम के बीच चलने वाले इस संघर्ष में पं० नेहरू एगिया की एक ऐसी महान शक्ति की वैदेशिक नीति के कर्णधार हैं जिसका भौतिक तथा नैतिक प्रभाव शान्ति तथा युद्ध दोनों में से, जिसके चाहे उसके पक्ष में फैसला करा सकता है.....उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत रूस अथवा अमेरिका किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। शान्तिपूर्ण तटस्थता न तो सम्भव ही है और न नैतिक दृष्टि से वाछनीय ही। क्या पं० नेहरू जीवित भारतीयों में सबसे महान होने तथा गांधी जी के उत्तराधिकारी होने के नाते अपने प्रभाव एवं प्रतिष्ठा द्वारा मध्यस्थ का कार्य नहीं कर सकते, और क्या

इस प्रकार वे करोड़ों मूक मानवों की शान्ति की आवाज को बुलंद नहीं कर सकते ? आज ससार के प्रथम श्रेणी के नेताओं में नेहरू जी के अतिरिक्त कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके व्यक्तित्व का इतना मैत्री पूर्ण प्रभाव दुनिया पर पड़ सके । किंकर्तव्यविमूढ़ राष्ट्रों में सम्पर्क स्थापित कराने के मार्ग को ढूँढ़ निकालने और उसका नेतृत्व करने का साहस पं० नेहरू में ही है ।”

१५ अक्टूबर को तीसरे पहर श्री मथाई और श्री वाजपेयी के साथ पं० नेहरू पेरिस पहुँचे तथा वहाँ विश्व के प्रमुख व्यक्तियों से वार्तालाप किया । उसी दिन रात को अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी जार्ज मार्शल से उन्होंने करीब २॥ घंटे तक बात की । दोनों राजनीतिज्ञों की यह पहली ही भेंट थी । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दोनों राजनीतिज्ञों के बीच हुई वार्ता तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से ही सम्बंधित रही होगी ।

दूसरे दिन पं० नेहरू सोवियत रूस के उप-परराष्ट्र मंत्री श्री विशिन्सकी, फ्रांस के राष्ट्रपति विनसेट अरियल, फ्रांस के परराष्ट्र मंत्री राबर्ट शूमेन और चीन के परराष्ट्र मंत्री डा० वांग शीह-चीह से उनके निवास स्थानों पर मिले तथा विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया । पं० नेहरू के पेरिस के इस छोटे से प्रथम सरकारी आगमन ने यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी आशाएँ उत्पन्न कर दी थीं । ससार के राजनीतिज्ञों पर पं० नेहरू के व्यक्तित्व और त्याग की छाया पड़ चुकी थी । पं० नेहरू भारत के प्रधान तथा वैदेशिक मंत्री के रूप में वहाँ ऐसे समय पहुँचे थे जब कि भारत ने अशान्ति पूर्ण विश्व में अपूर्व शान्ति के साथ रक्तहीन क्रान्ति द्वारा अपनी ऐतिहासिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी और जब कि विश्व की कुटिल कूटनीति के कालकूट को पानकर मानव मात्र की शान्तिपूर्ण रक्षा के लिए ऐसे ही किसी ‘शिव’ की आवश्यकता थी ।

१८ ता० को पं० नेहरू, श्री वाजपेयी, श्री मथाई, बहन श्रीमती

विजयालक्ष्मी पण्डित तथा उनकी दो पुत्रियों चन्द्रलेखा और नयनतारा के साथ लंदन वापस लौट आये । उन्होंने उस दिन ब्रिटिश परराष्ट्र मन्त्री मि० बेत्रिन के यहाँ जलपान किया, तथा १॥ घंटे तक अन्य राष्ट्रों के साथ मविष्य में भारत के सम्बन्ध के विषय में बात करते रहे । इसके पश्चात् वे एम्पायर पार्लियामेन्टरी ऐसोसियेशन द्वारा आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए जो आगत प्रधान मन्त्रियों के सम्मानार्थ किया गया था ।

१९ अक्टूबर को भारतीय विद्यार्थियों की ओर से इंडिया हाउस में नेहरू जी का शानदार स्वागत हुआ । प० नेहरू ने वहाँ भाषण देते हुए कहा कि “हम प्रगति पर हैं, और हमारी प्रगति, हमें विश्वास है कि, हमें इससे भी अच्छी अवस्था तक ले जायेगी । भारत में अभी हमारे समक्ष अनेक कार्य करने को अवशेष हैं । इसमें सन्देह नहीं कि हमने गलतियों की हैं और भयंकर भूले भी, लेकिन हमने बहुत-सी सफलताये भी प्राप्त की हैं ।.....वह समय निकट आ रहा है जब शासन का भार आप लोगों के कंधों पर डाला जायेगा । भारत के विशाल ढाँचे में भाग लेना और नवीन भारत का निर्माण करना अत्यन्त कठिन कार्य है, जिसमें लगाना आप सभी का कर्तव्य है ।.....वास्तव में व्यक्ति छोटे-छोटे कार्यों को भी अधिक से अधिक उत्तम ढंग से करने पर ही बड़ा होता है । कार्य की अच्छाई-बुराई, छोटाई-बड़ाई का कुछ मूल्य नहीं है । अतः हमें कभी यह न सोचना चाहिए कि जो कार्य हमें सौंपा गया है वह अधिक महत्त्व नहीं रखता, अतः उसे हमें न करना चाहिए । चाहे लिफाफे पर टिकट लगाने का ही कार्य क्यों न हो, उसे महत्वहीन न समझना चाहिए । वह व्यक्ति जो छोटी-छोटी चीजों को महत्व-शून्य समझ कर उपेक्षा की दृष्टि से देखता है वह स्वयं अपने जीवन को मूल्यहीन बना लेता है । भारत में हमें अनेक कार्य करने हैं जो तभी हो सकते हैं जब हम एक साथ मिलकर अपनी शक्ति का उपयोग करें । मैं यह नहीं कहता कि सभी व्यक्तियों के विचार एक से होने चाहियें, किन्तु राष्ट्र के हित सभी व्यक्तियों का लक्ष्य और उद्देश्य एक-सा होना चाहिए ।

यदि एक लक्ष्य रख कर हम सब मिल कर कार्य करेंगे तो उसे पूर्ण करके ही छोड़ेंगे ।”

२० अक्टूबर को बृटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्री एटली के सरकारी निवास स्थान, १० डाउनिंग स्ट्रीट में ५० नेहरू और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री खियाकनअली ख़ाँ में कार्भार की समस्या के सम्बन्ध में बात-चीत हुई। वार्तालाप में बृटिश परगट्र मंत्री श्री वेविन भी उपस्थित थे। मि० एटली मध्यस्थ थे, परन्तु बहुत प्रयत्न के पश्चात् भी समझौते का कोई मार्ग निकलता नजर न आया।

२१ अक्टूबर को भारतीय हाई कमिश्नर श्री नेनन द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में हजारों श्रोताओं के बीच बोलते हुए ५० नेहरू ने कहा, “मैं नहीं समझता कि भविष्य में किसी युद्ध की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि अन्त में विश्व को नहाना गांधी के सिद्धान्त को स्वीकार करना होगा। गजनीति के क्षेत्र में हमें कभी-कभी बड़ी बुराइयों को गंजने के लिए छोटी बुराइयों को स्थान देना पड़ता है तथा समझौता करना पड़ता है। भारतीय स्वतंत्रता एक सगृहणीय परिवर्तन है। इसने बृटिश और भारतीय जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है। भारत में अब भी बहुत से रुढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, इसी प्रकार बृटेन में भी कुछ लोग भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपनी घृणा तथा अप्रसन्नता प्रकट करने से बाज नहीं आते; परन्तु यह क्षणिक है। गाँधी जी कहते थे, “भारत किसी देश की जनता के विरुद्ध नहीं लड़ रहा है, बल्कि एक पद्धति के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है।”

२३ अक्टूबर की रात को ५० नेहरू अपने मित्र लार्ड नाउन्ट ब्रैटन के निवास स्थान, ग्राइलैंड के देहात वाले घर में उनके आग्रह पर विश्राम करने के लिए पहुँचे। पन्द्रह दिनों तक लन्दन में प्रधान मंत्रियों की कान्फ्रेंस तथा विभिन्न समारोहों के अवसरों पर उन्हें अठारह-अठारह बगैरे तक व्यस्त रहना पड़ा था।

२६ अक्टूबर को पं० नेहरू लन्दन से पेरिस के लिए रवाना हुए । हवाई अड्डे पर उन्हें विदा करने के लिए श्री नोएल बेकर, लार्ड माउन्ट-बैटन, श्रीयुत मेनन आदि व्यक्ति उपस्थित थे । नेहरू जी मंगलवार को पेरिस पहुँच गये । शुक्रवार को राष्ट्र-संघ के एक विशेष अधिवेशन में उनका भाषण होने वाला था । परन्तु जेनरल असेम्बली के अध्यक्ष डा० एवाट के अचानक अस्वस्थ हो जाने के फलस्वरूप वह कार्यक्रम उस दिन स्थगित कर दिया गया ।

पेरिस में पं० नेहरू ने संसार के प्रधान राजनीतिज्ञों से बातचीत की तथा पेरिस के रहने वाले भारतीयों से मिले । वे अमेरिकन रिपब्लिकन दल के नेता मि० डूलेज तथा उस दल के वैदेशिक सलाहकार श्री जान फास्टर से अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर देर तक बात करते रहे ।

फ्रान्स के नेता मो० शुमेन पं० नेहरू से अत्यन्त प्रभावित हुए, और डा० जुलियन हुवले ने उनके विषय में यह राय दी कि वे एक चमत्कारी पुरुष हैं, जो राजनीतिक गुत्थियाँ सुलझाते हुए गम्भीर वैज्ञानिक विषयों पर महत्त्वपूर्ण विचार कर सकते हैं ।

२१ अक्टूबर को फ्रान्स की इण्डियन-असोसियेशन का आतिथ्य ग्रहण करते हुए पं० नेहरू ने कहा, “यूरोप विश्व का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और आवश्यक भाग है अवश्य; परन्तु वही सम्पूर्ण संसार नहीं है, इस तथ्य को आज के पाश्चात्य राजनीतिज्ञ भुला देते हैं । पाश्चात्य देशों के प्राधान्य का अब वह युग समाप्त हो गया है और जहाँ कहीं यह प्रभुता अब भी अवशिष्ट है, वह भी बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी: लेकिन यह तथ्य अमेरिका और यूरोप के लोगों के दिमाग में नहीं बैठता । यही कारण है कि विश्व या विश्व की समस्याओं पर विचार करने में उनका दृष्टि-त्रिन्दु गलत होता है । यूरोप में जो कुछ होता है उसका प्रभाव एशिया पर पड़ेगा, और जो कुछ एशिया में होता है उसका यूरोप पर । हिन्दुस्तान कठिनाइयों से मरा रहने पर भी जीवनी-शक्ति से परिपूर्ण है । वह प्राचीन है पर अब भी उसमें यौवन का वही आवेग है । उसने

अनेक भूले कौं, और ठोकर खाकर गिरा मी; लेकिन फिर गिरकर उठने की उसमें ताकत थी। हाल में ही विजय महायुद्ध की ज्वाला में तप चुका है; परन्तु फिर भी उसने कुछ शिक्षा ग्रहण न की। आजकल की राजनीति में गलत और बुरे कर्मों के करने की प्रतिद्वन्द्विता की होड़ में हर राष्ट्र आगे बढ़ जाना चाहता है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है, और यदि वह प्रतिक्रिया बुरी है तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। मानव जाति के इस संकटकाल में यह स्मरण रखना होगा कि घृणा, हिंसा तथा गलत काम करने से लाभ नहीं होता। संसार आज बिन संकटों से गुजर रहा है, वे अतीत में संग्रह की हुई घृणा और हिंसा की प्रतिक्रिया का परिणाम है।”

संयुक्त राष्ट्र संघ की जेनरल असेम्बली के अध्यक्ष आस्ट्रेलियन पर-राष्ट्र मन्त्री डा० एवाट का निमन्त्रण स्वीकार कर भारत के प्रधान मन्त्री पं० नेहरू का भाषण ३ नवम्बर को संघ की असेम्बली में उस समय हुआ, जब मैक्सिको के उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद हो चुका था, जिसमें बड़े राष्ट्रों से अपील की गयी थी कि वे अपने मत-भेद मिटाने के लिए फिर से प्रयत्न करें। पं० नेहरू ने अपने भाषण में कहा, “आप का उद्देश्य स्पष्ट है, किन्तु उस उद्देश्य पर दृष्टि रखते समय बहुधा हम लोग छोटी-छोटी बातों में फँसकर इधर-उधर हो जाते हैं और वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। मैं जिस देश का निवासी हूँ उसने लम्बे पर शान्ति पूर्ण संघर्ष के पश्चात् अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। उस लम्बे संघर्ष में हमारे महान नेता ने हमें सिखलाया था कि हमें अपने उद्देश्य को ही नहीं, परन्तु उस उद्देश्य की प्राप्ति के साधनों को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। उद्देश्य तथा उस तक पहुँचने के साधन भी अच्छे होने चाहिए।”

“यह सब दो महायुद्धों के पश्चात् और उसके परिणाम स्वरूप बना है। इन से क्या शिक्षा मिली? निश्चित ही इस घृणा और हिंसा से शान्ति स्थापित नहीं हो सकती तथा अत्यन्त चमकीले-मड़कीले वादविवाद से हम

उस घेरे से नहीं निकल सकते । उससे निकलने के लिए हमें दूसरे मार्ग और साधन अपनाने होंगे ।

हम योरोपीय सस्कृति को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और योरोप कि समस्याओं को हम महत्त्व भी देते हैं, लेकिन विश्व योरोप से बड़ी चीज है । सिर्फ योरोप की समस्याएँ ही सम्पूर्ण विश्व की समस्याएँ नहीं कही जा सकती, एशिया में ऐसे बड़े खंड भी हैं, जिन्होंने अतीत में विश्व के मामलों में भले ही अधिक भाग न लिया हो, लेकिन आज वे जाग उठे हैं । उनकी जनता प्रगतिशील हो गयी है और उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

एशिया को आज भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्त्व प्राप्त है, और कल तो वह और भी बढ़ जायेगा । एशिया का कुछ भाग अभी भी स्वतंत्र नहीं है । आश्चर्य है कि जो कुछ हो चुका है उसके पश्चात् भी साम्राज्यवाद का अंत नहीं हुआ । हम पड़ोसी देशों के संघर्ष के साथ सहानुभूति रखते हैं । कोई भी शक्ति चाहे वह बड़ी हो या छोटी, यदि स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा उपस्थित करती है तो वह विश्व-शान्ति को क्षति पहुँचाती है ।.....”

३ नवम्बर की रात को ५० नेहरू पेरिस से मिश्र की राजधानी काहिरा के लिए रवाना हुए । वे वहाँ अरब सघ के मेहमान हुए । एक प्रेस-कान्फ्रेंस के समक्ष अपना विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “विश्व की समस्या एशिया को बाहर रख कर नहीं सुलझायी जा सकती । यदि हिन्दएशिया में, दूसरे देशों को दासत्व में रखने वाली शक्ति द्वारा और भी अधिक आक्रमणकारी कोई कार्रवायी की गई, तो भारत और विश्व में उसकी भयंकर प्रतिक्रिया होगी । वहाँ से साम्राज्यवाद और विदेशी आधिपत्य का मिटना आवश्यक है । पूर्व के देशों के निवासियों और नेताओं को एक दूसरे से मिलना तथा प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाना चाहिए ।”

(२५६)

५ नवम्बर को वे दिल्ली के लिए रवाना हुए, तथा ६ नवम्बर को
बल्डै होते हुए गोपहर ने वे दिल्ली के पालन हवाई अड्डे पर पहुँचे, जहाँ
स्युरिटी के लिए निर्वाचित अष्टक डा० इमरि सेतारनैक,
उपप्रधान मंत्री सरदार पटेल, तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी
आदि प्रमुख व्यक्ति स्वागतार्थ उपस्थित थे ।

७ नवम्बर को कश्चेत गयीं की विशेष बैठक में डॉ० नेहरू ने विदेश
में किये गये अपने कार्यों का वर्णन किया । उन्होंने व्यक्तार्थ कि न तो
प्रधान मंत्रियों को जाल्मन्स में ही और न वृद्धि प्रधान मंत्री इन्हीं के
आतिथी के द्वारा ही यह श्राव हो सका कि वृद्धि और भारत का भविष्य
ने किंचि प्रकार का सम्बन्ध रहेगा ।

८ नवम्बर को विधान-परिषद् की बैठक में अपनी ऐरोम-युग के
सम्बन्ध में भाग देते हुए नेहरू जी ने कहा कि मैंने वृद्धि-सम्बन्ध
सम्बन्ध के विषय में लखन में कभी कोई बात नहीं किया है; क्योंकि वह
एक ऐसा प्रश्न था कि कि पर विधान-परिषद् ही अपना निर्णय दे
सकती थी । उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ कह दिया है कि भारतीय
विधान-परिषद् अपनी इच्छानुसार सब कुछ करने के लिए स्वतन्त्र है,
और लेखा से कोई भी निर्णय कर सकती है । मैंने यह भी कहा कि
हम सभी देशों के साथ नैतिकता का सम्बन्ध चाहते हैं । हम इंग्लैंड
और राष्ट्र-मण्डल से भी अपना सम्बन्ध पूर्ण संतुष्ट बनाये रखते हैं ।



प्रधान मंत्री नेहरू का अमेरिका में पदार्पण

पं० जवाहरलाल नेहरू की अमेरिका-यात्रा एक ऐसी घटना थी जिसने साधारणतः सारे विश्व की और विशेषतः भारत की राजनीति को प्रभावित किया था। आज अमेरिका संसार का वह राष्ट्र है जो विश्व के रंगमंच पर अत्यन्त महत्वपूर्ण अभिनय कर रहा है। उसकी शक्ति, उसकी सम्पन्नता और उसकी राजनीति, उसे जगत् के बहुत बड़े भाग का नेतृत्व प्रदान किये हुए है। पं० नेहरू का अमेरिकन राष्ट्र द्वारा आमंत्रण, और उनका वहाँ जाना, एशिया, अफ्रिका और योरोप के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के लिए, उनकी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार हर्ष, आशा, आशंका और थोड़ा सदेह का कारण बन गया था, तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इस यात्रा से विभिन्न क्रिया तथा प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुई थीं।

भारत की स्वतंत्रता और उसके उत्थान ने संसार के आधुनिक स्वरूप को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस देश की ओर आज महती शक्तियों की दृष्टि लगी हुई है, तथा एशिया और अफ्रिका की पिछड़ी तथा अशक्त जातियाँ इसकी ओर आशा से देख रही हैं। अतः भारतीय नीति तथा उसके प्रयोजन पर सभी राष्ट्रों की सतर्क दृष्टि होना स्वाभाविक ही है।

१९४९ के अक्टूबर मास में भारत के प्रधान मंत्री का अमेरिका में जैसा भव्य स्वागत हुआ उसमें न केवल दो महान राष्ट्रों—अमेरिका और भारत—के पारस्परिक संहार्द के निरूपण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग ही समाविष्ट है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय कण्ठमकल को बनाये रखने वाले कुछ जटिल प्रश्नों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने

वाले मौलिक तत्वों का भी निरूपण है। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक ऐसी राजनीतिक समस्याएँ उठ चुकी थीं जिनमें भारत और अमेरिका समान रूप से दिलचस्पी ले रहे थे। अनेक विषयों में—उदाहरणतः काश्मीर तथा हैदराबाद की समस्या में—दोनों के दृष्टिकोण में स्पष्ट निष्ठा तथा विरोध प्रकट हो रहा था। अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघ में पाकिस्तान के अनुचित भारत-विरुद्ध कार्यकलापों का परोक्ष रूपसे पक्षपात पूर्ण समर्थन कर रहा था।

अमेरिका की प्रशान्त-क्षेत्र एवं सुदूर-पूर्व सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में भी भारत और अमेरिका के दृष्टिकोण में अंतर था। फिलिपाइन के तत्कालीन राष्ट्रपति ने प्रशान्त-संघ-योजना प्रस्तुत की थी। प्रशान्त तथा सुदूर-पूर्व में कम्युनिस्टों का नुकाबला करने के उद्देश्य से अमेरिका इस योजना में विशेष दिलचस्पी ले रहा था। एशियाई देशों के मामले में सैनिक स्तर पर हस्तक्षेप की यह योजना भारत को पसन्द न थी। लाल चीन के सम्बन्ध में भारत और अमेरिका के दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट था। चिन्तु भारत की इच्छा के प्रतिकूल उसका नाम जर्बर्त्ती अन्य राष्ट्रों के साथ इन सब योजनाओं के समर्थन में प्रचारित किया जा रहा था, यद्यपि भारत-सरकार ने इसका समय-समय पर पूर्ण खंडन भी किया था।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक दूसरे के विरोध में जड़न उठाने के पश्चात् भी भारत की आर्थिक प्रगति के सम्बन्ध में अमेरिका और भारत के दृष्टिकोण में विशेष अन्तर न था। सम्मान-जनक शर्तों पर ऋण अथवा अन्य प्रकार से दी गयी अमेरिकन आर्थिक सहायता स्वीकार करने के लिए भारत तैयार था। अमेरिका भी अपनी पूँजी भारत के व्यावसायिक क्षेत्र में लगाने का सकेत कर चुका था। विदेशी पूँजी की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए पं० नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि विदेशी पूँजी राष्ट्रीय विकास-विषयक हमारी योजनाओं तथा कार्यों में अड़क न होगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति डून्न द्वारा अनुन्नत राष्ट्रों के विकासार्थ आयोजित चतुःक्षेत्रीय-योजना से भी भारत

विशेष रूप से लाभान्वित होना चाहता था। इन सभी घटनाओं से आवृद्ध पं० नेहरू का अमेरिका-प्रस्थान विशेष राजनीतिक तथा आर्थिक महत्व रखता था।

पं० नेहरू के वाशिंगटन-आगमन के पूर्व से ही प्रमुख अमेरिकन समाचार-पत्र उनके विषय में विशेष लेख, संपादकीय आदि प्रकाशित करने लगे थे। 'वाशिंगटन पोस्ट' ने उनका विश्व नागरिक के रूप में परिचय देते हुए लिखा था कि पं० नेहरू के आगमन से "पूर्व और पश्चिम का अद्भुत मिलन (Dramatic meeting) होगा।...प्राचीन भारत और अर्वाचीन अमेरिका, दोनों यह महसूस कर रहे हैं कि एक के लिए दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है।" 'न्यूयार्क टाइम्स' ने पं० नेहरू की लोक-प्रियता का उल्लेख करते हुए लिखा था, 'यदि किसी की लोक-प्रियता उसके अपने देश के निवासियों के स्वेच्छाप्रेरित सहयोग में ओंकी जा सकती है तो अमेरिकन जनता प्रथम बार विश्व के सर्वाधिक लोक-प्रिय व्यक्ति का दर्शन करेगी।' इसके अतिरिक्त उसने लिखा था, "नेहरू जी को जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह विश्वास करता है कि भारत की आवाज को सशक्त बनाने के प्रयास में भ्रातृ-भाव के उस दर्शन से विश्व को प्रभावित करने की इच्छा निहित है, जो भारत की प्राचीन संस्कृति की देन है और जिसे गांधी जी ने पुनरुज्जीवित किया।" सम्प्रति, अमेरिका की भूमि पर पं० नेहरू का पैर पडने से पूर्व उनके प्रति साधारण जनता में जो उत्सुकता, कौतूहल और श्रद्धा समाचार-पत्रों ने उत्पन्न की, वह वाद में उनके विगट् स्वागत के रूप में पूर्णतः स्पष्ट हो गयी।

अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ट्रूमन के निजी वायुयान 'इण्डिपेण्डेन्स' पर आरूढ़ हो, ११ अक्टूबर सन् १९४९ में पहली बार पं० नेहरू ने अमेरिका की स्वतंत्र और स्वस्थ भूमि पर पैर रखा। हवाई अड्डे पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ स्वतंत्र नागरिकों के महादेश के राष्ट्र-नायक के रूप में आपका स्वागत किया। सैनिक ब्रेन्ड द्वारा आयोजित 'जन मन गग.....' के राष्ट्रीय वादन के बीच अमेरिका की

‘थर्ड इनफैन्टरी रेजिमेन्ट’ ने १९ तोपों से आपका अभिवादन किया । पं० नेहरू ने उसी समय संक्षेप में अमेरिकावासियों के प्रति अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कहा, “पारस्परिक लाभ तथा मानव जीवन के कल्याण के लिए पश्चिम और पूर्व के देश मैत्रीपूर्ण एवं लाभजनक सहयोग के आधार पर कई प्रकार से मिल-जुल कर कार्य कर सकते हैं ।” इसके पश्चात् उन्होंने अमेरिकन सैनिकों द्वारा प्रस्तुत ‘गार्ड आफ आनर’ का निरीक्षण किया ।

इन सब शिष्टाचारों के सम्पन्न होने के पश्चात् पं० नेहरू अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनके निवास-स्थल व्हाइट हाउस पहुँचे । सर्व प्रथम आधुनिक अमेरिका के उच्चायक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तथा जेफरसन की समाधि पर अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने के पश्चात् उन्होंने ट्रूमन द्वारा आयोजित प्रीतिमोज में भाग लिया जिसमें अमेरिका के सभी उच्चतम अधिकारी तथा नागरिक उपस्थित थे । इसके पश्चात् उन्होंने अपना निवास स्थानान्तरित कर भारतीय दूतावास में आश्रय लिया ।

ता० १२ को भारतीय प्रधान मन्त्री ने अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन की समाधि पर पुष्पाञ्जलि अर्पित की । इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य अमेरिकन शहीदों की महत्वपूर्ण समाधियों पर भी जाकर अपनी ओर से तथा भारत की ओर से श्रद्धाञ्जलि अर्पित की । इसी दिन तत्कालीन अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री श्री अचेसन दम्पति की ओर से आयोजित प्रीतिमोज में भी उन्होंने भाग लिया, तत्पश्चात् अमेरिका-स्थित भारतीयों तथा भारतीय छात्रों से मिले । इसके अतिरिक्त उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति श्री ट्रूमन से काश्मीर के सम्बन्ध में वार्तालाप भी किया ।

भारत-अमेरिका के पारस्परिक सम्बन्ध के इतिहास में १३ अक्टूबर सन् १९४९ का दिवस अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसी दिन अमेरिकन ‘प्रतिनिधि सभा’ में वक्तव्य देते हुए पं० नेहरू ने भारतीय नीति तथा उद्देश्यों को उनके समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट किया था । “आज विश्व दो शक्ति गुटों में विभाजित है । एक आग्ल-अमेरिकन गुट तथा दूसरा सोवियत रुस

का गुट्ट । पर भारत इनमें से किसी ढल से अपना सम्बंध स्थापित नहीं करना चाहता । वह भ्रातृत्व चाहता है, मैत्री चाहता है और चाहता है मानव समाज की स्वतन्त्रता ।.....स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने पर, न्याय के संकटापन्न होने पर और आक्रमण की दशा में न तो हम तटस्थ रह सकते हैं, न रहेंगे ।”

इसके पश्चात् पं० नेहरू तथा श्री ट्रूमन एवं परराष्ट्र मंत्री श्री अचेसन ने महत्वपूर्ण, गम्भीर राजनीतिक वार्ता की । इस वार्ता के पूर्व पं० नेहरू ‘नेशनल गैलरी आफ आर्ट’ का निरीक्षण कर चुके थे ।

नेहरू जी ने नेशनल क्लब में अपने सम्मान में आयोजित भोज के अवसर पर लगभग ७०० पत्रकारों के समक्ष भाषण देते हुए कहा, “भारत के शक्तिशाली व्यक्तित्व को मान्यता दी जानी चाहिए, तथा एशिया में उसका जो स्थान बन रहा है उसे उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता ।” भारतीय सस्कृति की सारगर्भित विवेचना करते हुए उन्होंने कहा, ‘अनेकता में एकता ही भारतीय सस्कृति की विशेषता है ।’ वही उन्होंने एशियाई उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए जोरदार अपील भी की । उन्होंने कहा ‘भारत एशियाई उपनिवेशों को परतंत्रता के बंधन से उन्मुक्त राष्ट्रीयता के विशुद्ध वातावरण में विकसित होते देखना चाहता है । वह इन देशों की जनता का शोषण और उत्पीड़न वर्दास्त नहीं कर सकता । हिन्द-एशिया, हिन्द-चीन और अन्य एशियाई उपनिवेशों की जनता में भारत की विशेष दिलचस्पी है ।” इसके अतिरिक्त पं० नेहरू ने भारत-अमेरिकी-आर्थिक-सम्बंध का भी विवेचन करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी भौतिक सुविधा के लिए अपनी किस्मत का सौदा नहीं करेगा ।

१५ अक्टूबर को पं० नेहरू अमेरिकन रक्षामंत्री श्री लुई जानसन के साथ न्यूयार्क पहुँचे । यहाँ उन्होंने फ्रेन्कलिन रूजवेल्ट की समाधि पर पुष्पाञ्जलि अर्पित की तथा श्रीमती रूजवेल्ट से वार्तालाप किया । यहाँ से लौटने के पश्चात् पं० नेहरू ने अमेरिका के प्रसिद्ध पत्रकारों से विभिन्न

विषयो पर वार्तालाप किया। शाम को श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित ने अपने प्रिय भ्राता को आमंत्रित किया। स्वागत-समारोह में अमेरिका के प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार एवं राजनीतिज्ञ उपस्थित थे।

१७ अक्टूबर को पं० नेहरू जनता के अपूर्व स्वागत के बीच से होते हुए न्यूयार्क टाउनहाल पहुँचे, जहाँ नगर के मेयर तथा अन्य उच्च अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मेयर के स्वागत भाषण का उत्तर देते हुए नेहरू जी ने आगा व्यक्त की थी, “विश्व में शान्ति और स्वतंत्रता के लिये, अमेरिका और भारत, दोनों देश पारस्परिक सहयोग की भावना से कार्य करेंगे।” आब ही उन्होंने ‘सिटी और कंट्री’ स्कूल के छोटी कक्षाओं के बालकों से मिलकर उनसे वार्तालाप किया तथा उनके बातों का जवाब देते हुए उनका अमिनन्दन-पत्र स्वीकार किया।

‘डाक्टर आफ ला’ की उपाधि से पं० नेहरू को विभूषित करने के उद्देश्य से १८ अक्टूबर को कोलम्बिया-विश्वविद्यालय में विशेष समावर्त्तन समारोह का आयोजन हुआ। उस दिन असंख्य बुद्धिजीवियों के बीच उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, “भारत की परराष्ट्र नीति ‘शान्ति की खोज’ के प्रयास पर आधारित है। यह ‘निषेधात्मक तथा तटस्थ नीति’ नहीं है; ‘यह निश्चयात्मक और ओजस्विनी’ है। इसका उद्भव भारत के अपने स्वातंत्र्य-संग्राम और महात्मा गांधी की शिक्षा से हुआ है।” इसी भाषण में उन्होंने कहा था, “जब मानव की स्वतंत्रता तथा उसकी शान्ति संकटापन्न होगी, हम तटस्थ नहीं रह सकते। उस समय तटस्थ रहने का अर्थ होगा उन आदर्शों के प्रति विश्वासघात जिनका हम समर्थन करते हैं तथा जिन्हें हम मूर्त रूप में देखना चाहते हैं।” विश्व-विद्यालय के कुलपति ने अपना स्वागत-भाषण पढ़ने के पश्चात्, प्रथानुक्रम उन्हें वह सम्मानित डिप्लोमा प्रदान किया।

१९ अक्टूबर को भारत-अमेरिकी-आर्थिक-सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए, ओवरसीज प्रेस क्लब में पं० नेहरू ने अपना वक्तव्य दिया, “भारत के विकास-कार्यों में काफी निजी अमेरिकन पूँजी लगायी जाने के कार्य में

मैं 'आर्थिक साम्राज्यवाद' का संकट निश्चित नहीं मानता ।" उसी दिन अमेरिकन-प्रेस-संवाददाता-संघ के समक्ष अपना विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण मविष्यवाणी की थी, "मार्क्सवादी और पूँजीवादी समाज अधिक दिनों तक साथ नहीं रह सकता । अंततोगत्वा एक के द्वारा दूसरे का अंत होगा ही ।" उनके कथनानुसार, "जो समाज मानव-जाति के भौतिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है, अंततः उसकी ही विजय होती है ।" एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था, "मैं विश्व को एक सूत्र में आवद्ध देखना चाहता हूँ, लेकिन यह नहीं चाहता कि सब एक से हो जाये । विभिन्नताओं से भरा-पूरा यह विश्व मुझे अच्छा लगता है । मुझे आशा है कि एकता के बावजूद मानव-स्वभाव में वर्तमान मूल्यवान् अनेकता भी कायम रहेगी ।" हिन्दएशिया, और हिन्दचीन के प्रश्नों के उत्तर में आपने कहा, "एशिया में विदेशी राष्ट्रों की औपनिवेशिक सत्ता समाप्त होनी चाहिए और वह समाप्त होकर ही रहेगी ।" इसी दिन पं० नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ की संरक्षण-समिति में भी भाषण दिया, तथा इस विश्व-संस्था में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, "राष्ट्र संघ भूत तथा वर्तमान के संघर्षों के बीच की कड़ी है । संसार को सदैव ऐसी संस्था की आवश्यकता रही है ।"

२० अक्टूबर को पं० नेहरू ने अमेरिकन-परराष्ट्र-व्यापार-मंडलों द्वारा आयोजित स्वागत-भोज में भाग लिया । इसमें उन्होंने भारत में अमेरिकन पूँजी का स्वागत करते हुए उसकी सुरक्षा तथा उसके लाभ की मान्यता के विषय में आश्वासन दिया । यहाँ उन्होंने भारत की भूत तथा मावी आर्थिक स्थिति का स्पष्ट चित्रण भी किया ।

२१ अक्टूबर को पं० नेहरू सदल-ब्रल बोस्टन पहुँचे । बोस्टन ! अमेरिका के स्वतंत्रता-संग्राम का पहला क्षेत्र जिसने इंगलैंड के सत्तापूर्ण गिकंजों से नवनिर्मित अमेरिकन राष्ट्र का परित्राण किया था । स्वागत-समाराह के पञ्चात् वे हारवर्ड-विश्वविद्यालय में पहुँचे, उसी दिन अनेक संस्थाओं का

निरीक्षण करने के पश्चात् सायंकाल में एक भोज में उन्होंने वहाँ के प्रधान मंत्री से गम्भीर वार्तालाप किया।

अभ्यर्थना एवं वंदना के बीच पं० नेहरू तीन दिनों तक कनाडा में भी रहे। यहीं उन्होंने विश्व-विख्यात नियाग्रा-जल-प्रपात की अपूर्व शोभा का भी निरीक्षण किया था। २४ अक्टूबर को, अपने आगमन के द्वितीय दिन, पं० नेहरू ने कनाडा की ससद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष अपना सारगर्भित वक्तव्य दिया। 'एशिया में पुनर्जागरण' का ऐतिहासिक क्रम ही उनके भाषण का प्रधान विषय था, "एशिया, जो महाद्वीपों का जनक है, और जिसकी गोद में ऐतिहासिक सभ्यताओं का विशाल भाग फला-फूला और समृद्ध हुआ है, आज फिर जाग उठा है। नव प्रातः स्वतंत्रता का अम्युदय प्रभूत सा है; क्योंकि पिछली दो शताब्दियों से उसकी प्रगति रोक दी गयी।" "एशिया का तथाकथित विद्रोह पश्चिम के कुछ राष्ट्रों के दम्भ और अत्याचार के बरुद प्रार्चान और स्वाभिमानियों की जायज चेष्टा है।.....हमारा यह विश्वास है कि जब तक एशिया की आधारभूत समस्याएँ हल न होंगी तब तक विश्व-शान्ति सम्भव नहीं है।" इस भाषण में नेहरू जी ने उपनिवेशवाद की धाजियों उड़ायीं, उनकी उस चेतावनी की साथकता आज स्पष्टतः नजर आ रही है। कोरियाई शान्ति-वार्ता और हिन्दुर्चान सम्बन्धी विराम-संधि-वार्ता में भारत का योगदान एशिया में उपनिवेशवाद को कायम रखनेवाली शक्तियों को चुनौती देता हुआ उसके बीतते हुए युग की असांस्कृतिक कामना को विफल सिद्ध करने में समर्थ हुआ है।

कनाडा को अपना संदेश सुनाने के पश्चात् पं० नेहरू २६ अक्टूबर को पुनः अमेरिका के शिकागो नगर में लौट आये। यहीं उन्होंने अनेक संस्थाओं में वक्तव्य देने के पश्चात् विकसित अमेरिकन वैज्ञानिक कृषि का भी सर्व प्रथम निरीक्षण किया। अपराह्न में उन्होंने शिकागो-विश्वविद्यालय में जो उपस्थित हो भाषण दिया। यहाँ विश्व-शान्ति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व-शान्ति केवल महात्मा गांधी के सिद्धान्तों

पर चलकर ही स्थापित हो सकती है। युद्ध से शान्ति का स्वप्न देखना भूल है। अहिंसा ही शान्ति का मार्ग है। शिकागो में पं० नेहरू ने भारतीय छात्रों द्वारा आयोजित अनेक समारोहों में भी भाग लिया।

२८ अक्टूबर को पं० नेहरू वायुयान द्वारा टेनेसी वैली क्षेत्र का निरीक्षण करने नाक्सविले पहुँचे। टेनेसी नदी के पार्व्व में स्थित यह घाटी वह स्थान है जिसने आधुनिक वैज्ञानिक युग के साधनों से सम्पन्न होकर अमेरिका के बहुत बड़े भू-भाग का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया है। टेनेसी-घाटी-प्रशासन-योजना विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तथा बड़ी नदी-घाटी योजना है।

पश्चिमी वर्जीनिया के पहाड़ी इलाके ह्वाइट सलफर स्प्रिंग्स में एक दिन आराम करने के पश्चात् नेहरू जी रक्षामंत्री लुई जानसन के वायुयान पर सवार होकर ३० अक्टूबर को सैनफ्रान्सिस्को पहुँचे। सैनफ्रान्सिस्को में ही संयुक्त-राष्ट्रसंघ के घोषणा-पत्र पर विश्व के राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था। हवाई अड्डे पर नागरिकों तथा अधिकारियों की जयध्वनि के बीच छः फौजी बैण्डों ने पहले 'जन मन गण...' की धुनि प्रसारित की, तत्पश्चात् अमेरिकन राष्ट्रीय गीत 'स्टार स्पागल्ड बैनर-.....' की।

३१ अक्टूबर को नेहरूजी ने कैलिफोर्निया-विश्वविद्यालय के 'ग्रीक थियेटर' में लगभग दस हजार श्रोताओं के समक्ष अपना सारगर्भित भाषण दिया। भारत की वैदेशिक नीति पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त उन्होंने यहाँ यह भी कहा, "यदि मानव-समाज का हित करना है तो विश्व के आर्थिक संकटों को दूर करना आवश्यक होगा। वर्तमान आर्थिक विषमता ही समाज की सब बुराइयों की जड़ है। यदि हम शान्ति-स्थापन करना चाहते हैं तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम शान्त बने रहें, न कि युद्ध की तैयारी करें। शान्ति अहिंसा से ही स्थापित की जा सकती है, हथियारों से नहीं।"

१ नवम्बर को पं० नेहरू अमेरिकन-व्यापार-मंडल के आमंत्रण पर वहाँ उपस्थित हुए। आज के युग में राजनीति और अर्थ का गहरा संबंध

है। राजनीति ने व्यापार पर और व्यापार ने राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। अमेरिका अपने व्यापार के कारण ही आज सर्वसम्पन्न तथा सर्व-शक्तिशाली राष्ट्र हो पाया है। इस भोज के अवसर पर अमेरिका के सर्वोच्च धनाढ्य व्यक्ति उपस्थित थे। यहाँ पं० नेहरू ने कहा, “अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने तथा विश्व में स्वतंत्रता एवं समता को सुतुलित करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। स्वतंत्रता और समता की आधारभूत समस्याओं के हल होने पर विश्व की समस्याएँ स्वतः हल हो जायेगी। मानवीय गुणों तथा मानवीय स्तर की रक्षा होना आवश्यक है।” उन्होंने आगे कहा, “विश्व की वर्तमान कठिनाइयों का प्रधान कारण मानवीय दृष्टिकोण का अभाव ही है। राजनीतिज्ञों का सीधा सम्बन्ध जनता से नहीं होता, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय निर्णयों में एक प्रकार की अमूर्त रिक्तता सी रहती है। मानवीय समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाने की जितनी आवश्यकता आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी।मानवीय बंधनों का परिज्ञान, और भय का मूलोच्छेदन ही कठिनाइयों से त्राण पाने का उपाय है। यह सोचना गलत है कि संस्कृति तथा विचार विभिन्नता के कारण ही लोग एक दूसरे के दुश्मन हैं। वैज्ञानिक और प्रावधिक प्रगति ने विश्व को विकासोन्मुख एकता का केन्द्र बना दिया है। इस क्रम पर अंकुश लगाने के बजाय उसे बढ़ावा देना चाहिए।”

इसी दिन पं० नेहरू को सैनफ्रान्सिस्को के मेयर की ओर से सम्मान-पत्र अर्पित किया गया। उन्होंने आगत नागरिकों के समक्ष पं० नेहरू का परिचय “मानव समाज की उन्नति के लिए सघर्षशील, महान और उत्साही नेता” के रूप में कराया। पं० नेहरू ने आभार प्रकट करते हुए कहा था, “अमेरिका द्वारा किया हुआ यह सम्मान मेरा नहीं अपितु भारत का है।”

सायंकाल सैनफ्रान्सिस्को-प्रेस-क्लब द्वारा आयोजित गोष्ठी में भाग लेकर पं० नेहरू ने वहाँ के पत्रकारों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया;

जिसमे उन्होंने पाकिस्तान द्वारा प्रचारित भ्रमपूर्ण आरोपो का खंडन करते हुए भारत की नीति पर प्रकाश डाला था । उन्होंने भारत की देशी रियासतो सम्बंधी नीति—विशेषतः काश्मीर तथा हैदराबाद से सम्बंधित उठाये गये कदमो—का समर्थन किया । उन्होंने पाकिस्तान द्वारा प्रचारित 'हिन्दू-मुस्लिम-भेद' तथा 'दो राष्ट्रों के सिद्धान्त' का भी खंडन किया ।

२ नवम्बर को पं० नेहरू वैनकु नगर पहुँचे । यहाँ के मेयर द्वारा आयोजित प्रीति-भोज मे अपना आभार प्रकट करते हुए उन्होंने भारत-कनाडा-सम्बन्ध, भारत की परराष्ट्र नीति और राष्ट्र मंडल मे रहने के भारत के निर्णय पर प्रकाश डाला । इसके अतिरिक्त उन्होंने ब्रिटिश कोलम्बिया युनिवर्सिटी मे भी अपना वक्तव्य दिया तथा एक प्रेस-कान्फ्रेंस मे भी भाग लिया । पं० नेहरू के दिये हुए इन वक्तव्यों से अमेरिका निवासियों तथा समाचार-पत्रों ने यह भविष्य वाणी की कि निकट भविष्य में भारत, अमेरिका तथा रूस के पश्चात् तीसरा महान राष्ट्र होगा ।

४ नवम्बर को पं० नेहरू ने मैसिडन पहुँच कर विसकासिन-विश्वविद्यालय मे सहस्रो छात्रों के समक्ष अपना भाषण दिया । विश्वविद्यालय के अध्यक्ष ने स्वागत करते हुए उन्हें उस देश का (भारत का) प्रतिनिधि बतलाया "जहाँ संस्कृति और विद्वत्ता का मूल्य सभी सासारिक वस्तुओं के मूल्य से ऊँचा समझा जाता है, और जहाँ विद्वान व्यक्ति ही महान माना जाता है ।"

पं० नेहरू इन पर्यटनो के पश्चात् पुनः न्यूयार्क लौटे । यहाँ उन्होंने प्रमुख निग्रो-नेताओं से भेंट की । वास्तव में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऐसे उन्नतिशील देश मे भी मानवीय अधिकारों की हत्या होती है । निग्रो जाति के साथ आज भी वहाँ अपमान पूर्ण व्यवहार होता है; यद्यपि उनकी जाग्रति के फलस्वरूप यह आज काफी कम हो गया है । 'नेशनल असोसिएशन फार दि एडवान्समेन्ट आफ कलर्ड पीपुल्स' की ओर से पं० नेहरू को निग्रो लोगो के अधिकारो के पक्ष मे बुलन्द आवाज उठाने तथा उनकी सेवाओं के लिए 'स्पीग्रान पदक' प्रदान किया गया ।

नियो-नेताओं द्वारा सत्कार किये जाने के पूर्व पं० नेहरू प्रिन्सटन विश्वविद्यालय में उपस्थित हो अपना माषण दे चुके थे, जिसका सारांश था, “यदि संस्कृति, साहित्य, सभ्यता तथा शान्ति की रक्षा करनी है, तो पूर्व और पश्चिम का भेद मिटा देना होगा। आखिर पूर्व के लोग भी मनुष्य हैं। अतः पूर्व-पश्चिम का नारा तुच्छता का द्योतक है। मनुष्य को उदार होना चाहिए। उसका हृदय इतना विशाल हो कि काले और गोरे के भेद का पता ही न चले।” इसी समय आपने जगत्-प्रसिद्ध विद्वान स्व० श्री अलबर्ट आइनस्टीन से भी विचार-विमर्श किया। पं० नेहरू को मैक्सिको आने का भी निमंत्रण मिला था, परन्तु समयामाव के कारण उन्होंने उसे अस्वीकृत कर दिया।

विशाल तथा ऐश्वर्यशाली अमेरिका का राजनीतिक प्रयोजनपूर्ण निरीक्षण करने के पश्चात् नेहरू जी स्वदेश वापस लौटे। उन्होंने अमेरिकन-पत्रकारों के समक्ष अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा, “मेरी समझ में इस यात्रा का और फाहे जो परिणाम हो, यह निश्चय है कि इससे भारत और अमेरिका के सम्बंध में व्यापक सुधार होगा। सुधार से मेरा अभिप्राय यह है कि दोनों देशों की मैत्री प्रगाढ़ होगी। एक दूसरे को समझने तथा इस दृष्टि से समस्याओं पर विचार करने की भावना बलवती होगी।”

अमेरिका के बड़े-छोटे पत्रों ने अपने-अपने अग्रलेख छाप कर पं० नेहरू के प्रति अपने विचार व्यक्त किये। किसी ने कहा, रूस-अमेरिका का झगड़ा उनके अतिरिक्त कोई नहीं सुलझा सकता। एक पत्र ने लिखा, एशिया का नेतृत्व निकट भविष्य में पं० नेहरू के हाथ में होगा तथा भारत ससार का एक महान राष्ट्र होगा। एक पत्र ने तो यहाँ तक लिखा कि पं० नेहरू के प्रतिनिधित्व में भारत ही साम्यवाद की बीमारी को दूर करने में सफल होगा। साम्यवादियों की आखिरी दिशा भारत होगी, जहाँ वे ठोकर खा कर असफल होंगे।



चीन और पं० नेहरू

पं० नेहरू आज विश्व-मानव के रूप में गान्ति स्थापन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वह विश्व तथा मानव के जीवित इतिहास में ज्वलंत दीप्त इतिहास है। जवाहरलाल आज न केवल भारत के बल्कि पृथ्वी के दोनों गोलार्धों के युग-पुरुष हैं। यदि भारत ने अचानक ही अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के बाद विश्व में अपना नैतिक स्थान बना लिया है, तो इसका श्रेय उनके दृष्टिकोण, निष्पक्षता और चातुर्य को है। आज हम यह कह सकते हैं कि भारत का अस्तित्व और भारत की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्ता पं० नेहरू के सत् प्रयत्न का ही फल है। वास्तव में पं० जवाहरलाल मूर्तिमान भारत हैं। मरदार पटेल के शब्दों में, “पं० नेहरू ने संकट-काल में देश का नेतृत्व किया और अपने महान् नेतृत्व द्वारा भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई।”

चीन और भारत दोनों महान प्राचीन राष्ट्र हैं। दोनों का सांस्कृतिक सम्बन्ध सदियों पुराना है। समय-समय पर दोनों ने अपने ज्ञान-आलोक का आदान-प्रदान कर एक दूसरे को दिव्य ज्योति से आलोकित एवं स्पष्टित किया है। आज भी दोनों राष्ट्रों के हृदय में ये पुरानी मधुर स्मृतियाँ हों, एक दूसरे की प्रेरणाओं की ज्वलंत प्रतीक बन दोनों को मित्रता सूत्र में आवद्ध देखना चाहती हैं।

चीन और भारत, दोनों देशों ने समान रूप से साम्राज्यवादियों के शोषण तथा पद-उलटन का वेदनापूर्ण अनुभव किया है; दोनों के हृदय में गुलामी के बाव और फफोले अभी सूखे नहीं हैं। जापानी ताकत से अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वर्तमान चीन के युद्ध स्तर में ३५ कोटि

भारतीय जनता की बुलंद आवाज मिलते हुए पं० नेहरू ने उसके न्याय-पूर्ण स्वातंत्र्य संग्राम का हमेशा समर्थन किया था तथा नैतिक साथ दिया था। जापानियों के इस बर्बर स्वार्थपूर्ण प्रयास में उन्हें उन प्रवृत्तियों का गला घुटता हुआ दिखलाई दिया था जो चीन के अभ्युदय की जननी है, और जिसका विकास बाद में एशिया का मस्तक ऊँचा करने वाला सिद्ध हुआ।

चीन और भारत दोनों देश एशिया के महान प्राचीनतम राष्ट्र हैं। प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से दोनों देश सम्पन्न हैं। दोनों देशों की जनशक्ति विशाल है। एशिया में इन दोनों देशों की मैत्री साम्राज्यवाद का जनाबा उठा देने वाली सिद्ध होगी, एवं उनका पारस्परिक ऐतिहासिक सम्बन्ध एशिया में भ्रातृभाव के विकास में सहायक होगा। इस महा प्रयास की नींव पंचशील के सिद्धान्तों पर आधारित होगी।

अक्टूबर सन् १९४९ में नये चीन की साम्यवादी गणतंत्र सरकार का अभ्युदय हुआ। चांग काई शेक की सरकार के पतन के पश्चात् माओत्से तुंग की सरकार की प्रतिष्ठापना हुई। अविवेकपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कट्टरियों तथा आलोचनाओं के पश्चात् भी नेहरू-सरकार ने नयी सरकार से भी अपना पूर्ववत् मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखा, क्योंकि भारत, सरकार नहीं बल्कि जनता की मूर्त भावनाओं, उनके विश्वास को अधिक महत्त्व देता था। वह उस सरकार से अपना निकट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए हमेशा प्रस्तुत था जिसे उसकी अपार जनता का सहयोग तथा मान्यता प्राप्त हो। चीन ऐसे महान राष्ट्र के अभ्युदय के क्रम की ओर दुनिया की सशंक आँखें लगी थी। विश्व के राष्ट्र यह जानना चाहते थे कि भारत साम्यवादी चीन की सरकार को मान्यता प्रदान करेगा या नहीं। भारत की नीति स्पष्ट थी। आर्थिक क्षेत्र में परमुखापेक्षी होते हुए भी भारत अपने नैतिक आधार को गिराकर, किसी विशेष राष्ट्र की स्वार्थपूर्ण गंदी, कूटनीतिक आँखों में प्रसन्नतापूर्ण चमक देखने की लालसा से ही आत्म-हनन कर एशिया में जो क्रान्तिकारी घटनाएँ घट रही थी उनकी उपेक्षा

नहीं कर सकता था। अतः प्रतिकूल परिस्थितियों की उपेक्षा करते हुए नेहरू-सरकार ने ३० दिसम्बर १९४९ को लाल चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता दे दी।

पं० नेहरू ने चीन को प्रमुता-सम्पन्न राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधान का पात्र मानते हुए सिर्फ मान्यता ही नहीं प्रदान की, अपितु उसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघ में महत्वपूर्ण तथा न्यायोचित स्थान दिलाने का भी उन्होंने प्रयत्न किया, किन्तु अमेरिका के स्वार्थपूर्ण गुटबंदी के कारण चीन वहाँ स्थान न पा सका। इससे क्षुब्ध हो पं० नेहरू ने कहा था, “सार्वभौमिकता के जिस सिद्धान्त को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ था उससे वह अलग हट गया है।..... यह उसी प्रवृत्ति का परिचायक है जिससे ‘लीग आफ नेशन्स’ का पतन हुआ।..... स्पष्टतः इस दृढ़ तथा शक्तिशाली राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता तथा स्थान न प्रदान किये जाने के कारण नयी समस्याएँ उत्पन्न हो गयी हैं।” सचमुच विश्व की गान्ति तथा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व के लिए यह घातक बात है।

चीन के पक्ष का हर स्थान पर जोरदार समर्थन करने, कोरिया के विध्वंसक युद्ध को विश्व-गान्ति तथा मानव-कल्याण के विरुद्ध समझ उसे बढ़ करने के प्रयत्न से, तथा कोरिया-युद्ध के बंदियों की बदला-बदली में अध्यक्ष-पद से एक तटस्थ राष्ट्र की भाँति निष्पक्ष तथा न्यायपूर्ण कार्य करने के फलस्वरूप, भारत की ओर से सगंका चीन अब उसे मित्र के रूप में देखने लगा है तथा उसके विशेष निकट आ गया है। भारत-स्थित सोवियत रूस के राजदूत के शब्दों में, “कोरिया का युद्ध समाप्त करने में भारत सरकार ने अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लिया है, यह असंदिग्ध है। एशिया के शान्तिपूर्ण निपटारे में भारत का जो भाग है उसे विस्मृत करना कठिन है।” स्वयं चाँनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने पं० नेहरू के गान्ति-प्रयास की सराहना की थी। यह मैत्री-सम्बन्ध १९५४ में तिब्बत की समस्या के हल-स्वरूप हुई भारत-चीन सन्धि से और भी अधिक दृढ़ हो गया।

चीन से सम्बन्धित समस्याओं के प्रति नेहरू जी की व्यापक दृष्टि से यह स्पष्ट हो गया है कि वे विश्व-शान्ति के लिए, एवं विशेष रूप से एशिया की शान्ति तथा एशियाई देशों के विकास के लिए, भारत-चीन की मैत्री तथा आपसी सहयोग को आवश्यक समझते हैं। यही कारण है कि उन्होंने भारत-चीन-मैत्री की दो हजार वर्ष पुरानी परम्परा को बनाये रखने का बराबर प्रयत्न किया।

नेहरू-सरकार की मित्रवत् नीति से अत्यधिक प्रभावित चीन के प्रधान मंत्री एवं परराष्ट्र मंत्री श्री चाओ एन लाई ने २५ जून सन् १९५४ को भारत में पदार्पण कर पारस्परिक मित्रता की शृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी। उनकी इस ऐतिहासिक यात्रा की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गहरी प्रतिक्रिया भी हुई थी। यह छिपी हुई बात नहीं है कि चाओ-नेहरू के हार्दिक मिलाप को अमेरिका ने, जो पाश्चात्य देशों की नीति का काफी हद तक नियंता है, संदेह की दृष्टि से देखा था। इस सम्मेलन के अवसर पर दोनों राष्ट्र—चीन और भारत—के प्रधान मन्त्रियों ने २८ जून सन् १९५४ को एक संयुक्त घोषणा प्रकाशित की थी; जिससे एशिया को बल प्राप्त हुआ तथा उसे कार्य के लिए एक नयी दिशा मिली। इस घोषणा के फलस्वरूप उसकी छिपी हुई संचित शक्ति निखर उठी तथा पश्चिमी राष्ट्रों की एशियाई राष्ट्रों के मामले में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति को गहरा धक्का लगा। एशिया की अंतरात्मा से उठी हुई इस पहली बुलंद आवाज ने पश्चिमी राष्ट्रों की नकेल को अपने हाथ में रखने वाले अमेरिका के कान खड़े कर दिये। चीन तथा भारत के इस संयुक्त रुख से असन्तुष्ट अमेरिका का प्रतिक्रियात्मक प्रतिवाद मनीला-समझौते में उपस्थित विपरीत सिद्धान्तों के रूप में प्रकट हुआ।

सितम्बर सन् १९५४ में आठ देशों के बीच मनीला-समझौता, दक्षिण-पूर्व-एशिया-प्रतिरक्षा-संगठन के नाम से सम्पन्न हुआ। इस समझौते के कूटनीतिक तात्पर्य से सतर्क भारत, चीन, बर्मा, लाos, हिन्दएशिया आदि प्रधान एशियाई राष्ट्रों ने इसमें भाग लेने से इन्कार करते हुए इसका

तीव्र विरोध किया। वास्तव में सन् १९४८ में अमेरिका के इशारे पर फिलीपाइन्स के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा प्रस्तुत प्रशान्त-संधि-योजना का ही परिवर्तित रूप मनीला-समझौता है। इस समझौते द्वारा अमेरिका का उद्देश्य एशियाई राष्ट्रों की राजनीति में कूटनीति पूर्ण हस्तक्षेप कर तथा उनमें फूट उत्पन्न कर एशिया की नवोदित शक्ति को कमजोर बनाते हुए अपनी महत्वाकांक्षा का उल्झ सीधा करना था। यथार्थतः मनीला-संधि सुरक्षा के बजाय अरक्षा तथा संदेह के वातावरण को जन्म देती हुई, दक्षिणी-पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के स्वअस्तित्व सम्बंधी मय तथा आशंका की स्थिति से लाभ उठाकर, पूर्व में मुनरो-सिद्धान्त की पुनरावृत्ति है। लगता है पश्चिम के शक्तिशाली राष्ट्र एकत्र फिर अपने पुराने साम्राज्यवादी नारे, “श्वेत मनुष्यों के पवित्र दायित्व” (White men’s Burden) तथा “उन्नत का अनुन्नत के प्रति कर्तव्य” (Big Brother Policy) के मथुर मायावी शब्द-जाल को बिछा कर एशिया महाद्वीप में, उसकी दुर्बलता से लाभ उठा कर, अपनी पकड़ और अपना प्रभाव-क्षेत्र फिर से स्थापित करना चाहते हैं।

चीनी गणतंत्र के प्रधान मंत्री श्री चाओ एन लाई का आग्रहपूर्ण निमंत्रण पाकर पं० नेहरू ने १९५४ के अक्टूबर में चीन की भूमि पर पदार्पण किया। इससे न केवल चीन-भारत-मैत्री के बन्धन ही दृढ़ हुए, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका गहरा असर पड़ा। जिन कारणों से पं० नेहरू की चीन-यात्रा महत्वपूर्ण मानी गयी है, उसका उल्लेख चीनी गणतंत्र के प्रधान मंत्री चाओ एन लाई तथा चीनी गणतंत्र के अध्यक्ष श्री माओत्से तुंग ने स्वयं अपने वक्तव्यों में किया है। जवाहरलाल के आगमन पर लाखों की संख्या में चीनी जनता ने हार्दिक उल्लास प्रकट करते हुए सड़क पर अनुशासित ढंग से एकत्र होकर उनका अभिनंदन तथा स्वागत किया था। मंचूरिया और दरेन स्थित चीन के इस्पात और नौसेना के कारखानों का निरीक्षण करने का अवसर चीन-सरकार ने नेहरू जी को दिया जबकि रूसियों के अलावा कोई अन्य विदेशी उन्हें नहीं देख सकता था।

पेकिंग में आयोजित एक मोर्चे के अवसर पर पं० नेहरू का स्वागत करते हुए चीन के प्रधान मंत्री चाओ एन लाई ने उनके प्रति अपने हार्दिक उद्गार व्यक्त किये थे । “हम पं० नेहरू से मली भौंति परिचित हैं । चीनी जनता के लिए यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उसे शान्ति की रक्षा के समान ध्येय में भारत जैसा मित्रता रखने वाला पड़ोसी, तथा प्रधान मंत्री पं० नेहरू जैसा महान मित्र मिला है । भारत और चीन दोनों ही एशिया की महान शक्तियाँ हैं । दोनों ही संसार के प्राचीन तथा साथ ही साथ तरुण देश हैं । दो हजार वर्षों से भी अधिक समय से भारत और चीन के बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बंध रहे हैं तथा इन दोनों के बीच युद्ध होने का उल्लेख इतिहास में कहीं नहीं मिलता ।

पं० नेहरू ने भी चीनी जनता तथा सरकार के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किया । उनकी मनोभावनाओं में यदि एक ओर दोनों देशों के प्राचीन ऐतिहासिक सम्बंधों की स्मृति छाई हुई थी, तो दूसरी ओर वर्तमान की आवश्यकताओं की ओर सकेत भी था । १९ अक्टूबर १९५४ को हवाई अड्डे पर चीनियों के बीच अपना हार्दिक उल्लास प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था, “मुझे आशा है कि चीन की मेरी यह यात्रा हमें एक दूसरे के और निकट लायेगी और हम शान्ति के लिए दृढ़ उत्साह से कार्य करेंगे ।”

२३ अक्टूबर को पेकिंग में आयोजित सार्वजनिक सभा में पं० नेहरू ने अतीत की सुखद स्मृतियों, वर्तमान के उत्तरदायित्व और भविष्य की कल्पनाओं का उल्लेख प्रभावशाली ढंग से किया था । चीन और भारत के पारस्परिक सम्बंध, और वर्तमान में इस सम्बंध के निरूपण में नेहरू की ऐक्य की दृष्टि से यह भाषण बहुत महत्वपूर्ण था । उन्होंने अपनी कृतज्ञता-यापन करने के पश्चात् कहा था, “मैं इस महान देश चीन में जो स्वयं एक छोटा सा संसार है, एक दूसरे महान देश से जो खुद भी एक छोटा सा संसार है आया हूँ । दोनों की जड़े अतीत में बहुत गहरी चली गयी हैं । इतिहास के आरम्भ से ही दोनों युग-युगान्तर में, विचार और

संस्कृति की अगणित बाह्य धाराओं को ग्रहण करते रहे हैं और उन पर अपने शक्तिशाली व्यक्तित्व की छाप डालकर उन्हें अपने रंग में रँगते रहे हैं ।.....चीन और भारत में हुए नये क्रान्तिकारी परिवर्तन, विषय वस्तु की दृष्टि से भिन्न होते हुए भी एशिया की नयी शक्ति के प्रतीक हैं ।.....”

“चीन और भारत का प्रभुता सम्पन्न देशों के रूप में उदय, तथा एशिया के अन्य देशों को प्राप्त स्वतंत्रता ने इस प्राचीन महा-द्वीप का नक्शा ही बदल डाला है । शक्तियों का वह पुराना संतुलन जिसके कारण एशिया पराधीन था, समाप्त हो चुका है और पीड़ा एवं संघर्ष के बीच धीरे-धीरे एक नया संतुलन पैदा हो रहा है ।”

“आज विश्व को एक महत्वपूर्ण चुनाव करना है—शान्तिपूर्ण प्रगति या युद्ध—इनमें से एक को उसे चुनना होगा । यह युद्ध पुराने तरह के युद्धों में न होगा बल्कि उससे बहुत अधिक बुरा तथा हानिकार होगा । यह हमारी पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकता है और मानव को पशु स्तर-तक गिरा सकता है ।”

“युद्ध को टालना ही काफी नहीं है । हमें युद्ध को जन्म देनेवाले कारणों को भी समाप्त करना है और शान्ति तथा सद्भावना के वातावरण को सक्रिय रूप से बनाना है ।.....हमें विरोध के इस चक्र से बाहर निकल कर अहिंसात्मक, शान्तिपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण सहयोग के आधार पर एक नया संसार बनाने का प्रयत्न करना होगा—एक ऐसा संसार जिसमें एक देश पर दूसरे देश का, एक जाति अथवा वर्ग पर दूसरी जाति अथवा वर्ग का न तो शासन होगा न शोषण ।”

“आज बड़े-बड़े राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध हैं ।.....लोग निःशस्त्रीकरण की बात करते हैं, लेकिन प्रत्येक राष्ट्र अपनी सैन्यशक्ति बढ़ा रहा है । युद्ध के नये एवं भयानकतम हथियार बनाये जा रहे हैं । यह शान्ति का रास्ता नहीं है । हमें यह मान लेना चाहिए कि शान्ति-स्थापन का संसार में केवल एक ही तरीका है, वह है सहअस्तित्व का, सहयोग का,

और अपनी इच्छानुसार रहने के प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार को स्वीकार करने का ।.....इसमें कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हों, हमें इसी पथ का अनुसरण करना चाहिए ।”

“मैं आपके पास शान्ति और सद्भावना का दूत बनकर आया हूँ । मैंने यहाँ शान्ति और सद्भावना को मूर्त देखा है । मुझे अपने चारों ओर ऐक्य का अनुभव हो रहा है । सुखद भविष्य में मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है । भारत और चीन मिलकर विश्व में शान्ति-स्थापित करने में सफल हों, यह मेरी कामना है ।”

चीन के परराष्ट्र सम्बन्ध पर लिखा गया भावी इतिहास भारत के इस सहयोग के उल्लेख के बिना पूर्ण न हो सकेगा । भारत के सहयोग से सम्बन्धित विवरण में कदम-कदम पर नेहरूजी के नाम का उल्लेख करना इस महत्वपूर्ण इतिहास-लेखक के लिए अनिवार्य सा हो जायेगा, क्योंकि भारत-चीन के पारस्परिक सम्बन्ध के निरूपण में नेहरू जी के योगदान में विशिष्टता है । यह नैतिक मान्यताओं, इतिहास की शिक्षा और मानव समाज के हित की शिक्षाओं के सही मूल्यांकन पर आधारित है । चीन के जन-नेताओं ने स्वयं यह महसूस किया है । इसकी आवश्यकता तब तक महसूस की जाती रहेगी जब तक मानव-समाज कायम रहेगा, और उसके नियमन, नियंत्रण तथा राष्ट्र की व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जाती रहेगी ।

सोवियत रूस और पं० नेहरू

जून सन् १९५५ में पं० नेहरू की रूस-यात्रा का समाचार सुनकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सफेद वालों तथा झुर्रीदार चेहरे से युक्त गंजी खोपड़ी वाले सभी देश के राजनीतिज्ञ सिर हिला हिला कर अपनी बंधी हुई विचार-शैली पर कल्पना के धोड़े दौड़ाने लगे। पूर्वी तथा पश्चिमी देश आगा तथा आशंकाओं से युक्त अटकल बाजियों लगाने लगे। कुछ ने सोचा भारत की नीति बदल रही है, कुछ ने कहा भारत रूस और चीन का पिछू हो साम्यवादी गुट से गठबंधन करना चाहता है। किन्तु कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और परिस्थिति का अध्येता तथा निष्पक्ष आलोचक यह बतला सकता है कि भारत नहीं, अपितु रूस की भारत के प्रति संशंक तथा संवेहात्मक दृष्टि में परिवर्तन हुआ है, जिसका यह शुभ परिणाम है कि दोनों सशक्त पड़ोसी राज्य मित्रवत् एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं।

आज से सात वर्ष पूर्व रूस के प्रमुख समाचार-पत्र भारत और भारत की नीति के विरुद्ध अपने मत प्रकट करते थे। रूस की शिक्षित जनता तथा उसके नेताओं के विचार में, “भारत का तत्कालीन आर्थिक विकास कृत्रिम और भ्रष्ट था, तथा जानबूझ कर भड़काने वाले मतभेदों के फल स्वरूप उसका (भारत का) राजनीतिक जीवन अस्त-व्यस्त था। भारत में शान्ति और व्यवस्था की स्थापना और स्वतंत्र परराष्ट्र तथा गृह-नीति निर्धारित करने का उसका कार्य बाह्य शक्तियों के प्रभाव से संचालित था।” उनके ये विचार, दक्षिणी-पूर्वी-एशिया-युवक-सम्मेलन ने माग लेने वाले एक तसी युवक के. एम. के. प्रमुख पत्र ‘न्यू टाइम्स’ में, अप्रैल १९४८ में प्रकाशित

‘भारत मे दो सप्ताह’ शीर्षक एक लेख के निम्नलिखित अंशो मे व्यक्त उद्गारों से और भी स्पष्ट हो जाते हैं । “ब्रिटिश शासक भारत से ‘हट गये’ हैं । उन्होंने भारत और पाकिस्तान में ‘तथाकथित ‘राष्ट्रीय नेताओं’ को ‘सत्ता हस्तान्तरित’ कर दी है; किन्तु विदेशी साम्राज्यवादियों ने भारत की नीति, आर्थिक व्यवस्था और उद्योग पर पूरा नियंत्रण रखा है ।” उनके विचारानुसार भारत की कोई अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति तथा राजनीतिक दृष्टिकोण न था । इतना ही नहीं सोवियत रूस की भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्बन्ध में भी भ्रामक तथानितान्त गलत धारणा थी । यहाँ तक कि रूसी विश्व-कोषे (Encyclopedia) मे भी उनके सम्बंध में ये आधार हीन बातें प्रकाशित हो चुकी थीं, कि गांधीवाद के प्रतिक्रियावादी सिद्धान्तों का प्रणेता गांधी साम्राज्यवादियों का पिछू और पूँजीपतियों का मित्र है; तथा जब भारत मे जन-आन्दोलन ने क्रांतिकारी-आन्दोलन का रूप धारण किया, इस ‘तथाकथित’ गांधी ने जनता के साथ विश्वासघात कर उसके विरुद्ध साम्राज्यवादियों का साथ दिया । आज इन विचारों का भ्रामक जाल रूसियों के मस्तिष्क से छिन्नमिन्न हो गया है । वे अपनी भयंकर गलती महसूस करने लगे हैं । जिन गांधी जी के सम्बंध मे ऐसे निम्नकोटि के विचार प्रकट कर भारत की आत्मा का अपमान किया गया था उन्हें सुधारा जा रहा है । आज रूस के समाचार-पत्रों एवं नेताओं ने एक स्वर से गांधी जी को प्रगतिशील नेता मानते हुए, ‘उन्हें अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोकतन्त्र वादी’ महामानव के रूप में स्वीकार कर लिया है । वे एक स्वर से कह रहे हैं, ‘प्राच्य के सम्बन्ध मे सोवियत विशेषज्ञों के पुराने दृष्टिकोण पर पुनः विचार किया जाना चाहिए ।’ यह इस बात का प्रमाण है कि रूस स्वयं लौह पर्दे से बाहर आकर, और वस्तु-स्थिति को अपनी आँखों से देखकर वास्तविकता को स्वीकार करने लगा है । ५ जनवरी के ‘न्यू टाइम्स’ में प्रकाशित ‘भारत की प्रगति के ५ वर्ष’ शीर्षक लेख मे उल्लिखित बातों को देखकर भारत के सम्बन्ध मे उनकी युगकारी परिवर्तित मनोवृत्ति की

ओर इंगित किया जा सकता है, “एशिया और विश्व में शान्ति बनाये रखने में भारत के लोगों की गहरी दिलचस्पी है।.....विशिष्ट राज-नीतिज्ञ जवाहरलाल नेहरू (‘तथाकथित राष्ट्रीय नेता’ नहीं) के नेतृत्व में अपने राष्ट्रीय हितों के पक्ष में काम करते हुए सरकार, न केवल दूसरे देशों द्वारा शान्ति की दिशा में उठाये गये अगले कदम का समर्थन करके, बल्कि स्वयं शान्ति को बढ़ाने के उपायों के सम्बंध में अगला कदम उठा कर शान्ति की नीति का अवलम्बन कर रही है।” सन् १९४८ में रूसी जिन्हें ‘तथाकथित राष्ट्रीय नेता’ कहकर सम्बोधित करते थे, आज उनके पथप्रदर्शक गांधी जी तथा पं० नेहरू को वे ‘विश्वशान्ति के प्रतिनिधि’ तथा ‘प्रगतिशील’ कहते नहीं अघाते।

अब हमें देखना चाहिए कि कुछ वर्ष पूर्व भारत के प्रति रूस की भ्रामक तथा असत्य बात फैलाने की इस नीति तथा दृष्टिकोण का क्या वास्तविक कारण तथा तात्पर्य था, एवं किन विशिष्ट परिस्थितियों ने इस विषाक्त वातावरण को छिन्न-भिन्न करने में सहायता दी। यह समझने के लिये हमें तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के कार्यों तथा उसकी नीति एवं उससे उत्पन्न प्रतिक्रिया का सिद्धान्तबलोकन करना होगा। सर्वतंत्र स्वतंत्र गणराज्य भारत की स्थापना के बाद भी उसके राष्ट्र मंडल (Commonwealth) से सम्बन्ध बनाये रखने के निश्चय ने; पं० नेहरू के १९४९ में अमेरिका पदार्पण ने; तथा कोरिया के सम्बंध में आरम्भ में उनकी रूस से सीधी मुठभेड़ आदि ने, उसे (रूस को) यह विश्वास दिला दिया कि भारत परोक्ष रूप से पूँजीवादी गुट के साथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आक्रमणकारी उत्तरी कोरिया के विरुद्ध प्रस्तुत शान्ति-भंग के दोषारोपण के प्रस्ताव का भारत द्वारा समर्थन, तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने, जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था, रूस की इस धारणा को और भी दृढ़ किया। रूसी दूष से पहले कम्युनिस्ट तथा उनके समाचार-पत्रों ने पं० नेहरू पर भारत की किस्मत का सौदा करने तक का दोषारोपण किया। हिन्दुस्तान की ‘बूर्जुआ तथा निम्न कोटि की,’ ‘सङ्घास से युक्त’ सत्त्वानि तथा सम्यता के

‘गंडे कीचड़’ से डूबने की गरज से, पजाना उठाकर चलने वाले यहाँ के एक दामन कम्युनिस्टों ने भी, जो मास्को की ‘उच्च संस्कार-युक्त’ खून से लाल संस्कृति को आदर्शोत्तम तथा ग्राह्य समझते थे, तथा जिनके जिन यहाँ और जिगर ‘सच्चे वनतंत्री’ मास्को के ‘सत्य वातावरण’ में बिचरग करते थे, वस्तुस्थिति को अंधकार में देखते हुए और भारत की वास्तविक नीति तथा सही स्थिति का बिक्र न करते हुए रूसी घटनाओं के प्रचारार्थ जो विष उगला उसने भी रूस को भारत के विरुद्ध गलत धारणा डनाने के लिए प्रेरित किया।

साल्लिन के शासन-काल तक रूस के सोवने और समझने का एक खात तरीका था। मार्क्सवाद ने उसकी बहुत आस्था ने रुढ़िवाज का रूप धारण कर लिया था। उसकी समझ ने मार्क्सवाद मानव मात्र की सभी समस्याओं का समाधान न होकर स्वयं साध्य हो गया था। यही कारण था कि किसी देश द्वारा विश्व-शान्ति तथा मानव-कल्याण के लिए पकड़े गये किसी भी दूसरे रास्ते को रूस संदेह तथा घृणा की दृष्टि से देखता था, और उसे विश्व की सर्वहारा जनता की दृष्टि में नीचे गिराने में वह कोई प्रयत्न नहीं न रखता था। भारत जो गांधीवादी नीति का अवलंब लेकर उस नहान लक्ष्य तक पहुँचना चाहता था, उसके साथ भी रूसी सरकार इसी नीति से पेश आयी। किन्तु साल्लिन की मृत्यु के पश्चात् यह वातावरण तथा दृष्टिकोण छिन्न-भिन्न हो गया।

इस विचार-परिवर्तन का दूसरा कारण था भारत की तटस्थ तथा शान्तिमय वैदेशिक नीति, जिसने अंत में सशक्त राष्ट्रों को अपनी सद्भावना तथा सदुद्देश्य का कायल करा दिया। भारत ने विश्व, विशेषतः एशिया के सघर्ष-रत दलित राष्ट्रों की उन्नति तथा स्वतंत्रता का पक्ष लेकर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार अपनी सशक्त आवाज बुलंद की तथा उसने कोरिया के प्रश्न पर, जब कि विश्व-शान्ति खतरे में थी, संसार को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए जो अद्भुत शान्तिमय प्रयत्न किया, उसके आशा पूर्ण प्रतिफल ने सम्पूर्ण विश्व के शान्ति-प्रेमी राष्ट्रों की भांति रूस

को भी इस बात का कायल करा दिया कि भारत सही माने में शान्ति का रक्षक है, तथा वह किसी भी शक्ति गुट के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता। इसके अतिरिक्त जुलाई १९५३ की कोरिया-युद्ध-विराम-संधि के अनुसार भारत ने बन्दी-प्रत्यार्पण-आयोग के अध्यक्ष-पद से जिस दायित्व तथा ईमानदारी से अपना कार्य पूर्ण किया उसने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके प्रति और भी विश्वास उत्पन्न कर दिया। पुनः जुलाई सन् १९५४ में जेनेवा-सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार न रखते हुए भी भारत ने कोरिया और हिन्दचीन में शान्ति के स्थापनार्थ जो प्रयास किया उससे भी रूस प्रभावित हुआ। मनीला-संधि का भारत द्वारा एशिया के हित के लिए खतरनाक समझकर विरोध भी चीन तथा रूस ने अत्यधिक पसन्द किया। इसके पश्चात् नेहरू की चीन-यात्रा ने रूस के समझ उसकी स्थिति और भाँ स्पष्ट कर दी। चीन और भारत ने पंचशील के सिद्धान्त पर आधारित सह अस्तित्व के सिद्धान्त को मान्यता देकर एक दूसरे को मित्रता के बंधनों में आवद्ध कर लिया था। रूस एशिया में भारत के महत्व से भली भाँति परिचित था। वह यह जानता था कि भारत से सहयोग-प्राप्ति के लिए, तथा चीन और भारत का मैत्री-संबंध अधिक दृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है कि रूस अपनी भारत के प्रति पूर्व-नीति में परिवर्तन करे। वह यह भी जानता था कि एशिया, प्रशान्त और सुदूर पूर्व के क्षेत्रों की समस्याओं को, जिससे युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया है, भारत की मध्यस्थता से हल किया जा सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रूस तटस्थ भारत की मैत्री को विश्व-शान्ति के उद्योग में आवश्यक समझने लगा था, इसलिए उसकी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाना उसके लिए स्वाभाविक था। ऐसी दशा में उसके लिए यह आवश्यक था कि वह अपने देश में भारत के सम्बन्ध में फैली भ्रान्त धारणाओं का पहले निराकरण करे तथा अपने दृष्टिकोण को बदले।

७ जन सन् १९५५ में रूसी प्रधान मंत्री के आग्रह पर भारत के प्रधान मंत्री पं० नेहरू मस्को के केन्द्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचे। उनके

साथ उनकी पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, परराष्ट्र मंत्रालय के सचिव श्री एन० आर० पिल्ले तथा संयुक्त सचिव श्री एम० ए० हुसेन थे। मास्को का केन्द्रीय हवाई अड्डा सोवियत संघ और भारत के गणतंत्र की राष्ट्रीय ध्वजाओं से सुशोभित था। रूस के प्रधान मंत्री श्री बुलगानिन, मंत्री मंडल के अन्य सदस्यों, सेना तथा शासन के सर्वोच्च अधिकारियों, प्रमुख सगपादकों, गण्यमान्य व्यक्तियों तथा प्रेस-प्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रीय गान की गम्भीर ध्वनि के पश्चात् सोवियत संघ के राष्ट्रीय गान के भव्य तराने गूँज उठे। श्री बुलगानिन तथा पं० नेहरू ने 'गार्ड आफ आनर' का निरीक्षण किया। पं० नेहरू ने मित्रतापूर्ण हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, "मैं अपने को एक यात्री समझता हूँ और आपकी सरकार और जनता के लिए महान् शुभेच्छाएँ लिए हुए एक यात्री के रूप में यहाँ आया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे आने से हमारे मित्रता के बंधन और दृढ़ होंगे।"

श्री बुलगानिन के पार्श्व में बैठे पं० नेहरू उस प्रासाद की ओर चले जहाँ मास्को में उनका आवास स्थित किया गया था। लेनिनग्राड राजमार्ग के दोनों ओर कतार बाँधे हजारों लोगो ने शान्ति के दूत पं० नेहरू का अभिनन्दन किया, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सोवियत-भारत-मैत्री के सम्मान में हृष-ध्वनि की, तथा भारत की जनता की समृद्धि एवं शान्ति के लक्ष्य की सफलता के लिए शुभकामनाये प्रकट कीं। गोर्की-मार्ग भी अत्यधिक जनाकीर्ण था। बहुतों के हाथ में फूलों के गुलदस्ते थे। सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगी बृहत् पताकाओं पर ये शब्द अंकित थे। 'भारत के प्रधान मंत्री श्री नेहरू का अभिवादन। स्वागतम्।'।

उसी दिन रूस के प्रमुख साम्यवादी पत्र 'प्रावदा' ने आगत अतिथि पं० नेहरू का अभिनन्दन करते हुए उनके तथा शान्ति प्रिय महान भारत के मित्रतापूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उसने गौरवमय भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हुए, भारतीय

जनता की सोवियत उन्नति और प्रगति के प्रति व्यक्त सहानुभूति तथा संवेदना के लिए कृतज्ञता यापन किया था, तथा बतलाया था कि विश्व-शान्ति तथा मानव-कल्याण के सम्बन्ध में दोनों राष्ट्रों के उद्देश्य एक से हैं। अंत में उसने यह विश्वास प्रकट किया था कि भारत के प्रधान मंत्री की सोवियत-यात्रा दोनों देशों के बीच मैत्री सम्बन्ध और भी सुदृढ़ बनाने में योग देगी तथा विश्व-शान्ति के लक्ष्य के लिए एवं सारे संसार में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम करने में हितकारी सिद्ध होगी।

८ जून को पं० नेहरू ने रूसी प्रधान मंत्री श्री बुलगानिन से, तत्पश्चात् अन्य उच्च साम्यवादी नेताओं से राजनीतिक वार्ता की। उन्होंने वर्तमान सोवियत रूस के प्रणेता लेनिन तथा स्टालिन की समाधि पर जाकर पुष्पाञ्जलि अर्पित की। उसी दिन उन्होंने मास्को का मव्य क्रेमलिन देखने के पश्चात् स्टालिन मोटर-कारखाना भी देखा।

९ जून को सोवियत सघ की सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष श्री वोरोशिलोव से वार्तालाप करने के पश्चात् उन्होंने वायुयान बनाने के एक कारखाने का निरीक्षण किया। आज ही उन्होंने श्री वोरोशिलोव तथा श्री बुलगानिन द्वारा आयोजित भोजन में भी भाग लिया। इस अवसर पर वहाँ के उच्च अधिकारी, राजनीतिज्ञ तथा पत्रकार उपस्थित थे। उन्होंने सोवियत रूस की विशाल कृषि, सिंचाई, जल-विद्युत-स्टेशनों आदि का तथा उनमें प्रयुक्त होने वाले आधुनिकतम यन्त्रों का भी निरीक्षण किया।

१० जून को पं० नेहरू ने मास्को नगर, बाल स्कूलों, भू-गर्भ-स्थित रेलवे स्टेशनों आदि का परिदर्शन किया। वहाँ से वे मास्को-विश्वविद्यालय पहुँचे। वहाँ के वातावरण तथा सर्व सम्पन्न अध्ययनालयों को देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था, “आपसे मिलकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। आपका देश अति विशाल है; लेकिन आपके मस्तिष्क और हृदय की महानता देश की विशालता से भी बड़ी है।”

पं० नेहरू सदल-नल ११ जून को स्टालिनग्राड पहुँचे। वहाँ के उच्च

नेता तथा जनता के हार्दिक अभिनन्दन के बीच अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “स्टालिनग्राड शब्द और उसकी कीर्ति से विश्व परिचित है। यह वही नगर है जहाँ की जनता ने अपनी वीरता न सिर्फ युद्ध में बल्कि शान्ति-काल में भी दिखलाई है।.....मैं अजित एवं विजयी स्टालिनग्राड को भद्राञ्जलि अर्पित करने यहाँ आया हूँ।” मास्को की भाँति यहाँ भी उन्होंने रूसी आर्थिक प्रगति के निर्माण में सहायक तथा तत्पर क्षेत्रों तथा कारखानों का निरीक्षण किया।

पं० नेहरू वायुयान से यूक्रेन पहुँचे जहाँ उनका सर्वोच्च अधिकारियों ने हार्दिक स्वागत किया। इसके अतिरिक्त पं० नेहरू ने सिम्फेरोपोल, क्रीमिया, आलूता आदि प्रदेशों का भी भ्रमण किया। आर्तक के मासूम बच्चों ने उन्हें विशेष रूप से मोहित किया। गाल्टा में पहुँच कर उन्होंने मजदूरों के अनेक स्वास्थ्य-सदन भी देखे।

१३ जून को पं० नेहरू सदल-बल तबिसीली पहुँचे। हवाई अड्डे पर वहाँ की सरकार के उच्च अधिकारियों, पत्रकारों तथा नागरिकों ने उनका स्वागत किया। पं० नेहरू ने अपने अभिनन्दन का उत्तर देते हुए कहा, “आपके इस हार्दिक स्वागत से मैं भारत और सोवियत संघ की जातियों के बीच समानता का अनुभव करता हूँ।” रस्तवी नगर में पं० नेहरू ने विशाल औद्योगिक कारखाने देखे। उन्होंने जार्जियाई-जनतंत्र की मंत्री परिषद् के अध्यक्ष जावाखिश्विली के निमंत्रण पर अपने सम्मान में आयोजित एक भोज में भी भाग लिया।

सोवियत राष्ट्र के इन भव्य प्रान्तों तथा नगरों का निरीक्षण करने के पश्चात् पं० नेहरू ने तुर्कमेन, ताश्कन्त, उजबेक, समरकंद, अल्ताई, लेनिनग्राड आदि प्रान्तों तथा नगरों का भी निरीक्षण किया। हर एक स्थान पर कृषि, जल-वाटी योजनाएँ, जल-विद्युत-संचालन प्रधान औद्योगिक कारखानों आदि का परिदर्शन करने में उन्होंने विशेष दिलचस्पी दिखलायी। उन्होंने सोवियत किसान, मजदूर तथा साधारण जनता की वास्तविक स्थिति का सूक्ष्म रूप से अव्ययन करने का प्रयत्न किया। हर स्थान पर उनका तथा

भारत के विश्व-शान्ति के प्रयत्नों का हार्दिक स्वागत हुआ। एक स्थान पर एक बूढ़े कृपक ने भारत के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा था, “हम जानते हैं कि भारत की जनता और उसकी सरकार युद्ध नहीं चाहती तथा विश्व-शान्ति के लिए प्रयत्नशील है। हम भी युद्ध नहीं चाहते, हम उन्हें प्यार करते हैं जो शान्तिप्रिय हैं।”

३० जून को पं० नेहरू रूस का परिदर्शन करने के पश्चात् सदल-चल मास्को लौट आये। २१ जून को मास्को के सबसे बड़े डिनमो स्टेडियम में आयोजित सोवियत-भारत-मैत्री-सभा में मास्को की अपार श्रमिक जनता तथा बुद्धिजीवियों की हर्षध्वनि के बीच उन्होंने अपना संक्षिप्त भाषण दिया, “.....आपके हार्दिक प्रेम और स्वागत के लिए हम असीम कृत-जता प्रकट करते हैं।.....हम इस महान् देश की जनता के प्रति भारतीय जनता का अभिवादन एवं शुभेच्छायें प्रकट करने आये थे। हम अपने देश और अपनी जनता के प्रति आपके प्रेम और सद्भावों से लदे हुए वापस जा रहे हैं।”

“.....यद्यपि हमने महात्मा गान्धी के नेतृत्व में अपने स्वातंत्र्य-संघर्ष में एक भिन्न मार्ग का अनुसरण किया है, फिर भी हम लेनिन की प्रशंसा करते हैं और उनके दृष्टान्त से प्रभावित हुए हैं। हमारी पद्धतियों में इस अंतर के बावजूद भी, हमारी जनता के भाव सोवियत संघ की जनता की तरफ कभी भी अमैत्रीपूर्ण नहीं रहे।.....”

“हम जनवाद एवं स्वतंत्रता में, तथा विशेषाधिकार के उन्मूलन में विश्वास रखते हैं। हमने अपने देश में शान्तिपूर्ण पद्धतियों द्वारा समाज-वादी ढंग से समाज के निर्माण करने का लक्ष्य अपने सामने रखा है।”

“.....भारत तथा चीन की लोक सरकार ने.....पंचशील के सिद्धान्त स्वीकार किये हैं। ये सिद्धान्त हैं; एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुसत्ता के प्रति सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप, समानता, पारस्परिक लाभ तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व।.....सोवियत-सरकार ने भी इसे मान लिया है। इसमें सन्देह नहीं

है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय आचरण सम्बन्धी ये सिद्धान्त संसार के सभी देशों-
द्वारा स्वीकृत एवं कार्यान्वित हो जायें, तो बहुत-बहुत तक भय और आशं-
कायें दूर हो जायेंगी जिनकी जाली छायाएँ संसार पर पड़ रही हैं।”

“यदि इस दुनिया को प्रगति करना है, वस्तुतः यदि इसको जिन्दा
रहना है तो राष्ट्रों के लिए शान्ति का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता
है। हमारे विचार में शान्ति का अर्थ केवल युद्ध में विरत रहना नहीं है,
वरन् अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की ओर सक्रिय एवं क्रियात्मक रुख अपनाना,
समझौता-वार्ता की विधियों द्वारा अपनी समस्याओं के मुलझाने का प्रयास
करना, तथा हमके बाद विविध प्रकार से राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए सहयोग
में शान्ति स्थापित करना है।.....युद्ध, युद्ध के खतरे, या युद्ध की अवधि
वैधान्तिकों में शान्ति कभी भी स्थापित नहीं हो सकती। भय को दूर करने
और शान्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए निःशर्त्तकण आवश्यक है।”

“हम एक जीवन्त विश्वासघाल संसार में रहते हैं, जो नूतन आवि-
ष्कार एवं नूतन विजय के पथ पर बढ़ता जा रहा है, जहाँ मानव को
अधिकाधिक शक्ति प्राप्त है। हम आशा करते हैं कि यह शक्ति, बुद्धिमानों
एवं नहिष्णुता द्वारा नियंत्रित एवं पन्चालित होगी और हर राष्ट्र सामूहिक
हित के लिए योगदान करेगा।”

“मानव जाति के हित के लिए हमारे देश की जनता तथा संसार के
अन्य देशों के बीच मैत्री एवं सहयोग चिरजीवी हो।”

पं० नेहरू के वक्तव्य के पश्चात् सोवियत-मंत्री-परिषद् के अध्यक्ष
श्री शुल्गानिन ने सोवियत-संस्कार और सोवियत-जनता की ओर से भारत,
भारतीय जनता तथा भारत के राष्ट्राध्यक्ष का अभिवादन किया, तथा
भारत के विज्ञान एवं सभ्यता की सफलता के लिए शुभकामनायें प्रकट कीं।

नेहरू जी ने इसी दिन सोवियत संघ के मंत्री-परिषद् के आर्थिक-
आयोग के अध्यक्ष मे वातें कीं, तथा ब्राडुझ सम्मेलन में भाग लेने वाले
देशों के नाटकोत्थित कूटनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित मंच में भी
शरीक हुए।

२२ जून को सोवियत संघ की मंत्री-परिषद् के अध्यक्ष श्री बुल्गानिन ने क्रैमलिन-प्रासाद में भारतीय गणतंत्र के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल से वार्ता की, तथा उसी दिन उन्हें एक भोज भी दिया, जिसमें प्रख्यात सोवियत राजनीतिज्ञ, पत्रकार तथा नेता उपस्थित थे। यहीं दोनों देशों के अधिनायकों ने मैत्री पूर्ण वातावरण में एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किया। इस वक्तव्य में विश्व की तात्कालिक राजनीतिक घटनाओं पर दृष्टिपात करते हुए, तथा पंचशील के सिद्धान्तों पर आस्था प्रकट करते हुए दोनों देश के प्रधान अधिकारियों ने उसे अपनी राष्ट्रीय नीति में स्थान देने की प्रतिज्ञा की थी। उसमें यह विश्वास प्रकट किया गया था कि ये सिद्धान्त जितने अधिक राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे, शान्ति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा, राष्ट्रों में पारस्परिक विश्वास उतना ही बढ़ेगा और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्ग उतना ही प्रशस्त होगा। इस प्रकार शान्ति का जो वातावरण पैदा होगा, उसमें अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ शान्तिपूर्वक वार्ताओं और मुलह-समझौतों से हल की जा सकेंगी।

इस प्रकार पं० नेहरू द्वारा विश्व-शान्ति तथा मैत्री के सद्बुद्ध्य से की गई ससार की यह प्रदक्षिणा कुशलतापूर्वक पूर्ण हुई। सचमुच आज जन-आस्था प्राप्त पं० नेहरू विश्व के ऐसे महान नेता हैं, जो विनाश के सुख पर खड़े विश्व को स्वर्गीय शान्तिदूत की भाँति जीवन का सन्देश दे रहे हैं। तिमिराच्छन्न विश्व के मायाकाश में वे शान्ति के शशि की भाँति गीतल किरणें बिखेर रहे हैं। वे विश्व के महान देशों की विखरी हुई संहारक शक्तियों को मानवता की विजय के लिए, शान्ति पथ पर चलने का सफल संदेश देने के लिए, अमेरिका गये, रूस गये, चीन गये, तथा विश्व के अन्य भागों में अपना संदेश लेकर पदार्पण किया। उनके सत् प्रयत्नों का ही परिणाम है कि युद्ध के प्रलय की घटाये छटने लगे हैं। दिनोत्तर आकाश स्वच्छ होता जा रहा है, तथा शान्ति की आभा प्रकाशवर्णी होती जा रही है।



नेहरू-सरकार की वैदेशिक नीति

वैदेशिक नीति से तात्पर्य किसी राष्ट्र की उस नीति से होता है जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय जगत में वह अन्य सार्वभौम सत्ता युक्त (Sovereign) राष्ट्रों से अपना कूटनीतिक सम्पर्क निर्धारित करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर अपना मन्तव्य प्रकाशित करता, अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसमें हस्तक्षेप करता है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत के प्रधान मन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों में भारत की वैदेशिक नीति के प्रधान तत्वों का निर्देशन किया, “भारत दूसरे राष्ट्रों के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना नहीं चाहता। हमारा प्रधान उद्देश्य सुव्यवस्थापूर्ण ढंग से अपनी समस्याओं का हल करना, तथा यदि सम्भव हो सके तो दूसरों की सहायता और उनके साथ सहयोग करना है। ऐसा करते समय हम यह प्रयत्न करेंगे कि हम अविवेक और क्रोध के प्रवाह में न बह जायें तथा शान्तिमय प्रस्तावों का वातावरण बनाये रखें। भारत की वैदेशिक नीति का आधारतत्त्व विश्व के सभी राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाये रखना है।”

यही कारण है कि आज भारत विश्व के अधिकतम राष्ट्रों से अपना मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में सफल हुआ है। दोनों ही शक्ति गुट उसे शान्ति का सच्चा रक्षक तथा मानव-कल्याण का इच्छुक मानकर, कम से कम प्रत्यक्ष रूप में, उसके प्रति मित्रता प्रदर्शित करते हैं। हमारे राजदूत करीब-करीब विश्व के सभी प्रभुसत्ता युक्त देशों में हैं तथा उनके

राजदूत भारत में हैं। हमारा सौहार्दपूर्ण सम्पर्क अमेरिका और बृटेन से है। हमारा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध साम्यवादी चीन तथा लाल रूस से भी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पं० नेहरू का कुछ दिवसों पूर्व इन देशों के राष्ट्र-नायकों और उनकी कोटि-कोटि जनता द्वारा साग्रह आमन्त्रण तथा अभूतपूर्व भव्य स्वागत, एवं शान्ति के अग्रदूत के रूप में उनके द्वारा विश्व-शान्ति के हेतु उपस्थित निस्वार्थ पंचशील नीति का ससार द्वारा समर्थन तथा ग्रहण है। आज दुनिया के सभी देश हमें मित्रवत् देखते हैं। हमारी किसी भी राष्ट्र के प्रति विरोधी भावना नहीं है। हम सभी राष्ट्रों की उन्नति की कामना करते हैं। जब तक कोई राष्ट्र हमारे स्वार्थों के हनन का प्रयत्न नहीं करेगा हमारा उससे ऐसा ही सम्बन्ध बना रहेगा।

यद्यपि भारत की वैदेशिक नीति की रूप-रेखा में अपनी बुद्धि की तूलिका से रंग भरने का कार्य, स्वतंत्रता के पञ्चात् पं० नेहरू ने ही किया था, किन्तु उसका प्रस्फुटन और उन्नयन बहुत पहले ही भारतीय इतिहास के पृष्ठों और कांग्रेस के रंग-मंच से हो चुका था। स्वयं नेहरू जी के ही कथनानुसार, “यह नीति हमारे अतीत तथा वर्तमान इतिहास, हमारे राष्ट्रीय संघर्ष तथा उन विभिन्न आदर्शों के समूह से प्रवाहित हुई है, जिन्हें हमने समय-समय पर घोषित किया था।”

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत की अपनी कोई अलग वैदेशिक नीति नहीं थी। उसकी वैदेशिक नीति लंदन-स्थित ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षा के अनुरूप उन्हीं द्वारा निर्धारित होती थी। इसमें शक नहीं कि समय-समय पर कांग्रेस के मंच से इस बात का संकेत अवश्य हो जाया करता था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पञ्चात् भारत की किस प्रकार की परराष्ट्र नीति होगी, यद्यपि उस समय उन संकेतों की ओर कोई विशेष ध्यान न दिया जाता था। स्वतंत्रता के अभ्युदय के पञ्चात् महान भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत तथा उसकी अस्थिर घटनाओं से अपना संपर्क स्थापित किया। उसने विश्व के अन्य प्रभुसत्ता

युक्त स्वतंत्र राष्ट्रों से अपना कूटनीतिक दौत्य सम्बन्ध भी स्थापित किया, तथा गांधीवादी आधारभूत सिद्धान्तों पर अपनी वैदेशिक नीति का निर्माण किया। सितम्बर १९४६ में जब अन्तःकालीन सरकार बनी थी तभी पं० नेहरू को उनके अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के ज्ञान के कारण परराष्ट्र विभाग का कार्य सौंपा गया था। भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के पश्चात् भी प्रधान मन्त्री के दायित्व के साथ-साथ परराष्ट्र मन्त्री का कार्य-भार भी उन्होंने ही सम्हाला।

किसी भी राष्ट्र की वैदेशिक नीति को संक्षेप में ही पूर्णतः वर्णित कर देना अत्यन्त कठिन कार्य है। इस गतिशील ससार में किसी राष्ट्र—जो स्वयं सम्पूर्ण विश्व का एक एकाई मात्र है—की वैदेशिक नीति भी हमेशा स्थिर, एक ही तरह के रुढ़िवादी सिद्धान्तों से पोषित रह कर नहीं पनप सकती। दुनिया की बदलती समस्याओं तथा नये वातावरण से उत्पन्न प्रक्रियाओं के बीच अपना राष्ट्रीय हित संतुलित बनाये रखने के लिए उसे आवश्यकतानुसार अपना रूप परिवर्तित करते रहना पड़ता है।

प्रधान मन्त्री-पद से समय-समय पर दिये गये पं० नेहरू के भाषणों में भारत की वैदेशिक नीति के आधारतत्वों का निर्देशन हुआ है। सत्य पर आधारित हमारी परराष्ट्र नीति के ये आधारतत्व काफी स्पष्ट रहे हैं। पं० नेहरू ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की वैदेशिक नीति का उद्देश्य अपने भरसक विश्व के अन्य राष्ट्रों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुव्यवस्था के लिए प्रयत्न करना है। उनका विचार है, “विश्व की मुक्ति, युद्ध, घृणा या क्रोध से नहीं, बल्कि शान्ति से होगी, क्षमा से होगी, दया से होगी, अहिंसा से होगी।” भारत मानव मात्र के कल्याण के लिए इन आदर्शों की प्राप्ति तथा पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है तथा हमेशा रहेगा।

किन्तु इस कथन का यह तात्पर्य कदापि न समझना चाहिए कि भारत अन्याय तथा अत्याचार का सशक्त विरोध नहीं करेगा। शान्तिपूर्ण

दग से विरोधी तत्वों का निवारण करने में असफल होने पर भी शान्ति की लीक पीटता हुआ वह चुपचाप अपने आत्मसम्मान तथा अधिकारों की निर्मम बलि खड़ा देखता न रहेगा । “स्वतन्त्रता के खतरे में पड़ने पर, न्याय के संकटापन्न होने पर, और आक्रमण की दशा में न तो हम तटस्थ रह सकते हैं, न रहेंगे ।” अतः यदि कोई देश अपने शत्रुतापूर्ण कार्यों द्वारा भारत को हानि पहुँचाने अथवा उसे नीचा दिखलाने का प्रयत्न करेगा तो वह कभी भी हाथ पर हाथ धरे चुपचाप कार्यरों की भाँति बैठा न रहेगा । भारत और पाकिस्तान के अमित्रतापूर्ण सम्बन्ध तथा घटित कार्यकलापों से हमारी यह नीति पूर्णतः स्पष्ट है । भारत पाकिस्तान से बराबर सहभ्राता की भाँति मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयत्न करता रहा । इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कभी-कभी पं० नेहरू ने सीमोल्लंघन भी कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने देश-भाइयों, मित्रों-सहयोगियों तथा समाचार पत्रों की कटु आलोचना भी सहन करनी पड़ी, फिर भी पाकिस्तानी नेताओं ने उनकी पुचकार का जवाब दुल्हती से दिया । जनता की इच्छा के विपरीत भी पाकिस्तान ने जब काश्मीर की शस्य-श्यामला कुँआरी भूमि पर सैनिक-अत्याचार प्रारम्भ किया तब नेहरू-सरकार तथा भारत की जनता क्षुब्ध हो उठी । काश्मीर-सरकार की सहायता की प्रार्थना पर पं० नेहरू ने पाकिस्तान को अपने अनैतिक तथा बर्बरतापूर्ण कार्यों को बन्द करने की चेतावनी दी । उन्होंने काश्मीर को भारत के एक अंग के रूप में स्वीकृत कर उसे सैनिक सहायता देने की माँग को स्वीकार किया । इस समस्या को लेकर वह आज भी विश्व में व्यङ्ग वाणों का अडिग हो साहस पूर्वक सामना कर रहा है तथा शरणागत काश्मीर को हर तरह की मदद करने के लिए प्रस्तुत है । इससे यह प्रतिपादित होता है कि भारत की ‘शान्ति और सुव्यवस्था की नीति’ निष्क्रिय नहीं है, वह सकारात्मक है ।

भारत साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा जातिगत विभेदों का विरोधी

है। हमारी इस नीति और भावना का उद्भव तथा विकास, सदियों के कटु स्वानुभावं के फलस्वरूप हुआ है। हम साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए इसलिए बाध्य हुए क्योंकि हम स्वयं बृटिश साम्राज्यवाद के शिकंजों से जकड़े रहकर उसके भयानक कष्ट का अनुभव कर चुके हैं। स्वानुभव के फलस्वरूप हम यह मली-भौंति जानते हैं कि साम्राज्यवादी राष्ट्र परतंत्र जाति का किस प्रकार शोषण करते तथा उसकी संस्कृति और सम्यता को नष्ट कर उसे पतन की ओर ढकेलते हैं। परतंत्र राष्ट्र की जनता का चरित्रबल तथा नैतिकता गिर जाती है और वह पद-पद पर देश और विदेश में अपमानित होता है।

आज भी भारत भूमि पूर्णतः उपनिवेशवाद से मुक्त नहीं हो पायी है। स्वतंत्रता के पश्चात् भी डच तथा फ्रेंच साम्राज्यवादी सत्ता भारत के अधिकृत प्रदेशों से तीव्र विरोध के पश्चात् भी अपने शासन का जूआ हटाने के लिए तैयार न थी। भारत-सरकार तथा उन प्रदेशों की जनता स्वतंत्रता के लिए शान्तिपूर्ण कोशिश करती रही। भारत के आदर्शों के शान्तिपूर्ण नैतिक तेज, जनता के असहयोग तथा शक्तिशाली राष्ट्रों के दबाव से फ्रेंच सरकार ने तो भारत स्थित फ्रेंच उपनिवेशों को भारत-सरकार को हस्तांतरित कर अपना मित्रता पूर्ण सम्बन्ध बनाये रखा। किन्तु दुनिया की बदलती मनोवृत्ति तथा जनता की अहिंसात्मक क्रान्ति ने भी अब तक डच सरकार की आंखें नहीं खोलीं। सत्ता मदान्ध गोआ-सरकार, अपने जन्मसिद्ध अधिकारों की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध जनता को अपनी पाशविक शक्ति से आज कुचल डालना चाहती है, परन्तु सत्ता की कालिमा पर छाता हुआ सत्याग्रह का तेज कुण्ठित होने के स्थान पर और भी प्रखरतर होता जा रहा है। दुनिया की आंखें धरबस इस तेज की ओर खिंची जा रही है। अपने आधारभूत शान्ति के सिद्धान्तों तथा अपने अपेक्षाकृत अल्प सैनिक साधनों के फलस्वरूप, मौखिक रूप से गोआ-सरकार की नीति की विरोधी होते हुए भी भारत-सरकार उसकी जनता को विशेष सहायता करने में असमर्थ है। गोआ

मे भारत तथा गोआ-स्थित भारतीयों की स्वार्थ रक्षा के अवलोकनार्थ भारत ने मिश्र को नियुक्त किया है ।

भारत ने सिर्फ अपनी भूमि पर स्थित पर-सत्ता-आक्रान्त जनता के ही पक्ष में नहीं, अपितु उन सभी पद-दलित राष्ट्रों की जनता के पक्ष में, जो अपने साम्राज्यवादी स्वामियों की अवांछित सत्ता को उतार फेंकने में सक्रिय हैं, आवाज बुलन्द कर नैतिक सहायता दे रहा है तथा उनकी मोंगो और कायों को मानवोचित बतलाते हुए उनका समर्थन कर रहा है । कांग्रेस के ये विचार नये नहीं हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही वह इनका समर्थन करता रहा है ।

इसी सिद्धान्त तथा मनोभावना की पूर्ति के लिए आज से पूर्व प्रथम महायुद्ध के अन्त के पश्चात् तिलक ने एक पत्र द्वारा १९१९ के शान्ति-सम्मेलन के अध्यक्ष (फ्रान्स के तत्कालीन प्रधान मंत्री) के समक्ष उनकी कार्यवाहियों के विरोध में भावी भारत की नीति प्रस्तुत की थी, “भारत अपने ईश्वर प्रदत्त साधनों से ही संतुष्ट है, दूसरे देशों के आन्तरिक कार्यकलापों में हस्तक्षेप को न तो वह प्रश्रय देता है और न उसकी बाह्य जगत के प्रति कोई महत्वाकांक्षा ही है । अपने विस्तृत क्षेत्रफल, विशाल साधनों तथा अपार जन-संख्या के बल पर ही वह एशिया की प्रधान शक्ति हो सकता है ।”

स्वतंत्रता के पश्चात् भी भारत अपने इस पूर्व कथित सिद्धान्त से स्वार्थ हानि की सम्भावना होते हुए भी नहीं डिगा । जब चीन ने अपने प्राचीन स्वत्वों के अनुसार अवसर पाकर तिब्बत को बल पूर्वक अपने राज्य में मिला लिया तब आर्थिक, प्रादेशिक, राजनीतिक हानि होते हुए भी भारत ने उसके अधिकार को ऐतिहासिक दृष्टि से न्याय पूर्ण होने के कारण प्रसन्नता पूर्वक मान्यता देना स्वीकार कर लिया । भारत के इस नैतिक त्याग से चीन अत्यधिक प्रभावित हुआ तथा वह प्राचीन-काल की भाँति फिर उसका प्रिय मित्र बनने का इच्छुक हो गया ।

स्वतंत्रता के पश्चात् भी भारत अपने इन आदर्शों से डिगा नहीं

और वह बग़र अग्नी भूमि पर स्थित तथा दुनिया के अन्य भागों में प्रकीर्णित उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का नरसक विरोध कर रहा है। राष्ट्रवाद्यक पं० नेहरू के कथनानुसार, "संसार में स्थायी शान्ति तभी स्थापित हो सकती है जब विश्व के समस्त राष्ट्र स्वतंत्र हो जायें एवं सभी जातियों को स्वतंत्रता और सुख प्राप्त हो।" यही नहीं, शान्ति की स्थापना तब तक नहीं हो सकती जब तक साम्राज्यवादी मनोवृत्ति सुखपूर्वक जाँच ले रही है। "शान्ति और साम्राज्य! मूल में ही एक दूसरे के विरोधी शक्तों का अनेकानेक नेत्र है।".....में समझता हूँ कि जब तक साम्राज्यवादी विचार दूर न होगा तब तक हम इस संसार में शान्ति नहीं पा सकेंगे। जब तक साम्राज्य मूछे-फूछे तथा शक्तिशाली रहते हैं; तब तक सम्भव है उनके खुरी लड़ाई न हो, पर तब भी शान्ति नहीं रहती क्योंकि तब संघर्ष और युद्ध की तैयारी भीतर ही भीतर चली रहती है।" साम्राज्यवाद-विरोधी तथा युद्धविरोधी भारत की इस नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण पहले ही हो चुका था। इसका कारण भी था। शान्ति, न्याय और अहिंसा ही हमारे स्वातंत्र युद्ध के अन्त थे। अतः बाह्य और आन्तरिक मानकों में सम्मेलन बिच्छड़ कर हम दुर्गामी नीति नहीं अपना सकते थे। भारत की इस नीति ने स्वतंत्रता के गन्तव्य की गतिविधि नहीं रुका।

यह एक सर्वविदित सत्य है कि जब इस सन्मनोऽ इन्डोनेशिया पर फिर से अग्नी अधिकार-सत्ता स्थापित करना चाहती थी, पं० नेहरू ने इन्डोनेशिया के निवासियों का पक्ष लेकर इसका पूर्ण विरोध किया तथा उस अतहास्य प्रदेश के गृह ने सशस्त्र राष्ट्रों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इसी प्रयत्न को हल करने के लिए उन्होंने दिल्ली में गस्तारू नदियों का एक सम्मेलन भी बुलाई था। पं० नेहरू के प्रयत्न सफल हुए अतः पर अनेक इस साम्राज्यवादी विचार को त्याग देने के लिए दशक डायनना; फलस्वरूप इन्डोनेशिया की स्वतंत्रता आनन्द रही। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप इन्डोनेशिया हमें विश्वास मित्र

के रूप में देखता है। वहाँ के राष्ट्रपति ने भारतीय जनतंत्र के समारम्भ के शुभ अवसर पर भारत में पदार्पण भी किया था।

भारत की यह नीति सिर्फ इन्डोनेशिया तक ही सीमित न रही, वह एशिया में स्थित अन्य साम्राज्यवादी उपनिवेशों को भी स्वतंत्रता के स्वच्छ वायु में विचरण करते देखना चाहता है। पं० नेहरू ने समय-समय पर अपने भाषणों में इसकी ओर संकेत भी किया है, “भारत एशियाई उपनिवेशों को परतंत्रता के क्रूर बंधन से मुक्त राष्ट्रीयता के विशुद्ध वातावरण में विकसित होते देखना चाहता है। वह इन देशों की जनता का गोषण और उत्पीड़न वर्दाक्ष नहीं कर सकता।” “एशिया में विदेशी राष्ट्रों की औपनिवेशिक सत्ता समाप्त होनी चाहिए और वह समाप्त होकर हो रहेगी।” सचमुच अपने जन्म-सिद्ध अधिकार स्वतन्त्रता के लिए अग्रसर वीर सेनानियों को साम्राज्यवादी घृणित भौतिक ताकत कब तक पद दलित कर सकती है? भारत ने अपनी इस उपनिवेशवाद-विरोधी, शान्तिप्रिय नीति का प्रतिपालन विश्व के अन्य दलित प्रदेशों के पक्ष में भी किया।

प्रधान मंत्री पं० नेहरू ने द्यूनीशिया के प्रति भी, जो फ्रेन्च गवर्नमेंट के क्रूर हाथों से स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील था, प्रत्यक्ष रूप से खुल कर अपनी इस नीति का सम्पादन करते हुए सहानुभूति प्रकट की। अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा ने परतंत्र द्यूनीशिया के पक्ष में स्पष्टतः समवेदना प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव भी पास किया था। अतः भारत आज भी दलित देशों के प्रश्न को अपनी नीति में प्रश्रय दे रहा है, तथा उनकी गोषित शापित जनता की स्वार्थ-रक्षा का प्रयत्न कर रहा है।

जब कि ईरान की सरकार ने अपने तेल के उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीय-करण करने के उद्देश्य से कानून बनाये, (जो बृटेन के स्वार्थ पर आघात करते थे) भारत ने उनके इस कार्य के साथ बृटेन से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध होते हुए भी सहानुभूति प्रकट की। यद्यपि भारत ने डा० मुसद्दिक की

अतिरेकता पूर्ण नीति को पसन्द नहीं किया और उन्हें अपने देश में धीरे-धीरे वैधानिक रूप से सुधार करने की सलाह देता रहा; फिर भी उसने ईरान की इस समस्या के प्रति समवेदना की नीति अपनायी तथा अंग्रेजों के उठे गलत कदम की तीव्र भर्त्सना की ।

यही नीति मिश्र की समस्या के साथ भी कार्यान्वित की गई । भारत ने मिश्र देश की जनता की, बृटेन से अपने सैनिकों को वहाँ की भूमि से हटा लेने की, मोंग को वैध बतलाया । हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हर एक राष्ट्र को अपनी आन्तरिक समस्याओं को सुलझाने का स्वयं अधिकार होना चाहिए, तथा उस देश की अनुमति के बिना किसी भी विदेशी शक्ति को उसमें हस्तक्षेप करने का बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए । इन्हीं सिद्धान्तों के प्रतिपादन-स्वरूप आज पं० नेहरू पंचशील नीति को शान्ति का विधायक बतला अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थान दिलाना चाहते हैं । कहने का तात्पर्य यह कि हमने उन सभी राष्ट्रों की नैतिक सहायता की तथा उनके संघर्ष के प्रति क्रियात्मक समवेदना प्रकट की जो अपने साम्राज्यवादी स्वामियों से अपने जन्मसिद्ध अधिकार-स्वतन्त्रता प्राप्ति-अथवा अपनी गृहनीति में सबल राष्ट्रों के बलात् हस्तक्षेप से त्राण पाने की दिशा में उन्मुख थे । इस दिशा में कदम उठा कर हमने विश्व-शान्ति के पथ पर स्थित कंटकों को दूर करने का प्रयत्न किया ।

भारत की वैदेशिक नीति जातिगत विभेदों (Racial discrimination) की विरोधी है । जब हम अमेरिका की उन्नति की प्रशंसा करते हैं, तब वहाँ हन्शियों के साथ किये जाने वाले वर्ताव को अन्यायपूर्ण कहते भी नहीं हिचकिचाते । भारत मानवीय अधिकारों के प्रस्तावपत्र (Charter of Human Rights) का सबसे बड़ा समर्थक है । हमारी सरकार ने दक्षिणी अफ्रिका में डा० मलान की सरकार द्वारा जातिगत विभिन्नता के नाम पर किये गये अत्याचारों का खुलकर विरोध किया । भारत ने दक्षिणी अफ्रिका में जातीय पृथक्करण के कानून के

विरोध में सघर्ष करते हुए भारतीयों के प्रति समवेदना प्रकट की। भारतीय स्वतन्त्रता दिवस (सन् १९५२) के अवसर पर भारतीयों के समक्ष भाषण देते हुए पं० नेहरू ने कहा था कि विश्व में शांति स्थापना तब तक सम्भव नहीं हो सकती जब तक डा० मलान अपनी इस निरंकुश और अत्याचारपूर्ण नीति का त्याग नहीं करते। सिर्फ अफ्रिका में ही नहीं, जातिगत विभेदों के नाम पर विश्व के जिस किसी हिस्से में असहाय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, भारत उनका नैतिक साथ देना अपना कर्तव्य समझता है।

शान्तिप्रिय भारत की परराष्ट्र नीति तटस्थता (Neutrality) की भावना से विशेष अनुप्राणित है। आज जब कि सम्पूर्ण ससार दो शक्ति गुटों में विभाजित हो गया है तथा छोटे-बड़े प्रत्येक राष्ट्र ने लाल या सफेद गुट से अपना चोली-दामन का सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, भारत ने दोनों ही गुटों से अलग रहकर विश्व-शान्ति की रक्षा में प्रयत्नशील रहने का निश्चय किया है। उसने न तो सोवियत गुट में ही अपना नाम लिखाया है और न आग्ल-अमेरिकन गुट से हो गठबन्धन किया है। वह आपसी घृणा से दग्ध दोनों प्रतिद्वन्द्वियों की 'स्वार्थपूर्ण' नीति से अलग रहना चाहता है। किन्तु, इसके बावजूद भी वह दोनों दलों से अपनी नीति के अनुसार मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में सफल हुआ है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में वक्तव्य देते हुए पं० नेहरू ने स्वयं स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, "आज विश्व दो शक्ति-गुटों में विभाजित है, एक आग्ल-अमेरिकन गुट तथा दूसरा सोवियत रूस का गुट। पर भारत इसमें से किसी 'दल' से अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहता। वह भ्रातृत्व चाहता है, मैत्री चाहता है, और चाहता है मानव-समाज की स्वतन्त्रता।"

नेहरू-सरकार की तटस्थता की नीति की सिर्फ विरोधी दल के नेताओं द्वारा ही नहीं अपितु अन्य राष्ट्रों द्वारा भी तीव्र आलोचना हुई, जो उसे दलों के गन्दे दलदल में फँसा देखना चाहते थे। एक ओर तो वे हमारी

वैदेशिक नीति पर 'मूर्खतापूर्ण पलायनवादी नीति' कहकर कटूक्ति कसते थे तथा दूसरी ओर उसे अतल के गर्त के मुख पर ओंख बन्द कर बैठने की नीति बतलाते थे। परिवर्तन के विरोधी कट्टर पंथी राजनीतिज्ञों को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में दोनों दलों से बचकर नवोदित अगस्त भारत अपने अलग व्यक्तित्व के स्थापन में कैसे सफल होगा। भारत के किसी भी गुट में सम्मिलित होने से इनकार करने पर दोनों हां दल उसकी ओर संशंक दृष्टि से देखते थे। दोनों ही गुट की यह धारणा थी कि यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से उसने किसी भी दल से अपना हाथ नहीं मिलाया है फिर भी परोक्ष रूप से किसी न किसी गुट से उसका अवश्य संबंध है। जिस प्रकार पीलिया के रोगी को समी चीजे पीली ही दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार घृणा और प्रतिहिंसा की गर्हित भावना में परिप्लावित ये शक्तिगुट इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके द्वारा उत्पन्न इस वातावरण से बच कर कोई राष्ट्र अपनी आदर्शमय शांतिपूर्ण सिद्धांतों की दुनिया अलग भी बसा सकता है, तथा सच्चे हृदय से उसे मानव कल्याण के लिए हितकर समझ कर उसमें हिस्सा बनाने के लिए अन्य राष्ट्र युद्ध विरोधी राष्ट्रों का आह्वान कर सकता है। दुनिया के उसी विषाक्त वातावरण में पले कुछ राजनीतिज्ञों ने तो भारत की इस नीति को 'राजनीतिक अवसरवादिता' तक कह कर सम्बोधित किया था। उनके अनुसार वह तटस्थ होकर राजनीतिक शतरंजी चालों से लाभ उठाने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। इन सब गलत धारणाओं तथा शंकाओं का परिणाम यह हुआ कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपने मित्र बनाने तथा उनमें अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कर उन पर अपना पूर्ण प्रभाव डालने में कुछ समय तक भारत असमर्थ रहा। किन्तु असत्य का आवरण अधिक समय तक नहीं रह सकता। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मानव कल्याण, न्याय तथा शान्ति की रक्षा के लिए निस्वार्थ प्रयत्न ने उसकी तटस्थ नीति की सार्थकता को स्थापित

कर दिया । आज दोनों ही गुट उसे मन, वचन, तथा कर्म से तटस्थ समझ उस पर विश्वास कर रहे हैं ।

तटस्थता की नीति के फलस्वरूप आज से कुछ ही वर्षों पूर्व, अपने प्रति सर्वोक्त राष्ट्रों के सहयोगाभाव में भारत कुछ समय तक अन्तर्राष्ट्रीय जगत में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में एक दम अकेला दिखलाई पड़ता था । भारत की इस घोषणा को, कि वह हर एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या को निष्पक्ष हो उसकी उपादेयता तथा न्याय की दृष्टि से देखेगा, संदिग्ध तथा असम्मति सूचक दृष्टि से देखा गया । यह पूर्णतः ज्ञात है कि जब फिलिस्तीन का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के विचाराधीन था, भारत ने समस्या सुलझाने के लिए स्वतंत्र इकाइयों से बने हुए संघीय शासन स्थापन करने की राय दी थी, किन्तु अभाग्यवश भारत की इस राय को न तो अरबों ने ही और न यहूदियों ने ही माना । इसका दुष्परिणाम हुआ उस देश में भयंकर रक्त पात, अपार आर्थिक हानि और विभाजन, तथा दोनों ही हिस्सों को कमजोर बनाते हुए इसराइल नामक एक नये छोटे से देश की व्युत्पत्ति ।

भारत अपने अन्तर्राष्ट्रीय स्वार्थ की रक्षा करते हुए सबल राष्ट्रों के विरोध के पश्चात् भी हमेशा निर्भयता पूर्वक न्याय पूर्ण कदम उठाने के लिए तत्पर रहता है । जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया तब पं० नेहरू ने रूस और चीन की अप्रसन्नता के भाजक होते हुए भी सुरक्षा-परिपद में दोषी राष्ट्र के विरुद्ध उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन किया । इसी प्रकार एशियाई राष्ट्रों पर प्रतिरक्षा संगठन के रूप में बलात् लादी जाने वाली मनीला-संधि का, अमेरिका के विपरीत हो जाने का भय होते हुए भी, पं० नेहरू ने विरोध किया । इस सुप्रयत्न के ढंड स्वरूप भारत को जेनेवा-सम्मेलन की सदस्यता से वंचित भी होना पड़ा था । इसके पूर्व भारत ने अमेरिका के इशारे पर प्रतिपादित प्रज्ञान्त क्षेत्रीय राष्ट्रों के संगठन को भी पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था । अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत की नीति न तो अवसरवादी ही है और न पलायनवादी

ही। उसकी तटस्थता न तो निस्सार है न तत्वहीन ही, अपितु सक्रिय है। उसके कथन और कर्म में भेद नहीं होता। उसकी नीति असंदिग्ध है। आज विश्व के समस्त राष्ट्र इस सत्य को मानने के लिए बाध्य हुए। यही कारण है कि आज भारतीय प्रतिनिधियों को शान्ति तथा न्याय का अग्रदूत मानते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत की इसी निष्पक्षता से प्रभावित चीन तथा अमेरिका दोनों ने ही उसे कोरिया-युद्ध-बन्दी प्रत्यार्पण आयोग का अध्यक्ष बनाना स्वीकार किया। यही कारण है कि आज से पूर्व सदेह की दृष्टि से देखने वाले दोनों गुटों के नायक अमेरिका, रूस, चीन के सत्ताधारियों द्वारा भारत की वैदेशिक नीति के प्रणेता पं० नेहरू ने सादर निमन्त्रित होकर जब उन देशों में पदार्पण किया तो अपार जनता ने शान्ति के रक्षक के रूप में उनकी वन्दना की। यह सम्मान पं० नेहरू का व्यक्तिगत नहीं अपितु शांति के प्रतिनिधि महान भारत के प्रधान मंत्री की हैसियत से था।

अब यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या भारत अपनी तटस्थता की नीति से आज के इस विडम्बनापूर्ण राजनीतिक युग में अपने उन आधार-भूत अंतर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों की रक्षा कर सकता है जिनके लिए वह कटि-बद्ध है। इसका यही उत्तर है कि आधुनिक जटिल विश्व में पूर्ण तटस्थता का कोई अर्थ नहीं है। अतः हमारी तटस्थता का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि हम उस गुटबन्दी वाली विशाल राजनीति से दूर रहना पसंद करेंगे, जिससे भविष्य में युद्ध की सम्भावना तथा विश्व की शांति भङ्ग होने की आशङ्का हो। भारत के परराष्ट्र मंत्री पं० जवाहरलाल के समय-समय पर दिये गये वक्तव्यों द्वारा इसे पूर्णतः स्पष्ट किया जा सकता है, “हमारी नीति किसी रूढ़िगत अप्रगतिवादी पद्धति का अनुसरण करना नहीं है; हमारी नीति कार्य की स्वतंत्रता की है। यदि हम यह कहे कि हम पूर्णतः तटस्थ नीति को मानने वाले हैं तो इसका अर्थ इसके अतिरिक्त और कुछ न होगा कि हम हमेशा के लिए जनकार्य से अवकाश ग्रहण

कर रहे हैं, जिसे राष्ट्रीय अर्थ में हम संन्यास कह सकते हैं। कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता, और निश्चित ही हमारी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से पूर्ण अवकाश ग्रहण करने की कोई इच्छा नहीं है।” “जब मानव की स्वतंत्रता तथा उसकी शांति संकटापन्न होगी हम तटस्थ नहीं रह सकते। उस समय तटस्थ रहने का तात्पर्य होगा उन आदर्शों के प्रति विश्वासघात करना जिनका हम समर्थन करते हैं, तथा जिन्हें हम मूर्त रूप में देखना चाहते हैं।” “भारत की परराष्ट्र नीति शान्ति की खोज पर आधारित है, ... यह निश्चयात्मक तथा ओजस्विनी है।” भारत की वैदेशिक नीति में ‘तटस्थता’ शब्द का तात्पर्य है किसी भी प्रकार के अनैतिक युद्ध से दूर रहते हुए उसे बंद करने का प्रयत्न करना।

पूँजीवादी तथा साम्यवादी सत्ता द्वारा उत्पन्न यह युद्ध निष्क्रिय (Cold war) हो अथवा सक्रिय हम इससे दूर रहेंगे। निष्क्रिय संघर्ष कुछ अंशों में सक्रिय युद्ध से भी बुरा है—बुरा भयङ्कर ध्वंस के अर्थ में नहीं बल्कि इस माने में कि वह अधिक अपमान पूर्ण है तथा हमेशा के लिए उच्च आदर्शों से गिरा देने वाला है। हम आज के इस निष्क्रिय युद्ध में सम्मिलित नहीं होना चाहते। हमें इससे कोई मतलब नहीं, कि इसमें कौन सही है तथा कौन गलत रास्ते पर है। हम आपसी घृणा के इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं; क्योंकि इस तरह से न तो हम मानव मात्र की सेवा ही कर सकते हैं न अपने आदर्शों द्वारा संजोई शान्ति की रक्षा ही।

कुछ आलोचकों ने पं० नेहरू की वैदेशिक नीति को उनकी ‘अधिनायक वादी सनक की प्रतिच्छाया जो मन की मौज के साथ बदलती रहती है,’ कहकर भी सम्बोधित किया है। परन्तु ऐसा कहना भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम, कांग्रेस की पूर्व नीति तथा उसके प्रस्तावों, तथा भारतीय नेताओं द्वारा समय-समय पर दिये गये वक्तव्यों से अनभिज्ञता प्रकट करना है। स्वतंत्र भारत की वैदेशिक नीति के आधार तत्त्व किसी एक व्यक्ति के ‘पागलपन की उपज’ नहीं, अपितु कांग्रेस के महान अध्यक्ष-

साथी गत नेताओं के हृदय के खून से सने आदर्शमय विचार हैं, जिन्हें पं० नेहरू ने अपनी वैदेशिक नीति के रूप में पुनर्जीवन दिया।

स्वतंत्रता के पश्चात् भी भारत के ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने के निश्चय ने, तथा अमेरिकन आर्थिक सहायता ने, अनेक राष्ट्रों को यह धारणा बनाने का अवसर दिया कि वह ऐंग्लो-अमेरिकन गुट के प्रभाव से अछूता नहीं है, किन्तु यह आरोप भी आधारहीन तथा तथ्य रहित है। कुछ आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थ वश यदि भारत उक्त राष्ट्रों से अपना सम्बन्ध बनाये रखता है तो इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि उसने उनके हाथ अपने सिद्धान्तों को बेच दिया है और वह उनकी नीति का दास है। जहाँ हमारे सिद्धान्तों—न्याय, शान्ति, स्वतंत्रता—का सवाल होगा हम स्वतंत्रता का बन्धन तोड़कर भी सत्य का साथ देंगे।

यह कहना मूर्खतापूर्ण होगा कि हमारी विश्व के हर एक राष्ट्र से समान मित्रता है; यह प्रत्यक्ष रूप से असाध्य है। भूगोल, वाणिज्य, आर्थिक विचार, सांस्कृतिक सम्बन्ध आदि अनेकों ऐसे सूत्र हैं, जो भारत को अन्य देशों की अपेक्षा कुछ राष्ट्रों से विशेष सम्पर्क स्थापित करने के लिए बाध्य करते हैं। उदाहरणतः उसका अन्य दूरस्थ राष्ट्रों की अपेक्षा एशिया के राष्ट्रों से अधिक घनिष्ठ सम्पर्क होना स्वाभाविक ही है। उसी प्रकार औद्योगिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक सहायता के लिए उसका अमेरिका अथवा इंग्लैण्ड का मुखापेक्षी हो उन पर निर्भर रहना स्वाभाविक ही है। आज अमेरिका के अतिरिक्त कोई भी ऐसा भौतिक रूप में सम्पन्न देश नहीं है, जो भारत को उसकी सर्वतोमुखी उन्नति के लिए वैज्ञानिक यंत्रों, विशेषज्ञों तथा पूंजी आदि अन्य साधनों से पूर्णतः मदद कर सके। इसके अतिरिक्त भारत का सुरक्षा-विभाग (Defence service) ब्रिटिश नमूने पर ही बना है; अतः सुरक्षा के सामानों के लिए उसे बहुत कुछ बृटेन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत और बृटेन दोनों में ही पार्लियामेन्टरी-शासन पद्धति है, जिससे दोनों राष्ट्र एक दूसरे के और भा नजदीक आ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत की

यह नीति अपने हितों तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्मित की गयी है। इस सम्बन्ध का यह कदापि तात्पर्य नहीं हो सकता कि वह नैतिक रूप से भी इनकी कूटनीति से संचालित होता है। भारत की वैदेशिक नीति न तो परमुखापेक्षी है न कोरी आदर्शवाद ही, अपितु वह व्यवहारिक तथा यथार्थतापूर्ण है।

पं० नेहरू ने अपने भाषणों में समय-समय पर इस असत्य आरोप का, कि भारत की वैदेशिक नीति किमी रूप में ऍंग्लो-अमेरिकन नीति से प्रभावित है, उत्तर देते रहे हैं। गत ८ वर्षों से बृटेन तथा अमेरिका से भारत के सहयोग का यह कदापि अर्थ नहीं है कि भारत की वैदेशिक नीति इन देशों के अधीनस्थ है। यदि ऐसा होता तो भारत एक ऐसी नीति का प्रतिपादन कभी न करता जिसे ऍंग्लो-अमेरिकन गुट पूर्णतः नापसन्द करते हैं। यह सर्वविदित है कि विश्व में भारत ही वह सर्व प्रथम सरकार थी जिसने लाल चीन की सरकार को, अमेरिका का विपरीत दृष्टिकोण होते हुए भी, मान्यता प्रदान की। ग्रेटबृटेन ने भी भारत-सरकार का पदानुसरण कर पेकिंग-सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। किन्तु अमेरिकन सरकार ने चीन की इस नयी जनतन्त्रो सरकार को आज तक मान्यता न दी यद्यपि भारत ने उसे राह पर लाने का कोई प्रयत्न वाकी न छोड़ा। अमेरिका के ही दुष्प्रयत्न से ६० करोड़ जनता की प्रतिनिधि लाल चीन की सरकार को उसके अधिकार से वंचित कर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्यायपूर्ण ढंग से सिर्फ कुछ लाख जनता का ही प्रतिनिधित्व करने वाली फारमोसा-स्थित चांग-काई शेक की सरकार को सुरक्षा-परिपद में स्थान दिया। भारत ने इस नीति का खुलकर विरोध किया। पं० नेहरू ने इस विषय पर विचार करते हुए कहा है, “सार्वभौमिकता के जिस सिद्धान्त को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ था उससे वह अलग हट गया है।.....यह उसी प्रवृत्ति का परिचायक है जिससे ‘लीग आफ नेशन्स’ का पतन हुआ।”

इसी प्रकार भारत ने वियतनाम की बाओदाई सरकार को जो साम्राज्यवादी सरकारों की कठपुतली थी, मान्यता प्रदान नहीं की जबकि-अन्य यूरोपीय देशों ने सिर्फ उसे मान्यता ही नहीं प्रदान की अपितु उसकी सब प्रकार से सहायता भी की।

यही नहीं जब चीन के एक अंग फारमोसा का प्रश्न बुद्धिजीवी दुनिया के विचाराधीन था, तथा अमेरिका बलात् लाल चीन के जनराज्य को उस प्रदेश के जन्मसिद्ध स्वत्व से वंचित रखना चाहता था, भारत ने उसकी इस नीति के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द की। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों, तथा उसकी निष्पक्ष नीति को देखकर चीनी अधिनायकों ने पं० नेहरू को चीन में पदार्पण करने को साग्रह आमंत्रित किया। पं० नेहरू इस निमंत्रण को स्वीकार कर वहाँ गये भी। वही उन्होंने चीनी प्रधान मंत्री के साथ एक संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर भी किया, जो उनके पंचशील के सिद्धान्त को मान्यता देता था। ये सिद्धान्त हैं:—

(१) एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान।

(२) अनाक्रमण।

(३) आर्थिक, राजनीतिक और विचारधारा सम्बंधी किसी भी कारण से एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप।

(४) समानता और पारस्परिक लाभ का अनुल्लंघन।

(५) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व।

आज हमारा चीनी-सरकार के साथ मित्रतापूर्ण सम्बंध है। आज रूस भी हमारी मित्रता का इच्छुक है। १९५५ में पं० नेहरू की रूस-यात्रा के अन्तिम समय सोवियत-सरकार ने भी इन सिद्धान्तों को मान्यता प्रदान कर दी। आज विश्व के अनेक शान्तिप्रिय राष्ट्र इन सिद्धान्तों के अनुसार अपनी नीति सञ्चालित करने के लिए तत्पर हैं। भारत के इस पदक्षेप की अमेरिका में अत्यधिक आलोचना हुई। कुछ व्यक्तियों ने तो अमेरिकन 'कांग्रेस' में यहाँ तक प्रस्ताव उपस्थित किया कि भारत को दी

जाने वाली अमेरिकन आर्थिक सहायता बंद कर दी जाये । यदि पं० नेहरू की वैदेशिक नीति वागिंगटन की सरकार के दबाव के अन्तर्गत होती तो वह कदापि ऐसा करने का साहस न करती ।

भारत विश्व की सभी समस्याओं में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहता, यद्यपि वह जानते हुए भी आँख बन्द कर शान्ति के विरुद्ध कुचक्र की मक्खी निगलने के लिए भी तत्पर नहीं है । वास्तव में इस सत्य को कोई भी इन्कार नहीं करेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं तथा अन्य देशों की समस्याओं में महत्वाकांक्षा बग होकर अधिक सिर डालना हमारे अपने राष्ट्रीय हित को संकट में डाल सकता है । दूसरों पर स्थाई प्रभाव डालने से पहले यह आवश्यक है कि हम अपने घर को सम्पन्न तथा सुव्यवस्थित करें, और जब हमारा घर, हमारा अपना देश—महान भारत—आर्थिक औद्योगिक तथा सैनिक दृंग से पूर्ण सशक्त हो जायेगा, तब वह विश्व को आवश्यक अवसरों पर बिना प्रयास प्रभावित करने में तथा उसे शान्ति का सही रास्ता दिखलाने में समर्थ हो पायेगा । भारत की यह बिल्कुल आकांक्षा नहीं है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में अवांछित रूप से हस्तक्षेप कर प्रधान 'रोल' अदा करे । यहाँ तक कि भारत द्वारा एशिया के नेतृत्व की बात भी भ्रमपूर्ण है । अधिक से अधिक एशिया के राष्ट्रों के सम्बन्ध में कार्य करने की उसकी जो इच्छा है, वह है अपने भ्रसक शोषण और दासता के विरुद्ध उनके संघर्ष में मित्रवत् उसकी मदद करना । हाँ, इसमें शक नहीं कि वह सत्य की नैतिक सहायता करने से कभी विमुख न होगा ।

अन्त में यह प्रश्न उठ सकता है कि भारत की वैदेशिक नीति अपने कार्यक्षेत्र में अब तक सफल रही अथवा असफल । इसमें सन्देह नहीं कि आरम्भ में भारत की वैदेशिक नीति, एक विशेष दृढिगत पद्धति से परिचित विश्व के राजनीतिज्ञों को एक अजीब-सी धुली-मिली अव्यवहारिक काल्पनिक आदर्शवाद (Utopian) से प्रेरित लगी; और वह सिर्फ भागत के विरोधी दल के नेताओं द्वारा ही नहीं ग्रहिण्कृत हुई,

बल्कि विश्व के अन्य तथाकथित राजनीतिज्ञों ने भी उसकी कटु आलोचना की; परन्तु आज शंका तथा अविश्वास का बादल छिन्न-भिन्न हो चुका है, आज इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि भारत की वैदेशिक नीति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरी है। सभी यह मानने के लिए तत्पर हैं कि भारत ने विश्व-शान्ति तथा मानव-कल्याण का अग्रदूत बनकर उसकी रक्षा करते हुए आज के विषाक्त धूमिल वातावरण में उसे पुनरुज्जीवित करना चाहता है। भारत ने हमेशा अपनी नीति के अनुसार दो राष्ट्रों को विश्व-शान्ति भंग करते हुए युद्धरत होने से बचाने का प्रयत्न किया है। आज उसके अभिप्राय और उद्देश्य को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखने का अनुचित साहस नहीं किया जा सकता। उसकी निष्कपटता प्रत्यक्ष और खुली हुई है। विश्व के हर कोने में उसके मित्र हैं। अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ही उस पर विश्वास रखते हैं।

किसी भी विषय अथवा नीति को उसकी उपादेयता की दृष्टि से न देखकर बाद विशेष के रंगीन चश्मे से देखने वाले, दल के गन्दे दलदल में फँसे तथा मूल्यांकन की रुढ़िगत तुला को देश, जाति तथा काल की सीमा को भूलकर काम में लाने वाले तथाकथित राजनीतिज्ञों के उत्तर में हम कह सकते हैं; वर्तमान भारतीय वैदेशिक नीति में चाहे कितनी भी त्रुटियाँ क्यों न हों वह असामर्थिक तथा राष्ट्र के लिए अहितकर कदापि नहीं है। भारत की वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक अल्प सम्पन्नता को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इससे उत्तम वैदेशिक नीति देश के हित को ध्यान में रखते हुए दूसरी नहीं हो सकती। आज न तो हममें इतनी शक्ति है, और न भविष्य में स्वहित-रक्षा को छोड़कर हमारी कमी यह इच्छा ही रहेगी कि हम दूसरों को जबर्दस्ती अपनी बात मानने के लिए बाध्य करें। अतः यदि इस नीति में त्रुटियाँ हैं तो भी हमें इसी नीति को, जो आज सबसे अधिक सुरक्षित है तथा जो हमारे आदर्शों द्वारा सिद्धित हुई है, अपनाने

के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं है। अतः प्रेसिडेन्ट ट्रूमन के उन ऐतिहासिक शब्दों को जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के आलोचकों को उत्तर देते हुए कहा था, नेहरू सरकार की वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में भी प्रेषित करना अनुपयुक्त न होगा, “चार्टर अपूर्ण हो सकता है, पर हमारे समक्ष कोई दूसरा रास्ता नहीं।” अन्त में पं० नेहरू की वैदेशिक नीति को पूर्णतः न्याय संगत कहकर उसका समर्थन किया जा सकता है।

यंत्रणा के कान्तार-पथ तथा विकट कूटनीति के गह्वर अन्तराल को चीर कर प्रकट हुई सन्तोष की प्रातः किरण में, आज हम यह आशा करते हैं कि महान भारत पं० नेहरू के उस विराट व्यक्तित्व तथा नेतृत्व से संचालित होकर, जो नई कल्पना, नये आदर्श तथा रचनात्मक एकता से विभूषित है; अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण को जीवित रखकर, सभी कठिनाइयों को पार करता हुआ अपने लक्षित आदर्शों को प्राप्त करेगा, और एक बार फिर अपने प्राचीन गौरव को पुनरुज्जीवित कर विश्व का पथ प्रदर्शित करते हुए वसुधैव कुटुम्बकम् का चिर प्राचीन पाठ पढ़ायेगा।

